खण्ड–518, अंक–07
सोमवार, 9 ज्येष्ठ, शक संवत् 1944
(30 मई, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2022)

(खण्ड-518 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-91
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर श्री अध्यक्ष द्वारा शोकोद्गार	91-92
पिजन हॉल के माध्यम से प्राप्त डायरेक्ट्री में मिली अशुद्धियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	93
राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा चरित्र हनन और राजनीतिक छवि धूमिल करने सम्बन्धी श्री मो0 ताहिर खान की व्यक्तिगत सूचना	93-94
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	94
उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95-97
मा0 सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई ...	97-98
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	98
सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों की नियम-301 की सूचनाएँ स्वीकृत करने का आग्रह	98-99
बिना इन्श्योरेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट तथा बिना फिटनेस के गतिमान सरकारी वाहनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-103
जनपद लखनऊ में सेक्टर-7, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड से लगे हुए चिरैयाबाग गांव के बगल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जमानिया में सम्पर्क मार्ग के कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद अयोध्या के तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम मुगीशपुर में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद लखनऊ की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी नालों की सफाई कराकर उसको ढकवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अशरफाबाद धौरहरा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	105-106

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज में सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में बारून शाहगंज इसौली मार्ग एवं कतिपय अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
जनपद बुलन्दशहर के बाहर की ओर एक रिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण तथा पनियहवा रेलवे ब्रिज के पास बोटिंग व जलयान परियोजना के माध्यम से बिहार व नेपाल को जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के ग्राम लुधौरा के अन्तर्गत पुल/सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत ग्राम सिंहपुर में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत किसानों को ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर का गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज एवं मार्टीनगंज मुख्यालय तथा मुहम्मदपुर के नन्दाव में राजकीय बालक/बालिका विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद कानपुर नगर की चौबेपुर पुलिस द्वारा जातीय आधार पर दुकानदार पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्राम चमरवा में रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत करैल क्षेत्र के ग्राम टूटूवारी में बन्द पड़ी पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	113
जनपद श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कालेज एवं स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	113-114
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के ब्लाक बिलरियागंज में क्षेत्र पंचायत से संबंधित कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम कंजौली से खन्दौली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
प्रदेश में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं मिड-डे मील कर्मियों के लम्बित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम बदरपुर से दोगवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत खेड़ा महासोना रोड पर ईदगाह के सामने से अड़ौली रजवाहा होते हुए जमुनाठेर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के अन्तर्गत नौगढ़ बांध में सेमर साधोपुर गांव में एक लिफ्ट कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत कछौना, पतसैनी में रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में 80 से 100 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत मसकनवां बाजार में स्थित नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ब्लाक नानोत के पाण्डो खेड़ी ग्राम में बरसाती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत हाटा से करमहा मोड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत दो नई तहसीलों का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख में बस अड्डा एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लोक निर्माण विभाग, उन्नाव श्री ओ0पी0 सोनकर के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज सिधौली में आईटीआई भवन का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के चोला औद्योगिक क्षेत्र का विकास कराकर नवीन उद्योगों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र बल्देव नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुए वाहन संख्या-यू0पी032 जी0यू0 5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी पर अधूरे रिंग बंधे के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना के अन्तर्गत ग्राम हिरनही में कस्तूरबा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज के नक्शे में संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम जटपुरा में प्राइमरी स्कूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में लो0नि0वि0 द्वारा ग्राम अलाउद्दीन से ग्राम चकमहमूद तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद झांसी के झलकारी बाई नगर में रोड, ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी कालोनी, सेक्टर-डी से कूड़ा प्रबन्धन संयंत्र को दूर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद अमरोहा की विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत नगलीया जट से ग्राम कोटा तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-705/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (195)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 (सदन के पटल पर रखी गई)	129
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-706/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (196)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 (सदन के पटल पर रखी गई)	129
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-707/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (197)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 (सदन के पटल पर रखी गई)	129
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (200)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गई)	130
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1041/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (202)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गई)	130
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-283/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (234)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	130

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-284/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-2-2017-आदेश (235)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	130
भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-2, वर्ष 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	131
प्रतिवेदन सदन के पटल पर ससमय नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	131
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	131-212
मा0 सदस्यों के भाषण हेतु समय का निर्धारण	213
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	213-228
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	228-229
डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	229
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 21, जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 03, जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 01 व जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	229-232
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 व जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	232
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 11 व जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	233-234
डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 व जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	235
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	235-236
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	236
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	236-237
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	237

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 11 याचिकाएँ (व्यपगत)	237-238
श्री कवीन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	238-239
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	239-240
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	240
श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	240-241
श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	241
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	241-242
श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	242
श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	242
श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	242-243
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिका, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ तथा जनपद अम्बेडकरनगर से 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	243-244
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	244
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 13 याचिकाएँ (व्यपगत)	245-246
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	246

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	246-247
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	247
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	247
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	247-248
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ तथा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	248
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	249
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	250
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	250-251
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	251-252
श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)	252
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	252-253
श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	253
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 31 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई) ..	253-256
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	256-257
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	257

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	257-258
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	258
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	258
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	258-259
श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	259
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	259-260
श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 11 याचिकाएँ (व्यपगत)	260-261
श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई).....	262
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	262
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	262
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	262
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	263
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 08 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	263-264
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	264-265
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 02 तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	265

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री श्यामधनी राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	265-266
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	266-267
श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	267-268
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	268-269
श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	269
श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	269-270
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	270-271
श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	271
श्रीमती पूजा पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 20 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गई)	271-273
सदस्यों द्वारा याचिका के प्रति सक्रियता पर माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा ...	273-274
सदन चलते समय जिले में किसी तरह की बैठक न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश	274
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित) ...	274-278
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित) ...	278-280
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित) ...	280-283
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	283-286

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद अयोध्या के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	287-289
प्रदेश में डी0एल0एड0 कालेज से सम्बद्धता पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर व्यवसायिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) ...	289
जनपद बागपत के ग्राम बाछौड़ में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	289-291
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में गल्ला मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य ...	291-294
जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री योजना के तहत कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	294-298
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	298-299
जनपद कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल के सी0टी0 स्कैन मशीन व अन्य जांच उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	299-300
नत्थियां	301-311

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवी विधान सभा

सोमवार, दिनांक 30 मई, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-358

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
18. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
22. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
23. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह साँगा, श्री — कानपुर नगर
26. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
27. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
28. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
29. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
30. अरमान खान, श्री — लखनऊ
31. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
32. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
35. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
36. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
37. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
42. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
43. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
44. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
47. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
48. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
49. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
50. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर

54. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
55. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
56. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
57. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
58. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
59. ओमकुमार, श्री बिजनौर
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
66. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
70. कैलाश, श्री चन्दौली
71. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
72. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
73. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
76. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
77. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
78. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
79. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
82. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
83. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. चन्द्र प्रकाश, श्री फतेहपुर
85. चेतराम, श्री शाहजहाँपुर
86. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
88. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जयमंगल, श्री महाराजगंज
94. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
95. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
96. जाहीद, श्री भदोही
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
99. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
100. जीत लाल, श्री प्रतापगढ़
101. जैकिशन, श्री गाजीपुर
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
104. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
111. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
112. दिनेश, श्री मेरठ
113. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
114. दुधराम, श्री बस्ती
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
120. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
121. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी

122. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
123. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
124. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
125. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
126. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
132. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
134. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
135. पंकज, श्री जौनपुर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
137. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
138. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
139. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
141. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
142. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
143. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
144. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
145. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
146. पूनम शंखवार, श्रीमती कानपुर देहात
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
151. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
152. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
153. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
154. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
155. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
156. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
157. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
158. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
159. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
160. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
161. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
162. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
163. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बाबूराम, श्री पीलीभीत
167. बाबूलाल, श्री आगरा
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
170. बिजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
171. ब्रिजेश कुमार, श्री उन्नाव
172. बेचई, श्री आजमगढ़
173. बेदी, श्री गाजीपुर
174. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
175. बृजभूषण राजपूत, श्री महोबा
176. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
177. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
178. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
179. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
180. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
181. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
182. मनीष रावत, श्री सीतापुर
183. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
184. मनोज कुमार पाण्डेय , श्री रायबरेली
185. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
186. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
187. मनोहर लाल, श्री ललितपुर

188. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
189. महबूब अली, श्री अमरोहा
190. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
191. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
192. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
193. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
194. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
195. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
196. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर हरदोई
197. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
198. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
199. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
200. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
201. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
202. मेघश्याम, श्री मथुरा
203. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
204. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
205. मोहम्मद हसन रूमी, श्री कानपुर नगर
206. मो0 नासिर, श्री मुरादाबाद
207. मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
208. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
209. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
210. योगेश धामा, श्री बागपत
211. योगेश वर्मा, श्री खीरी
212. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
215. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
216. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
217. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
218. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
219. रमेश, श्री जौनपुर
220. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
221. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
222. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
225. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
226. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
227. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
228. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
229. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
230. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
231. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
232. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
233. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
234. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
235. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
236. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
237. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
238. राजमणि, श्री प्रयागराज
239. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
240. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
241. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
242. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
243. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
244. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
245. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
246. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
247. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
248. राजेश चौधरी श्री मथुरा
249. राजेश त्रिपाठी श्री गोरखपुर
250. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
251. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
252. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
253. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर

254. रामकेश निषाद, श्री — बांदा
255. रामखिलाड़ी सिंह, श्री — सम्भल
256. राम चन्द्र यादव, श्री — अयोध्या
257. रामदुलार, श्री — सोनभद्र
258. राम निवास वर्मा, श्री — बहराइच
259. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
260. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री — बलरामपुर
261. राम फेरन, श्री — श्रावस्ती
262. रामरतन कुशवाहा, श्री — ललितपुर
263. राम सिंह, श्री — प्रतापगढ़
264. राहुल बच्चा, श्री — कानपुर नगर
265. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री — रायबरेली
266. रितेश कुमार गुप्ता, श्री — मुरादाबाद
267. रेखा वर्मा, श्रीमती — औरैया
268. लकी यादव, श्री — जौनपुर
269. लक्ष्मी राज, श्री — बुलन्दशहर
270. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
271. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — खीरी
272. वाचस्पति, श्री — प्रयागराज
273. विकास गुप्ता, श्री — फतेहपुर
274. विक्रम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
275. विजय पाल (आढ़ती), श्री — हापुड़
276. विनय कुमार, श्री — गोण्डा
277. विनय प्रकाश गोंड, श्री — कुशीनगर
278. विनय वर्मा, श्री — सिद्धार्थनगर
279. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
280. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
281. विनोद शंकर अवस्थी, श्री — खीरी
282. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
283. विपिन कुमार 'डेविड', श्री — एटा
284. विपिन सिंह, श्री — गोरखपुर
285. विपुल दुबे, श्री — भदोही
286. विमलेश पासवान, डॉ0 — गोरखपुर
287. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री — गाजीपुर
288. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री — कुशीनगर
289. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
290. वीर विक्रम सिंह, श्री — शाहजहाँपुर
291. वीरेन्द्र चौधरी, श्री — महराजगंज
292. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री — एटा
293. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री — अयोध्या
294. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री — देवरिया
295. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
296. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
297. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
298. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
299. शिव प्रताप यादव, डॉ0 — बलरामपुर
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
301. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 — बरेली
302. श्यामधनी राही, श्री — सिद्धार्थनगर
303. श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
304. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
305. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
306. संग्राम सिंह, श्री — बलिया
307. संजय कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
308. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
309. संजीव अग्रवाल, श्री — बरेली
310. संजीव कुमार गोंड, श्री — सोनभद्र
311. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
312. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
313. संदीप सिंह, श्री — प्रयागराज
314. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
315. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
316. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
317. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
318. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
319. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा

320.	सरवन कुमार निषाद, इंजी0	गोरखपुर	
321.	सरिता भदौरिया, श्रीमती	इटावा	
322.	सरोज कुरील, श्रीमती	कानपुर नगर	
323.	सरोज सोनकर, श्रीमती	बहराइच	
324.	सर्वेश सिंह, श्री	फिरोजाबाद	
325.	सलोना कुशवाहा, श्रीमती	शाहजहाँपुर	
326.	साकेन्द्र प्रताप, श्री	बाराबंकी	
327.	सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	प्रयागराज	
328.	सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	
329.	सुचि, श्रीमती	बिजनौर	
330.	सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	
331.	सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	
332.	सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी	
333.	सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच	
334.	सुरभी, डॉ0	फर्रुखाबाद	
335.	सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया	
336.	सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	
337.	सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	
338.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहाँपुर	
339.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर	
340.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	
341.	सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर	
342.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	
343.	सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री	गाजीपुर	
344.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया	
345.	सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर	
346.	सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ	
347.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	
348.	सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी	
349.	स्वामी ओउमवेश, श्री	बिजनौर	
350.	हंसु राम, श्री	बलिया	
351.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	
352.	हरिओम, श्री	कासगंज	
353.	हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर	
354.	हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़	
355.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज	
356.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज	
357.	हिमांशु यादव, श्री	बदायूं	
358.	हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़	

नोटः- उप मुख्य मंत्री, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास (श्री केशव प्रसाद मौर्य), प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान, कृषि विपणन मंत्री (श्री दिनेश प्रताप सिंह), आयुष, खाद्य सुरक्षा मंत्री (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में कोरोनाकाल में हुई मृत्यु तथा उनके कारणों का ब्यौरा उपलब्ध कराने विषयक

***1-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न कोरोनाकाल में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी हाँ, प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा राज्य स्तर से संचालित कोविड पोर्टल पर अपलोड किये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 महामारी के प्रारम्भ से दिनांक 13-05-2022 तक कोविड-19 रोग के संक्रमण से कुल 23,512 रोगियों की मृत्यु सूचित हुई है।

जी हाँ, विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री रविदास मेहरोत्रा जी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, ये बहुत गम्भीर और लोक महत्व का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में दो साल में कोरोना से जो मौतें हुई हैं, उसका आंकड़ा छिपाया गया है। मान्यवर, हमारे यहाँ जनवरी, फरवरी में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं था। लखनऊ शहर में सबसे पहले एक गायिका ने नाच-गाने का कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में मा0 स्वास्थ्य मंत्री और एक सांसद मा0 दुष्यंत सिंह जी मौजूद थे। उसके बाद उनको कोरोना हो गया और बाद में तमाम लोग उससे संक्रमित हो गये।

मान्यवर, 19 तारीख को एनाउंस किया गया कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा और 24 मार्च को एनाउंस किया गया कि 12:00 बजे रात्रि से सम्पूर्ण लॉकडाउन हो गया। मान्यवर, मेरा पहला सवाल यह है कि जब 19 मार्च को यह कहा गया कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा और 24 मार्च की रात्रि 12:00 बजे से लॉकडाउन हो गया तो यह घोषणा 19 मार्च को क्यों नहीं की गयी कि 24 मार्च से लॉकडाउन हो जायेगा।

[†] छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर मा0 मंत्री जी नहीं दे पायेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा मा0 मंत्री जी ने की थी। जो रिलेवेन्ट प्रश्न है, वह पूछिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, 24 तारीख को लॉकडाउन का एनाउंस किया गया और कहा गया कि सभी ट्रेनें और बसें बन्द हो गई हैं। जो प्रवासी मजदूर थे, जो लोग अपने शहर से बाहर थे, उनको बाहर से लखनऊ आने का मौका क्यों नहीं दिया गया ? मान्यवर, उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? इसीलिए हजारों लोग रास्ते में जब लौट रहे थे। ...

श्री अध्यक्ष-

मा0 मेहरोत्रा जी, आप इस पर अनुपूरक करिए। आप बड़े पुराने सदस्य हैं, इसके ऊपर जो अनुपूरक बनता है, उस पर आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। आपको इस बात का अधिकार है। इससे सम्बन्धित जो भी 1,2, 3 एवं 4 अनुपूरक आपके ध्यान में आता है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी पर बात कर सकते हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसी पर बात कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर थे, उनको लाने का काम नहीं किया गया और मजदूर।...

श्री अध्यक्ष-

इसमें लॉकडाउन का कुछ नहीं है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसको और शार्ट कर दे रहे हैं। इस पर आंकड़ा दिया गया है कि 23 हजार 512 लोग मरे हैं। मान्यवर, यह आंकड़ा पूरी तरह से झूठ है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास जो सच्चा आंकड़ा है, वह हमें दे दीजिये। मैं मा0 मंत्री जी को दे दूंगा, तब पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरे पास आंकड़ा है कि 18 लाख 17 हजार लोगों की उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हुई है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी कोई भी सूचना मत दीजिए, जो उचित न हो।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, यहाँ पर बार-बार कहा जा रहा है कि कोरोनाकाल में कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना से कितने मंत्रियों की मौत हुई और प्रदेश सरकार में वर्तमान में मंत्री पद पर रहते हुए कितने मंत्रियों की मत्यु हुई है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका यह पूछना है कि कितने मंत्रियों की मृत्यु हुई है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसके साथ में दूसरा सवाल यह है कि मंत्रियों के साथ, 13 विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के किसानों के मसीहा, किसानों के नेता चौधरी अजीत सिंह की भी कोरोनाकाल में कोरोना से मौत हो गई। देश के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की मृत्यु हो गई, लेकिन आप कहते हैं कि हमने बड़ा प्रबन्धन किया।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये। मेरा निवेदन है कि आप 4 मिनट से एक प्रश्न तक नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रश्न करिये, नहीं तो मैं दूसरा प्रश्न लेने जा रहा हूँ ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि अगर आपने अच्छा प्रबन्धन किया, तो कितने मंत्रियों की, कितने विधायकों की और कितने पूर्व मंत्रियों की मौत हो गई।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब पटल पर आ गया है और जो इन्होंने अनुपूरक पूछा है कि कुल कितने लोगों की डेथ हुई है, जो आंकड़े हमारे यू0पी0 सरकार के पोर्टल पर हैं, उसमें 23,512 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन समय-समय पर मृत्यु जैसे गम्भीर दुख के समय भी, राजनीतिक दलों ने इस पर भी राजनीति की। मा0 अध्यक्ष जी, कुछ लोग मा0 सर्वोच्च न्यायालय चले गये और सर्वोच्च न्यायालय में दो मुकदमे इसमें दायर एक मुकदमा गौरव बंसल वर्सेज भारत सरकार और दूसरा मुकदमा रीपक कंसल वरसेज भारत सरकार है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप यह कह रहे हैं कि सवाल यह नहीं था तब सवाल यह भी नहीं था कि लॉकडाउन उन्होंने क्यो लगाया था और क्यों नहीं लगाया था। मा0 मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये, उसके बाद आप पूछिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर 23512 लोगों की कोरोना से डेथ होने के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद मा0 सर्वोच्च न्यायालय में मामले दाखिल हुए, मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह डायरेक्शन दिया कि कोरोना महामारी से जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि दी जाये, फिर यह तय हुआ कि यह आंकड़े हो सकता है कि पूरे ना हों। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कोविड मैनेजमेंट के लिए हमने पोर्टल बनाया था, पोर्टल पर जैसे ही किसी व्यक्ति को कोरोना महामारी की सूचना मिलती थी हम उसको दर्ज करते थे, और हम कोरोना की जांच कराते थे। निगेटिव या पाजिटिव आने पर ही हम उससे निकल सकते थे। सारे के सारे आंकड़े हमारे पोर्टल पर दर्ज होते थे, फिर भी कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की कि कोरोना के निगेटिव होने के 1 महीने के अन्दर भी लोगों की डेथ हुई है। तब मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे सभी लोगों को जो कोरोना महामारी से निगेटिव हो गये हैं, 30 दिन के अन्दर उनकी डेथ हो गयी है उनका भी आंकड़ा एकत्र किया जाये। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी समाचार माध्यमों में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में इस बात का विज्ञापन प्रकाशित कराया कि जिन सभी लोगों की उनके परिजनों ने अपील की जिनकी मृत्यु कोरोना महामारी से या कोरोना महामारी के 30 दिन के अन्दर हुई है या केवल शंका है, कोरोना से डेथ हुई कृपया दरख्वास्त दें। उनको हम अनुदान राशि जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है हम उपलब्ध करायेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास मा0 अध्यक्ष जी, 41 हजार 8 सौ 71 पत्र हमें प्राप्त हुए, उसमें से 39 हजार 2 सौ 67 लोगों को जो अनुदान राशि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था उनको हमने भुगतान किया था। 1774 मामले रिजेक्ट किये गये हैं। जिला अधिकारी महोदय प्रत्येक जनपद में ए0डी0एम0 और सी0एम0ओ0 की कमेटी बनाकर, उन सभी दरख्वास्तों पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कराये, उसके बाद 39 हजार 667 लोगों को भुगतान किया गया है। 830 सूचनाएं ऐसी मिली हैं जो अभी प्रक्रियाधीन हैं उनका एड्रेस वेरीफिकेशन हो रहा है जो एड्रेस उन्होंने दरख्वास्त में लिखा है वह वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं या कुछ कागज की कमी है। पूरी सूचना हमने मा0 सदस्य के प्रश्न के अनुसार उपलब्ध करा दी है जहाँ तक इन्होंने मंत्रियों, विधायकों के बारे में पूछा है। चूंकि यह सप्लीमेंट्री में था, हम उनको तत्काल लिखित रूप में सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 रविदास जी आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 सदस्य जी, मा0 मंत्री जी को यह मालूम ही नहीं है कि कितने मंत्रियों की मृत्यु हुई है। आप इसको नियम-49 में स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

स्वीकार करना या न करना मेरा अधिकार है, आप दे दीजिये, मैं उसको देख लूंगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है और आप नियम-49 में आधे घंटे की चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि 39 हजार से ज्यादा लोगों को हमने मुआवजा दिया है, इसका मतलब आपने कोरोना से मृत्यु होना स्वीकार कर लिया। तो मुख्य उत्तर में मृतकों की संख्या 23,512 क्यों लिखा गया ? इन दोनों आंकड़ों में विरोधाभास है, इसलिए इसका जवाब दे दें।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो यू0पी0 गवर्नमेंट का पोर्टल था जिस पर हम मरीजों की कोरोना में जांच करते थे। प्रारम्भिक रिपोर्ट में जिसको भी कोरोना प्रदर्शित होता था, कोरोना महामारी की जांच होते ही उस रोगी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। पाजिटिव से निगेटिव होने के बाद ही पोर्टल बन्द होता था। उसके अनुसार मृतकों की संख्या 23,512 है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि कहा था कि कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद 30 दिन के भीतर भी अगर कोई मरा है तो उसको भी आपको मुआवजा देना है, इसलिए इस संख्या में अन्तर आया है।

प्रदेश के जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं हैं, उन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, प्रदेश के 27 जनपदों यथा-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, हापुड़, अमरोहा, बाराबंकी, बरेली, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, उन्नाव में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं खोले जा सके हैं।

प्रदेश के उपर्युक्त 27 जनपदों में से जहाँ पर कोई भी राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान तथा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्राइवेट मेडिकल कालेज नहीं हैं, ऐसे 16 असेवित जनपदों यथा बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सापेक्ष जनपद महराजगंज एवं सम्भल में प्राइवेट पार्टनर चिन्हित कर कन्सेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हो गये हैं, तथा शेष 14 जनपदों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था कि प्रदेश के कितने ऐसे जनपद हैं जहाँ पर अभी तक मेडिकल कालेज स्थापित करने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि प्रदेश में 27 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर हम अभी तक मेडिकल कालेज स्थापित नहीं किये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटे-छोटे दो प्रश्न हैं, पहले तो माननीय मंत्री जी हमको यह बता दें कि जिन जनपदों में मेडिकल कालेज बन रहा है या बनाने की प्रक्रिया चालू है, माननीय मंत्री उन जनपदों के चयन का मानक क्या रखे थे कि हम इन जनपदों का चयन करेंगे। दूसरा आपने बताया कि 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज स्थापित करेंगे तो क्या इन जनपदों के लिए सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सरकार अपने फण्ड से वहाँ मेडिकल कालेज बनाये। पिछली सरकार से यह बात आ रही है कि हम इनको पी0पी0पी0 मोड पर बनायेंगे तो पी0पी0पी0 मोड पर बनाने की एक प्रक्रिया होती है कि हम बिड कब करेंगे और बिड में कितने बिडर आये, तो यह सालों साल से प्रक्रिया चली आ रही है और जब भी सदन बैठता है और प्रश्न लगता है तो वही उत्तर आ रहा है कि हम 16 जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज बनाने जा रहे हैं। आप पी0पी0पी0 मोड पर बनाने जा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई समय-सीमा है ? इन दोनों का पहले उत्तर आ जाये, फिर मेरा तीसरा अनुपूरक प्रश्न होगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, 27 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर अभी राजकीय मेडिकल कालेज नहीं हैं। माननीय सदस्य ने विस्तृत रूप से पूछा है कि कुल कितने राजकीय मेडिकल कालेज हैं तथा कितने

निर्माणाधीन हैं ? अभी 33 जनपदों में 35 मेडिकल कालेज हमारे पास उपलब्ध हैं। 15 मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। निजी मेडिकल कालेज 19 जनपदों में 31 हैं। निजी प्लस राजकीय मेडिकल कालेज 8 जनपदों में हैं जिनको मिला करके 19 हैं। पी0पी0पी0 मोड पर 16 हैं, दो जनपदों का हमने पी0पी0पी0 मोड पर कर दिया है। इसमें सम्भल और महराजगंज शामिल हैं। शेष 14 जनपदों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ने एक सवाल और किया है कि राजकीय और प्राइवेट में देने का मानक क्या है, तो ये मरीजों की संख्या के आधार पर हमने आंकड़ा एकत्र किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अधिक रोगी गम्भीर रोगों के हैं, उनका आंकड़ा एकत्र करके हमने उस आधार पर निर्णय लिया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि जिन जनपदों में मेडिकल कालेज बन रहे हैं, उन जनपदों का चयन का मानक क्या है और हम किस जनपद में मेडिकल कालेज बनायेंगे, उसमें माननीय मंत्री जी ने रोगियों का आंकड़ा रखा है।

माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि मेरा यह सवाल इसमें नहीं है, न मा0 मंत्री जी उत्तर दे पायेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अगले सवाल का जवाब गलत सिद्ध होगा आपने रोगियों की संख्या के आधार पर जनपदों का चयन किया है। यहाँ प्रभावशाली नेताओं, मंत्रियों या सौ-सौ के हिसाब से उन जनपदों का चयन हुआ है। मैं चूंकि बलिया जनपद की बात कर रहा हूँ। बलिया जनपद से मैं कई बार विधायक बन रहा हूँ। जैसे हमारे गाजीपुर में, देवरिया में बन रहा है मुझे कोई शिकायत नहीं हैं देवरिया से गोरखपुर की दूरी 50 कि0मी0 है, वहाँ पर एम्स है, दो-दो, तीन-तीन मेडिकल कालेज हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो आप बता रहे हैं अगर यह आधार होता तो आपके रहते हुए बलिया में सबसे पहले बनना चाहिए था। आपसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से हमारे सम्बन्ध भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, पुराने साथी भी हैं तो कम से कम क्या एक जनपद बलिया को वरीयता पर देकर बनवा देंगे ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर उमाशंकर जी यही सवाल कर देते कि राजकीय बना दो तो हम छोटे भाई का जरूर ख्याल करते, लेकिन सवाल है तो जवाब हमें देना ही पड़ेगा। हम दावे के साथ सभी मा0 सदस्यों से कहते हैं कि पूरे प्रदेश में दवाइयों की जितनी भी बड़ी कम्पनियां हैं, उनके हेडक्वार्टर गोरखपुर और पूर्वांचल में हैं। आप देखेंगे कि गोरखपुर का जैसे उदाहरण दिया कि एम्स वहाँ पर है, मेडिकल कालेज वहाँ पर है तो वहाँ पर मरीजों की संख्या भी बहुत

है। इन्सेफलाइटिस के बारे में हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया यह नहीं जान पा रही थी कि इन्सेफलाइटिस क्या है ? बच्चे काल-कलवित हो रहे थे। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जिन्होंने लोक सभा में सदस्य रहते हुए संसद में कई बार इस विषय को उठाया कि इन्सेफलाइटिस की पहचान होनी चाहिए और जब वह मुख्य मंत्री बने तो संचारी रोग अभियान छेड़कर उस पर कंट्रोल किया। चूंकि सदन में मैं कह सकता हूँ कि जब हम लोग अभी गुजरात गये थे तो वहाँ पर देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था। बेस प्रेक्टिस किस-किस राज्य में कौन सी चल रही है तो जे0ई0एस0 और ए0ई0एस0 के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जापानी इन्सेफलाइटिस पर बेहतर ढंग से कंट्रोल किया गया है। आप भी यह जान लीजिये कि बलिया की भी हम चिन्ता करते हैं। बलिया तो वैसे भी बागी कहा जाता है। बलिया के बारे में मैं आपको खुला ऑफर सदन में दे रहा हूँ। आपके पास तो भगवान कुबेर का आशीर्वाद है, मैदान में आइये, पी0पी0पी0 करिये, हम आपको दिये दे रहे हैं।

(सदस्य श्री उमाशंकर सिंह जी द्वारा खड़े होकर प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब छोटे भाई और बड़े भाई की आपस में बात हो गयी है। आप लोग आपस में बात कर लीजियेगा, हो जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कालेजों के शिक्षकों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधा देने के सम्बन्ध में

***3-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उक्त मेडिकल कालेजों के शिक्षकों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधायें देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्थापित फेज-1 के 05 मेडिकल कालेजों में, वर्तमान में एम0बी0बी0एस0 का तृतीय बैच एवं फेज-2 के 08 मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 का प्रथम बैच संचालित है।

उक्त मेडिकल कालेजों में एन0एम0सी0 के मानक की पूर्ति एवं शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। इन सृजित पदों पर नियमित चयन एवं संविदा के आधार पर लगातार भर्ती की जाती है, ताकि मेडिकल कालेज में पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

उक्त मेडिकल कालेज, एस0जी0पी0जी0आई0 की भांति सुपर स्पेशियलिटी की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रचलित नीति के अनुसार इन मेडिकल कालेजों के संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैंने सवाल किया था कि क्या शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो दूर क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कालेज या स्वशासित मेडिकल कालेज बने हैं, इनमें शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एस0जी0पी0जी0आई0 की भांति समकक्ष वेतन देने का काम करेंगे तो मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि इतने-इतने मेडिकल कालेज हैं, और यू0जी0सी0 की ग्रांट के अनुसार उनको वेतन अनुमन्य है, इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो राजकीय मेडिकल कालेज बड़े शहरों के अतिरिक्त हैं, उन मेडिकल कालेजों में या जो स्वशासित मेडिकल कालेज हैं, इनमें शिक्षकों की कमी कितने प्रतिशत है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय प्रश्न से जुड़ा नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रश्न ही देख लें। क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उक्त मेडिकल कालेजों के शिक्षकों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समकक्ष वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर सरकार विचार करेगी ? कमी तो पहले से है, अब अगर कह रहे हैं कि प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है तो आप ही निर्णय करिये ?

श्री अध्यक्ष-

उसमें मेरा निर्णय नहीं है। मा0 मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की है, मेडिकल कालेज अभी जिले के हिसाब से चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से तो बहुत लम्बा हो जायेगा। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कालेज के बारे में पूछा है, जिलों से पूछ लेते तो पूरी जानकारी मिल जाती।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं जैसे राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर जिले में है, उसी की जानकारी दे दें कि वहाँ पर कितने प्रतिशत शिक्षक हैं ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, माननीय सदस्य जोकि स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं इनको सब पता है और जानबूझ कर अंजान बन रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह जानते हैं कि

एस0जी0पी0जी0आई0, लोहिया, पी0जी0आई0सी0एच0 जो सुपर स्पेशियलिटी के हमारे अस्पताल कहे जाते हैं। वहाँ हम अलग वेतनमान देते हैं और जो स्पेशियलिटी अस्पताल हैं जहाँ पर एम0बी0बी0एस0, एम0एस0 और एम0डी0 की पढ़ाई होती है, उनको अलग वेतनमान देते हैं। आप की डिमांड यह है कि जो सुपर स्पेशियलिटी के हमारे अस्पताल कहे जाते हैं जहाँ पर न्यूरो, नेफ्रो, कैंसर, गैस्ट्रो, डी0एम0 और एम0सी0एच0 की पढ़ाई होती है उनका वेतनमान हम गांव वाले मेडिकल कालेजों को दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक नियम बनाना पड़ता है। अगर हम नियम बराबर तोड़ते रहेंगे, सदन नियम तोड़ दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तैयार हैं लेकिन जो सर्वोच्च शिक्षा संस्थान हैं जहाँ एम0सी0एच0, डी0एम0 की पढ़ाई होती है वहाँ पर वेतनमान अलग है और जो साधारण ढंग के मेडिकल कालेज हैं जहाँ पर एम0बी0बी0एस0 और एम0डी0 की पढ़ाई है उनका वेतन अलग है, उससे संबंधित इनका सवाल है। माननीय सदस्य अगर आपकी स्पेसिफिक रूप से कोई सूचना है आप जो कमी के बारे में कह रहे हैं तो मैं अगले प्रश्न में जवाब दूंगा लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं लिखित रूप से भेज दूंगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से 2022 के बीच में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद हमारे पास मात्र 13 मेडिकल कालेजेज थे हम वहाँ पर सीमित संख्या में डॉक्टर बना रहे थे। सीमित संख्या में एम0डी0 और डी0एम0 की पढ़ाई करा रहे थे। आप सोचिये कि जिन परिस्थितियों में हमें देश मिला था, बाहर से हम चिकित्सक बुला नहीं सकते थे। बाहर से आकर लोग काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सभी जनपदों में 75 जनपदों में मेडिकल कालेज खुलकर के चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है और हम उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जानबूझ करके अंजान बन करके काम नहीं कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस चिंता में मैं भी शामिल हूँ। सुपर स्पेशियलिटी का अब कोई मानक अलग नहीं रह गया है कि यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा। इलाहाबाद में भी सुपर स्पेशियलिटी जैसी पढ़ाई होती है कई सब्जेक्टों में तो सारे मेडिकल कालेज में जब तक सुपर स्पेशियलिटी के कोर्स नहीं चलेंगे वह मेडिकल कालेज पूरी तरह से संचालित नहीं माने जायेंगे। इसलिए आपका यह ऐम होना चाहिए कि पहले सुपर स्पेशियलिटी का कोर्स सब जगह हो जाये लेकिन उसके लिए पहले एम0डी0 और एम0एस0 की कक्षाएं हों। आप शिक्षक की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कालेज खोलते जा रहे हैं और कक्षाएं वहाँ पर एम0बी0बी0एस0 की मान्यता वाले शिक्षक नहीं हैं तो जब तक शिक्षक की कमी दूर नहीं होगी एम0एस0 और एम0डी0 दस साल से संचालित 11 माह से संचालित अम्बेडकरनगर के मेडिकल कालेज में अगर एम0एस0 और एम0डी0 की कक्षाएं इसलिए नहीं शुरू हो पाईं कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है तो उस शिक्षकों

की कमी दूर करने के लिए मान्यवर, जैसे 90 हजार रुपये असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन है जोकि संविदा पर है एक लाख बीस हजार रुपये एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन है अगर कोई डॉक्टर अच्छा सर्जन है तो वह एक दिन में उतना पैसा कमा ले रहा है। वह आपके यहाँ पर शिक्षक बनने क्यों जायेगा। जब तक इस यथार्थ को आप स्वीकार नहीं करेंगे और उसको कम से कम एस0जी0पी0जी0आई0 और लोहिया इंस्टीट्यूट में वहाँ पर एम0बी0बी0एस0 की भी पढ़ाई हो रही है और के0जी0एम0यू0 में भी एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई हो रही है। एम0बी0बी0एस0 में भी पढ़ाने वाला डॉक्टर भी वही वेतन पा रहा है जो इलाहाबाद में सुपर स्पेशियलिटी न्यूरो सर्जरी नहीं है। जिन सब्जेक्टों में सुपर स्पेशियलिटी है उसमें पढ़ाने वाला जो वेतन पा रहा है वह साधारण वेतन पा रहा है। वह सुपर स्पेशियलिटी का वेतन नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विसंगति को दूर करने के लिए कि क्या माननीय मंत्री जी जो लखनऊ मेडिकल कालेज में पढ़ाने वाले शिक्षक चाहे वह एम0बी0बी0एस0 में पढ़ा रहा हो चाहे सुपर स्पेशियलिटी में पढ़ा रहा हो या लोहिया इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो या सैफई में पढ़ाने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हो चाहे वह एम0बी0बी0एस0 पढ़ा रहा है या चाहे वह सुपर स्पेशियलिटी में पढ़ा रहा है उसी के भांति जितने भी अन्य मेडिकल कालेज हैं चाहे वह अम्बेडकरनगर के हों चाहे वह सहारनपुर के हों, बांदा के हों, आजमगढ़ के हों, कन्नौज के हों, उरई के हों, उनको भी वही वेतन देने की कृपा करें। मेरा यही आग्रह है।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, एस0जी0पी0जी0आई0 को जो हम वेतन देते हैं वो ऐम्स के बराबर देते हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 के बराबर हम के0जी0एम0यू0, लोहिया, पी0जी0आई0, पी0जी0आई0सी0एच0 नोएडा को देते हैं। अब माननीय सदस्य की यह चाहते है कि जो सारे मेडिकल कालेजेज जहाँ पर उच्च स्तरीय पढ़ाई नहीं होती है उनको भी वही वेतनमान दिया जाये। मुझे लगता है कि सवाल से ज्यादा इनका सुझाव है और सुझाव पर हम विचार करेंगे और जैसा हो सकता है वह जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न संख्या-04 मा0 अवधेश प्रसाद जी का है।

फसलों को सांड़ों एवं छुट्टा जानवरों से बचाने की नीति अथवा योजना बनाने के सम्बन्ध में

***4-श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रसन्न कुमार, इं0 बृजेश कठेरिया तथा पंकज कुमार मलिक-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को गौवंश आश्रय स्थलों से गौवंश सुपुर्द किये जाने हेतु दिनांक 08 अगस्त, 2019 को मा0 मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ हुई है। इसके साथ ही कुपोषण से ग्रसित बच्चों के परिवारों को दुधारू गौवंश सुपुर्दगी में दिये जाने की व्यवस्था है।

उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 15-05-2022 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित 6187 गौ आश्रय स्थलों (अस्थायी गौ आश्रय स्थल/कान्हा गौशाला/कांजी हाउस/वृहद गौसंरक्षण केन्द्र) में कुल 838015 गौवंश संरक्षित हैं। मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत तथा कुपोषित परिवारों को 131288 गौवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। इस प्रकार कुल 969303 निराश्रित गौवंशों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त संरक्षित गौवंश को रुपये 30 प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अवधेश जी, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया गया। आप अनुपूरक कर लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का सवाल है और प्रदेश के 80 फीसदी किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। आज स्थिति यह है कि किसानों की रात घर में नहीं बीत रही है, खेतों में सांड़ों और छुट्टा जानवरों को रखाने में बीत रही है और सांड़ फसल भी खाते हैं, गुर्राते भी हैं और जान भी लेते हैं। मा0 मंत्री जी और सरकार से मेरा सीधा सवाल था कि किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है, उसका विवरण दें ? सरकार की तरफ से, मा0 मंत्री जी की तरफ से तथा विभाग की तरफ से इस विषय पर किसी प्रकार का कोई सार्थक उत्तर नहीं दिया गया। श्रीमान, आप बहुत ही अनुभवशील हैं और आपके बैठने से इस कुर्सी की शोभा बढ़ी है इसलिए मैं आपसे केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे सवाल को देख लें और उस पर मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को भी देख लें। निश्चित तौर से आपका जो न्याय होगा और आपका जो आदेश होगा वह सिरमाथे पर होगा। इन्होंने छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने के

सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है, बल्कि उससे हटकर इन्होंने गौशालाओं की चर्चा की है। इस सरकार को गौशालाओं में कितनी महारत हासिल है, गौशालाओं में जो जानवर रखे गये हैं। चाहे वह गाय हों, चाहे वह सांड़ हों, रोजाना दर्जनों की संख्या में वह मर रहे हैं। उनको न भूसा मिल रहा है न पानी मिल रहा है न चारा मिल रहा है और न दवाई मिल रही है। उसमें भी यह फेल है। इसलिए मेरा सीधा सा सवाल है कि मा0 मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें कि किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने की इनकी क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अवधेश प्रसाद ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न ही गलत है। इन्होंने छुट्टा जानवरों के बारे में प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह छुट्टा जानवर नहीं हैं, बल्कि यह छोड़े गये जानवर हैं। छुट्टा जानवरों में और छोड़े गये जानवरों में जमीन-आसमान का अन्तर होता है और यह जानवर किसके द्वारा छोड़े गये हैं वह भी सबको विदित है। जिनको आप छुट्टा जानवर कहते हैं कि यह छुट्टा जानवर हैं, हम उनको निराश्रित गौवंश कहते हैं। मैं आपके द्वारा मा0 सदन और सभी मा0 सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि गायें जब तक दूध देंगी तब तक यह उन्हें अपने घरों में रखेंगे, लेकिन जब वह दूध देना बन्द कर देंगी तब उनको छोड़ देंगे। यह पशु कहीं बाहर से नहीं आये हैं, बल्कि यह सभी इन्हीं के द्वारा छोड़े गये पशु हैं जिनको यह छुट्टा जानवर कहते हैं। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस तरीके से यह लोग अराजकता फैलाने के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं। हमारी सरकार को अभी मात्र दो महीने ही हुए हैं और दो महीनों में ऐसा कौन सा सांड़ या गौवंश हो गया जो फसल को रौंदने का काम कर रहा है ? इसलिए मा0 अवधेश जी का जो प्रश्न है हमने सुसंगत धाराओं और सुसंगत नियमों में उसका उत्तर दे दिया है कि हम गौशालाओं को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। अब किसान पशु छोड़ेगा नहीं, हम उसे पशु छोड़ने नहीं देंगे। हम गाय का दूध भी खरीदेंगे और गाय का गोबर भी 2 रुपये किलो खरीदेंगे और उससे सी0एन0जी0 बनाने का काम करेंगे। यह सभी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं इसलिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है।

(इसी मध्य विपक्ष के कुछ सदस्यों के अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अवधेश जी का यह प्रश्न है इसलिए पहले वह अनुपूरक पूछ लें उसके बाद आप लोग पूछ लीजियेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने सवाल का जो उत्तर दिया है कि यह छुट्टा जानवर चाहे वह गाय हैं अथवा जो भी हैं वह विपक्ष द्वारा छोड़े जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि विपक्ष के द्वारा छोड़े जाते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह जानवर जो छूटे हैं, सत्ता पक्ष के लोग जो खेती करते हैं, उनके भी खेतों को चरते हैं, और इधर हम लोग जो बैठे हैं उनकी खेती को भी चरते हैं। यह सवाल किसी पार्टी अथवा राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है और इसको आप बहुत ही हल्के ढंग से ले रहे हैं। किसानों के प्रति न तो आपको कोई दर्द है और न ही कोई पीड़ा है। अगर किसानों के प्रति किसी को दर्द है, कोई पीड़ा है तो वह हम लोगों को है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने नगर पालिका, नगर निगमों व स्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया है, तो उस प्रख्यापन की नीति क्या है ? और जो आपकी गौशालायें हैं, उन गौशालाओं में गायों को चारा खिलाने के लिए या बन्द जानवरों को चारा खिलाने के लिए प्रदेश में कितने कर्मचारी लगाये गये हैं और उनका वेतन कितना है ? और इन गौशालाओं के रख-रखाव के लिए किस विभाग की जिम्मेदारी तय होगी ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार बहुत गम्भीर है। मा0 अवधेश प्रसाद जी, हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशालायें बना रहे हैं और हम एक अभियान चलाकर हर जिले में साल भर के लिए भूसा इकट्ठा करा रहे हैं। इसके लिए हमने दान भी मांगा है और गौ संरक्षण का पूरा प्रबन्ध भी कर लिया है। मान्यवर, हमारी जो देसी गायों की नस्ल है वह समाप्त होती जा रही है। आस्ट्रेलिया देसी गायों को ले गया, हमने देसी गायों को संरक्षित करके इन गौशालाओं में रखने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहूँगा कि चार दिन पहले मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से गायों को लेकर बात की थी और मैंने उनसे कहा था कि मान्यवर हम उत्तर प्रदेश में गौ-अभ्यारण बनाना चाहते हैं ताकि गायों को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने गम्भीर होकर मुझसे कहा कि धर्मपाल सिंह गौ-अभ्यारण में तो जंगली जानवर रहते हैं, गाय जंगली जानवर नहीं है, ये गौ-माता है। गाय में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर एवं गाय का मूत्र होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मइया रहती है। आज निराश्रित गौवंश की

हमको चिंता है, हम इनको बिल्कुल संरक्षित करके रख रहे हैं और हमने आपको सुसंगत नियमों में ये दे भी दिया है। मान्यवर, जो किसान अब गायों को दूध दूहने के बाद छोड़ेंगे, उनके लिए योगी सरकार ने कानून बना दिया है अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इस प्रश्न में कई मा0 सदस्यों के नाम हैं तो मैं इनको एक-दो तीन करके बुलाऊंगा आप सबका नाम नोट करके, सबके प्रश्न नोट करके एक साथ उत्तर दे देंगे। मा0 पंकज मलिक जी।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आत्मनिर्भर गौशालायें बतायी हैं क्या उसमें गायें अपने आप सारा काम कर लिया करेंगी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 30 रुपये बहुत कम हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद 30 रुपये की बात इन्होंने कही है तो इसका भी पूरा पैसा हर जगह नहीं गया है, तो इस धनराशि को बढ़ाने के लिए सरकार विचार करेगी और जितना पैसा बचा है वह कब तक दे दिया जायेगा ? चूंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं तो जो इस तरह का गौवंश है, जो इस तरह के पशु जाते हैं जो किसानों की खेती का नुकसान करते हैं उनकी भरपाई के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ? इससे पशुओं का भी नुकसान होता है, पशु घायल हो जाते हैं उनके इलाज की क्या व्यवस्था है और किसान का जो नुकसान होता है उसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रसन्न कुमार जी।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, खूंखार पशुओं के हमले से जो लोग घायल होते हैं उनके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये, आंकड़े मत दीजिये। आंकड़े मा0 मंत्री जी बतायेंगे।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भंवर सिंह एक आदमी था जिसे अभी पांच दिन पहले एक आवारा पशु ने इतनी जोर से मारा कि उसकी वहीं पर मौत हो गयी। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि उस आदमी के परिवार को

भरण-पोषण के लिए कोई मुआवजा दिया जा सके ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक आशू पुत्र श्री अशोक है उसको भी आवारा पशु ने मारा है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई है, एक लूम गांव का राजुल पुत्र श्री श्याम सिंह है जब वह अपने खेत को गौवंश से बचाने के लिए गया तो सारे गौवंश उसके पीछे भागे जिससे उसे होद में कूदना पड़ा।

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूँ कि जो गौवंश किसान का नुकसान कर रहे हैं और 18-18, 20-20 की संख्या में किसान के खेत में घुसते हैं, कम से कम उन्हें किसान बीमा जो फसलों का बीमा होता है, उस बीमे को दिलाने का कष्ट करें तभी किसान सुरक्षित हो पायेगा वरना किसान सुरक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह इनकी मांग है, प्रश्न नहीं है। इनका सुझाव है इसे नोट कर लीजियेगा। यह अच्छा सुझाव है।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मान्यवर, दो महीने में गौवंश कैसे खतरा कर सकता है ? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की विधान सभा क्षेत्र में तठरऊ में श्री भगवान दास, उर्रा में उसमान अली, मलिकपुर में पक्षी लाल तथा तीन लोगों की छुट्टा जानवरों से मृत्यु हो गयी। सुमेरपुर में जागेश्वर, कुसुमरा में राम खिलाड़ी तथा दो लोग मरणासन्न स्थिति में चले गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़ा दिया है कि इतने निराश्रित गौवंश को संरक्षण दिया गया। अगर इतने ही सरकार की नजर में थे जो आपके संरक्षण में हैं। उस आंकड़े के अतिरिक्त जो खेतों में झुण्ड के झुण्ड सैंकड़ों गौवंश घूम रहे हैं, क्या सरकार की उन पर नजर है ? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ? यदि है तो छुट्टा जानवर खेतों में घूम रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, उन पर सरकार ध्यान देगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न है गौवंश या छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों की फसल का जो नुकसान होता है तो क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी या नहीं ? तीसरा प्रश्न यह है कि छुट्टा जानवरों के कारण मृतक के परिवारी जन हैं, क्या सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है। हमने पशु गणना करा ली है और जिनको यह सांड़ कह रहे हैं उनकी हम चिन्ता कर रहे हैं और उनको भी चिन्हित कराकर गौशाला में भिजवाने का काम कर रहे हैं। हम इनका पूरा प्रबन्ध करेंगे। मान्यवर, कसाई और किसान में अन्तर है। कसाई की चिन्ता हम नहीं करेंगे लेकिन किसान की चिन्ता हम जरूर कर रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है इनको दर्द इसी बात का है कि अब गौ कटान बन्द है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि छुट्टा पशुओं की

पशु गणना की जा चुकी है। जो किसान पशु पालक टैग निकालकर ही पशुओं को छोड़ेगा तो हमारे गांव का चौकीदार, गांव का लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी उसकी पहचान करेगा। सुसंगत धाराओं में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत उस किसान पर मुकदमा भी दर्ज होगा और जुर्माना भी पड़ेगा। मान्यवर, हम चिन्ता कर रहे हैं कि इस तरह की कोई कठिनाई अब न आने पाये।

(सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा तथा सदस्य श्री पंकज कुमार मलिक जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैंने आपको अपने आप अवसर दिया। यह डिबेट नहीं हो रही है। आप लोग बैठ जायें। अगला प्रश्न लेते हैं, मौहम्मद फईम इरफान जी, जो प्रश्न आपने किया है, माननीय मंत्री जी पहले ही उसका उत्तर दे चुके हैं। फिर भी आप अनुपूरक प्रश्न कर लीजिए।

सरकारी अस्पतालों में खाली पदों की स्थिति एवं उन पर नियुक्ति की जानकारी संबंधी

***5-श्री मौहम्मद फईम इरफान जी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक उक्त पदों में से कितने पदों पर तैनाती सरकार द्वारा की गई है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करेगी तथा आबादी के सापेक्ष अस्पतालों को जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों, चिकित्सा उपकरणों आदि अन्य जरूरी सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेवल-1 से लेवल-7 के चिकित्सकों के कुल 19011 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 6312, स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत पद 9665 के सापेक्ष कुल पद 2987 तथा फार्मासिस्ट के कुल 6847 स्वीकृत पद के सापेक्ष कुल 221 पद रिक्त हैं।

दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2022 तक कुल 5112 चिकित्साधिकारियों, 1740 स्टाफ नर्स एवं 1134 फार्मासिस्टों की तैनाती की गयी है।

इन पदों पर रिक्तियों व उनको भरने की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है तथा उक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उ0प्र0 अधीनस्थ

सेवा चयन आयोग, लखनऊ से प्राप्त वर्षवार संस्तुतियों एवं प्रोन्नति के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। आबादी के सापेक्ष अस्पतालों को जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित बेडों, चिकित्सा उपकरणों आदि अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न जनहित की शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी नामक जनहित के चार प्रमुख मुद्दों में से एक अर्थात् प्रदेश की बदहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बजट की कमी से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हिस्सेदारी केवल 25 से 30 प्रतिशत और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की 70 से 75 प्रतिशत है। भले ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने में निजी स्वास्थ्य सेवाओं ने अपनी हिस्सेदारी नाममात्र की कर दी और सारा बोझ बदहाल सरकारी सेवाओं को ही उठाना पड़ा। कोरोनाकाल में ऑक्सीजन सिलेण्डर, दवाओं और बेडों की कमी से हुई मौतों का भयंकर मंजर जिसमें इलाज तो क्या इज्जत से अन्तिम संस्कार होने के भी लाले पड़ गये।

मैं मा0 मंत्री जी से पहला अनुपूरक पूछना चाहता हूँ कि चिकित्सकों के स्वीकृत 19011 पदों के सापेक्ष 6312 पदों की तैनाती के बाद अवशेष दो तिहाई 12699 पद चिकित्सकों व स्टाफ नर्स के 6678 पद खाली बचे हुए सहित अन्य कितने पदों पर इस वर्ष तैनाती का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वीकृत खाली पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती तथा अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लू0एच0ओ0 के निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने हेतु आवश्यक बजट या धनराशि का कोई आकलन कराया है। यदि हाँ तो आंकलित धनराशि कितनी है। यदि नहीं तो क्या शीघ्र ही ऐसा आंकलन करने का आश्वासन मा0 मंत्री जी सदन को देंगे।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य ने चिकित्सकों के पदों के बारे में, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स के बारे में जो सवाल पूछा है मैं इस सवाल का जवाब पूर्व में ही बता चुका हूँ कि चिकित्सकों की पूरी तरह से संख्या इसलिए नहीं भरी जा सकी क्योंकि उपलब्धता ही नहीं थी। पद सरकार ने सृजित किये थे। मा0 योगी जी की सरकार में लेवल-1 पर चिकित्सकों की भर्ती होती है और विशेषज्ञों की भर्ती लेवल-2 पर सीधी करने के लिए सरकार ने काम किया है और जितने भी पद खाली हैं चाहे चिकित्सकों, विशेषज्ञों या स्टाफ नर्स व फार्मासिस्ट इन सभी पदों का अधियाचन हमने लोक सेवा आयोग को भेजा है। सदन इस बात को लेकर चिन्तित है कि

4000 हजार पद हमने निकाले और एक लाख आवेदन बच्चों ने किये लेकिन इसमें 3000 हजार बच्चे ही पास हो पाये। यह पढ़ाई का हाल हमारे विपक्ष के साथियों ने अपनी सरकार में कर रखा था। वर्ष 2012 से 2017 तक वाले बच्चे ही ज्यादातर इसमें फेल हुए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे-ऐसे नर्सिंग कालेजों को मान्यता दे दी थी जिनका मानक ही पूरा नहीं था। अब उन सबकी मान्यता की जांच कराकर रद्द कर रहे हैं। हम अब सरकारी कालेजों में नर्सिंग क्लास बढ़ाने का काम कर रहे हैं और शीघ्र ही हम पद भर देंगे धनराशि की कोई कमी नहीं हो पायेगी। यह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्राथमिकता का विभाग है।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

समाजवादी पार्टी सरकार में मेरे वालिद साहब विधायक थे तो उन्होंने अपनी विधान सभा में 30 बेड का अस्पताल बनवाया था। मैं गुजारिश करूँगा मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से कि उस अस्पताल में मूल संसाधन की कमी है। आप उस अस्पताल में मूल संसाधन पूर्ण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री ब्रजेश पाठक-

आप हमको पत्र लिखकर दीजिये। हम हर सम्भव उस अस्पताल की समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017 से 2021-22 तक विधवा आवेदिका को विधवा पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में

***6-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017 से 2021-22 तक विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त के सापेक्ष कितनों को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई है एवं कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार शेष विधवा पेंशन आवेदिकाओं को समयबद्ध विधवा पेंशन दिलाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती बेबीरानी मौर्य)-

प्रदेश में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.06 लाख, वर्ष 2018-19 में 3.14 लाख, वर्ष 2019-20 में 3.59 लाख, वर्ष 2020-21 में 1.85 लाख तथा वर्ष 2021-22 में 3.05 लाख, इस प्रकार कुल 13.69 लाख आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष समस्त आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई है। वर्तमान में प्रदेश में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के कुल 48,423 आवेदन लम्बित हैं, जोकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तिम त्रैमास में प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के सापेक्ष पेंशन की प्रथम किश्त संबंधित आवेदकों के बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हाँ, प्रत्येक आवेदक द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का आवेदन करने की तिथि से 04 माह के अन्दर पात्रता की श्रेणी में होने पर पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मेरा बेसहारा व अत्यन्त निर्धन अभाव ग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों व विधवा महिलाओं से संबंधित है जिनके पास भरण-पोषण का कोई जरिया नहीं होता है और स्वयं के ही नहीं, उनके बच्चों के भरण-पोषण का भी कोई जरिया नहीं होता है। उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का भी कोई जरिया नहीं होता है। लेकिन मा0 मंत्री जी के उत्तर के जवाब से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार गरीब वर्ग की महिलाओं के प्रति बहुत उदासीन है। और प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद महामहिम राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन भी कर चुकी हैं। मान्यवर, प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि प्रदेश में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 2,06,000, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 3,14,000, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 3,59,000, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,85,000 और वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 3,05,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पेंशन निर्गत करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। मान्यवर, इसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। जब हम वित्तीय वर्ष 2020-21 का आंकड़ा देखते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि 1,74,000 विधवायें जो पेंशन के लाभ से वंचित कर दी गयी थीं। मान्यवर, उस समय लॉकडाउन भी कुछ महीनों तक था और उनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति का और कोई जरिया नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा पहला प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,74,000 विधवाओं के पेंशन लाभ से वंचित होने के क्या कारण रहे हैं। दूसरा, क्या सरकार ने ऐसे जिम्मेदार और जवाबदेह अधिकारियों/कर्मचारियों पर, जिनके कारण 1,74,000 विधवायें पेंशन से वंचित हो गई थीं, कोई वैधानिक कार्यवाही की है। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है। मान्यवर, इन दो अनुपूरक प्रश्नों के जवाब हमें माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिये। इसके बाद मैं दो छोटे-छोटे अनुपूरक प्रश्न और कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप वह दोनों अनुपूरक प्रश्न भी अभी कर लीजिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, एक साथ ज्यादा अनुपूरक करने पर उसका जवाब नहीं आ पाता है। इसलिए मैं दो बार में अनुपूरक प्रश्न कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 मंत्री जी कृपया आप उत्तर दे दीजिये।

श्रीमती बेबी रानी मौर्या-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है उसमें उन्होंने यह आंकड़ा मांगा है कि वर्ष 2017 से 2022 तक विधवा महिलाओं की पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमें जो कुल आवेदन प्राप्त हुए थे वह 13.69 लाख थे। इन पांच वर्षों में आवेदन बढ़े भी हैं और हमें मार्च, 2022 तक कुल 48,423 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष हम जून, 2022 तक पेंशन दे देंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि हम महलाओं की चिंता नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार के बजट में महिलाओं की पेंशन को बजट को दोगुना किया गया है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदन को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरी सप्लीमेंट्री कहीं से भी विषयान्तर नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया है कि क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017 में 2021-22 तक विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त के सापेक्ष कितनों को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई है और कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न था कि वर्ष 2017-2018, 2018-2019 या 2019-2020 में जो विधवाओं की पेंशन स्वीकृत की गई है उनमें से इतनी मृत्यु दर नहीं हो सकती है कि सीधे एक वित्तीय वर्ष में 1,74,000 विधवाओं की कमी आ जाये। मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 1,74,000 विधावाओं के पेंशन लाभ से वंचित होने के कारण क्या रहे हैं। मेरा अनुपूरक तो मेरे प्रश्न में ही निहित है जिसका जवाब आना चाहिए था। मेरा दूसरा अनुपूरक रहा है कि क्या सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियो पर जिनकी वजह से 1,74,000 विधवाओं को पेंशन से वंचित होना पड़ा उन पर सरकार ने कोई वैधानिक कार्यवाही करने का काम किया है। यदि नहीं किया तो क्यों ? इस प्रकार मेरे पूर्व के अनुपूरक का जवाब नहीं आया है। आपकी अनुज्ञा से मैं वह दो अनुपूरक प्रश्न भी किये लेता हूँ जो रह गये थे। मान्यवर, यह विभाग बेहद गरीब और निराश्रित महिलाओं से जुड़ा है। इनके जो सी0एच0सी0 अर्थात् कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उन्हीं के जरिये इनके ऑनलाइन आवेदन किये जाते हैं। तो मेरा विषय यह है कि वहाँ पर मनमाने तरीके से शुल्क वसूली की जाती है। नियमावली में यह

व्यवस्था है कि 20 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता है। 20 में से 17 रुपये विभाग को जाता है और 3 रुपये कॉमन सर्विस सेंटर का होता है। मान्यवर, 100-100 रुपये तक की वसूली की जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि क्या सरकार कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन करने का शुल्क प्रदर्शित करने के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगाने की व्यवस्था करेगी। दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक ट्रांजेक्शन फेल्योर के कितने मामले रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट विवरण इस सदन के अन्दर रखेगी।

श्रीमती बेबी रानी मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने कहा है कि जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पायी हैं तो उसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है और उसमें यह है कि जो महिलायें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पायेंगी उनके लिए प्रत्येक गांव, मोहल्ले, कस्बे, वार्ड में कोई भी महिला उक्त योजनान्तर्गत लाभ पाने से वंचित नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन न कर पाने की स्थिति में कोई महिला पात्र होते हुए भी अपात्रता की श्रेणी में रखी जाती है तो सम्बद्ध क्षेत्र का ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी, लेखपाल या निकायकर्मी या जो नामित किया गया होगा, वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर आ गया। डॉ0 साहब, उन्होंने यह बताया कि जो ऑफलाइन आवेदन करेंगे, वह भी स्वीकार है और जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह आपका प्रश्न था और उसका उत्तर आ गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न में जो दो बातें आपने कही हैं, उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

प्रदेश में आवारा जानवरों हेतु निर्मित गौशालाओं के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी निर्धारित करने विषयक

***7-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा जानवरों हेतु निर्मित गौशाला स्थलों में पशु बीमार होकर अथवा भूख के कारण उनकी मृत्यु हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गौशालाओं के संचालन हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके रख-रखाव की पुनर्समीक्षा कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

***8-श्री रवि शर्मा-**

[03-मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

(प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जवाहर लाल राजपूत अनुपस्थित थे)

(प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रवि शर्मा अनुपस्थित थे)

उ0प्र0 में कोरोना संक्रमण से अस्पतालों में एवं अस्पतालों से बाहर कोरोना से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में

***9-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोनाकाल में संक्रमण से अस्पतालों में एवं अस्पतालों से बाहर हुई मृत्यु की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

जी हाँ, प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा राज्य स्तर से संचालित कोविड पोर्टल पर अपलोड किये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 महामारी के प्रारम्भ से दिनांक 13-05-2022 तक कोविड-19 रोग के संक्रमण से चिकित्सालयों में भर्ती, होम आइसोलेशन एवं क्वारन्टाइन केन्द्रों में भर्ती कुल 23,512 रोगियों की मृत्यु सूचित हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, जब कोरोना की पहली लहर आयी तो अचानक दैवीय आपदा आयी। उस समय व्यवस्था होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अचानक कोई दैवीय आपदा आ जाये तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। पहली लहर में भी लोगों को दवायी नहीं मिली। कोई व्यवस्था नहीं हो पायी, लोगों की जानें गयीं। लेकिन जब दूसरी लहर आयी तो उस समय सरकार ने पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में इतना प्रचार किया कि हमने इतने बेड सृजित कर दिये, इतने अस्पताल चिन्हित कर दिये, दवाइयों का पर्याप्त इन्तजाम कर दिया। हर चीज की पूर्ण व्यवस्था कर दी। लेकिन जब लहर आयी तो सिर्फ हिन्दुस्तान ने ही नहीं पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह लोग ऑक्सीजन तक के लिए तरसते रहे, दवाइयों तक के लिए तरसते रहे, बिस्तर तक के लिए तरसते रहे, डॉक्टर के लिए तरसते रहे। न डॉक्टर मिला, न ऑक्सीजन मिली, न

दवाई मिली। इस तरह लाखों लोग इस दुनिया से चले गये। लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार ऐसे गम्भीर विषय पर भी इतनी गम्भीर है कि मात्र 23 हजार 512 रोगियों की मृत्यु दिखाने का काम सरकार ने किया है। जबकि मेरे पास छोटी-मोटी कुछ बातें हैं कि प्रयागराज में 2020 में 229 प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे और 2021 अप्रैल-मई में 734, मेरठ में अप्रैल-मई में 1876, इसी तरह गाजियाबाद में 11817, प्रयागराज में 734 और लखनऊ में केवल ढाई महीने में 1300 डेथ सर्टिफिकेट जारी किये गये और यह केवल महानगर पालिकाओं के माध्यम से किये गये, जबकि इसमें न नगर पालिकाओं का कोई रिकार्ड है, न इसमें सरकारी अस्पतालों का कोई रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो टोटल मृत्यु की संख्या होगी। आप कोविड वाला पूछ रहे हो।

श्री मनोज कुमार पारस-

मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। इसलिए इससे साबित होता है कि सरकार ने किस तरह से मात्र 23 हजार 512 लोगों की मृत्यु को दर्शाया है। जबकि मृत्यु लाखों में हुई है।

मा0 अध्यक्ष जी, जबकि मृत्यु लाखों में हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मण्डल, 17 महानगर पालिकाएं, वर्तमान समय में 518 नगर पंचायतें और 200 नगर पालिकाएं हैं। अगर इन सभी का रिकार्ड मांग लिया जायेगा तो भी लाखों में आयेगा। जबकि उत्तर प्रदेश में 97,600 ग्राम हैं। अगर ग्राम पंचायतों को भी उन सबमें शामिल किया जायेगा तो सरकार की आंखें खुलेंगी कि कितने लोग इस दुनिया से चले गये हैं, आपकी अव्यवस्था के कारण लोग दुनिया से चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, प्रश्न पर ही आ रहे हैं। आपने बहुत ढिंढोरा पीटा और एक तरफ आपने कहा है कि हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छी व्यवस्था की है। आपको सर्टिफिकेट केन्द्र सरकार ने दिया और वहाँ भी आपकी ही सरकार है। यह तो वही बात हुई कि जैसे एक बच्चा बार-बार हर कम्पटीशन में हार जाता था।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कीजिये कहानी मत सुनाइये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, उसकी मां कहती थी कि बेटा फिर हार गया। एक दिन बच्चा दौड़कर आया और बोला कि मां मैं जीत गया हूँ तो मां ने कहा कि आज कैसे जीत गया तो बच्चे ने कहा

कि आज मैंने किसी को भी बोलने ही नहीं दिया। तो इसलिए आपको ही सर्टिफिकेट देना है, आपने ही बता दिया कि हमने व्यवस्था की है, आपने ही बता दिया कि इतने लोगों की जानें चली गयी हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक महानगर पालिका और गांवों में जांच करायेगी कि कोरोनाकाल से कितने लोगों की मृत्यु हुई है जिससे कि उन्हें मुआवजा मिल सके, उनकी मदद की जा सके ? अभी इससे पहले प्रश्न में मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने आवेदन कराये, लोगों ने आवेदन किये हैं, लेकिन लोग डर भी रहे थे क्योंकि सरकारी अमला बता रहा था कि आप आवेदन कराने जाओगे तो आपसे पूछा जायेगा कि आप क्यों नहीं उन्हें अस्पताल ले गये, आपने उनकी जांच क्यों नहीं कराई ? इस वजह से लोगों ने आवेदन नहीं किया है। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी संस्था के माध्यम से जांच कराकर सही आंकड़ा प्रस्तुत करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने लाख लोगों की जानें गयी हैं ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, जवाब में ही स्पष्ट है कि 23,512 लोगों की कोविड पोर्टल पर डेथ दर्ज हुई और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो विज्ञापन दिये गये थे उन विज्ञापनों के अगेंस्ट हमें 41,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे स्वतः स्पष्ट है जोड़-घटाने का विषय है कि 18,359 की अतिरिक्त मृत्यु हमारे रिकार्ड में है और हमने उनको अनुदान भी दिया है। मा0 सदस्य का सवाल है कि लाखों लोग दुनिया में मरे हैं, इन्होंने ही कहा है कि लाखों लोग दुनिया में मरे हैं, आप रिकार्ड देख लीजिये। अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हैं और हमारी भी छोटी सी कहानी सुन ली जाये और उस कहानी को पूरा सदन भी सुन ले कि एक बच्चा शैतानी कर रहा था और वह खड़े होकर लघु शंका कर रहा था तो उसके पिता जी के पास गये तो वह छत पर बैठकर दीर्घ शंका कर रहे थे। उसी प्रयास में आप हो।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का पहले भी उत्तर आ चुका था फिर भी मैंने आपको इस बात के लिए अवसर दिया। इस प्रश्न पर मा0 रविदास मेहरोत्रा जी ने भी पूछा था, मा0 फईम जी ने भी पूछा था। सभी लोगों ने पूछा था। मा0 पारस जी पूछ लीजिये। मा0 पाण्डेय जी जो मूल प्रश्नकर्ता हैं, उनको पूछ लेने दीजिये। आप दोनों लोग तय कर लीजिये कि किसको प्रश्न पूछना है। मैंने आपको बुलाया है आप अपना अवसर छोड़कर उनको देना चाहते हैं, तो दे दीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी प्रश्न पूछ लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोविडकाल में कितने मा0 विधायक, कितने मा0 मंत्री ...

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न आ चुका है और मा0 मंत्री जी उसका उत्तर भी दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि देखकर बता देंगे। मा0 अवधेश प्रसाद जी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसकी सूचना दे देंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इसका उत्तर नहीं आया है।

मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न पूछना था और मा0 मंत्री जी के संज्ञान में भी लाना था कि डी0सी0एच0 एक बड़ी संस्था है जो हेल्थ पर काम करती है उसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग 68,000 लोगों की मृत्यु बतायी गयी है। गांव व घरों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु को कोविड में दर्शाया नहीं गया है और लोगों ने दाह संस्कार कर दिया और उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मा0 मंत्री जी से हमारा इससे पहला वाला और यह दूसरा प्रश्न है। यद्यपि आप उस समय मा0 स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे लेकिन यह कन्टीन्यूटी की सरकार है इसलिए यह जानकारी आपके पास होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सेकेण्ड लेना चाहूँगा।.....

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप क्विट कर चुके हैं। आप प्रश्नकाल के बाद मा0 मंत्री जी से एक सेकेण्ड ले लीजिएगा। मा0 मंत्री जी आप उत्तर दीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, मेरा मा0 मंत्री जी से सीधा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह नहीं लिखा जायेगा और इसका कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों ही प्रश्नों का जवाब पहले ही हो चुका है, मनोज पाण्डेय जी केवल मनोज पारस जी का वजन बढ़ा रहे हैं और महाराज हम इन दोनों ही सवालों का जवाब दे चुके हैं।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ चुका है, हम हाजी इरफान सोलंकी जी का प्रश्न लेते हैं, आप लोग बैठिये। हमारे जिले का मामला है आप लोग बैठिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमारा दल दो मिनट के लिए सदन से बहिर्गमन करता है।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

आपके सारे सदस्य तो जा नहीं रहे हैं। हाजी इरफान जी वॉकआउट हो गया है।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

नहीं मान्यवर, हमारा सवाल है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, आप वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, सब लोग वॉकआउट नहीं कर रहे हैं।

प्रदेश के नीट पास समस्त छात्रों के लिए मेडिकल कालेज में दाखिले का प्रदेश में इन्तजाम करने के सम्बन्ध में

***10-श्री हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नीट पास छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्रों को प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दाखिला दिया गया है ? क्या सरकार प्रदेश के नीट पास शत-प्रतिशत छात्रों को प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दाखिले सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

नीट उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट कम विकल्प के आधार पर शत-प्रतिशत सीटों पर दाखिला दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी मेडिकल कालेज और प्राइवेट मेडिकल कालेज में कितनी-कितनी सीटें हैं ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो राजकीय मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें कुल सीटें पांच हजार तीन सौ सत्तानबे हैं और प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में कुल छह हजार सत्ताइस सीटे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने प्रवेश पिछले पांच सालों में हुए हैं, तो पांच साल में कुल चालीस हजार सात सौ छत्तीस प्रवेश एम0बी0बी0एस0 में हुए हैं।

प्रदेश में मेडिकल कालेज की स्थिति के सन्दर्भ में

***11-श्री जगदीश नारायण-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने तथा कौन से मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता से संचालित हैं ? क्या सरकार जनपद जौनपुर में स्थापित मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज यथा मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बांदा, बदायूं, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन एवं आजमगढ़ पूर्ण क्षमता से संचालित हैं।

केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत स्थापित/संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम तृतीय बैच प्रवेशित है।

केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत स्थापित/संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा हरदोई, एटा, मीरजापुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रथम बैच प्रवेशित है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल पर सरकार का जवाब आया है कि प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता से संचालित हैं। मेरा इतना सा सवाल है कि क्या सरकार जनपद जौनपुर में स्थापित मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित करेगी, उनका जवाब नहीं आया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा जौनपुर मेडिकल कालेज वर्ष 2015 में शुरू हुआ और आज 2022 हो गया है, अभी तक इसमें 50 प्रतिशत ही काम हुआ

है। इसको राजकीय से हटाकर किस योजना में डाल दिया गया है ? जब इसका जी0ओ0 जारी हुआ था तो राजकीय मेडिकल कालेज लिखा था फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर स्वायत्तशासी का बोर्ड लग गया तो किन परिस्थितियों में यह राजकीय से हटाकर स्वायत्तशासी किया गया और इसको आप कब तक पूर्ण क्षमता से चलाने का काम करेंगे ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे पुराने मित्र भी हैं। स्वायत्तशासी जितने भी कालेजेज होते हैं वह ऑटोनामस हैं वह उसी अनुक्रम में हैं और राजकीय मेडिकल कालेज हैं। मा0 सदस्य ने सवाल पूछा है कि पूर्ण क्षमता से कितने कालेजेज चल रहे हैं तो पूर्ण क्षमता का मतलब यह है कि पांचों वर्ष में एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश है, एम0डी0 और एम0एस0 की कक्षाएं चल रही हैं। क्रमानुसार पहले प्रथम वर्ष में एडमिशन लेते हैं फिर पास होकर द्वितीय वर्ष में जाते हैं और फिर तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पांचवें वर्ष में जाते हैं। इसी प्रकार एम0डी0 में भी प्रवेश होता है। चूंकि नया मेडिकल कालेज है और वह राजकीय ही है आप एकदम चिंता मत करिये। वहाँ की व्यवस्था देखने मैं स्वयं जाने वाला हूँ, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूँ और पूरी तरह से मैं पूरे सदन को भरोसा दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था उच्च स्तरीय होगी, विश्वस्तरीय होगी, इसके लिए हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

प्रदेश के जनपदों में दन्त रोग के चिकित्सकों की तैनाती विषयक

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन जनपदों में कितने दन्त चिकित्सकों की तैनाती की गयी है तथा वर्तमान में कितने दन्त रोग चिकित्सक के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 19011 पदों के सापेक्ष कुल 12699 चिकित्सक तैनात हैं। वर्तमान में दन्त चिकित्सकों के कुल 174 पद रिक्त हैं।

शासन के पत्र संख्या-2022/पांच-5-2021, दिनांक 13-10-2021 द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष दन्त सर्जन के रिक्त 174 पदों पर चयन हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मनोज जी आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय सदस्य, आप तो चले गये थे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बुला लिया।

श्री अध्यक्ष-

क्या करें, आपका प्रश्न है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं (हंसी)।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश में दन्त रोग से सम्बन्धित था और दन्त चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में था। सरकार ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 19011 पदों के सापेक्ष कुल 12699 पद पर ही तैनाती है।

हम सरकार से सीधे-सीधे यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बचे हुए शेष 6413 पदों पर भर्ती करायेगी, यदि करायेगी, तो कब तक ? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जनपद हैं, जहाँ पर दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं है ? उसी में यह भी पूछना चाहते हैं कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में दन्त चिकित्सकों की कुल कितनी तैनाती है और जिन जनपदों में दन्त चिकित्सक नहीं नियुक्त हैं, क्या सरकार उन पर अनिवार्य रूप से दन्त चिकित्सक नियुक्त करेगी ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष, महत्वपूर्ण सवाल है। चिकित्साधिकारियों के 19011 पद हमारे पास स्वीकृत हैं, 12699 चिकित्सक तैनात हैं। लेवल-1 एवं लेवल-2 दन्त चिकित्सक-1 एवं दन्त चिकित्सक-2 (विशेषज्ञ) चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा वर्षवार नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही की जाती है। विज्ञापन के माध्यम से हम नियुक्तियां कर रहे हैं और शीघ्र ही सभी पदों को हम भर देंगे। स्पेसिफिक रूप से कुछ जनपदों का आपने सवाल पूछा है, उनकी जानकारी एकत्र करके हम आपके माध्यम से दे देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग के पास बहुत सारे विभागों के लिए चयन की प्रक्रिया करनी रहती है। इसलिए मेरा एक सुझाव है, क्या आप स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य चयन आयोग बनाने पर विचार करेंगे, जिससे कि जल्दी इनका चयन हो सके ?

श्री अध्यक्ष-

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, आपका सुझाव आया है, चूंकि लोक सेवा आयोग से सारी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, जो गजटेड पद हैं, जो उच्च स्तरीय पद हैं और हम सहायक स्तर के पद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरते हैं, ऐसी प्रक्रिया पूर्व से प्रचलित है और मुझे लगता है, यदि ऐसी ही समस्या खड़ी होती रही, तत्काल नहीं हुआ तो इस पर भी सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सरकार विचार कर सकती है।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में

***13-श्री महबूब अली-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ? क्या सरकार जनहित में जनपद अमरोहा सहित प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को वर्ष 2022-23 में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 09 जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं 73 जनपदों में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है। एम0आर0आई0 की जांच टर्शरी इकाई के स्तर की जांच है। अतः प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करने की कार्य योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में संयुक्त प्रान्त इस प्रदेश का नाम था। इसके बाद 1950 में परिवर्तन करके इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से सभी हास्पिटल्स में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की व्यवस्था कर दी जायेगी। माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें आया है कि इतने में हुई है और इतने में नहीं हो सकती। अगर आश्वासन ही दे देते, क्योंकि यह हेल्थ से सम्बन्धित, एक व्यक्ति की जान से जुड़ा यह

सवाल है। आज प्रदेश में अगर देख लिया जाये और हिसाब लगायें तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं करीब 50 अरब रुपया प्रदेशवासियों का सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 में खर्च हो रहा है और करीब 4 अरब रुपया सी0टी0 स्कैन में खर्च हो रहा है। अगर सारे हास्पिटल्स में आप व्यवस्था कर देंगे तो हम महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं आप यकीनन प्रदेशवासियों की चिकित्सा के लिए चिन्ता करते हैं। मेरा आपसे सीधा अनुरोध है, स्वास्थ्य मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों के हजारों करोड़ के अनावश्यक खर्चे को बचाने हेतु, मेरे मण्डल में 5 जनपद हैं, 5 में से 4 में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की व्यवस्था नहीं है। मेरा सीधा प्रश्न है, क्या अमरोहा सहित प्रदेश के 09 जनपदों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की समय-सीमा तथा समस्त जनपदों में या प्रथम चरण में मण्डल मुख्यालय वाले जिलों में एम0आर0आई0 की व्यवस्था सरकार करायेगी ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, वह दो स्तरीय है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स होते हैं, उसमें हम सी0टी0 स्कैन उपलब्ध कराते हैं, चूंकि एक्सीडेंटल केसेज भी आते हैं और तत्काल उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होती है और जो विशेष सुपर स्पेशियलिटी या स्पेशियलिटी वाले हास्पिटल्स हैं। वहीं पर आवश्यकता सी0टी0 स्कैन मशीन की होती है। सी0टी0 स्कैन मशीन लगा देने से जांच प्रारम्भ नहीं हो जाएगी, जब तक सभी विभाग वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। आपकी जो चिंता है उसके लिए भी सरकार प्रयासरत् है कि हमारे सभी जनपदों में मेडिकल कालेज खुल जायें। सभी जनपदों में मेडिकल कालेज खोल रहे हैं तो वहाँ पर उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था का इन्तजाम भी कर रहे हैं। 75 जनपदों में उच्च स्तरीय चिकित्सा की व्यवस्थाएं होंगी यह सरकार का काम है और यह काम हम करके रहेंगे।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अगर आप प्रश्न के उत्तर में पढ़ेंगे तो एक अल्फाज दिया है टर्शरी। इस तरह से लपेट कर बात करने से शायद यह व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती है।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, जो टर्शरी स्तर की चिकित्सा व्यवस्था होती है वह उच्च स्तरीय विशेष हास्पिटल्स में होती है जो स्पेशल हास्पिटल्स हैं जहाँ पर सुपर स्पेशियलिटी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और जहाँ पर सामान्य चिकित्सा व्यवस्था है वह डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में है। वहाँ हम सी0टी0 स्कैन उपलब्ध कराते हैं और टर्शरी लेवल में हम एम0आर0आई0 की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरे सदन का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तृतीयक देखभाल चिकित्सीय सेवाएं विशेषज्ञ अस्पतालों या क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं

जो नैदानिक और उपचार सेवाओं से लैस हैं और स्थानीय अस्पतालों में आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं। इनमें ट्रामा केन्द्र, उन्नत नेफ्रोलॉजी सेवाएं, अंग प्रत्यारोपण, उच्च जोखिम और गर्भावस्था विकिरण विज्ञान आदि शामिल हैं। क्या इन अस्पतालों में जिसमें टर्शरी के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी और गरीब आदमी अगर मेरे ख्याल से प्रदेश का देखा जाये तो 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25 हजार से कम है, क्या यह कम आमदनी वाले लोग इन जगहों पर जा सकते हैं, अगर नहीं जा सकते हैं तो कोई सरल उपाय निकालें। अगर आपको आम आदमी के स्वास्थ्य की यकीनन चिन्ता है तो उसकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए यह सारी व्यवस्थाएं करायें। गरीबों का गम्भीर हालातों में एम0आर0आई0 न होने की वजह से, सी0टी0 स्कैन न होने की वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। जिसके कारण कई गम्भीर बीमारियों का पता नहीं चल पाता और दूर-दराज के रहने वाले लोग मर जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा सरल उपाय निकाल लें मा0 मंत्री जी कि जिससे आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो जायें।

नागरिक सुरक्षा में अवैतनिक वार्डनों की व्यवस्था दिल्ली, बंगाल, पंजाब और राजस्थान आदि प्रदेशों की तर्ज पर करने विषयक

***14-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के अवैतनिक वार्डनों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार प्रदेश के अवैतनिक वार्डनों को टी0ए0, डी0ए0, प्रशिक्षण खर्च, ड्यूटी की निर्धारित राशि, बीमा आदि की व्यवस्था दिल्ली, बंगाल, पंजाब, राजस्थान आदि प्रदेशों की तर्ज पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के अवैतनिक वार्डनों की संख्या वर्तमान में 8585 है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, यह सिविल डिफेंस से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि अवैतनिक वार्डन हैं जो प्रशासन की कानून व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं। जुलूसों में, जाम में, यहाँ तक कि कोविड में भी इन्होंने बड़ी मदद की है। इनको भत्ता मिलता था, प्रोत्साहन भत्ता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 23 अक्टूबर, 1996 के आदेश से यह भत्ता बन्द कर दिया गया है। जब इनकी ट्रेनिंग होती थी केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बक्शी के तालाब में और नागपुर स्थित एन0डी0आर0एफ0 एकेडमी में तो उनको ट्रेनिंग का भत्ता, आने-जाने का भत्ता भी मिला करता था। इधर अब यह बन्द कर दिया गया है। यह इम्पार्टेन्ट संगठन है। इसमें मेरा सवाल सीधा-सीधा यह है कि जो पहले ट्रेनिंग का भत्ता मिलता था और प्रोत्साहन भत्ता मिलता था यह

क्यों बन्द कर दिया गया। क्या इसको पुनः चालू करने में सरकार विचार करेगी ? क्योंकि पहले जो भत्ता मिलता था वह मात्र 28 रुपये यात्रा भत्ता का मिलता था। अब महंगाई के हिसाब से क्या उस भत्ते को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि यह त्वरित मदद है प्रशासन की तो इनकी बेहतर ट्रेनिंग का भी सरकार इन्तजाम करेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने यह भत्ता बन्द नहीं किया है। ड्यूटी भत्ता हम 31 रुपये प्रतिदिन देते हैं और प्रशिक्षण भत्ता 28 रुपये प्रतिदिन देते हैं। मा0 सदस्य ने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस समय तो इसको बढ़ाने की कोई बात नहीं है। मा0 सदस्य को नागरिक सुरक्षा के बारे में प्रश्न यह करना चाहिए था कि नागरिक सुरक्षा है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, उन्होंने जो प्रश्न किया है, आप उसका उत्तर दे दीजिये। आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, प्रशिक्षण भत्ता मात्र 28 रुपये प्रतिदिन है। एक तो मैंने कहा कि वह 28 रुपया भी उनको मिल नहीं रहा है तो आप इसको देने पर विचार करें और दूसरा 28 रुपया आज कल क्या होता है तो क्या आप इसको बढ़ाकर इसे आज के हिसाब से देने पर विचार करेंगे ? आपके पीछे असीम अरुण जी बैठे हैं, वे कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, आप उनसे पूछिये कि यह कितना उपयोगी संगठन है ? मेरा बड़ा सिम्पल क्वेश्चन है आपसे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप दो बातों का उत्तर दे दीजिये। एक तो 28 रुपया जो मा0 सदस्य के अनुसार नहीं मिल रहा है और आपने कहा कि मिल रहा है तो वह मिल जाये, मा0 सदस्य का एक प्रश्न यह है। दूसरा आप उसको बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे। आप केवल इन दो प्रश्नों का स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, अगर वह नहीं मिल रहा है तो हम दिलवाने का काम करेंगे और दूसरा अभी उसको बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में आक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में

***15-श्री तुफानी सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में आक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करा दी गयी है तथा कितनों में कराया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए शेष चिकित्सा

विश्वविद्यालों में भी आक्सीजन प्लाण्ट स्थापित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 02 चिकित्सा विश्वविद्यालयों यथा के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा, 13 राजकीय मेडिकल कालेज, 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं 04 चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना करा दी गयी है। इस प्रकार किसी भी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आक्सीजन प्लाण्ट स्थापित कराया जाना अवशेष नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

श्री तुफानी सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, ये ऑक्सीजन क्या बला है, गांवों में पहली बार कोरोना आने के बाद लोगों ने जाना कि ऑक्सीजन क्या चीज है ? ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए कितनी हितकर है, कितनी उपयोगी है ? इसे तब जाना गया, जब ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई। आपके पास कोई सही आंकड़ा तो है नहीं कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मरे ? आप लोग अभी तक इसका सही आंकड़ा सदन को नहीं बता पाये हैं। लेकिन के0जी0एम0सी0 में ऑक्सीजन के अभाव में कितने सीनियर डॉक्टरों की मृत्यु हो गई है, उसका आंकड़ा आपको जरूर मिलेगा। मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि किसी भी मेडिकल कालेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित कराया जाना अवशेष नहीं है। अभी आपका ध्यान हमारे एक वरिष्ठ मा0 विधायक जी ने जौनपुर मेडिकल कालेज की तरफ आकृष्ट कराया था, उन्होंने जौनपुर मेडिकल कालेज का जिक्र किया था। मैं भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जौनपुर मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित/अधिष्ठापित नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जौनपुर मेडिकल कालेज का स्थलीय निरीक्षण करने की बात कही है। इसके लिए हम सभी आभारी हैं कि आप वहाँ पर चलकर उसका निरीक्षण करेंगे। प्रश्न मेरे दो-तीन छोटे-छोटे हैं। एक यह है कि क्या सरकार ने ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या को देखते हुए ऑक्सीजन प्लाण्ट के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की है ? दूसरा क्वेश्चन यह है कि कितने जम्बो ऑक्सीजन सिलेण्डर का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है ? तीसरा क्वेश्चन यह है कि क्या आपकी वातावरण से सीधे ऑक्सीजन लेकर उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजन सिलेण्डर बनाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने सवाल किया है कि क्या ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित करा दिया गया है तो 100 परसेंट करा दिया गया है। कोई मेडिकल कालेज शेष नहीं है। जहाँ तक आप जौनपुर की बात कर रहे हैं तो अगर मा0 सदस्य की बात सही निकली तो हम कार्यवाही भी करेंगे। किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि इनकी जानकारी अधूरी निकली तो आप इनके लिए क्या करोगे, ये आप तय कर दो।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अपनी बात बताओ ?

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूँ कि इनका यह कहना कि क्या सभी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित हो गये हैं तो हमारा जवाब है कि शत-प्रतिशत हो गये हैं। इनका कहना है कि जौनपुर में नहीं हुआ है। मैंने कह दिया कि हो गया है और इनका कहना है कि नहीं हुआ है। तो अगर ये सदन को गुमराह कर रहे हैं तो इनके लिए क्या कार्यवाही होगी, यह आप जानें।

श्री अध्यक्ष-

इनको जानकारी नहीं होगी तो आप जानकारी दे दीजिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

इनको जानकारी करनी चाहिए न। अध्यक्ष जी, जहाँ तक इनका सवाल है तो शत-प्रतिशत हो गया है और शत-प्रतिशत हो गया है। जो लोग ऑक्सीजन प्लाण्ट चलाते हैं तो हम आपको उनकी अतिरिक्त जानकारी दिये दे रहे हैं कि हमने उनकी ट्रेनिंग भी कराई है, ऑनलाइन भी कराई और व्यक्तिगत रूप से भी कराई है। जो कम्पनियां ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, जब तक मशीन/प्लाण्ट की ट्रेनिंग कम्पलीट नहीं हो गई, तब तक हमने उनको हैण्डओवर नहीं लिया है और हमारे सभी प्लाण्ट कार्यरत हैं। सभी चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जौनपुर में भी चल रहा है।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाने के विषयक

***16-श्री नफीस अहमद-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

अल्पसंख्यकों के शिक्षार्थ निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

राज्य वित्त पोषित पूर्वदशम्, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना।

केन्द्र वित्त पोषित पूर्वदशम्, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम मीन्स योजना।

मेडिकल/इंजीनियरिंग कोचिंग योजना।

मदरसा मिनी आई0टी0आई0 योजना।

बहुउद्देशीय शैक्षिक हब (मॉडल इण्टर कालेज) योजना।

मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना।

छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण योजना (आई0डी0एम0आई0)।

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना (एस0पी0ई0एम0एम0)।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। बार-बार यह कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।

लेकिन हकीकत में माननीय अध्यक्ष जी, जमीन पर यह चीज दिखती नहीं है। मेरा सवाल था जिस पर मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक पूछना चाहता हूँ कि सत्र 2021-22 में अल्पसंख्यक छात्रों को जो वजीफे दिये गये, उसके लिए कितना धन खर्च हुआ और कितने बच्चों को इसका लाभ पहुंचा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न जल्दी कर लीजिये, 12:20 होने जा रहा है।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि बहुउद्देशीय शैक्षिक हब (मॉडल इण्टर कालेज) योजना के तहत उत्तर प्रदेश में यह योजना कहाँ-कहाँ संचालित की जा रही है और किस स्थिति में है ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सत्र 2021-22 में कितने मदरसों को चिन्हित किया गया और इसके लिए कितना बजट आवंटित करके खर्च किया गया ? मेरा चौथा प्रश्न यह है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कहाँ-कहाँ संचालित की जा रही है और उसमें कितने छात्रों को इससे लाभ पहुंच रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

अतारांकित

उ0प्र0 में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान पेंशन राशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

1-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि में वर्ष 2018 के पश्चात् वृद्धि नहीं की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकतंत्र सेनानियों को वर्तमान में दी जा रही सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में आवारा पशुओं से जनता को हो रही परेशानी तथा फसलों के नुकसान के दृष्टिगत आवारा पशुओं के लिए कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

2-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क व खेतों पर आवारा पशुओं से जनता को हो रही परेशानी तथा फसलों के नुकसान के दृष्टिगत आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गौमय औषधीय उत्पादों पर शोध, निर्माण और विपणन को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

3-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौमय (गोबर, गौमूत्र, दुग्ध, दही आदि) का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गौ आधारित औषधीय उत्पादों पर शोध, उनके निर्माण और विपणन को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

जी हाँ।

आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माण अनुज्ञा का प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 तत्सम्बन्धी नियम-1945 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवहरित किया जाता है। यदि किसी आयुर्वेदिक औषधि निर्माता फर्म द्वारा ऐसी स्वानुभूत औषधियों की निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के निमित्त आवेदन किया जाता है, जिसमें घटक द्रव्य के रूप में गौमय (गोबर, गौमूत्र, दुग्ध, दही आदि) पदार्थ भी शामिल हैं, तो आयुर्वेद निदेशालय द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तत्सम्बन्धी नियम, 1945 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त औषधियों से सम्बन्धित प्रपत्रों का परीक्षण करके औषधि निर्माता को निर्माण एवं बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है।

विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृति निदेशालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थान/अकादमियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

4-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृति निदेशालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थानों, अकादमियों में स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में सृजित पद 73 के सापेक्ष रिक्त 37 पद, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में सृजित पद 30 के सापेक्ष रिक्त 13 पद, कथक केन्द्र, लखनऊ में सृजित पद 11 के सापेक्ष रिक्त 05 पद, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में सृजित पद 18 के सापेक्ष रिक्त 03 पद, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में सृजित पद 14 के सापेक्ष रिक्त 03 पद, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में सृजित पद 38 के सापेक्ष रिक्त 08 पद तथा अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में सृजित पद 12 के सापेक्ष 05 पद रिक्त हैं।

सुसंगत नियमों के अन्तर्गत रिक्त पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में मवेशियों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाने विषयक

5-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में मवेशियों द्वारा किसानों की फसल नष्ट होने से बचाव हेतु कोई कारगर योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

उपरोक्त नीति के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सरेनी (182), रायबरेली में 04 अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों एवं 01 वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसमें कुल 809 गौवंश संरक्षित किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त 03 कांजी हाउस एवं 01 कान्हा उपवन में कुल 1253 गौवंश संरक्षित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के चिकित्सालय में स्वास्थ्य समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में स्थित महिला चिकित्सालय में दो अल्ट्रासाउण्ड की मशीनों के संचालन हेतु कोई डॉक्टर तैनात नहीं है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अयोध्या के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन की मशीन विगत पांच वर्ष से खराब होकर बन्द है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद के किसी भी अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बन्द अल्ट्रासाउण्ड मशीन व सी0टी0 स्कैन का संचालन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद अयोध्या के जिला महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड की मशीनों के संचालन हेतु कोई डॉक्टर तैनात नहीं है।

जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन की मशीन निष्प्रयोज्य होने के कारण बन्द है। जिला चिकित्सालय, अयोध्या में पी0पी0पी0/आउटसोर्स के माध्यम से सी0टी0 स्कैन की सेवायें प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 यथा संशेधित 2021 में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद नहीं है। सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों के पद मेडिकल कालेज में होते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर सहायक आचार्य पद पर कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

7-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-09-2021 जो कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में शासकीय आदेशों की अवहेलना एवं भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्रता करने वाले कर्मियों के विरुद्ध चिकित्सा अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन में लम्बित प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 20-09-2021 प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु पत्र दिनांक 29-09-2021 प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 29-09-2021 श्री मुदस्सर अहमद व श्री मनीष सिंह, सहायक आचार्य द्वारा संस्थान में लड़ाई-झगड़ा, संविदा कर्मियों का शोषण, संस्थान के निदेशक के आदेशों की अवहेलना एवं वन विभाग की अनुमति के बिना संस्थान के पेड़ों की अवैध रूप से कटाई आदि के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने से संबंधित है।

उक्त दोनों कार्मिकों के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) संयुक्त चिकित्सालयों के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

8-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के पार्क रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए जनहित में उक्त अस्पताल का विस्तारीकरण कार्य सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ के विस्तारीकरण हेतु सूचना निदेशालय के पुराने भवन एवं परिसर को शासनादेश संख्या-160/2021/458/पांच-6-2021, दिनांक 05-05-2021 के द्वारा ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गयी है। चिकित्सालय के विस्तारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र व एम्बुलेन्स सेवा के सम्बन्ध में

9-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा कितने केन्द्रों में एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध है ? क्या सरकार जिन केन्द्रों पर एम्बुलेन्स सेवा नहीं है ? उक्त केन्द्रों पर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कुल 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः लालगंज, सरेनी, डलमऊ एवं खजूरगांव हैं। इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर 102 एवं 108 एम्बुलेन्स सेवायें उपलब्ध हैं।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर 102 एवं 108 एम्बुलेन्स सेवायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों की जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के सम्बन्ध में

10-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 100 वर्षों से अधिक प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रदेश में स्थित प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में सौ शैय्या अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में

11-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के फैजुल्लागंज में 100 शैय्यायुक्त अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2953/पांच-6-209-07(जी)/2020 द्वारा प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। प्रश्नगत शासनादेश संख्या-2953/पांच-6-209-07(जी)/2020, दिनांक 31-03-2020 द्वारा केवल निर्माण एजेंसी का चयन किया गया है। शासनादेश संख्या-1584/पांच-6-2021-07-(जी)/2020, दिनांक 27-12-2021 द्वारा प्रश्नगत स्थल पर 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के निर्माण पर निर्णय लिया गया।

अस्पताल के निर्माण की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में सीतापुर रोड पर शिया कालेज से पक्का पुल की ओर शिया कालेज की वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा मुक्त कराने विषयक

12-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सीतापुर रोड पर शिया कालेज से पक्का पुल की ओर शिया कालेज की वक्फ सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान आदि का निर्माण किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कर वक्फ की सम्पत्ति कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल बोर्ड के अभिलेखानुसार उक्त सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल बोर्ड के अभिलेखानुसार उक्त सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है।

प्रदेश में नये मेडिकल कालेज जिलेवार शुरू किये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री हर्षवर्धन वाजपेयी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये मेडिकल कालेज जिलावार शुरू करने की योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मेडिकल कालेज स्थापित कर सुचारु रूप से संचालित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कालेजों में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, तथा इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश में केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत 05 एवं फेज-2 के अन्तर्गत 08 मेडिकल कालेज तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कालेज जौनपुर कुल मिलाकर 14 मेडिकल कालेज स्थापित/संचालित हैं।

फेज-1 के अन्तर्गत 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम तृतीय बैच प्रवेशित हैं।

फेज-2 के अन्तर्गत 08 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-एटा, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मीरजापुर, गाजीपुर, देवरिया तथा सिद्धार्थनगर एवं मेडिकल कालेज, जौनपुर में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रथम बैच प्रवेशित हैं।

उपर्युक्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों के स्वीकृत 790 पदों के सापेक्ष कुल 526 चिकित्सा शिक्षक कार्यरत हैं। इन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के बायलाज में विहित व्यवस्थानुसार चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

आवश्यकतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद हवाई पट्टी से उड़ानें शुरू करने की जानकारी सम्बन्धी

14-श्री मोहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में हवाई पट्टी से अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें किसी निश्चित समयावधि तक सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मुरादाबाद में स्थित हवाई पट्टी भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत द्वितीय चरण की बिडिंग में यात्री विमान सेवाओं के लिए चयनित हुई है। विमान सेवाओं हेतु उक्त हवाई पट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है तथा उड़ानों के संचालन हेतु 'एयरोड्रोम लाइसेंस' के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0) भारत सरकार में आवेदन किया गया है। एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात् उक्त हवाई पट्टी यात्री विमान सेवाओं के लिए उपलब्ध होगी।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत उड़ानें प्रारम्भ होने की तिथि का निर्धारण नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूरा कराने के सम्बन्ध में

15-श्री मोहम्मद फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मद इब्राहीमपुर विकास खण्ड बिलारी (पूर्व विकास खण्ड बनियाखेड़ा आंशिक) में शासनादेश संख्या-34/2016/41/पांच-6-2016-22(निर्माण)/2015, दिनांक 03-02-2016 द्वारा निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मद इब्राहिमपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रुपये 187.87 लाख के सापेक्ष निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण इकाई द्वारा मुख्य भवन, छत पूर्ण, चिकित्साधिकारी आवास प्लिंथ स्तर, श्रेणी-1 आवास छत स्तर एवं श्रेणी-2 आवास डोर स्तर तक पूर्ण, ओवरहेड टैंक का नींव कार्य पूर्ण किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के झांसी नगर में होम्योपैथिक कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

16-श्री रवि वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के झांसी नगर में रोगियों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज के दृष्टिगत जनहित में होम्योपैथिक कालेज की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जनपद झांसी के झांसी नगर में रोगियों के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की उपलब्धता हेतु 03 होम्योपैथिक चिकित्सालय (डिस्पेंसरी) स्थापित/संचालित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद झांसी में कुल 09 होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित/संचालित है।

सम्प्रति जनपद झांसी में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

17-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिनांक 05 अप्रैल, 2022 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है तथा जनपद अयोध्या के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किये जाने विषयक शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद अयोध्या के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध मा0 विधायक जी के द्वारा कई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए डॉ0 अनिल कुमार कुशवाहा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तथा जनपद जौनपुर में ट्रामा सेण्टर के पूर्ण क्षमता से संचालन के सम्बन्ध में

18-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ट्रामा सेण्टर पूर्ण क्षमता में कार्यरत हैं ? क्या सरकार जनपद जौनपुर में निर्मित ट्रामा सेण्टर के संचालन की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन 03 ट्रामा सेण्टर पूर्ण क्षमता से कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन 21 ट्रामा सेण्टर उपलब्ध मानव संसाधनों से आंशिक रूप से क्रियाशील है।

जनपद जौनपुर में स्थित ट्रामा सेण्टर में निश्चेतक-01, आर्थोपैडिक सर्जन-01, ई0एम0ओ0-01, एक्स-रे टेक्नीशियन-01, लैब टेक्नीशियन-01, नर्सिंग अटेन्डेंट-09, मल्टीटॉस्क वर्कर-06 तैनात हैं। ट्रामा सेण्टर में सी0टी0 स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्स-रे मशीन, वेन्टीलेटर, पैरामीटर, एच0एफ0एन0सी0 बाईपैप उपकरण उपलब्ध हैं। ट्रामा सेण्टर में उपचारित मरीजों की संख्या संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तैनात आशा बहुओं को मानदेय और स्कूटी दिये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात आशा बहुओं के कार्यों के महत्व के दृष्टिगत इनके मानदेय को बढ़ाये जाने तथा उनके द्वारा त्वरित सेवाओं को प्रदान किये जाने के लिए स्कूटी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

आशा बहुओं द्वारा सामान्यतः अपने घर के समीप 1000 की जनसंख्या पर (लगभग 200 घरों में) स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता सुलभ किये जाने हेतु भ्रमण किया जाता है।

प्रदेश में अवशेष जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में

20-श्रीमती पूजा पाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं खोले जा सके हैं ? क्या सरकार उक्त जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, प्रदेश के 27 जनपदों यथा-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, हापुड़, अमरोहा, बाराबंकी, बरेली, फर्रूखाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, उन्नाव में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं खोले जा सके हैं।

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-301 पर।

प्रदेश के उपर्युक्त 27 जनपदों में से जहाँ पर कोई भी राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान तथा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्राइवेट मेडिकल कालेज नहीं हैं, ऐसे 16 असेवित जनपदों यथा बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली तथा श्रावस्ती में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सापेक्ष जनपद महाराजगंज एवं सम्भल में प्राइवेट पार्टनर चिन्हित कर कन्सेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हो गये हैं, तथा शेष 14 जनपदों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग के जरिये तैनात नर्सों व अन्यों का बकाया वेतन देने के सम्बन्ध में

21-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग से तैनात नर्सों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भुगतान बकाया है ? क्या सरकार उनके वेतन बकाया का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा का ताजमहल व लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा के पर्यटक स्थल सूची में नाम होने न होने सम्बन्धी

22-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की वर्तमान सूची में ताजमहल (आगरा) तथा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ शामिल है ? यदि नहीं, तो उक्त के कारणों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों की कोई अधिकारिक सूची जारी नहीं की जाती है।

ताजमहल आगरा तथा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश पर्यटन के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं, जहाँ बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है।

उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों की कोई अधिकारिक सूची जारी नहीं की जाती है। अतः किसी भी स्थल के उक्त सूची में होने या न होने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

यूक्रेन से प्रदेश में लौटे मेडिकल छात्रों की संख्या व उनके कोर्स को पूरा करने के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में

23-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने मेडिकल छात्र रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न स्थिति के कारण यूक्रेन से लौटकर वापस आये हैं ? क्या सरकार यूक्रेन से वापस आये मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, प्रदेश स्थित मेडिकल कालेजों में कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न स्थिति के कारण यूक्रेन से लौटकर वापस आये उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल छात्रों की निश्चित संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु जो भी निर्णय भारत सरकार/नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली द्वारा लिया जायेगा, तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में विज्ञापन के सापेक्ष 2021 में शत-प्रतिशत नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में

24-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हेतु वर्ष 2021 में कितने चिकित्सक के पद विज्ञापित किये गये तथा उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक नियुक्त किये गये ? क्या सरकार चिकित्सकों की शत-प्रतिशत नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हेतु शासन के पत्र दिनांक 24-03-2021 द्वारा चयन वर्ष 2020-21 में 3620 पदों का अधियाचन लोक सेवा

आयोग प्रेषित किया गया। उक्त सभी पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापित पदों के सापेक्ष कुल 1237 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा कुल 2382 पदों का पुनर्विज्ञापन किये जाने हेतु अग्रेनीत किया गया। मा0 आयोग द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जनरल सर्जन-154, बाल रोग विशेषज्ञ-146, ई0एन0टी0-42, हड्डी रोग विशेषज्ञ-67, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट-24, स्त्री रोग विशेषज्ञ-194, मनोरोग विशेषज्ञ-36, माइक्रोबायोलॉजिस्ट-17, नेत्र रोग विशेषज्ञ-59, फारेंसिक विशेषज्ञ-15, चर्म रोग विशेषज्ञ-21, पैथालॉजिस्ट-62, रेडियोलॉजिस्ट-4, जनरल फिजिशियन-72, निश्चेतक-89, कुल-1002 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती की जा चुकी है।

जी हाँ, लोक सेवा आयोग की संस्तुति के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में आई0पी0डी0 में मरीजों का इलाज कराने के सम्बन्ध में

25-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में वर्ष 2019 से 2021 तक आई0पी0डी0 में कितने मरीजों का इलाज हुआ तथा उक्त में से कितने मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत कितने कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया गया है तथा उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

वर्ष	आई0पी0डी0 मरीजों की कुल संख्या	आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उपचारित मरीजों की संख्या	आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उपचारित कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या
2019	58148	2920	0
2020	38897	1433	0
2021	38852	1463	01

कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या-01

विवरण

मरीज का नाम	सत्तार
रजिस्ट्रेशन का दिनांक	07-04-2021
किस विभाग में भर्ती थे	सर्जरी
चिकित्सक जिनके अन्तर्गत भर्ती हुआ	डॉ0 संतोष सिंह
कोविड-19 पॉजिटिव के कारण ट्रांसफर का दिनांक	14-04-2021
चिकित्सकों का नाम जिन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने पर मरीज का इलाज किया	डॉ0 दीपक गुप्ता, डॉ0 शक्ती जैन, डॉ0 विक्रम निगम
मृत्यु की तिथि	15-04-2021

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के प्रेमनगर नगरा में राजकीय अस्पताल स्थापित करने के सन्दर्भ में

26-श्री रवि शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के प्रेमनगर नगरा की आबादी लगभग 01 लाख है, में कोई राजकीय अस्पताल नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को इलाज हेतु लगभग 09 कि0मी0 दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में प्रेमनगर नगरा में राजकीय अस्पताल स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रेमनगर नगरा में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। इसके दोनों ओर 04 कि0मी0 की दूरी पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुलिया नम्बर-9 एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजघाट संचालित है।

क्षेत्रीय जनता को नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। अतः अस्पताल स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण से उत्पन्न बीमारियों से मेडिकल कालेजों को आच्छादित करने के सम्बन्ध में

27-श्रीमती पूजा पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न बीमारियों के इलाज हेतु प्रदेश के मेडिकल कालेजों को जीवन रक्षक प्रणाली, चिकित्सा

सुविधा, चिकित्सा उपकरण आदि से आच्छादित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक शासकीय आदेश जारी करते हुए कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न बीमारियों के इलाज हेतु प्रदेश के मेडिकल कालेजों को जीवन रक्षक प्रणाली, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा उपकरण आदि से आच्छादित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

सरकारी अस्पतालों में खाली पदों की स्थिति एवं उन पर नियुक्ति की जानकारी

28-श्रीमती पूजा पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित नर्सों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्ष 2018 से 2022 तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर एवं नर्सों की तैनाती की गई है ? क्या सरकार शेष रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में चिकित्सक के कुल 19011 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 10,580 पद सामान्य चिकित्सकों के एवं 8,431 पद विशेषज्ञ चिकित्सकों के हैं। प्रशिक्षित स्टाफ नर्स के कुल 9665 पद स्वीकृत हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्ति के दृष्टिगत 2,586 सामान्य चिकित्सकों, 1002 विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा 1740 स्टाफ नर्सों की तैनाती की गई।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं नर्सों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत तैनाती की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

कुपोषण और बाल मृत्यु दर में प्रदेश की खराब स्थिति को सुधारने के उपाय करने विषयक

29-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण और किशोर मृत्यु दर आंकड़ों के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है ? क्या सरकार इस दिशा में सुधार हेतु बीते 3 वर्षों के किये गये प्रयासों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबीरानी मौर्य-

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4(NFHS-4) (2015-16) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 05 वर्ष तक के बच्चों में बौनापन (Stunting) 46.3 प्रतिशत, अल्पवजन (Underweight) 39.5 प्रतिशत व सूखापन (Wasting) 17.9 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(NFHS-5) (2019-21) में क्रमशः 39.7 प्रतिशत, 32.1 प्रतिशत व 17.3 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4(NFHS-4) से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(NFHS-5) के मध्य बौनापन में 6.6 प्रतिशत, अल्पवजन में 7.4 प्रतिशत एवं सूखापन में 0.6 प्रतिशत का सुधार हुआ है। विभाग द्वारा किशोर मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया है।

जी हाँ

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड ऊंचाहार में महान तपस्वी गौकर्ण ऋषि के नाम से गौकना को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने विषयक

30-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या पर्यटन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड ऊंचाहार में महान तपस्वी गौकर्ण ऋषि के नाम से गौकना को पर्यटक स्थल के रूप में चयनित किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त पर्यटन स्थल पर होने वाले विकास कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित नहीं किया जाता है, अपितु ऐसे स्थान जहाँ पर्यटकों का आगमन बड़ी संख्या में होता है, वहाँ पर पर्यटकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा यात्री छावक, शौचालय, बेंचें, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था आदि की स्थापना की जाती है।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-302-303 पर।

जनपद रायबरेली में प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वतंत्र विद्युत फीडर से सेवित करने विषयक

31-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वतंत्र विद्युत फीडर से सेवित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। मानक के अनुसार मात्र 100 शैय्या एवं अधिक शैय्या क्षमता के चिकित्सालयों पर स्वतंत्र विद्युत फीडर सेवित करने की योजना है।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वतंत्र विद्युत फीडर स्थापित करने का मानक नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी के रख-रखाव हेतु बीते एवं चालू वर्षों में आवंटित धनराशि की जानकारी

32-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के नगर बिलारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी को रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-2021 में कितनी धनराशि प्राप्त और व्यय हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी धनराशि उक्त अस्पताल हेतु आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई थी। जनपद मुरादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी हेतु प्राप्त सामान्य अनुरक्षण बजट से वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 4,79,389/- एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 6,67,650/- का व्यय मरम्मत एवं रंगाई-पुताई में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रख-रखाव मद में धनराशि आवंटन की कार्यवाही अभी नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दाउद नगर एवं फैजुल्लागंज हेतु कर्मियों की तैनाती व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

33-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए विभाग द्वारा आवंटित कोड के आधार पर चिकित्सीय सुविधाएं यथा कर्मियों की नियुक्ति, दवा आदि आवंटित होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद लखनऊ के नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउदनगर, फैजुल्लागंज हेतु कोड आवंटन कर मानक अनुसार कर्मियों की तैनाती व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सीय सुविधाएं/दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

स्थानीय व्यवस्था के अनुसार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 महिला चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट एवं 01 लैब असिस्टेंट की तैनाती करते हुए जन सामान्य को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में स्थित लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज में रेडियोथेरेपी एवं एम0आर0आई0 मशीन के संचालन के सम्बन्ध में

34-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज में कैंसर थेरेपी हेतु रेडियोथेरेपी मशीन वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो उक्त का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में एम0आर0आई0 मशीन संचालित है ? यदि हाँ, तो उक्त हेतु किस चिकित्सक की तैनाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज में रेडियोथेरेपी विभाग की कोबाल्ट मशीन के पुनः संचालन हेतु कोबाल्ट-60 सोर्स दिनांक 20-04-2022 को बोर्ड ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप टेक्नोलाजी (BRIT) मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त सभी नियामक प्रक्रियाओं की पूर्णता के पश्चात् एटामिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) द्वारा दिनांक 18-05-2022 को

अनुमति प्रदान की गयी। इस प्रकार दिनांक 19-05-2022 से मरीजों का इलाज रेडियोथेरेपी मशीन द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हाँ।

वर्तमान में रेडियोथेरेपी विभाग में कोई संकाय सदस्य तैनात नहीं है। अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत डॉ0 आरुषि, सीनियर रेजीडेंट तैनात हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश में आवारा छुट्टा पशुओं की आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं अनुदान/बजट के सम्बन्ध में

35-श्री अतुल प्रधान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा छुट्टा पशु के लिए आश्रय स्थल संचालित हैं, यदि हाँ, तो वर्तमान उक्त आश्रय स्थलों में छुट्टा पशुओं के लिए प्रति पशु कितना अनुदान/बजट की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में स्थापित/संचालित गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश के लिए रुपये 30/- प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि दिये जाने की व्यवस्था प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी को आरोग्य निधि में धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

36-श्री रवि शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी को आरोग्य निधि में विगत दो-तीन वर्षों से धन उपलब्ध न होने के कारण मरीज बीमारियों के लिए धन के अभाव में इलाज कराने में असमर्थ हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी को आरोग्य निधि में धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक दिनांक 03-12-2019 के द्वारा मेडिकल कालेज, झांसी में मरीजों के उपचार हेतु आरोग्य निधि मद में धनराशि आवंटित की गयी थी। इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में उक्त मद में धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

वर्तमान में मरीजों के हित में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत झांसी नगर के लक्ष्मी मंदिर का संवर्धन एवं सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में

37-श्री रवि शर्मा-

क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत झांसी नगर के ऐतिहासिक लक्ष्मी मंदिर का संवर्धन एवं सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थल का स्थानीय मा0 विधायक की संस्तुति पर चयन कर उसका पर्यटन विकास कराया जाता है।

झांसी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मढ़िया महादेव मंदिर स्थल का चयन वर्ष 2021-22 में योजना के अन्तर्गत किया गया है, जिसके क्रम में रुपये 44.90 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है व योजना के कार्य प्रगति पर हैं तथा वर्तमान में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित झांसी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला अस्पताल मुरादाबाद परिसर में स्थापित जन औषधि केन्द्रों तथा उन पर उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों की जानकारी सम्बन्धी

38-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल मुरादाबाद परिसर में स्थित जन औषधि केन्द्र सहित पूरे जिले में कितने जन औषधि केन्द्र स्थापित हैं ? क्या सरकार

को जानकारी है कि जिला अस्पताल मुरादाबाद परिसर में स्थित जन औषधि केन्द्र बन्द हैं ? यदि हाँ, तो कब से ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जन औषधि केन्द्रों में सूचीबद्ध 600 दवाइयों में से कितनी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? क्या सरकार उक्त जन औषधि केन्द्रों पर मांग के अनुरूप दवाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जिला मुरादाबाद में 02 सरकारी चिकित्सालयों तथा 18 निजी क्षेत्रों में कुल 20 जन औषधि केन्द्र स्थापित हैं।

जिला अस्पताल मुरादाबाद परिसर स्थित जन औषधि केन्द्र का संचालन दिनांक 01-09-2020 से अधिकृत वेण्डर द्वारा अनुबन्ध की शर्तों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण रोक दिया गया था। प्राप्त प्रत्यावेदन पर सुनवाई के उपरान्त वेण्डर के द्वारा प्रस्तुत तथ्य के दृष्टिगत जन औषधि केन्द्रों को पुनः संचालित करने हेतु दिनांक 25-01-2021 को अनुमति प्रदान की गयी। सम्बन्धित सरकारी जन औषधि केन्द्र वर्तमान में दिनांक 06-09-2021 से संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जन औषधि केन्द्रों में पी0एम0बी0आई0 द्वारा आपूर्तित सूचीबद्ध दवाइयों में से लगभग 300 प्रकार की दवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जन औषधि केन्द्रों को दवायें सीधे भारत सरकार के उपक्रम पी0एम0बी0आई0 द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में चिकित्सालय निर्माण हेतु धनराशि निर्गत कराने के विषयक

39-श्री रवि शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में 500 शैय्या युक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण विगत 2-3 वर्षों से बन्द है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में शासनादेश दिनांक 06-06-2013 द्वारा स्वीकृत 500 बेडेड चिकित्सालय के विस्तारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रारम्भ कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश दिनांक 11-01-2021

द्वारा अन्तिम बार रुपये 440.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रुपये 13798.11 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रुपये 13108.21 लाख (कुल लागत का 95 प्रतिशत) अवमुक्त किया जा चुका है। मात्र 5 प्रतिशत की धनराशि रुपये 689.90 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है। इसी बीच कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन रुपये 18007.26 लाख उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पुनरीक्षित आगणन के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य की भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई की वीरगाथा को भावी पीढ़ी एवं पर्यटकों से परिचित कराने के लिए 'झलकारी बाई पुरातात्विक संग्रहालय' की स्थापना के सन्दर्भ में

40-श्री रवि शर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में 1857 ई0 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झलकारी बाई की वीरगाथा को भावी पीढ़ी एवं पर्यटकों से परिचित कराने के उद्देश्य से झलकारी बाई पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

वीरांगना झलकारी बाई से सम्बन्धित पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध होने पर नियमानुसार पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी को भारत के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कार्यवाही करने के सन्दर्भ में

41-श्री रवि शर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी को भारत के पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हाँ।

जनपद झांसी को प्रदेश, देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर प्रमुख पर्यटन गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित करने हेतु उ0प्र0 विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। मुख्य योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

1-झांसी जनपद में साइनेज की व्यवस्था।

2-मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी में मढिया महादेव मंदिर, मोठ किले का विकास, मउरानीपुर में बगियाघाट धाम में हनुमान मंदिर का पर्यटन विकास, बरुआसागर स्थित स्वर्गाश्रम झरने का विकास।

3-केदारेश्वर मंदिर मउरानीपुर, एरच में स्थित किला हनुमान गढ़ी मंदिर परिसर में मूलभूत पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं ऐतिहासिक पारीछा बांध परिसर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।

4-प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत झांसी के किले एवं अन्य स्थलों पर डाक्युमेन्ट्री/टी0वी0सी0 आदि बनवाकर प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म (यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू) आदि के माध्यम से भी जनपद झांसी के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार, ट्रैवल ब्लागर्स के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर शार्ट वीडियोज का निर्माण कर प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाग द्वारा प्रतिभाग किये जाने वाले आयोजनों में भी झांसी पर निर्मित टी0वी0सी0 फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलो में 3 वर्ष व मण्डलों में 7 वर्ष से तैनात अधिकारियों को हटाने के सम्बन्ध में

42-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासनादेश संख्या 3/2018/1/3/96-का-4-2018 के विपरीत जिले में 3 वर्ष व मण्डल में 7 वर्ष से अधिक समय से तैनात अधिकारियों को चिन्हित कर उनका स्थानान्तरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या 3/2018/1/3/96-का-4-2018 द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-2022 तक के लिए जारी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति की निर्धारित समयावधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। नवीन वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत होने के उपरान्त परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विगत 05 वर्षों में रसगुल्ले और मिठाई बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों के नमूनों की जानकारी के सम्बन्ध में

43-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में रसगुल्ले अथवा अन्य मिठाई बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों के कितने नमूने जांच हेतु भरे गये, उनमें कितने नमूने जांच में फेल पाये गये तथा कितने फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में विगत 05 वर्षों (दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2022 तक) में रसगुल्ले अथवा अन्य मिठाई बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों से कुल 496 नमूने संग्रहीत किये गये। उक्त नमूनों की जांच में कुल 227 नमूने मानक के अनुरूप नहीं (फेल) पाये गये।

मानक के अनुरूप नहीं पाये गये उक्त नमूनों के विरुद्ध कुल अभियोजन कार्यवाही में अर्थदण्ड से सम्बन्धित 190 वाद मा0 न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में तथा कारावास एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित 23 वाद मा0 न्यायिक न्यायालय में दायर किये गये, जिनमें से मा0 न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय द्वारा कुल 96 वाद निर्णीत कर रुपये 51,10,000/- (रुपये इक्यावन लाख दस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थायी रूप से चिकित्सक एवं मानक अनुरूप उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देने के सम्बन्ध में

44-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के त्रिवेणी नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ? यदि हाँ तो उक्त केन्द्र पर स्थायी चिकित्सक एवं मानक अनुरूप उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं का विवरण क्या है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थायी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ का पद सृजित नहीं है। उक्त चिकित्सालय में संविदा पर चिकित्सक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0, वार्ड ब्वाय, स्वीपर तैनात हैं तथा चिकित्सालय में मानक के अनुरूप ओ0पी0डी0 पैथालॉजी जांच, टीकाकरण एवं औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दाउद नगर में बच्चों के टीकाकरण के साथ-साथ कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

45-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दाउद नगर व रहीम नगर गुदौली में बच्चों के टीकाकरण के साथ-साथ कोविड टीकाकरण की सुविधा उक्त केन्द्रों पर सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दाउद नगर व रहीम नगर गुदौली में बच्चों के टीकाकरण के साथ-साथ कोविड टीकाकरण का कार्य पूर्व से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में हवाई अड्डे का निर्माण के सम्बन्ध में

46-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में हवाई उड़ान सुचारु रूप से संचालन हेतु हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मेरठ में स्थित हवाई पट्टी नागरिक वायुसेवा के संचालन की दृष्टि से विकास कार्यों हेतु वर्ष 2014 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी थी, किन्तु नागरिक वायुसेवा हेतु मेरठ हवाई पट्टी को आर्थिक रूप से सक्षम न पाये जाने के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तत्समय विकास कार्य नहीं कराया गया।

मेरठ हवाई पट्टी केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर0सी0एस0) के तृतीय चरण की बिडिंग में चयनित हुई है तथा आर0सी0एस0 वायुसेवा के संचालन हेतु मेरठ हवाई पट्टी का विकास कराये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा ड्राफ्ट मास्टर प्लान उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार मेरठ हवाई पट्टी के प्रथम चरण के विकास के लिए 300 एकड़ तथा द्वितीय चरण के विकास के लिए 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता इंगित की गयी है। उक्तानुसार वांछित भूमि की उपलब्धता एवं उसके क्रय/अधिग्रहण पर आने वाले व्यय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ से आख्या मांगी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

47-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो विभागवार वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में सहायक प्रोफेसर के कुल 20 पद रिक्त हैं। विभागवार विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	विभाग	असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद
1	एनेस्थिसियोलॉजी	2
2	डेन्टिस्ट्री	1
3	डरमेटोलॉजी	1
4	इन्डोक्रायनोलॉजी	1
5	फारेन्सिक मेडिसिन	1
6	जनरल मेडिसिन	3
7	जनरल सर्जरी	2
8	मेडिकल आंकोलॉजी	1
9	माइक्रोबायोलॉजी	1
10	नियोनेटोलॉजी	1
11	न्यूक्लियर मेडिसिन	1
12	आप्थलमेलॉजी	1
13	पीडियाट्रिक	1
14	पी0एम0आर0	1
15	साइकियाट्री	1
16	रेडियो डायग्नोसिस	1
योग		**20**

रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पशु चिकित्सालय में चिकित्सक और उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में

48-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कितने राजकीय पशु चिकित्सालय हैं तथा कितनों में डॉक्टर, उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर मानकानुसार पशु चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 13 पशु चिकित्सालय हैं। 11 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सक तैनात हैं जबकि रिक्त 02 पशु चिकित्सालयों (शोभवापुर एवं भीरागोविन्दपुर) का राजकीय कार्य निकटस्थ तैनात पशु चिकित्सकों से सम्पादित कराया जा रहा है। पशु चिकित्सालयों में उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के उर्सला, डफरिन सहित अन्य अस्पतालों में साइकल/मोटर साइकिल से अस्पतालों में शुल्क व्यवस्था के सम्बन्ध में

49-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के उर्सला, डफरिन सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में पार्किंग में साइकल/मोटर साइकिल से शुल्क वसूले जाने की वर्तमान व्यवस्था का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, विवरण निम्नवत है :-

यू0एच0एम0 (उर्सला), जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर नगर में वर्ष 2016 में साइकिल स्टैण्ड की पार्किंग टेण्डर के माध्यम से नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर वर्तमान में भी निर्धारित शुल्क पर पार्किंग संचालित है।

ए0एच0एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर में ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा साइकिल/मोटर साइकिल का शुल्क वसूला जाता है और चालान के माध्यम से एस0बी0आई0 शाखा कानपुर नगर में धनराशि जमा की जाती है।

के0पी0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क है।

मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेण्टर, कानपुर नगर के पार्किंग में साइकिल/मोटर साइकिल का कोई स्टैण्ड नहीं है और न ही कोई शुल्क वसूला जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में पोस्टमार्टम की व्यवस्था 24 घंटे कराये जाने विषयक

50-श्री रवि शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में रात्रि में पोस्टमार्टम की कोई व्यवस्था न होने के कारण लोगों को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद झांसी में 24 घंटे पोस्टमार्टम कराये जाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद झांसी में रात्रि में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी एवं सी0एच0सी0 मऊरानीपुर में पोस्टमार्टम व्यवस्था उपलब्ध है।

24 घंटे पोस्टमार्टम की व्यवस्था उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित हो रहे राजकीय होम्योपैथिक हास्पिटल निर्माण हेतु जमीन उपलब्धता होने पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में

51-श्री जगदीश नरायण-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक हास्पिटल निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर उस पर भवन निर्माण कराने का क्या कोई प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

राजकीय होम्योपैथिक हास्पिटल निर्माण के नाम से विभाग में कोई योजना/प्राविधान नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में होम्योपैथी विधा के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय (डिस्पेंसरी) स्थापित हैं। इन चिकित्सालयों के लए भूमि की उपलब्धता की स्थिति में जिला योजना के माध्यम से परिव्यय आदि की उपलब्धता के अनुसार समुचित प्रस्ताव/आगणन

जनपदों से प्राप्त होने पर नियमानुसार बजट आदि की व्यवस्था हो जाने पर शासन द्वारा भवन निर्माण हेतु एजेन्सी नामित कर शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जाती हैं। तदुपरान्त नामित एजेंसी के द्वारा प्रश्नगत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

52-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं व जांच के अभाव में मरीजों को इलाज में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं व जांच की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं, जनपद बलिया के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मानकानुसार दवायें एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम समय पर आयोजित कराने के सम्बन्ध में

53-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षण सत्र 2022-23 के प्रवेशार्धिकों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने का अवसर समयावधि के अन्दर प्राप्त हो सकने के दृष्टिगत क्या सरकार प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम का उक्तानुसार निर्धारण करेगी ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

संख्या 42 सन् 2018) के अध्याय-दो की धारा-06(तीन) के अनुसार प्रवेश परीक्षा कराये जाने का प्राविधान है तथा प्रवेश की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, भारतीय दंत परिषद् एवं भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के नगर पालिका महिला अस्पताल के संचालन एवं समुचित उपकरण तथा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में

54-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित महिला अस्पताल का संचालन न होने के कारण महिलाओं को इलाज में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कराकर अस्पताल का संचालन तथा चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं, 16 बेड का राजकीय महिला चिकित्सालय पडरौना में संचालित है, जिसमें 02 महिला चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट आदि तैनात हैं। चिकित्सालय पर सामान्य प्रसव, दैनिक ओ0पी0डी0 इत्यादि की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार अस्पताल में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत अस्पतालों का विवरण के सम्बन्ध में

55-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कितने व कौन से अस्पताल वर्तमान में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में कुल 43 चिकित्सालय पंजीकृत हैं, जिसमें से 25 राजकीय चिकित्सालय एवं 18 प्राइवेट चिकित्सालय हैं। (सूची संलग्न है)।

जी हाँ, उपरोक्तानुसार सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2021-22 में अति-कुपोषित बच्चों को पोषित आहार दिलाने के सम्बन्ध में

56-श्री नफीस अहमद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2021-22 में कुल कितनी संख्या में अति-कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनको पोषित आहार दिलाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

वर्ष 2021-2022 में जनपद आजमगढ़ में कुल 11832 अति-कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी है।

जी हाँ।

चिन्हित अति-कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषित आहार के रूप में प्रतिमाह 2.0 कि0ग्रा0 चना दाल, 1.5 कि0ग्रा0 फोर्टिफाइड गेहूँ दलिया, 500 मि0ली0 फोर्टिफाइड खाद्य तेल एवं 1.5 कि0ग्रा0 फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस, सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 आदि मुफ्त करने की योजना के सम्बन्ध में

57-श्री जगदीश नरायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस, सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 आदि जांच सुविधाओं को मुफ्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जनपदों में सरकार के द्वारा डायलिसिस एवं सी0टी0 स्कैन की जांच की सुविधा विभागीय तौर पर एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 की जांच सुविधा को मुफ्त करने का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-304 पर।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र के गोपालपुर देवरांचल में सुपर स्पेशलिस्ट हास्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में

58-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर देवरांचल से जिला मुख्यालय की दूरी अधिक होने से क्षेत्रवासियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तथा समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हास्पिटल की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर देवरांचल से 10 कि0मी0 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज, हरैया व परशुरामपुर स्थित है। इन केन्द्रों के माध्यम से देवरांचल के मरीजों को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जी नहीं। उपर्युक्तानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में रिक्त पदों को भरने तथा कार्य संचालन हेतु अस्थायी नियुक्ति के सन्दर्भ में

59-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्वीकृत स्थायी कार्यालय कर्मियों के सापेक्ष वर्तमान में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि स्थायी कर्मियों के अभाव में पाठ्यक्रम के साथ सम्बद्धता और परीक्षा आदि विश्वविद्यालयीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने अथवा कार्य-संचालन हेतु उक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से शैक्षणिक संवर्ग एवं प्रशासनिक संवर्ग सहित कुल 42 नियमित पद तथा आउटसोर्सिंग पर गैर शैक्षणिक संवर्ग के 23 पद सृजित हैं। इस प्रकार कुल 65 पद सृजित हैं।

उपर्युक्तानुसार सृजित नियमित एवं आउटसोर्सिंग पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 24 पदों पर कार्मिक नियुक्त हैं। उपर्युक्तानुसार प्रतिनियुक्ति/

संविदा/ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों से विश्वविद्यालय का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहा है।

सृजित नियमित पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही हेतु सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को दिनांक 28-09-2021 द्वारा अधियाचन भेजा गया है तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर तैनाती हेतु दिनांक 04-05-2022 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज के भवन का पूर्ण निर्माण कराने के लिए धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में

60-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का भवन निर्माण कितना शेष है ? क्या सरकार शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए धनराशि आवंटित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मेडिकल कालेज जनपद जौनपुर का निर्माण कार्य 55 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं शेष 45 प्रतिशत निर्माणाधीन है।

जी हाँ।

मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। शासन में भी इस हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध है। वित्त विभाग के शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में नव निर्मित मेडिकल कालेज में ओ0पी0डी0 चालू कराने के सम्बन्ध में

61-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नवनिर्मित मेडिकल कालेज में ओ0पी0डी0 आरम्भ न होने से स्थानीय मरीजों को दूरदराज के अस्पतालों में जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में ओ0पी0डी0 आरम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद जौनपुर में जनसामान्य हेतु जिला अस्पताल में स्थानीय रोगियों के उपचार की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अतएव, गम्भीर रोगियों के अतिरिक्त अन्य के उपचार हेतु सामान्यतः अन्यत्र प्रस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। सम्प्रति उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में ओ0पी0डी0 के संचालन हेतु कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मेरठ के सरधना में स्थित माता मरियम चर्च का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में

62-श्री अतुल प्रधान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के सरधना में स्थित पुरातन धरोहर माता मरियम चर्च का जीर्णोद्धार करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी धार्मिक भवन/चर्च का जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है। जनपद मेरठ के सरधना में स्थित पुरातन धरोहर माता मरियम चर्च भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए0एस0आई0) द्वारा संरक्षित है।

जनपद मेरठ के जिला अस्पताल तथा नगर पंचायत फलावदा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं कर्मचारियों के तैनाती के सम्बन्ध में

63-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के जिला अस्पताल (प्यारेलाल) में कितने सर्जन तैनात हैं तथा नगर पंचायत फलावदा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत चिकित्सक एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद मेरठ में सरकारी पैनल या सरकारी सहायतार्थ अस्पतालों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ में 03 जनरल सर्जन, 02 आर्थोपैडिक सर्जन, 03 नेत्र सर्जन एवं 02 ई0एन0टी0 सर्जन तैनात हैं। नगर पंचायत फलावदा में स्थित सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र में एलोपैथिक चिकित्सक-05, दन्त शल्यक-01, स्टाफ नर्स-03, एलटी-01, एक्स-रे टेक्नीशियन-01, डेन्टल हाइजिनिस्ट-01, डार्करूम सहायक-01, फार्मासिस्ट-02, वरिष्ठ सहायक-01 पद स्वीकृत हैं। स्थानीय व्यवस्था के आधार पर 01 चिकित्साधिकारी, 01 दन्त शल्यक, 01 आयुष चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट, 02 महिला स्वास्थ्यकर्ता, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त कर उक्त चिकित्सालय को क्रियाशील कर दिया गया है।

जनद मेरठ में (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलावदा को छोड़कर) कुल 15 सरकारी अस्पताल हैं। जनपद मेरठ में कोई भी प्राइवेट हास्पिटल सरकारी सहायतार्थ अस्पताल में नहीं आता है, अपितु आयुष्मान पैनल में 15 सरकारी अस्पताल एवं 52 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा देने के सम्बन्ध में

64-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को एम्स के रूप में विकसित करने की कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक संचालित है, जहाँ पर मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज, चक्रपानपुर में एम0आर0आई0 जांच की सुविधा बहाल करने के सम्बन्ध में

65-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में एम0आर0आई0 जांच की सुविधा नहीं है तथा वर्तमान में सी0टी0 स्कैन मशीन खराब होने से जांच के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जांच मशीनों को ठीक कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में एम0आर0आई0 जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मिशन निदेशक के पत्र दिनांक 23-04-2022 द्वारा ई0सी0आर0पी0-II के अन्तर्गत

एम0आर0आई0 मशीन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में सी0टी0 स्कैन मशीन पूर्ण रूप से क्रियाशील है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज, चक्रपानपुर में गम्भीर रोग जैसे किडनी, कैंसर और न्यूरो जैसी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में

66-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज, चक्रपानपुर में गम्भीर रोग जैसे किडनी, कैंसर और न्यूरो बीमारियों का इलाज की सुविधा न उपलब्ध होने से रोगियों को दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में उक्त इलाज हेतु चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

नवस्थापित मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी नगर के ग्वालियर रोड स्थित पहूज बांध को पर्यटन की दृष्टि से पहूज रिवर फ्रंट विकसित कर छोटे क्रूज के संचालन विषयक

67-श्री रवि शर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी नगर के ग्वालियर रोड स्थित पहूज बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पहूज रिवर फ्रंट विकसित कर छोटे क्रूज के संचालन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

रिवर फ्रंट विकसित करने का कार्य एक तकनीकी कार्य है। जल स्रोत/नदी आदि का निकटवर्ती क्षेत्र सिंचाई विभाग के अधीन होता है एवं उसे विकसित करने हेतु सिंचाई विभाग ही अधिकृत संस्था है।

पर्यटन विभाग द्वारा रिवर कूज का संचालन निजी निवेशकों के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड पर कराया जाता है। पहूज बांध पर रिवर क्रूज का संचालन का कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग को अभी तक निजी निवेशक से प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल विकास परियोजना फिरोजाबाद शहर प्रथम/अरांव के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिका को मानदेय एवं अति मानदेय प्राप्त न होने के सम्बन्ध में

68-श्री मनीष असीजा-

क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में बाल विकास परियोजना शहर प्रथम/अरांव के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिका को मानदेय प्राप्त न होने के सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अपर निदेशक (वित्त) बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ को प्रेषित संख्या 3169/जि0का0अ0/मानदेय/2021-22 दिनांक 26/03/2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद के उक्त पत्र दिनांकित 26-03-2022 में उल्लिखित आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की परीक्षणोपरान्त लम्बित अवधि के मानदेय एरियर भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुगराबादशाहपुर व सुजानगंज पर वर्ष 2015 से मार्च, 2022 तक जननी सुरक्षा योजना में हुए फर्जीवाड़ा की जांच विषयक

69-श्री पंकज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुगराबादशाहपुर व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजानगंज पर वर्ष 2015 से मार्च, 2022 तक कितने लाभार्थियों को जननी सुरक्षा का लाभ मिला है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2022 तक जनपद जौनपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुगराबादशाहपुर में कुल 22559 लाभार्थियों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजानगंज में कुल 14517 लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सुल्तानपुर के बिन्देश्वरीगंज, बहुरावां के क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने एवं चिकित्सीय सुविधाएं चालू कराने के विषयक

70-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के बिन्देश्वरीगंज, बहुरावां के क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने एवं चिकित्सीय सुविधाएं चालू कराये जाने विषय प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 सं0-857882 दिनांक 30 मार्च, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

बहुरावां के अधूरे भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को महानिदेशालय के पत्रांक 35/17फ/नि0नि0अ0/2022-23, दिनांक 12-04-2022 द्वारा इस कार्य को विलम्ब से किये जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण एवं संशोधित आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित पिठला के पास रायबरेली-फैजाबाद रोड के पश्चिम 100 शैय्या के अस्पताल में डाक्टरों की संख्या व दवा की आपूर्ति विषयक

71-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित ग्राम पिठला के पास रायबरेली-फैजाबाद रोड के पश्चिम 100 शैय्या युक्त अस्पताल में कितने डॉक्टर वर्तमान में तैनात हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी दवा की आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

100 शैय्या युक्त चिकित्सालय कुमारगंज, अयोध्या में 16 डॉक्टर तैनात हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपूर्ति की गयी दवाओं की सूची संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-305-309 पर।

जनपद अयोध्या स्थित विकास खण्ड अमीनगंज के ग्राम देवगांव रानिकपुर के पास पचास शैय्या के अस्पताल को चालू कराये जाने के विषयक

72-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में विकास खण्ड अमीनगंज के ग्राम देवगांव रानीपुर के पास 50 शैय्या युक्त अस्पताल का भवन बनकर तैयार है ? किन्तु संचालित नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डॉक्टर एवं स्टाफ की तैनाती कराकर संचालित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। 50 शैय्या युक्त अस्पताल के भवन निर्माण की भौतिक प्रगति 92 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रश्नगत भवन विभाग को हस्तान्तरित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भवन पूर्ण नहीं है।

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा राजकीय मेडिकल कालेज में कुल स्थापित वेन्टीलेटरों की संख्या की जानकारी

73-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में वर्ष 2017 से पूर्व कितनी वेन्टीलेटर स्थापित थे, तथा वर्ष 2017 के बाद उपरोक्त में कितने वेन्टीलेटरों को मरीजों के इलाज हेतु स्थापित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में वर्ष 2017 से पूर्व 858 वेन्टीलेटर स्थापित थे। वर्ष 2017 के बाद 2837 वेन्टीलेटरों को मरीजों के इलाज हेतु स्थापित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 3695 वेन्टीलेटर स्थापित हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने की कार्य योजना बनाने तथा 2018 से 2021 तक जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में कुपोषित बच्चे चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में

74-राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में वर्ष 2018 से 2021 तक कितने कुपोषित बच्चे चिन्हित किये गये हैं तथा उनके पोषण हेतु क्या कार्रवाई हुई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हाँ।

विवरण संलग्न† है।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2018 में 6512, 2019 में 5968, 2020 में 5698 एवं 2021 में 4691 बच्चे तथा जनपद प्रयागराज में वर्ष 2018 में 8359, 2019 में 7163, 2020 में 6857 एवं 2021 में 6194 बच्चे कुपोषित चिन्हित किये गये हैं।

कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषण सम्बन्धी मानकों के अनुसार बच्चों में कैलोरी व प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार के रूप में प्रतिमाह फोर्टिफाइड गेहूँ, दलिया, चना, दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल व फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोषण पुनर्वास केन्द्र, वी0एच0एस0एन0डी0 पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु उन्हें विभागीय योजनाओं से आच्छादित करते हुए निरन्तर पोषण हस्तक्षेपों के माध्यम से कुपोषण उन्मूलन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में मेडिकल कालेज स्थापित कराने हेतु विषयक

75-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में मेडिकल कालेज स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-310 पर।

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना है, जिसमें जनपद शामली भी सम्मिलित है।

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-28/2021/1/198702/2021/71-4099/1045/2021, दिनांक 17-09-2021 द्वारा ड्राफ्ट पॉलसी निर्गत की जा चुकी है। तदनुसार कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण कराते हुए पात्र आवेदकों को यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी कराने के सम्बन्ध में

76-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने पात्र लाभार्थियों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड आनलाइन आवेदन के पश्चात् वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त आनलाइन आवेदनों का निस्तारण कराते हुए पात्र आवेदकों को यू0डी0आई0डी0 कार्ड जारी कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फिरोजाबाद में यू0डी0आई0डी0 कार्ड लाभार्थियों की कुल संख्या-27613 तथा लम्बित 2178 हैं।

जी हाँ।

01 माह में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के क्षय रोगियों के हितार्थ निक्षय पोषण योजना (डी0बी0टी0) हेतु बजट आवंटन कराने के सम्बन्ध में

77-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के क्षय रोगियों के निक्षय पोषण योजना (डी0बी0टी0) के भुगतान हेतु टी0बी0 पेशेंट न्यूट्रीशन सपोर्ट डी0बी0टी0 हेड सहित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के समस्त मदों में पी0एफ0एम0एस0 एवं बैंक खाते की लिमिट/बजट आवंटन करने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद फिरोजाबाद का मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एन0एच0एम0/एन0टी0ई0पी0/बजट/डी0बी0टी0/2022-23/64, दिनांक 04-04-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु दिनांक 13 मई, 2022 को रुपये 40,04,53,360/- (रुपये चालीस करोड़ चार लाख तिरपन हजार तीन सौ साठ मात्र) आवंटित किया गया है, जिसमें से जनपद फिरोजाबाद को रुपये 53,70,000/- (रुपया तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने के सम्बन्ध में

78-श्री अजय कुमार-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000.00 रुपये प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी नहीं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000.00 रुपये किये जाने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में अवैध अस्पतालों को चिन्हित कर डॉक्टरों और हास्पिटलों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के सन्दर्भ में

79-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में अवैध अस्पताल एवं लैब संचालित हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध अस्पतालों एवं लैबों को चिन्हित कर डॉक्टरों और हास्पिटल पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में कुल 35 चिकित्सालय/लैब अपंजीकृत पाये गये हैं।

अपंजीकृत 34 चिकित्सालयों को द क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट-2010 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए चिकित्सालयों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। 01 चिकित्सालय को कार्यवाही कर सील कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 3 वर्ष में गौशालाओं का निर्माण तथा गायों के संरक्षण में धन आवंटित करने के सन्दर्भ में

80-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र इटवा सहित पूरे जनपद में विगत 3 वर्ष में कितने गौशालाओं का निर्माण अन्ना पशुओं (गायों) के लिए किया गया है एवं उक्त गौशालाओं में वर्तमान में कितनी गाय हैं तथा उक्त अवधि में गायों के संरक्षण हेतु प्रति पशु हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 3 वर्षों में 77 अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल एवं 3 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें 8614 गौवंश को संरक्षित कर उनके भरण-पोषण हेतु 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से धनराशि दी जा रही है। दिनांक 31-03-2022 तक निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण हेतु रुपया 1358.00 लाख की धनराशि हस्तान्तरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की सभी सी0एच0सी0 तथा सी0एम0ओ0, छय रोग, मलेरिया तथा डी0एल0ओ आफिस में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक पेन्ट तथा मरम्मत में खर्च धनराशि का विवरण देने के सन्दर्भ में

81-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की सभी सी0एच0सी0 तथा सी0एम0ओ0, छय रोग, मलेरिया तथा डी0एल0ओ आफिस में 01-04-2020 से 31-03-2022 पुताई, पेन्ट तथा बिल्डिंग मरम्मत तथा नई बिल्डिंग बनवाने में उपरोक्त वर्षों में कुल कितने धनराशि शासन से सी0एम0ओ0 आफिस को प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्ष में किस-किस सी0एच0सी0 पर किस किस मदों में कहां-कहां व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां। कुल धनराशि रुपये 3,63,39,466/- प्राप्त हुई है।

जी हां। विवरण संलग्न† है।

---

† देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ-311 पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र सं0 एच0एम0-126/चि0 3-2021 जिला अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जांच विषयक

82-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-07-21 के क्रम में विशेष सचिव चिकित्सा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ में पत्र संख्या-एच एम-126/सिच0-3-2021, दिनांक 24-08-2021 द्वारा जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर को दिनांक 08-09-2021 को जांच हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो जांच प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-एच0एम0-126/चि0-3-2021, दिनांक 24-08-2021 द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 07-07-2021 के सम्बन्ध में जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा प्रकरण की जांच मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर से कराई गई। जांच में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनापुर एवं उसके अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुधवाना व बरुआ खुला पाया गया। उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सीय सेवायें प्रदान की जा रही थीं तथा साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थायें सन्तोषजनक पाई गई। टीकाकरण का कार्य सुचारु रूप से संचालित था। उक्त चिकित्सालयों के निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनापुर, शाहजहांपुर के आदेश संख्या-चि0अधी0/चेतावनी/2021-22, दिनांक 17-09-2021 द्वारा कठोर चेतावनी निर्गत की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

आशा, शहरी आशाओं एवं आशा संगीनियों तथा संविदा पर कार्यरत एन0एन0एम0 के राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को आवंटित एवं वितरित कराने के सम्बन्ध में

83-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-2/2022/44/5-10-2020-एफ-25/17 दिनांक 07-01-2022 के क्रम में आशा, शहरी आशाओं एवं आशा संगीनियों तथा संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 के राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को आवंटित एवं वितरित कराने का कार्य करा दिया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

आशा, अरबन आशा एवं आशा संगिनी को कोविड नियंत्रण हेतु कोविड टीकाकरण एवं अन्य कोविड सम्बन्धी स्वास्थ्य गतिविधियों में दिये गये योगदान को देखते हुए 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक (24 माह हेतु) रु0 500/- प्रतिमाह की दर से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य बजट से किये जाने हेतु रु0 20456.00 लाख की धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा चुकी है। इसके साथ ही उक्त विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान बी0सी0पी0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04-05-2022 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित कर दिये गये हैं।

इसी प्रकार संविदा ए0एन0एम0 को राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1600.80 लाख मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18-05-2022 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को आवंटित/अवमुक्त कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजबाद में शासनादेश संख्या-2/2022/44/5-10-2020-एफ-25/17, दिनांक 07-01-2022 के क्रम में आशा, शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों तथा संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 के राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में

84-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में शासनादेश संख्या-2/2022/44/5-10-2020-एफ-25/17, दिनांक 07-01-2022 के क्रम में आशा, शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों तथा संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 के राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा वित्त नियंत्रक परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ को प्रेषित रुपये दो करोड़ तैंतीस लाख छियासठ हजार का बजट मांग पत्र संख्या बजट मांग/2021-22/12978, दिनांक 26-03-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

आशा, अरबन आशा एवं आशा संगिनी को कोविड नियंत्रण हेतु कोविड टीकाकरण एवं अन्य कोविड सम्बन्धी स्वास्थ्य गतिविधियों में दिये गये योगदान को देखते हुए 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक (24 माह हेतु) रु0 500/- प्रतिमाह की दर से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य बजट से किये जाने हेतु रु0 221.40 लाख की धनराशि

जनपद फिरोजाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा चुकी है। इसके साथ ही उक्त विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान बी0सी0पी0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04-05-2022 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित कर दिये गये हैं।

इसी प्रकार जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 को राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु आवश्यक धनराशि रु0 17.50 लाख मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18-05-2022 के द्वारा आवंटित/अवमुक्त कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

तलाकशुदा महिलाओं को चिन्हित कर कल्याणकारी योजनाओं (जैसे विधवा पेंशन आदि) को बनाने के सम्बन्ध में

85-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी संख्या में तलाकशुदा महिलाओं को जीवन यापन हेतु विधवा पेंशन की भांति जन-कल्याणकारी योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

ऐसे नीतिगत निर्णय आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता एवं निहित वित्तीय उपाशय के आधार पर लिये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिना संस्था के मातृ चिकित्सालय/अस्पताल के उ0प्र0 में विगत वर्ष 2021-2022 में जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेजों की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में

86-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग के नवीन कालेज संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं मान्यता सम्बद्धता हेतु संस्था का भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानक के अनुसार संस्था का मातृ हास्पिटल अनिवार्य है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि बिना संस्था के मातृ चिकित्सालय/अस्पताल के प्रदेश में विगत वर्ष 2021-2022 में जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग के कतिपय कालेजों की मान्यता प्रदान कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत फरह और बल्देव सी0एच0सी0 तथा राया पी0एच0सी0 में स्वास्थ्य उपकरणों को स्थापित करने के सन्दर्भ में

87-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत सी0एच0सी0, फरह, सी0एच0सी0, बल्देव एवं पी0एच0सी0, राया आदि स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिजिटल एक्स-रे मशीन, आटोमेटिक सेनीटाइज मशीन एवं अन्य स्वास्थ्य वर्धक मेडिकल ट्राली एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जारी विधायक निधि के व्यय में सरकारी धन का दुरुपयोग कर लोकल स्वास्थ्य उपकरण, प्लेन एक्स-रे मशीन स्थापित कर दी गयी है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 सदस्य, विधान सभा, बल्देव की विधायक निधि से खरीदे गये डिजिटल एक्स-रे मशीन व अन्य सामान मानक के अनुरूप नहीं होने की जांच आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र दिनांक 20-05-2022 के द्वारा शासन को प्रेषित की गयी है।

उक्त का परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गौमूत्र से बनने वाली औषधि व अन्य सामग्री बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाने विषयक

88-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौमूत्र से निर्मित की जाने वाली औषधि व अन्य सामग्री बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी नहीं।

आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माण अनुज्ञा (ड्रग्स लाइसेंस) ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 एवं तत्सम्बन्धी ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स रूल्स-1945 (केन्द्रीय अधिनियम) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। गौमय (गोबर, गौमूत्र, दुग्ध, दही आदि) घटक युक्त औषधियों की निर्माण एवं विक्रय की अनुज्ञा आयुर्वेद निदेशालय से जारी की जाती है।

गौमूत्र से निर्मित की जाने वाली औषधियों एवं अन्य सामग्री बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की कोइ कार्य योजना आयुष विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-02 लेते हैं।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

वह भी लेंगे, अब निधन के निर्देश हैं, जब कोई जानकारी न हो, तो आस-पास पूछ लिया जाता है, पूछने में कोई नुकशान नहीं है।

[12:21] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जयपाल सिंह का 6 मई, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री जयपाल सिंह का जन्म 19 नवम्बर, 1939 को ग्राम नालपुर, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तथा टेक्निकल डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जयपाल सिंह वर्ष 1993 तथा 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र खरखौंदा, जिला मेरठ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जयपाल सिंह सुश्री मायावती मंत्रि-मण्डल, श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रि-मण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों से जुड़े रहे तथा गूजर समाज सुधार सभा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय गूजर विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वे किसान आन्दोलन में मेरठ कारागार में बन्दी भी रहे थे। कृषि तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जयपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह का 16 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री बृजेन्द्र सिंह का जन्म 11 नवम्बर, 1937 को विसावर, जिला मथुरा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बृजेन्द्र सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र सादाबाद (मथुरा) वर्तमान जिला हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बृजेन्द्र सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत तिहाड़ जेल, दिल्ली

तथा जिला कारागार, मथुरा में बन्दी रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक, मथुरा के डायरेक्टर एवं जिला कारागार, मथुरा के विजिटर रहे थे। वे गौ-हत्या निरोध समिति के प्रान्तीय प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य शिक्षक और तहसील कार्यवाहक, भारतीय जनसंघ के जिला महामंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रहे थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बृजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम लखन यादव का 19 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम लखन यादव का जन्म 31 दिसम्बर, 1943 को ग्राम बैजलपुर, अमरगढ़, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम लखन यादव वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम लखन यादव एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के अन्तर्गत वे जिला कारागार प्रतापगढ़ में बन्दी भी रहे थे। वे जनता पार्टी तथा लोकदल (ब) के जिला जनरल सेक्रेटरी रहे और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से अध्यक्ष तथा संयोजक के रूप में सम्बद्ध रहे थे। कृषि एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम लखन यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री समीउल्ला खां का 23 मई, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री समीउल्ला खां का जन्म 01 अक्टूबर, 1955 को कपौवा शेरपुर, जिला गोण्डा में हुआ था। उन्होंने हाई-स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री समीउल्ला खां वर्ष 1989 में निर्दलीय तथा 1991 में जनता दल से निर्वाचन क्षेत्र उतरौला (गोण्डा) वर्तमान जिला बलरामपुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। समीउल्ला खां विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार गोण्डा में बन्दी रहे थे। वे क्षेत्र समिति, श्रीदत्तगंज तथा बाढ़ राहत कार्य समिति के अध्यक्ष रहे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। समीउल्ला खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

विधान सभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोक संतृप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

ॐ शान्ति।

(अनेकों सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

[12:26] पिजन हॉल के माध्यम से प्राप्त डायरेक्ट्री में मिली अशुद्धियों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री अवधेश प्रसाद जी को बोल लेने दीजिये, वह एक वरिष्ठ नेता हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, पिजन हॉल में एक डायरेक्ट्री मिली जिसको मैंने देखा, उसमें केवल 65 या 66 जिलों का नाम है और 65 या 66 जिलों के माननीय विधायकों के नाम हैं, पते हैं और मोबाइल नं0 हैं। मुझे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, श्रीमन् कि और जिलों का नाम क्यों नहीं आया और मेरे जनपद अयोध्या का नाम क्यों नहीं आया ? जिसका सारी दुनिया में नाम है, मर्यादा है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना विभाग की डायरी नहीं है। मेरा निवेदन सुन लीजिये आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ। जो आपको पिजन हॉल में डायरी मिली है वह सूचना विभाग की नहीं है। किसी एक संस्था ने एक डायरी छपवाई और उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए कहा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ थीं, इसलिए दे दी गयीं। आपने जो सुझाव दिया उनको हम कनवे कर देंगे, लेकिन उसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं की जा सकती। सूचना विभाग जो डायरी लेकर आयेगा उसमें सारी की सारी बातें होंगी, जो आपने कही है। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि उसमें कोई कमी न रहे।

[12:29] राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा चरित्र हनन और राजनीतिक छवि धूमिल करने सम्बन्धी श्री मो0 ताहिर खान की व्यक्तिगत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों ने एक अवैध और सक्रिय गिरोह बना रखा है।

श्री अध्यक्ष-

आप किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री मो0 ताहिर खान-

अध्यक्ष जी, यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष-

सीरियस मामला है तो किसमें बोल रहे हैं। सीरियस मामले को भी बोलने के लिए नियम है।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, हमारे परिवार की जान को खतरा है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों ने एक अवैध और सक्रिय गिरोह बना रखा है और वह भू-माफिया हैं तथा बड़े अपराधी भी हैं। मेरे चरित्र-हनन के लिए और मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए एक अनजान महिला द्वारा मेरे परिवार और मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने कल पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो इश्यू है, आप लिख कर दे दीजिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मैं दे दूंगा। उसका उनके पास जवाब नहीं होगा, बिना किसी सूचना के माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या किसी के पास जवाब नहीं होगा।

[12:29] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत आज 07 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। एक सूचना, माननीय सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी की सूचना सुनी जायेगी। बाकी सब अग्राह्य हैं, अपोषणीय हैं।

(कई माननीय द्वारा आग्रह किया गया कि उनकी भी सूचना सुन ली जाये)

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-300 की बात हो रही है, उसमें आप लोगों की सूचना नहीं है।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मेरी और वर्मा जी की सूचना एक ही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर ओम प्रकाश जी ही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। यह नियम-300 में नहीं आती है। सिर्फ एक सूचना आती है जो ग्राह्यता के लिए सुनी जायेगी श्री लाल जी वर्मा एवं श्री ओम प्रकाश जी की। जनपद आजमगढ़ में जल निकासी नहीं है। क्या दुर्गा जी आप तो 09 बार के विधायक हैं और नियम-300 में ऐसी सूचना देते हैं। अरे जल निकासी नियम-300 में कैसे आ सकती है ? आपसे क्या पूछेंगे लोग मैं तो आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ।

(श्री मनोज कुमार पारस के द्वारा आग्रह करने पर कि उनकी भी सूचना सुन ली जाये)

श्री अध्यक्ष-

पारस जी आप बैठिये।

[12:30] उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-8 के अनुसार माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। श्रीमन् उक्त नियम के अनुसार माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया। उक्त नियमावली के नियम-9 में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। माननीय अध्यक्ष जी, उपवेशन जब चालू है और उसमें यह व्यवस्था भी है और यह आपके संज्ञान में भी है। जब आप यहाँ बैठते थे तो इसके लिए आपने भी कई बार अपनी बात उठाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि उपवेशन चल रहा है और ऐसे समय में उपाध्यक्ष का पद खाली है तो मैं आपसे जरूर इसके लिए निवेदन करूंगा कि आप स्वयं नियमावली के ज्ञाता हैं और अच्छी तरह से विधान सभा चला रहे हैं। इसलिए मैं जरूर यह व्यवस्था चाहूँगा और बगल में कुर्सी खाली भी है, उससे आपको भी कहीं न कहीं सहूलियत मिलेगी। मैं यह जरूर चाहूँगा कि आप मन के भी बड़े हैं और आपका पद भी बड़ा है। इसलिए यह व्यवस्था जरूर करेंगे कि उपाध्यक्ष हों। उपाध्यक्ष भी सदन में रहेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री जी, इसकी शोभा और बढ़ेगी और आपने कहने का भी काम किया है। जब आप इधर बैठते थे तो आप कई बार चर्चा करते थे। कोई भी बने, वह व्यवस्था के तहत होगा। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं जरूर चाहूँगा कि इस पर गम्भीरता से और ऐसे समय में जब हाउस चल रहा हो, ऐसा करेंगे तो इस व्यवस्था में चार चांद लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चार चांद लगाइये। (हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह पिछला दृष्टान्त न दें, आप और अच्छे काम करने के लिए आये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह तो बता दें कि यह कौन से दृष्टान्त की बात कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय लाल जी वर्मा जी ने कहा कि पिछला दृष्टान्त न दें तो वह यह बता दें कि वह कौन सा दृष्टान्त था, जो न दें ? मान्यवर, यह इनसे कम से कम पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बता दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं बता देता हूँ, जैसे पिछली बार 17वीं विधान सभा में लास्ट का एक महीना रह गया और जब अन्तिम सत्र आया तो उस अन्तिम सत्र में ही चुनाव किया गया। 4 साल 11 महीने में कोई चुनाव नहीं हुआ तो उसका उदाहरण न दें, इस बार शुरू में ही इसी उपवेशन में ही चुनाव करा लें, यह मेरा आग्रह है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब यह सत्ता में थे, उसका भी दृष्टान्त बता दें। 2007 से 2012 तक का बता दें। मान्यवर, हम तो यह समझे कि यह 2007 से 2012 तक का बताने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह वह सब भूल चुके हैं, अब दूसरी जगह बैठे हैं। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, संगत का असर पड़ता है। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक सूचना नियम-300 में आई है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी पूरी तरीके से सदन चलाने में सक्षम हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसी राय के हैं। सदन ठीक चल भी रहा है। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो अधिष्ठाता मण्डल की व्यवस्था बनाई है, वह भी व्यवस्था बहुत माकूल है और बहुत उपयोगी है। हमने जितने अधिष्ठाता देखे कि नये-नये लोग आये और पहली बार अधिष्ठाता बने, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाउस चलाया और देर तक चलाया।

श्री अध्यक्ष-

उसमें ओम प्रकाश जी भी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर, यह भी उसमें हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे इधर के हों, चाहे इन्द्रजीत सरोज जी हों, चाहे श्री ओम प्रकाश जी हों, चाहे वर्मा जी हों, चाहे अरविन्द गिरि जी हों, चाहे मनीष असीजा जी हों, चाहे पंकज जी हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोगों को आपने अधिष्ठाता बनाया है वह सभी लोग सदन को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और हम समझते हैं आप खुद बहुत सक्षम हैं

अभी आप 16, 17 घंटे काम करने में सक्षम हैं कोई दिक्कत ही नहीं है और यहाँ तक कि पुराने दृष्टान्त जो कहा जाता है, वह पहले ही याद दिला दिया बात पूरी हुई नहीं उन्होंने वह दृष्टान्त याद दिला दिया। मान्यवर हमको याद है माननीय वर्मा जी यहाँ बैठते थे और श्री राजभर जी आज हमारे बीच में हैं नहीं वह यहाँ बैठते थे और उनके समय वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक का कोई दृष्टान्त नहीं और माननीय ओम प्रकाश जी को याद हो, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक श्री ओम प्रकाश जी भी इस मंत्रि-मण्डल को सुशोभित कर रहे थे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, थोड़ा-सा और पीछे चले जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वैसे तो आपके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन हम समझते हैं जब इसकी आवश्यकता महसूस होगी तब इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैनें माननीय ओम प्रकाश जी को सुना, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। चूंकि यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये अग्राह्य करता हूं।

[12:37] मा0 सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज माननीय दो सदस्यों का जन्मदिन है। श्री बेदी हैं क्या वह देखिये श्री बेदी कितने अच्छे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री बेदी निर्वाचन क्षेत्र जखनिया, गाजीपुर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं, आपके पिता का नाम श्री मन्नू है, आपका जन्म 30 मई, 1960 को जौनपुर में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है, आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से शुभकामनायें देता हूँ।

श्री दानिश आजाद अंसारी हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् के अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ तथा अन्य विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी का जन्म 30 मई, 1988 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री समी उल्लाह अंसारी है।

आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी0 कॉम तथा मास्टर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण की है। आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से मॉस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की है। आप भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री रहे तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कई दायित्वों का निर्वहन किया, पूर्व में फखरुद्दीन अली मेमोरियल समिति के सदस्य भी रहे। आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

[12:38] नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएँ लेते हैं। आज नियम-301 में कुल 62 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गई हैं।

सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों की नियम-301 की सूचनाएँ स्वीकृत करने का आग्रह

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम आज जितने सदस्य यहाँ बैठे हैं, उनकी सूचनाएँ ले लीजिये। जो कल सूचनाएँ ली जायेंगी उसमें यह सदस्य नहीं रहेंगे। यह व्यवस्था हो जाये तो बहुत अच्छा होगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इससे यह होगा कि हम सारे सदस्यों की सूचनाएँ इसमें आ जायेंगी और कोई यह नहीं कहेगा कि हमारा छूट गया। मेरा आपसे आग्रह है कि आज जितने माननीय सदस्य उपस्थित हों उनकी सूचनाएँ ले लें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

जैसे सुझाव आये हैं, उसके अनुसार सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएँ ले ली जायेंगी, लेकिन जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएँ आज ली जायेंगी उनसे निवेदन है कि वह कल नियम-301 में सूचनाएँ न दें, ताकि कल अन्य सदस्यों की सूचनाएँ ली जा सकें।

अब मैं नाम पुकारता हूँ, जो मा0 सदस्य सदन में उपस्थित होंगे केवल उनकी सूचनाएँ ली जायेंगी। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह थोड़ा सा ऊंचा बोल दें, ताकि हमें सुनाई पड़ जाय।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका विषय पढ़ देता हूँ, क्यों आप पूरी सूचना को पढ़ेंगे।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़ दीजिये।

(सदस्य श्री महबूब अली द्वारा नियम-301 की सूचना को सदन में पढ़ा गया)

बिना इन्श्योरेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट तथा बिना फिटनेस के गतिमान सरकारी वाहनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महबूब अली-

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 60,545 पंजीकृत सरकारी वाहन चलायमान हैं, जिसमें से लगभग 50-52 हजार सरकारी वाहनों का न तो कोई इन्श्योरेंस है और न ही प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध है। ऐसे डग्गामार बिना फिटनेस के सरकारी वाहनों के चलने से प्रायः सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसे सरकारी वाहन जो प्रदूषणयुक्त धुआं फेंक रहे हैं और जिनका प्रदूषण फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे सरकारी वाहन पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण से तरह-तरह की असाध्य बीमारियां फैल रही हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश के आम-जनमानस में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से बिना इन्श्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट तथा बिना फिटनेस के गतिमान सरकारी वाहनों के रख-रखाव के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-12-2021 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 53 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री शाहिद मंजूर की जनपद लखनऊ में सेक्टर-7, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड से लगे हुए चिरैयाबाग गांव के बगल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जमानिया में सम्पर्क मार्ग के कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम मुगीशपुर में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी

नालों की सफाई करा कर उसको ढकवाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अशरफाबाद धौरहरा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज में सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग एवं कतिपय अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के बाहर की ओर एक रिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण तथा पनियहवा रेलवे ब्रिज के पास बोटिंग व जलयान परियोजना के माध्यम से बिहार व नेपाल को जोड़ने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के ग्राम लुधौरा के अन्तर्गत पुल/सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती ओममणी वर्मा की जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत ग्राम सिंहपुर में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के अन्तर्गत किसानों को ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री महबूब अली की बिना इन्श्योरेंस, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट तथा बिना फिटनेस के गतिमान सरकारी वाहनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर का गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज एवं मार्टीनगंज मुख्यालय तथा मुहम्मदपुर के नन्दाव में राजकीय बालक/बालिका विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर की कानपुर नगर की चौबेपुर पुलिस द्वारा जातीय आधार पर दुकानदार पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री जियाउर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्राम चमरवा में रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री संग्राम सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत करैल क्षेत्र के ग्राम ठूठूवारी में बन्द पड़ी पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित

कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कालेज एवं स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के ब्लाक बिलरियागंज में क्षेत्र पंचायत से संबंधित कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह की जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम कंजौली से खन्दौली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की प्रदेश में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं मिड-डे मील कर्मियों के लम्बित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री अजय की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम बदरपुर से दोगवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत खेड़ा-महासोना रोड पर ईदगाह के सामने से अड़ौली रजवाहा होते हुए जमुनाठेर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री कैलाश की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के अन्तर्गत नौगढ़ बांध में सेमर साधोपुर गांव में एक लिफ्ट कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत कछौना, पतसैनी में रेलवे फाटक से ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह लोधी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में 80 से 100 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत मसकनवां बाजार में स्थित नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री किरत सिंह की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ब्लाक नानोत के पाण्डो खेड़ी ग्राम में बरसाती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत हाटा से करमहा मोड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद बस्ती के

विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत दो नई तहसीलों का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री रामकृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख में बस अड्डा एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लोक निर्माण विभाग, उन्नाव श्री ओ0पी0 सोनकर के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज सिधौली में आईटीआई भवन का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के चोला औद्योगिक क्षेत्र का विकास कराकर नवीन उद्योगों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र बल्देव नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुए वाहन संख्या यू0पी032 जी0यू0 5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी पर अधूरे रिंग बंधे के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना के अन्तर्गत ग्राम हिरनही में कस्तूरबा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज के नक्शे में संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम जटपुरा में प्राइमरी स्कूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में लो0नि0वि0 द्वारा ग्राम अलाउद्दीन से ग्राम चकमहमूद तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद झांसी के झलकारी बाई नगर में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी कालोनी, सेक्टर-डी से कूड़ा प्रबन्धन संयंत्र को दूर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा की विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत नगलीया जट से ग्राम कोटा तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री अनिल पाराशर, श्री राजीव गुम्बर, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री विकास गुप्ता, श्री पंकज गुप्ता, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश सिंह।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकारा था, मैं सिग्नेचर करने के लिए गया था, इसलिए अनुरोध है कि हमारी सूचना को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

सिग्नेचर आपके इसी टैब पर होता है, आप क्यों वहाँ गये। मैं यह व्यवस्था दे रहा हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने अपना टैब खोला है, जो उपस्थित हैं उस दिन उनकी उपस्थिति मानी जायेगी।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मेरा भी नाम पुकारा गया था मैं पानी पीने के लिए गया था, इसलिए अनुरोध है कि मेरी नियम-301 की सूचना को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी उपस्थिति भी मान्य है।

जनपद लखनऊ में सेक्टर-7, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड से लगे हुए चिरैयाबाग गांव के बगल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहिद मंजूर-

[महोदय, अवगत कराना है कि सेक्टर-7, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड से लगे हुए चिरैयाबाग गांव के बगल की सड़क जो जनता आटा चक्की से लगभग 50 मीटर आगे (रेलवे लाइन तथा खड़न्जा के बगल में स्थित कच्ची सड़क) हिन्दुस्तान ट्रेडर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स तक ग्राम-बरौली, खलीलाबाद के खसरा संख्या-154/1, 1544 मि0 में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन संबंधी प्रस्ताव को उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् स्थानीय निवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु प्रस्तावित सड़क के निर्माण की मांग जनहित में बहुत दिनों से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आवास विकास परिषद् द्वारा उक्त सड़क को केवल कागजों पर ही बनाकर शासन को बार-बार भ्रमित व गुमराह किया जा रहा है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास विकास परिषद् तथा जिले एवं उच्च स्तर पर स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार लिखित और उच्च स्तरीय प्रयास के बावजूद आज तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से सेक्टर-7, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ से लगे हुए चिरैयाबाग गांव के बगल की सड़क जो जनता आटा चक्की से लगभग 50 मीटर आगे (रेलवे लाइन तथा खड़न्जा के बगल में स्थित कच्ची सड़क) हिन्दुस्तान ट्रेडर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स तक ग्राम-बरौली, खलीलाबाद के खसरा संख्या-154/1, 1544 मि0 में 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जमानियां में सम्पर्क मार्ग के कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-379, जमानियां, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत निम्न मार्गों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, नहर की बनी पटरियों व मिट्टी व लेपन कार्य का जब तक जांच की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाये तब तक भुगतान न कराया जाये।

उक्त सड़कें निम्नवत् हैं :-

1-भक्सी दिलदारनगर भदौरा गहमर मगरखाई सम्पर्क मार्ग।

2-बरूइन दिलदारनगर उसिया गौडसरा अमौरा सम्पर्क मार्ग।

3-बरूइन से महली डिलाचवर सम्पर्क मार्ग।

4-बहुबरा कुसुमपुर सम्पर्क मार्ग।

5-बेटावर से महुआरी सम्पर्क मार्ग।

6-अरंगी खजुरी सम्पर्क मार्ग।

7-दरौली से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग।

8-बरूइन महली सम्पर्क मार्ग।

9-बरूइन से महली सम्पर्क मार्ग।

10-मतसा सैदाबाद महेवा सम्पर्क मार्ग।

11-धनाड़ी से परशुराम यादव के मशीन होते हुए कर्मनाशा नदी तक सम्पर्क मार्ग।

अतः लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग की जांच कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम मुगीशपुर में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के स्थित ग्राम मुगीशपुर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या में आज से लगभग 6 वर्ष पहले क्षेत्र के गरीब, कमजोर परिवारों से आने वाले सभी वर्ग के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हुई थी। जिसके भवन के लिए करोड़ों रुपया शासन द्वारा निर्माण में खर्च हुए थे, लेकिन इतने लम्बी अवधि बीतने के बाद भी पठन-पाठन का कार्य नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में व्यापक असंतोष पैदा हो गया है। स्थिति दिनों-दिन भयावह होती जा रही है।

इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त विद्यालय जनहित में चालू कराया जाये।]

जनपद लखनऊ की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी नालों की सफाई कराकर उसको ढकवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में 27 नाले हैं। यह सभी नाले लबालब भरे हैं और हल्की सी बरसात होने पर यह नाले उफना जाते हैं और नाले का पानी घरों में भर जाता है जिससे लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के घरों में पानी भरने के कारण उनका जीवन दूभर हो जाता है। इन सभी नालों को साफ कराकर इनको ढकवाने के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है। फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सभी नालों को साफ कराकर उसको ढकवाने का काम पूरा किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अत्यन्त गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लखनऊ मध्य के सभी खुले हुए नालों को साफ कराकर ढकवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अशरफाबाद धौरहरा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अशरफाबाद धौरहरा संदीप मौर्या के आवास से संतोष

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के खेत तक मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, विकास खण्ड-गौरीगंज, जिला-अमेठी के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्ग रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क का निर्माण कार्य जो सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे वहाँ की जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर बरसात के दिनों में निकलना दूभर हो जाता है, जिससे वहाँ के जनमानस में काफी रोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ तक सड़क के अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग को पूरा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में बारून शाहगंज इसौली मार्ग एवं कतिपय अन्य सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित सिंह चौहान-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र संख्या-274, बीकापुर में बारून शाहगंज इसौली मार्ग शाहगंज बाजार में सी0सी0 रोड बनी है, जिसकी चौड़ाई 3.30 मीटर है, जिससे आमने-सामने वाहनों के आने पर जाम की स्थिति लग जाती है। पटरी न बनाये जाने से यह समस्या होती है। रोजाना सैकड़ों लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सी0सी0 मार्ग के बगल में इण्टरलॉकिंग लगाना जरूरी है। इसी तरह क्षेत्र की अन्य सड़कें हैं जहाँ गांवों में सी0सी0 मार्ग बने हैं वहाँ भी पटरी न बनने से यही समस्या है।

1-सुरूवारी ड्वेढ़ी मार्ग पर ड्वेढ़ी बाजार।

2-पलिया गौवा, मिर्जापुर, निमौली मार्ग पर पलिया गौवा ग्राम एवं जिलेदार का पुरवा में।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-कीरत पुरवा थरेरू मार्ग पर थरेरू ग्राम के पास।

4-सीबार सम्पर्क मार्ग पर सीबार ग्राम में।

5-कलाफरपुर सम्पर्क मार्ग।

6-सिडहिर सम्पर्क मार्ग पर सिडहिर गांव में।

7-मजनावा सम्पर्क मार्ग पर मजनावा गांव में।

8-जैन मंदिर सम्पर्क मार्ग रौनाही थाने के बगल।

9-सरियावां सम्पर्क मार्ग पर जगदीशपुर में।

10-बीकापुर मलेथू कनक इनायत नगर मार्ग पर।

11-सौरी सम्पर्क मार्ग पर सौरी ग्राम में।]

जनपद बुलन्दशहर के बाहर की ओर एक रिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में वर्तमान में जनपद से दूसरे जनपद में आने-जाने के लिए मार्गों पर आये दिन भारी जाम के कारण जनपद वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण यदि बुलन्दशहर के बाहर की ओर एक रिंग रोड बनवायी जाये तो जनपद वासियों को भारी राहत मिल जायेगी, जिसके बनवाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण तथा पनियहवा रेलवे ब्रिज के पास बोटिंग व जलयान परियोजना के माध्यम से बिहार व नेपाल को जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित खड्डा विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। नारायणी की पवित्र जलधारा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं का विभाजन करती है। बिहार सीमा पर स्थित मां मदनपुर का दिव्य स्थान है तो वनाच्छादित बाल्मीकिनगर टाइगर प्रोजेक्ट बिहार सरकार द्वारा संचालित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार को पर्यटन की दृष्टि से सुसज्जित किये जाने हेतु नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण कर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही बिहार और नेपाल से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास से परिचित कराने का अवसर मिलेगा। नारायणी रिवर फ्रंट के निर्माण के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साथ ही पनियहवा रेलवे ब्रिज के पास बोटिंग व जलयान परियोजना के माध्यम से बिहार और नेपाल को जोड़ा जा सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के ग्राम लुधौरा के अन्तर्गत पुल/सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-243, खागा, जनपद फतेहपुर के ग्राम लुधौरा, अंजना, भैरव के मध्य पुल एवं पहुंच मार्ग एवं ग्राम कुल्ली-बदलमऊ एवं मुजफ्फरपुर कछरा के मध्य ससुरखदेरी नदी में रपटा के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण शासन स्तर पर लम्बित है। जनहित में उक्त निर्माण कार्यों को कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत ग्राम सिंहपुर में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ओममणी वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-234, नरैनी, जनपद बांदा के ग्राम सिंहपुर में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का अर्द्ध निर्माण को पूर्ण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत किसानों को ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या अन्तर्गत कृषि ऋण मोचन योजनान्तर्गत लगभग 4 हजार किसानों का ऋण मोचन अभी तक नहीं हो पाया है। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार पात्र किसानों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा 03-01-2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को विस्तृत सूचना के साथ अवशेष धनराशि की मांग की थी, परन्तु अभी तक ऋण मोचन योजना की धनराशि

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्धित किसानों को भुगतान शासन स्तर से नहीं किया गया है। जनपद के किसानों द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायत की जाती रही, लेकिन अभी तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया, जिसके कारण जनपद के किसानों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अयोध्या के किसानों को ऋण मोचन योजना की धनराशि तत्काल स्वीकृत कर खातों में स्थानान्तरित कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान चित्रकूट में जल अकाल जैसे गम्भीर लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि चित्रकूट जनपद में पानी का अकाल गम्भीर बना हुआ है। चित्रकूट जनपद के दर्जनों गांव में मंदाकिनी नदी के सूख जाने से पेयजल का संकट बढ़ा है तथा पशुओं का स्वास्थ्य खराब होने से परिवारों में आजीविका घटी है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट जनपद की पेयजल नदी है। इस नदी को चित्रकूट की जीवन रेखा कहा जाता है। जनश्रुति है कि पिछले सैकड़ों वर्ष में आये अकाल के बावजूद इस नदी की अविरल निर्मल धाराएं कभी नहीं सूखीं। वर्ष 2007 के बाद 2011 से पयश्वनी/ मंदाकिनी नदी बन्धुवइन बांध के बाद से सूख रही है। चित्रकूट धाम कर्वी, नगर पालिका के अधिकांश मुहल्लों में तथा कामदगिरी पर्वत में परिक्रमा पथ में पेयजल की आपूर्ति पयश्वनी नदी राजाघाट में बने इंटेकवेल से किया जाता है। इंटेकवेल के आस-पास जबरदस्त गन्दगी तथा सीवर नाला सीधे नदी में लगाया गया है। नदी किनारे बसे गांव जैसे बहादुरपुर, कपसेठी में नदी संवाद के दौरान महिलाओं ने बताया कि नदी में स्नान करने से खुजली होती है। पेट की बीमारी होती है। कर्वी विकास खण्ड के 19 गांव तथा पहाड़ी विकास खण्ड के 20 गांव जो नदी किनारे बसे हैं। नदी सूखने से गांवों के हैण्डपम्प सूखते हैं अथवा हैण्डपम्पों में खारा पानी आता है।

चित्रकूट में आस्था की सबसे पवित्र मंदाकिनी नदी रामघाट में दुर्गन्ध मारती है, क्योंकि इसकी सहायक पयश्वनी तथा सरयू दोनों सीवर और गन्दे नालों-नालियों से बजबजा रही हैं तथा रामघाट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े सीवर नाले सीधे नदी में गिर रहे हैं। आने वाले तीर्थयात्री जब चित्रकूट की पावन नदी को देखते हैं तो उनका मन दुःख से भर जाता है।

नदी मरण के कारण-

1-मंदाकिनी, पयश्वनी नदी की सीमाओं में पक्के निर्माण अनरवत् बढ़ते जाना, नदी सीमा की जानकारी न होना, नदी सीमांकन न होना।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-नदी में नगर परिषद् के करीब 20 नाले तथा घरों के सीवर सीधे नदी में लगा देना, जिसके कारण नदी के जल में आक्सीजन स्तर का कम होना।

3-नदी में न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित न होने के कारण इसका दोहन सरकारी, गैर सरकारी दोनों में होना।

4-नदी के 40 किमी0 परिधि में जंगलों का अंधाधुंध दोहन, पहाड़ों में खनन के कारण पहाड़ों से निकलने वाली जलधारा का सूखना।

5-नदी के किनारे के जंगलों का समाप्त होना तथा मंदाकिनी नदी और उसकी सहायक नालों के कैचमेंट में वाटर शेड परियोजनाएं जन भागीदारी के सहयोग से न चलाना।

6-नदी में बंधुवइन जैसे बांध की ऊंचाई अधिक होना, फाटकदार गेट न होना तथा नदी के डाउनसाइड चेक डैम आदि का होना।

7-सरकारी मान्यताओं में नदी को पेयजल नदी नहीं घोषित किया गया जिसका परिणाम है कि नदी में पेयजल की मात्रा को स्थिर रखने का काम सिंचाई विभाग नहीं करता।

8-सिंचाई विभाग के पास नदी संरक्षण की कोई मार्गदर्शिका नहीं है और वह अकेले निर्णय लेने में अक्षम है। यह विभाग नदी संरक्षण में अक्षम है।

अतः जल जैसे गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चित्रकूट की मृत मंदाकिनी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार नदी पुनर्जीवन की परिभाषा को परिभाषित कर सर्वमान्य बनाये तथा नदी के लिए ऐसा कानून बनाये कि सरकार और समाज नदी की हिंसा करना बन्द कर दे। नदी में न्यूनतम जल प्रवाह सरकार सुनिश्चित करे। इसके साथ नदी मरण के उपरोक्त कारणों पर तत्काल जांच कराकर उनको दूर कराने की शीघ्र कार्रवाई करे।]

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर का गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

जनपद-झांसी की गुरसहाय मुख्य नहर की लाइनिंग की गयी है। उक्त लाइनिंग त्रुटिपूर्ण है। उसके कारण मुख्य नहर एवं रजबहों व माइनरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे नहरें व माइनरें संकरी एवं उथली हो गयी हैं। नहर संकरी एवं उथली होने के कारण पानी ओवर-फ्लो हो जाता है और नहर फट जाती है। लाइनिंग का ढाल उल्टा कर दिये जाने के कारण पानी आगे नहीं जा पाता है। उक्त नहर की लाइनिंग एवं तल को तोड़कर पूर्व की भांति

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कच्ची कर देने से पहले की भांति पानी अधिक निकलेगा और आगे तक जा सकेगा, जिससे किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिल पायेगा और पैदावार बढ़ जायेगी।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय विषय पर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-221, उरई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला परिषद्, उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिससे वहाँ के लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित में इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला परिषद् उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण में उक्त कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत दीदारगंज एवं मार्टीनगंज मुख्यालय तथा मुहम्मदपुर के नन्दाव में राजकीय बालक/बालिका विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक फूलपुर के दीदारगंज एवं मार्टीनगंज मुख्यालय तथा मुहम्मदपुर का नन्दाव क्षेत्र शिक्षा में काफी पिछड़ा है। क्षेत्रीय जनता बराबर मांग कर रही है कि वहाँ पर राजकीय बालक/बालिका विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना की जाये। सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन के लोग तथा जनपद के अधिवक्ता, नौजवान, व्यापारी, किसान सभी लोग विद्यालय व महाविद्यालय की मांग पर एक मत होकर आये दिन कहीं न कहीं धरना-प्रदर्शन कर शासन-प्रशासन को मांग-पत्र दे रहे हैं। जनपद के सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी एकमत होकर मांग कर रहे हैं, तमाम लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। इस विषय को लेकर जनपद में काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है तथा जनता आन्दोलित है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव, आपके माध्यम से सरकार से फूलपुर के दीदारगंज एवं मार्टीनगंज मुख्यालय तथा मुहम्मदपुर के नन्दाव में राजकीय बालक/बालिका विद्यालय व महाविद्यालय स्थापित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर की चौबेपुर पुलिस द्वारा जातीय आधार पर दुकानदार पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना पुलिस द्वारा दिनांक 03-04-2022 की रात्रि गश्त के दौरान बैटरी दुकानदार विजय सैनी और उसकी दुकान पर खड़े ग्राहक संजय कमल, अमन व देवेन्द्र सिंह आदि को खड़े देख कर पूछताछ की। पूछताछ में थानाध्यक्ष ने यह कहकर कि गश्त देखकर भागे क्यों नहीं ? पुलिस का भय खत्म हो रहा है। दुकानदार और उसके साथियों को थाने ले गये। वहाँ जातियां पूछकर जाति-विशेष के देवेन्द्र सिंह को छोड़ दिया और अन्य सबका 151 आई0पी0सी0 में चालान कर दिया। मेरे द्वारा थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अधीक्षक आउटर को फोन द्वारा सूचित किया गया, परन्तु जातीय आधार पर की गयी कार्यवाही जिसमें निर्दोष लोगों का चालान कर कस्बे में भय व्याप्त करने का प्रयास किया गया है।

अतः मैं जातीय आधार पर निर्दोष दुकानदार पर कार्रवाई करने वालों को दण्डित करने व सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्राम चमरवा में रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउर्रहमान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत ग्राम चमरवा के रेलवे क्रासिंग को लेकर है। मुरादाबाद-रामपुर रेलवे लाइन रेलवे फाटक अक्सर बन्द रहता है जिससे करीब 100 गांवों की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह फाटक बन्द होने के कारण कई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाये जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गयी। इस रेलवे क्रासिंग पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत करैल क्षेत्र के ग्राम ठूठूवारी में बन्द पड़ी पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र फेफना, जनपद बलिया के अन्तर्गत करैल क्षेत्र का मशहूर गांव ठूठूवारी में लगभग 08 वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण हुआ था। इस टंकी से आस-पास के गांवों में पानी की सप्लाई होती थी, जो पिछले 05 वर्षों से बन्द पड़ा है। पेयजल की सप्लाई न होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति करवाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-289, भिनगा जिला श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिकटहवा में बन्ठेहवां बकवा पक्की रोड से बन्ठेहवां गांव तक पक्की रोड या सी0सी0 निर्माण लगभग 700 मीटर कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह ग्राम अभी तक कच्ची सड़क से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कालेज एवं स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया बिहार बार्डर पर स्थित है। यहाँ पर स्पोर्ट्स कालेज व खेल स्टेडियम न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अन्यत्र जाना पड़ता है। क्योंकि बैरिया विधान सभा क्षेत्र में रोजगार का साधन कृषि के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सीमित संसाधनों से ही संतोष करना पड़ता है। बैरिया तहसील मुख्यालय पर वहाँ

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की भौगौलिक स्थितियों को देखते हुए स्पोर्ट्स कालेज एवं स्टेडियम का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कालेज एवं स्टेडियम निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमितलाई-इटवा-प्रभुपुर मार्ग के निर्माण/विशेष मरम्मत की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उक्त सम्पर्क मार्ग जो कई गांव को जोड़ते हुए तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय को जोड़ता है। वर्तमान समय में पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। जिससे आम जनमानस को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। साथ ही साथ उक्त सम्पर्क से जहाँ-जहाँ गांव जुड़े हैं वहाँ जल की निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जनहित में उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य/विशेष मरम्मत एवं आबादी के पास नाली का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे मांग करता हूँ कि जनहित में चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमितलाई-इटवा-प्रभुपुर मार्ग की विशेष मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली निर्माण कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के ब्लाक बिलरियागंज में क्षेत्र पंचायत से संबंधित कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़, ब्लाक बिलरियागंज में निम्न सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में-

1-दिनांक 20-07-2021 को शपथ-ग्रहण समारोह दिन में 11:00 बजे सम्पन्न हुआ तथा समितियों का गठन होना अनिवार्य होता है। समिति के गठन के पश्चात् ही क्षेत्र पंचायत

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्ण रूप से क्रियाशील होती है। खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम की सचिव थीं, उनके द्वारा मा0 सदस्यों को दिये गये एजेण्डा में समितियों के गठन हेतु कहीं नहीं उल्लेख किया गया है।

2-बैठक में उपस्थित सदस्यगण भली-भांति अवगत हैं। समितियों के गठन एवं बैठक के सम्बन्ध में कोई चर्चा सदन में नहीं की गयी है। केवल शपथ-ग्रहण ही कराया गया। माननीय सदस्यों ने सुना एवं स्वयं देखा, याची को उपरोक्त की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

3-मा0 क्षेत्र पंचायत प्रमुख बिलरियागंज द्वारा यदि बगैर एजेण्डा एवं बिना चर्चा के समितियों का गठन किया गया है एवं फर्जी तरीके से कार्य योजना तैयार की गयी है तो कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति याची को उपलब्ध करायें।

4-क्षेत्र पंचायत बिलरियागंज की प्रथम बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि उपस्थित सदस्यों के समक्ष क्यों नहीं की गयी, स्पष्ट रूप से अवगत करायें।

5-क्षेत्र पंचायत बिलरियागंज में पिछले वर्ष कितने परियोजनाओं पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनमें से कितनी परियोजनाओं पर कितना-कितना भुगतान किया गया है। कितनी परियोजनाओं पर भुगतान अवशेष है। भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परियोजनावार समस्त बिल-वाउचर एवं मापी पुस्तिका की छायाप्रति याची को उपलब्ध करायें।

6-क्षेत्र पंचायत बिलरियागंज में दिनांक 20-07-2021 के पूर्व की स्वीकृत परियोजनाओं के पश्चात् कितनी धनराशि पन्द्रहवां वित्त, पंचम वित्त एवं चतुर्थ राज्य वित्त आदि की धनराशि अवशेष है, याची को पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम कंजौली से खन्दौली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

[महोदय, जनपद हाथरस के अन्तर्गत विकास खण्ड-सादाबाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बल्देव-मई-खंदौली रोड जिसकी लम्बाई 22 कि0मी0 है, जिसका टेण्डर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 08-10-2021 को मेसर्स गर्ग सन्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0 260, सेक्टर-09 सी, चण्डीगढ़ के पक्ष में हुआ था, उक्त रोड के टेण्डर को 7 माह पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु अभी तक उक्त सड़क पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। ग्राम कंजौली पर आबादी क्षेत्र है जहां जल भराव के कारण सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्राम कंजौली से खन्दौली

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक सड़क बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। गहरे-गहरे गड्ढे हो गये हैं, गर्भवती मातायें, बहनें सफर नहीं कर पाती हैं। वाहनों से उतरकर पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, स्कूल की बसें छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर चल नहीं पाती हैं। इस समस्या का निराकरण न होने के कारण क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं मिड-डे मील कर्मियों के लम्बित मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

अवगत कराना है कि आशा बहुओं को देश में कोरोना वारियर्स के विश्लेषण के साथ सुशोभित किया गया है। इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड मिला है। परन्तु आशा बहुएं महीनों से लम्बित मानदेय के लिए परेशान हैं और इसी तरह आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं मिड-डे मील कर्मी का वेतन पिछले 8 से 12 माह से लम्बित है। विधान सभा चुनाव के बाद से इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गयी है। मानदेय न मिलने से आशा बहुओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय-

[महोदय, मेरे जनपद गोण्डा में राजकीय विश्वविद्यालय की नितान्त आवश्यकता है। जनपद गोण्डा प्रदेश का अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस जनपद को जोड़ने वाली सड़क लाइन पर उपरिगामी पुल न होने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले को आधे से पौन घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है। सड़क का समुचित विकास न होने के कारण गोण्डा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अभी तक जिले में भारी उद्योग की इकाइयां स्थापित नहीं हो पायी हैं तथा गोण्डा जनपद में पालीटेक्निक का कार्य तथा आई0टी0आई0 का कार्य तथा कृषि विश्वविद्यालय का कार्य तथा राजकीय विश्वविद्यालय (देवीपाटन मण्डल) का कार्य भी लम्बित है। किसी भी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिले के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी अच्छी कनेक्टिविटी हो। समय एवं ऊर्जा का अनावश्यक अपव्यय होता है। शासन की योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों को राजधानी की फोरलेन से जोड़ने एवं बिना किसी बाधा की आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की नीति घोषित की गयी है। इस जनपद के परिप्रेक्ष्य में इस सुविचारित नीति का परिपालन नहीं किया जा रहा है। गोण्डा जनपद की कनेक्टिविटी के इस रेलवे उपरिगामी पुल का जनहित में निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्त रेलवे उपरिगामी पुल का निर्माण की कार्यवाही समयबद्ध कराने का कष्ट करें।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम बदरपुर से दोगवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रपाल सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-68 डिबाई, जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत ग्राम बदरपुर से दोगवां तक सम्पर्क मार्ग कच्चा है, जोकि मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है। कच्चा मार्ग होने के कारण बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और आम जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। जनहित में इस मार्ग का पक्का/डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त कच्चे मार्ग का पक्का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-141, धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर गांवों से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले बहुत से क्षेत्रों के मार्ग कच्चे होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है। बरसात के दिनों में मार्ग कच्चा होने से जगह-जगह गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि 1-ब्लाक धौरहरा में ग्राम डिहुआ डामर रोड से बसौना डामर रोड के मध्य पिच निर्माण कार्य, 2-ब्लाक ईशानगर में

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खालेपुरवा मजरा सरपतहा से नकहिया डामर रोड तक नई पिच मार्ग का निर्माण, 3-ब्लाक रमियाबेहड़ में ग्राम दुलही से रायपुर होते हुए ग्राम टाण्डा तक नई सड़क का निर्माण तथा रपटा पुल का निर्माण, 4-ब्लाक धौरहरा में घुरघुट्टा रोड से सरगड़ा होते हुए रैनी बंधा तक नई सड़क का निर्माण एवं पुलिया निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत खेड़ा महासोना रोड पर ईदगाह के सामने से अड़ौली रजवाहा होते हुए जमुनाठेर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-67, अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर में खेड़ा महसोना रोड पर (सराय छबीला) रोड पर ईदगाह के सामने से अड़ौली रजवाहा होते हुए अकबराबाद कूड़ा होते हुए जमुनाठेर तक काली सड़क का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह मार्ग क्षेत्र के लगभग 20 गांवों को आपस में जोड़ने का काम तो करेगा ही, साथ में इस क्षेत्र के किसानों को मण्डी व चीनी मिलों तक पहुंचने का मार्ग भी सुगम करेगा। जनहित में उक्त निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के अन्तर्गत नौगढ़ बांध में सेमर साधोपुर गांव में एक लिफ्ट कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-383 चकिया, जनपद चन्दौली में वनवासियों के निवास हैं जिसमें वे 50 वर्ष से अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उनका मकान बरसात के कारण गिर गया जिससे ये लोग उसी स्थान पर अपना मकान पक्का निर्माण करा रहे हैं तो वन विभाग के कर्मचारी उनका मकान गिरा दे रहे हैं। जबकि मा0 प्रधानमंत्री एवं उ0प्र0 सरकार हर व्यक्ति, अपना छत योजना के अन्तर्गत मकान उपलब्ध करा रही है। परन्तु वनवासियों द्वारा अपना पुराना मकान उसी स्थान पर बनाने पर वन विभाग के कर्मचारी गिरा रहे हैं। इससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। इसकी जांच कराकर 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे वनवासियों को आवास हेतु पट्टा करके उक्त भूमि आवंटित किया जाना आवश्यक है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्रकरण की जांच कराकर पट्टा प्रदान करते हुए वनवासियों को भवन निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत कछौना, पतसैनी में रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बालामऊ, जनपद हरदोई की नगर पंचायत कछौना, पतसैनी में मुख्य मार्ग पर रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज बनवाये जाने की महती आवश्यकता है क्योंकि बालामऊ जंक्शन मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा जल्दी-जल्दी ट्रेनों का आवागमन बना रहता है जिससे रेलवे फाटक घंटों बन्द रहता है। आने-जाने वाले लोगों व स्थानीय व्यापारियों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है तथा समय बर्बाद होता है। ऐसी स्थिति में जनहित को ध्यान में रखकर उक्त रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर नगर पंचायत कछौना-पतसैनी में रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में 80 से 100 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा स्याना क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटे होने के कारण गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे कि मरीजों को लेकर 50 से 60 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। कभी-कभी तो दूरी होने के कारण मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। इसलिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में 80-100 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत मसकनवां बाजार में स्थित नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 301-गौरा, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मसकनवां बाजार में नवीन सब्जी मण्डी स्थापित है। क्षेत्र के किसानों तथा व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। मेरा क्षेत्र दो मण्डी समितियों में बंटा हुआ है। इसलिए जनहित में नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत कराते हुए गल्ला मण्डी भी बनाया जाय, ताकि खाद्यान्न/गल्ले का उचित मूल्य किसानों/व्यापारियों को मिल सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए नवीन सब्जी मण्डी को उच्चीकृत करते हुए गल्ला मण्डी भी बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ब्लाक नानोता के पाण्डो खेड़ी ग्राम में बरसाती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरत सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 07-गंगोह, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम पाण्डो खेड़ी, ब्लाक-नानोता में बरसाती नदी पर पुल नहीं है जिससे जनता को अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है और लगभग 10 कि0मी0 की काफी दूरी से घूमकर जाना पड़ता है, जनहित में उपरोक्त पुल का नवनिर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अहन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पाण्डो खेड़ी, ब्लाक नानोता में बरसाती नदी पर नवनिर्माण पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत हाटा से करमहा मोड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत आने वाली मुख्य मार्ग की सड़क हाटा से करमहा मोड़ तक (लो0नि0वि0) वाया लक्ष्मीपुर, भड़कुड़वा, तुलादास दूरी लगभग 09 कि0मी0 की स्थिति बहुत ही दयनीय व जर्जर है। बरसात के दिनों में घुटने तक पानी भर जाता है। मुसाफिरों को सड़क पर चल पाना दूभर हो जाता है और दुर्घटना होने का भी भय बना रहता है। जनहित में सड़क निर्माण अति आवश्यक है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत दो नई तहसीलों का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया 1529 राजस्व गांव के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है जिस कारण वहाँ के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में समय अधिक लगता है। उक्त तहसील को विक्रमजोत तथा परसुराम तहसीलों में विभाजित करने की प्रक्रिया लम्बित है तथा वर्षों से जनता की मांग के उपरान्त भी अभी तक उक्त दो नई तहसीलों का सृजन नहीं हो पाया है जिससे वहाँ के निवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत दो नई तहसीलों का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख में बस अड्डा एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कृष्ण भार्गव-

[महोदय, मैं, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत वहाँ से प्रस्थान करने वाले यात्रियों हेतु बस अड्डा न होने के कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा मिश्रिख एवं नैमिष में बस अड्डा स्थल होने के उपरान्त भी यात्रियों को सड़क पर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।

मिश्रिख व नैमिष में बस अड्डा न होने के कारण वहाँ से गुजरने वाली बसों को भी रुकने में असुविधा होती है।

अतः जनपद सीतापुर के अन्तर्गत धार्मिक स्थल नैमिषारण्य एवं मिश्रिख में बस अड्डा एवं यात्री प्रतीक्षालय बनवाये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे गृह जनपद बलरामपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा 'भूमि विकास

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं गृह स्थान योजना बलरामपुर' के अन्तर्गत ग्राम सभा धुसाह, तहसील, ब्लाक व जनपद बलरामपुर में स्थित किसानों की बहुपयोगी बेशकीमती जमीन जो वर्ष 2003 में अधिग्रहीत कर ली गई थी, परन्तु अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। जमीन परती पड़ी हुई है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। अतः किसानों को वर्तमान सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाये अथवा किसानों की भूमि को वापस किया जाये।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए किसानों को तत्काल वर्तमान सर्किल रेट से मुआवजा दिलाने अथवा किसानों की भूमि को वापस किये जाने की मांग करता हूँ।]

अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लोक निर्माण विभाग, उन्नाव श्री ओ0पी0 सोनकर के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि श्री ओ0पी0 सोनकर अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव भ्रष्टाचार में आरोपी होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर चार वर्षों तक निलम्बित रह चुके हैं एवं लखीमपुर खीरी में अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यों में अनियमितता बरतने पर निलम्बित रह चुके हैं। इसके बाद अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड प्रतापगढ़ में वर्ष 2010 से 2013 के मध्य सेवाकाल के समय कम दरों पर प्राप्त निर्माण कार्यों के ठेके एवं अन्य कारण से निर्माण कार्यों की बचत वाली धनराशि जो शासन को शासकीय राजस्व हितों में समर्पण करनी थी, उस धनराशि को समर्पण नहीं करके विभिन्न स्वीकृत कार्यों के अनुबन्ध पर जो उस अनुबन्ध का हिस्सा नहीं थी, न उस कार्य के तकनीकी स्वीकृत आगणन में प्राविधानित थी, अतिरिक्त मद के माध्यम से केवल अनुबन्ध संख्या का उपयोग कर लेखा शीर्षक बदलते हुए करोड़ों रुपये की धनराशि का स्वहितों में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भुगतान कर दिया गया जो गबन की श्रेणी में आता है एवं आपूर्ति आदेश जो प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा प्रतिबन्धित है, के माध्यम से करोड़ों का भुगतान करने का मामला संज्ञान में आया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए अधिशाषी अभियन्ता कार्यकाल में इनके द्वारा किये गये भुगतान का मिलान वास्तविक कार्य उनके सापेक्ष गठित अनुबन्ध संख्या एवं शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का लेखा शीर्षक एवं अतिरिक्त मद से किये गये भुगतानों के कार्य एवं लेखा शीर्षक में भिन्नता है। भुगतान किये गये बाउचरों की टी0ए0सी0 से जांच कराकर छंटनी कर वित्तीय अनियमितता कर अतिरिक्त मदों से

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किये गये भुगतानों की सूची से शासन को अवगत कराया जाये एवं नियमानुसार कार्यवाही सृजित की जाये जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके एवं ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर जनहित एवं राजकीय राजस्व के हितों वाले कार्यों से अलग किया जा सके।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज सिधौली में आईटीआई भवन का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 119-मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत मीरगंज सिधौली में आईटीआई भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है जिससे जनहित में पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के चोला औद्योगिक क्षेत्र का विकास कराकर नवीन उद्योगों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत चोला में औद्योगिक क्षेत्र हेतु दशकों पूर्व भूमि का अधिग्रहण हुआ था, परन्तु कतिपय कारणवश उक्त योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसी स्थिति में चोला स्थित औद्योगिक विकास क्षेत्र को विकसित कराकर उद्योगों की स्थापना के लिए नवीन योजना तैयार की जाय जिससे वृहद स्तर पर इस क्षेत्र के आस-पास के नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जनहित में बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद क्षेत्र के चोला औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कराकर नवीन उद्योगों की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र बल्देव नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा के अन्तर्गत बल्देव विधान सभा में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे हमारे क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत दाऊजी महाराज के मन्दिर से गुजरता है। दाऊजी महराज जी विशाल प्राचीन मन्दिर है जिसमें लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक दर्शन करने आते हैं क्योंकि दाऊजी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महराज भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी हैं और यहाँ पर धार्मिक भावनाओं एवं पर्यटक दृष्टि से श्रद्धालु एवं पर्यटक नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से आते हैं। बल्देव दाऊजी महाराज पर कट न होने के कारण श्रद्धालुओं को आगरा से वापस आना पड़ता है अथवा मथुरा में राया कट पर उतरना पड़ता है। श्रद्धालु एवं पर्यटकों को लगभग 40-50 कि0मी0 की दूरी चलकर दाऊजी मन्दिर में घूमकर आना पड़ता है। यहाँ पर और भी गोकुल, महावन, रसखान समाधि आदि पर्यटक स्थल हैं। अतः जन भावनाओं और श्रद्धालु एवं पर्यटकों की परेशानी को देखते हुए अतिशीघ्र बल्देव में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने-उतरने का कट शीघ्र बनाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुए वाहन संख्या यू0पी032 जी0यू0 5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह नागर -

[महोदय, जनपद लखनऊ, हुसैनगंज थाना के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 परिसर, 32 स्टेशन रोड से दिनांक 28-04-2022 को वाहन संख्या यू0पी0-32 जी0यू0-5625 (होण्डा एक्टिवा) चोरी हो गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने तथा वाहन बरामदगी हेतु वाहन स्वामी रामनरेश सिंह द्वारा उक्त दिनांक को ही आवेदन दिया गया तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के पोर्टल एवं दिनांक 04-05-2022 को ई-थाना द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गयी। पी0सी0एफ0 परिसर में स्थित पी0एन0बी0 बैंक के सी0सी0टी0वी0 कैमरे के वीडियो फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है और न ही वाहन बरामद किया गया है। पुलिस की उक्त कार्यप्रणाली से जनता में अत्यन्त रोष है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी पर अधूरे रिंग बंधे के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह -

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र-रसड़ा अन्तर्गत बहने

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाली टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय यहाँ के कृषकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है क्योंकि टोंस नदी में गाजीपुर से जनपद बलिया तक बने रिंग बंधे में दो जगह 500-500 मीटर का गैप छोड़ दिये जाने की वजह से इसी रास्ते से बाढ़ का पानी ग्रामसभा सरायभारती, अतरसुवां, मुस्तफाबाद, कोप, खजुहाँ, बेसवान, तिराहीपुर, प्रधानपुर, फिरोजपुर, कोडरा, मिर्जापुर, लखुआं, जेवनिया आदि गांवों में फैल जाता है तथा यहां की कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही साथ इन सभी गांवों का अस्तित्व भी खतरे में है जोकि कभी भी कटान की वजह से टोंस नदी में विलीन हो सकते हैं।

यही नहीं, इन गांवों के किनारे वर्षों पूर्व ठोकर आदि का निर्माण भी कराया गया था परन्तु विगत 10-12 वर्षों से इन पर कोई भी अनुरक्षण कार्य न किये जाने के कारण यह सभी ठोकरें अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा रसड़ा के टोंस नदी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के गम्भीर संकट को देखते हुए अधूरे रिंग बंधे को पूर्ण कराने के साथ ही साथ पुराने ठोकरों के अनुरक्षण के साथ आवश्यकतानुसार नई ठोकरों का निर्माण किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना के अन्तर्गत ग्राम हिरनही में कस्तूरबा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज के नक्शे में संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[महोदय, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम हिरनही निवासियों एवं ग्राम प्रधान के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि तहसील पडरौना के अन्तर्गत गाम सभा हिरनही में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय के प्रांगण में भवन की सुविधा न होने के कारण कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संचालन हाई-स्कूल तक किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय को उच्चीकृत कर आवासीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। कस्तूरबा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज के भवन के लिए जिस जमीन को चयनित किया गया है, वह जमीन प्राथमिक व जूनियर हाई-स्कूल के मध्य की जमीन है जिसमें बालक-बालिकाएं खेल-कूद के साथ-साथ क्षेत्र के नौजवान सेना में भर्ती होने की तैयारी भी करते हैं। कस्तूरबा गांधी इण्टरमीडिएट कालेज के भवन बनने से बच्चों की खेल-कूद के साथ-साथ सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों की तैयारी भी बाधित होगी जबकि सरकार खेल-कूद को प्राथमिकता देते हुए गांव-गांव में खेल-कूद की सुविधा हेतु खेल सामग्री व क्रीड़ा स्थल उपलब्ध करा रही है। वहीं

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी तरफ जिला प्रशासन प्राथमिक व जूनियर हाई-स्कूल के मध्य की खेल कूद की जमीन को अधिग्रहण कर इण्टरमीडिएट आवासीय विद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है जबकि विद्यालय के बगल में 55 मीटर लम्बा व 30 मीटर चौड़ा जगह खाली है। खाली पड़ी भूमि पर कस्तूरबा गांधी आवासीय इण्टर कालेज का भवन बनाया जाना बच्चों व सेना में तैयारी करने वाले नौजवानों के हित में होगा। प्रकरण बच्चों के खेल-कूद एवं सेना में भर्ती होने वाले नौजवानो के हित से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद -

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर में मुख्य धार्मिक स्थल से गुर्जरों के डेरे तक 800 मीटर मार्ग पर लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे आये दिन जनहानि होती रहती है। इस सड़क का जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम जटपुरा में प्राइमरी स्कूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर, ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम जटपुरा में कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। उक्त ग्राम के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु अन्य किसी गांव में जाना पड़ता है जिस कारण बच्चों को एवं उनके माता-पिता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्षेत्र की जनता द्वारा ग्राम में ही प्राइमरी स्कूल की मांग किये जाने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता है। इसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम जटपुरा में प्राइमरी स्कूल बनवाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में लो0नि0वि0 द्वारा ग्राम अलाउद्दीन से ग्राम चकमहमूद तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र 24, नूरपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम अलाउद्दीनपुर से ग्राम चकमहमूद होते हुए ईदगाह तक 950 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण कराया गया था। उक्त रोड के दोनों ओर सघन बस्ती हो गयी है और यह मार्ग नाली के समान हो गया है जिसमें हर समय पानी भरा रहता है। निकट भविष्य में बरसात का मौसम प्रारम्भ होने वाला है जिसमें 10 हजार की आबादी का जनजीवन प्रभावित होगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर अलाउद्दीनपुर से चकमहमूद होते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क को सम्पूर्ण चौड़ाई में नाले की व्यवस्था सहित 950 मी0 में सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के आदेश सरकार द्वारा जारी किया जाय।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी के झलकारी बाई नगर में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि झांसी नगर में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से झलकारी बाई नगर (पुलिया नं0-9) की ओर जाने वाले मार्ग पर झांसी-बांदा एवं झांसी-मुम्बई रेलवे क्रासिंग समपार संख्या-367 अत्यधिक व्यस्त क्रासिंग में से है। प्रायः यहाँ गाड़ियों का लम्बा जाम लगने के कारण स्थानीय नागरिकों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है। उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। यहाँ पर ओवरब्रिज की अत्यन्त आवश्यकता है। जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी कालोनी, सेक्टर-डी से कूड़ा प्रबन्धन संयंत्र को दूर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी कालोनी के सेक्टर-डी से लगी भूमि पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा कूड़ा प्रबन्धन गृह संचालित है, जिसके कारण सभी कालोनीवासी और आस-पास के लोग बुरी दुर्गन्ध से त्रस्त रहते हैं। क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर भी दुष्परिणाम पड़ रहा है। लम्बे समय से क्षेत्रवासी कूड़ा प्रबन्धन संयंत्र को कहीं दूर स्थानान्तरित करने की मांग करते आ रहे हैं। लोगों को हो रही समस्या के दृष्टिगत नगर के मध्य से कूड़ा प्रबन्धन संयंत्र को नगर से बाहर आबादी से दूर लगाया जाना आवश्यक है। जनहित में नगर निगम, लखनऊ को इस पर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

अतः विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत इस व्यापक लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा की विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत नगलीया जट से ग्राम कोटा तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि ग्राम नगलीया जट से ग्राम कोटा तक कच्चा मार्ग है। इस रास्ते से कई ग्राम जुड़े हैं व बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। इस मार्ग की क्षेत्र के लोगों को बहुत आवश्यकता है। इसमें बहुत गड्ढे हैं जिससे क्षेत्रवासी का निकल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0 है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनहित के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 299-तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सबसे पुरानी तहसील तरबगंज है, जिसमें कोई मण्डी समिति नहीं है। मण्डी समिति गोण्डा व नवाबगंज में है, जो विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी की ओर से लगभग 60 कि0मी0 की

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूरी पर है। तरबगंज में मण्डी समिति न होने के कारण क्षेत्र के कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

[12:49] राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-705/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (195)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-705/ग्यारह-2-21-9(47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (195)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-706/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (196)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-706/ग्यारह-2-21-9(47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (196)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-707/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (197)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-707/ग्यारह-2-21-9(47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (197)-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (200)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-21-9(47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (200)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1041/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (202)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1041/ग्यारह-2-21-9(47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (202)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-283/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (234)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-283/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (234)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-284/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (235)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-284/ग्यारह-2-22-9(56)-19-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (235)-2022, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-2, वर्ष 2022†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-2, वर्ष 2022 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप अभी बोलेंगे या कुछ देर में बोलेंगे जैसा आप कहें।

[12:53] प्रतिवेदन सदन के पटल पर ससमय नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो अधिनियम बने हैं उसमें इन विभागों से अपेक्षा की जाती है कि अपना प्रतिवेदन समय से दें लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसमें अधिकांश विलम्ब का कारण किया जाता है विलम्ब के कारण के नाते यह प्रतिवेदन आपके सदन के पटल पर समय से नहीं रखे जाते हैं जो यह अधिनियम की यह मंशा है यह उस मंशा के विपरीत है। इसमें आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए और आपको कभी-कभी इनको मना भी कर देना चाहिए कि नहीं स्वीकार किया जायेगा। जिससे इनके ऊपर दबाव बने कि यह लोग अपनी सूचना समय से दें। मैंने ऐसा एक बार किया भी था क्योंकि यह विभाग मनमाने ढंग से जब इनको फुर्सत होती है प्रतिवेदन तैयार करके विलम्ब का कारण देकर आपके यहाँ प्रेषित कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसकी ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाण्डे जी इसमें जो आपने व्यवस्था दी थी मैं उसको जरूर देखूंगा और आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था का मैं पालन करने का प्रयास करूंगा।

[12:55] वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा††

श्रीमती पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का समय दिया, इस बाबत आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सरकार को यह बताना चाहूँगी कि यह जो बजट हम सबके समक्ष रखा गया है, यह विशुद्ध रूप से एक लोक-लुभावन बजट है जो सुनने और देखने

---

† छापा नहीं गया

†† दिनांक 28 मई, 2022 की कार्यवाही से।

में अत्यन्त लुभावना है किन्तु धरातल और यथार्थ की कसौटी पर सन्देहास्पद है। फिर चाहे रोजगार का विषय हो चाहे युवाओं, महिलाओं का विषय हो, इस बजट में इन विषयों पर संदर्भित जितनी भी बातें लिखी गयी हैं, उनका सच्चाई और यथार्थ से कोई भी सम्बन्ध नहीं दिखता है। दूसरी, सबसे बड़ी विसंगति इस बजट में आस्था के आधार पर भेदभाव की है। जहाँ सरकार राम, रैदास, बाल्मीकि के नाम पर धन देने की घोषणा कर रही है तो क्या अन्य धर्मावलम्बियों की आस्थाओं को अनदेखा कर दिया गया ? (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भलीभांति जानती हूँ कि सदन में बहुमत के आधार पर जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में ईसाईयत और इस्लाम बाहरी है। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती हूँ, न यह मेरा विषय है, लेकिन सरकार को यह ध्यान में रखना ही होगा कि बुद्ध, महावीर, नानक और कबीर ये सब इसी भूमि पर पैदा हुए और इसी भूमि पर पले-बढ़े हैं। उन्होंने समग्र मनुष्यता के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह इस भूमि पर ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने मनुष्यता से देवत्व तक का सफर तय किया और शिखर तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की यह भूमि बुद्ध की है, महावीर की है, नानक से संबंधित है, कबीर की है, इस भूमि पर करोड़ों-करोड़ लोगों की आस्था इन भगवानों में भी है। अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि यदि वह धार्मिक तुष्टिकरण करती है तो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के अनुयायियों का भी करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। लोकतंत्र में जनादेश अनिवार्य सत्य है और पांच साल के कार्यकाल के बाद जिसको जनता ने नकार दिया उसे सरकार में दोबारा लाया जाना भी जनादेश का अपमान है। (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।) मैं यह बताना चाहूँगी जिसकी अपनी जमीन न हो, वह दूसरों की जमीन की बात न करे और अपनी भाषा और अपना बर्ताव विनम्र और शिष्ट रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगी कि भगवान बुद्ध में करोड़ों लोगों की आस्था है। आप और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को भी भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा है। ...

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं जिस जिले में ब्याह कर गयी हूँ और जिस जिले ने मुझे चुनकर, सम्मान देकर इस सदन में भेजने का काम किया है और जिस जनपद की भूमि भगवान बुद्ध की महत्ता और महानता का यशोगान करती है, उसका नाम कौशाम्बी है। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जनपद के पुनर्निर्माण को भी बजट में शामिल किया जाय।

श्री अधिठाता-

मा0 सदस्या अब आप समाप्त करिये।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संतों के कल्याण हेतु आपने एक बोर्ड की घोषणा की है, उसमें बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर की परम्परा के संतों को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाय। तभी हम यह संदेश दे पायेंगे, तब यह विश्वास जीत पायेंगे कि सरकार सबकी है, सबके लिए काम कर रही है। मैंने जो एक-दो बातें कही वह महज सरकार या मुख्य मंत्री जी से कहने की बात नहीं है। अपेक्षा, विश्वास तब और बढ़ जाता है जब मुख्य मंत्री के पद पर बुद्ध, कृष्ण की श्रेणी में रखे जा सकने वाले एकमात्र महान क्रान्तिकारी गुरू गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, महा मण्डलेश्वर आदित्यनाथ योगी जी खुद बैठे हैं और जिनके लिए सब सम हैं। मैं इसके लिए सरकार से पुरजोर अपील करती हूँ कि बुद्ध की भूमि कौशाम्बी के विकास कार्यों को इस बजट में शामिल किया जाये और धार्मिक असमानता, असंतुलन को ठीक किया जाय। धन्यवाद। जय संविधान, जय कमेरा।

डॉ नीलकंठ तिवारी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सिर्फ दो-तीन विषयों पर निवेदन करूंगा। जिस दिन बजट आया उस दिन के सुबह का अखबार पढ़ रहा था। अखबार में नेता प्रतिपक्ष का एक बयान कोने में छोटा सा छपा था कि यह बजट नहीं बंटवारा है। बंटवारा तो है, लेकिन 2012 से 2017 वाला बंटवारा नहीं है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अर्थायाम से जुड़ा हुआ बंटवारा है। जिस तरह प्राणायाम में शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्राण वायु का संचार किया जाता है, उसी तरह अर्थायाम में समाज के हर तबके के विकास की परिकल्पना को लेकर, उसको आगे बढ़ाने को लेकर अर्थ का बंटवारा होना चाहिए। बजट की यही मंशा होनी चाहिए और उस अर्थायाम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 के पहले यह बंटवारा भाई, भतीजे, पत्नी, पिता, रिश्तेदार, मौसा, नेताओं के अपने-अपने परिवारों में होता था। लेकिन यह बंटवारा अर्थायाम नहीं है। आज अर्थायाम की परिधि में बंटवारा आदरणीय योगी जी की सरकार ने मा0 सुरेश खन्ना जी के बजट में करने का काम किया है। इस बजट पर अभी एक मा0 सदस्या चर्चा कर रही थीं। आपके माध्यम से मैं उनको थोड़ा सा जानकारी जरूर देना चाहता हूँ कि एक बार उनको ब्रज क्षेत्र में जाकर रसखान की समाधि को भी जरूर देखना चाहिए, जिसको आदरणीय योगी जी की सरकार ने विकसित करने का काम किया है। औरंगजेब की बहन या जो भी रही होंगी, जिनका नाम ताजबीवी था। आपने शायद नाम न सुना हो, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मैं आपको बताने का निवेदन करता हूँ कि आप उनको जानें, उस ताजबीबी के मकबरे को ब्रज क्षेत्र में आदरणीय योगी जी की सरकार ने सुन्दर बनाने का काम किया है।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 04 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस बजट में एक अत्यन्त सुन्दर काम किया गया है जो पहली बार किया गया है उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम की भूमि है, बाबा विश्वनाथ की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, गोरखनाथ की भूमि है, चित्रकूट है यहाँ पर बहुत ढेर सारे पुरोहित रहते हैं, पंडे रहते हैं यह लोग समाज के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का वाचन करते हैं। उन पुरोहितों की हालत कही-कहीं बहुत ही चिन्तनीय है अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करूंगा और इस बजट को प्रस्तुत करने वाले आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि ऐसे पुरोहित समाज के लोग पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए पौरोहित्य कल्याण बोर्ड के गठन के बारे में पहली बार इस सरकार ने चिन्ता किया। यह अत्यन्त अद्भुत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सांस्कृतिक पहचान, हमारे सांस्कृतिक केन्द्र, अध्यात्म और आराधना के केन्द्र जितने भी उत्तर प्रदेश में थे, सबके विकास की परिकल्पना को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में यह बजट तैयार किया गया है। जरा सोचिये 100 करोड़ रुपये राम राज्य की भूमि अयोध्या के लिए व्यवस्थित की गई है। 100 करोड़ रुपये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जो विश्व की प्राचीनतम नगरी है जहाँ पर आज श्रद्धालुओं की संख्या श्री विश्वनाथ धाम बनने के बाद एक लाख लगभग रोज हो गयी है। ऐसे में नगर का सौन्दर्यीकरण हो। अयोध्या धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन डाक्यूमेंट को ले करके आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में अत्यन्त सुन्दर बन रहा है। उस सुन्दर परिकल्पना को साकार किया जा सके इसके लिए सभी मदों को अलग-अलग करने के साथ एक सौ करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है कि जहाँ कम वहाँ हम जरूरत पड़े वहाँ इस सौ करोड़ रुपये को ले करके इसको प्रस्तुत किया जा सके। अन्त में मैं एक निवेदन करूंगा कि यह बजट सर्वसमाज को ले करके तैयार किया गया है यह बजट पूरी तरह पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अर्थायाम को ले करके तैयार किया गया है अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी तैयार किया गया है, इतना ही, आपसे निवेदन है कि काशी में चूंकि पौरोहित्य कल्याण बोर्ड आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा चूंकि पुरोहितों की संख्या सबसे ज्यादा काशी में है, तो जो पौरोहित्य कल्याण बोर्ड बन रहा है धर्मार्थ कार्य विभाग का चूंकि निदेशालय वहीं पर है उससे जोड़ करके वहीं पर इसका कार्यालय बनाया जाय। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2022-23 के लिए बोलने का मौका दिया है। यह बजट जैसा सरकार बता रही है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार यह भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वह पहले से बढ़ करके आता है। यह बजट नहीं मैंने बातों में कहा था कि अभी यह विभागों का बंटवारा है। यह बजट नहीं बंटवारा है। जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, अभी जनता पर नहीं

पहुंचा है बजट। बजट आने के बाद लोगों ने जब बजट को देखा जो वादे किये गये थे लोक कल्याण संकल्प-पत्र में और अपना बजट देखकर कहीं न कहीं निराशा आती है।

अगर बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाये तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से और खेती से जुड़ी है। यह बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट का पढ़ें, जिसमें यह सरकार कह रही है कि पिछली इन्वेस्टमेंट मीट के तहत कई एम0ओ0यू0 हुए थे और पहले ही पेज पर कहा गया है और सरकार खुद लिख रही है कि एम0ओ0यू0 के तहत 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार यह न बता पा रही हो कि एम0ओ0यू0 के बाद कहाँ पर बना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और अगर हम आंकड़ों को देखें जो हमें बताते हैं कि 2017-2018 के बजट इस्टीमेट में जो गैप है वह लगभग 16 परसेंट का है। 2018-2019 में 08 परसेंट, 2019-2020 में 20 परसेंट तथा 2020-2021 में लगभग 20 परसेंट का गैप है। अगर एक्चुअल बजट में इतना गैप दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे ? क्या विभागों की कैपिसिटी खर्च करने की है ? सरकार यह बताये कि जो बजट पेश हुआ है वह खर्च किया जायेगा ? दूसरा, विभागों के माध्यम से जितना बजट खर्च करने का प्रावधान है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर में देखें तो उसमें भी दिखाई देता है कि 38 परसेंट का गैप है। मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ में हम बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से मा0 मंत्री जी तथा मा0 सदस्य जगह-जगह गये, उन्हें खुद महसूस हुआ कि कमी क्या नजर आ रही है। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था चाहे वह मेडिकल कालेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हों, चाहे हमारे सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 हों, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वह दिखाई नहीं देता और अगर हम मा0 मंत्री जी का ही मानें तो हर जगह कमी नजर आ रही है। कमी केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, वार्ड ब्वाय की कमी है और जहाँ तक दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए थी तो दवाइयों में भी बड़े पैमाने पर कमी दिखाई दे रही है और यहाँ तक डिप्टी सी0एम0 ने विभाग के मंत्री होने के नाते खुद जाकर पकड़ा कि करोड़ों रुपये की दवाईयां जो एक्सपायरी डेट की थीं वह दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, वाटर सप्लाई, सैनीटेशन में आगे क्या होगा वह तो देखा जायेगा।

हाउसिंग एक तरफ से पूरी ठप्प पड़ी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर का इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा होगा जितना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर सपना दिखाया गया था कि नये सिटीज बनाये जायेंगे, स्मार्ट सिटीज बनायेंगे और कहाँ रुक गये आकर ? जो स्मार्ट

सिटी का सपना है उदाहरण के लिए अगर लखनऊ में जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है ? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि मेट्रो है, रिवर फ्रंट है, पार्क है, अण्डरग्राउण्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है। आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है ? आज आप शहरों में देख लीजिये गन्दगी की भरमार है और मुझे याद आता है मान्यवर बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने लखनऊ में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लाण्ट लगवाया था और उनकी कोशिश थी कि इस प्लाण्ट से बिजली बनायी जाय, लेकिन उस प्लाण्ट से बिजली कभी बन नहीं पायी। एक पत्रकार जब उस प्लाण्ट की स्थिति देखने गया होगा तो वहाँ के कर्मचारी से पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लाण्ट लगा है इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है ? तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था जिससे पूछताछ हो रही थी उसने जवाब दिया कि यहाँ पर जो कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है इसलिए बिजली नहीं बन पा रही है। कूड़े की भी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। स्वच्छ भारत का जो सपना दिखाया गया वह न केवल शहरों में बल्कि छोटे-छोटे कस्बों से लेकर गांवों में जिस तरीके से गन्दगी फैली हुई है उसके लिए क्या-क्या व्यवस्था है ? आप कह रहे हैं कि हम स्मार्ट फोन बांटेंगे क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिये थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए आप टैबलेट दे रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ आप ई-गवर्नेन्स की तरफ जा रहे हैं तो वहीं पर ई-वेस्टेज का आप क्या करेंगे ? इसी तरह अगर हम आपके पिछले बजटों को देखें तो वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में गिरावट दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वह है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जेनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना चाहिए था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था उस दिशा में पांच साल सरकार क्या करती रही ? हमारी सरकार में बिजली विभाग की जो बैलेंस सीट बिल्कुल क्लीयर हो गयी थी, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है ? लेकिन जब हम बजट देखते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, जितना बढ़ावा देना चाहिए था उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाना चाहिए था, दिखने में तो स्पोर्ट्स के लिए बजट में है, लेकिन आखिरकार पहुंच कहाँ रहा है ? मैंने कहा कि बजट में तो है लेकिन बंटवारा होकर जमीन पर कहाँ पहुंच रहा है ? हाउसिंग डिपार्टमेंट के विषय पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। डेयरी को लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गिरावट हुई है। आपके बजट को कम किया गया है और मैं तो कहूँगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत से प्रदेशों में सरकार होगी, आप तुलना करिये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और अन्य प्रदेशों में इसके लिए क्या बजट मिलता है ? इसमें गिरावट है या नहीं है ? डेयरी डेवलपमेंट हमारी एग्रीकल्चर इकोनामी को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी के लिए

क्या काम हुआ है ? जो हमारी पराग है उसको आप कितना आगे बढ़ा रहे हैं ? अगर हम इसी में देखें तो जो गैप नजर आ रहा है वह बड़े पैमाने पर दिख रहा है। हमारी सरकार के समय में जो इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू हुआ था उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया है। वर्ष 2016-17 तक लगातार इसमें बजट रोक दिया गया, उसके बाद लगातार बजट कम हो गया है। यह भी कहीं न कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जगह-जगह प्लाण्ट लगना शुरू हो गये थे और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे एक बार मिले थे, वो यू0पी0 का मार्केट देख करके और यू0पी0 का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहाँ पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहाँ पर काम शुरू करेंगे तो हमारा पराग कहाँ जायेगा ? उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपके पराग में होगा जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके, अमूल जैसी बड़ी सोसाइटी का।

मान्यवर, उसका परिणाम है कि अमूल का प्लाण्ट लगाने के लिए मैंने लखनऊ के चकगंजरिया में जमीन दी। शायद नेता सदन ने उसका उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा बराबर का प्लाण्ट बनाया जिससे अगर अमूल मार्केट में आयेगा तो कहीं पराग को पछाड़ न दे। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लाण्ट लगाया। वाराणसी का प्लाण्ट लगना था पर अब लगने जा रहा है। जिस समय समाजवादी सरकार थी और नेताजी मुख्य मंत्री थे मदर डेरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लाण्ट लगा था। बीच में एक सरकार आई उसने काम नहीं किया। मुझे बाद में मौका मिला और 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लाण्ट वहाँ भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेरी के क्षेत्र में खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया तो वह समाजवादी सरकार ने। बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया ? कहने को तो प्रचार होता है दूध पीता है इण्डिया। क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा ? माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वे इस बात को जरूर बतायेंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है ? और मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन्होंने कितना काम किया है ? मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लाण्ट लगाया था। उस समय मैं कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो हम देंगे। मैं यह भी कहता था कि अगर हमें चार रुपये ज्यादा देना पड़े तब भी पर लीटर चार रुपये ज्यादा देकर दिखायेंगे। आप गौ-रक्षा कर रहे हैं। गाय मां को बचा रहे हैं तो गाय मां की संख्या बढ़नी चाहिए। आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए तथा गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसी योजना लायेंगे जिसमें भैंस के मिल्क से चूंकि भैंस के मिल्क में फैट कन्टेन्ट ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के मिल्क में बेटर होती है। क्या सरकार काऊ के मिल्क को कम से कम चार रुपये ज्यादा देकर खरीदने

का इन्तजाम करेगी ? अगर आपका सबसे बड़ा बजट है, तो फिर गाय के मिल्क के लिए बजट क्यों न हो ? यह बात इसलिए मुझे याद आ गयी क्योंकि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहना चाहूँगा कि कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं। वित्त मंत्री जी ने उसके लिए पैसा नहीं रखा है। हो सकता है इत्र से आपको लगाव न हो, लेकिन हर एक को खुशबू पसंद है। दिल्ली से एक माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं। पी0डब्लू0डी0 जैसे सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं। इत्र के बारे में बेहतर समझते होंगे क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े मार्केट में से एक इत्र का मार्केट भी है। वहाँ पर मैं परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था क्योंकि यह चीजें ट्रेडीशनल हैं। वहाँ हजारों साल पुराना कारोबार है। परफ्यूमरी पार्क अधूरा बना हुआ है। हमें गोबर नहीं चाहिए हमें परफ्यूमरी पार्क चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस बायो गैस का गोबर वाला प्लाण्ट देने की बात कर रहे हैं, उसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था। हमारे सदस्य कभी-कभी यह कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूँ ? आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इसलिए ट्वीट करता हूँ कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि मेट्रो के उद्घाटन में हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है और जैसा नेता सदन ने कहा कि वह हमारे मित्र हैं क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी और आपकी सरकार थी। उस समय भी मैंने ट्वीट करके अपने लोगों के बीच में कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वह पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे यूपी व नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं तो नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको तो कम से कम मैं चाहूँगा कि वह फाइल दोबारा देख लें तो उस फाइल में नजर आ जायेगा कि मेट्रो किस सरकार के समय की बनी हुई है। जब उस मेट्रो का उद्घाटन हुआ तब उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा-दिल्ली मेट्रो में बैठ कर गये थे। मा0 अध्यक्ष अगर सांड़ वाली फोटो गलत आ गयी हो तो हम बताना चाहते हैं कि वह एक त्यौहार है, लेकिन हम सांड़ केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड़ से लोगों की जान जा रही है। वह फोटो हो सकता है कि त्यौहार की आ गयी हो लेकिन वह तस्वीर बिल्कुल ठीक है और यही सच्चाई है। मिर्जापुर में सोलर प्लाण्ट का उद्घाटन हुआ था जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी उद्घाटन में आये थे, लेकिन वह परियोजना भी समाजवादी पार्टी की सरकार की ही बनाई हुई परियोजना थी। उसकी सही फोटो मैं लेकर आया हूँ। वित्त मंत्री जी अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए पता नहीं कहाँ से कुछ लाइनें बहुत रिसर्च के बाद लिखकर लाये थे और लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसे ही पढ़ते हैं हालांकि मैं शायर नहीं हूँ लेकिन बजट के हिस्से में कुछ लाइनें लिखी हैं आपसे अपनी बात को कहने के लिए, तो हम

भी अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कुछ लाइनें पढ़ना चाहेंगे। जब तक अमन और चैन नहीं आता है, तो काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना, मेरी पीढ़ी को एक मिसाल बनकर चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम यह सोच रहे थे कि आप कोई नई लाइनें सुनायेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

मैं अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पर बहस की थी और यहाँ पुराने मा0 सदस्य भी होंगे जिस पर दिन-रात बहस की थी। वह सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण है और पांच बजट पिछली सरकार के और छठवां बजट यह है। उन सस्टेनेबल गोल्स को कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बताने का काम करे। जो आंकड़े हम पढ़ते हैं जो नीति आयोग से आते हैं शिक्षा सूचकांक में तो यूपी सबसे नीचे राज्यों में चौथे नम्बर पर दिखता है।

आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिये हों और जिस उत्तर प्रदेश की वजह से लगातार आपकी केन्द्र की सरकार बन रही हो, उस दिल्ली और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में हमारी शिक्षा का यह स्तर है। मैं हमेशा प्राइमरी स्कूल में जाता हूँ। मैं वहाँ पर एक बार नहीं गया, बल्कि जब मैं मुख्य मंत्री था तब भी मैं वहाँ पर गया था। मैं अपनी कमी भी जानता हूँ। जब मैं एक स्कूल में गया और वहाँ पर जाकर मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या आपने पहचाना मुझे, तो वह छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया, तो मैंने पूछा कि बताओ कौन हूँ मैं, तो वह बोला कि आप राहुल गांधी हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहें।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सोच-समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ कि यह किस बात पर हंस रहे हैं। इन्हें चिन्ता और दुःख इस बात का नहीं है कि यू0पी0 नीचे से चौथे नम्बर पर है बल्कि इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया है। कमाल है आपको। आपकी सरकार किसने बनवा दी। इनको प्रदेश की चिन्ता नहीं है जिस बात पर इनको दुख होना चाहिए उस पर यह लोग हंस रहे हैं। इन्हें दुख इस बात का नहीं है

कि स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहाँ पर खड़े हैं। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि यह सब लाइव चल रहा है और जनता सब देख रही है। प्राइमरी एजुकेशन के सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहाँ-कहाँ से आकर पढ़ा रहे हैं। आप इस बात की जांच करिये कि जो हम लोग कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों की भारी कमी है। आप कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में दो करोड़ बच्चों को पढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े हैं और बहुजन समाज के जो बच्चे हैं केवल वह उन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिये कि जो सम्पन्न लोगों के बच्चे हैं वह कहाँ पर पढ़ने चले गये। ऐसी स्थिति में क्या प्राइमरी स्कूल का बच्चा मुकाबला कर सकेगा।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका टाकी)

हमने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से सीखकर कुछ तो इम्पलीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इम्पलीमेंट करते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो मैं एनर्जी ड्रिंक भी बता सकता हूँ कि कौन सी पीनी चाहिए। वह अभी बनी नहीं है, लेकिन कभी-कभी मिलती है। आप लोगों के माध्यम से कभी-कभी बताया जाता है कि कौन सी वह एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे होंगे तो समझ जाओगे और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब सरकार में था तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सबसे पहले अक्षय पात्र फाउण्डेशन का मथुरा का प्लाण्ट देखने को मिला जहाँ पर एक साथ लाखों की संख्या में बच्चों को भोजन कराया जा सकता है। यहाँ जो माननीय सदस्य मथुरा से जीतकर आये होंगे वह जानते होंगे कि वहाँ पर अक्षय पात्र फाउण्डेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने जो टारगेट सेट किया है वह भी उन्होंने अचीव किया है। जब मुझे उनकी तैयारी अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको सेम-टू-सेम और भी जगहों पर इम्पलीमेंट करना चाहता हूँ। उनकी बहुत सारी चीजें थीं और बहुत सारी रुकावटे भी थीं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के भी कई इशूज थे, लेकिन उन सबके बावजूद भी मैं उनको लखनऊ लेकर आया और इसे क्रियान्वित कराया। आज लखनऊ में डेढ़ लाख से अधिक बच्चों को हॉट कुक्ड भोजन मिलता है। वह मशीन से रोटी बनाते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी है वह उसे सी0एस0आर0 से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचेन को मैंने बनाने का काम किया था और आज लखनऊ में लाखों-लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी आपको याद होगा कि इसी विधान सभा में उनके खाना को चेक करने के लिए तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी थे, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री थे, कुछ हमारे मंत्रीगण थे, मैं भी था, हम लोगों ने यहीं पर बैठकर खाना खाया था ताकि हम लोग उसकी गुणवत्ता को देख सकें कि हमारे बच्चों को आखिर कैसा खाना मिल रहा है। उसके बाद हमने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह इस प्रकार की किचेन बनाई जायेगी और

अक्षय पात्र बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गयी जो दो सौ करोड़ का बजट दिया गया था वह बजट पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वह बजट जाड़े के लिए ऊन के स्वेटर में चला गया। उसमें सरकार यह ही नहीं तय कर पायी कि वह इतना कास्टली हो गया कि उस स्वेटर में इलॉस्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी। पता नहीं उसमें क्या रहा मुझे जानकारी नहीं है। यह सरकार बेहतर समझती होगी। टेण्डर डाक्युमेंट में स्पेसिफिकेशन थे वह जानकारी मुझे नहीं है। वह किचेन नहीं बन पायी। मैंने अक्षय पात्र बनारस को दिया था। आपने और जगह रोक दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेता सदन बतायें कि आपने बनारस की उस अक्षय पात्र किचेन को क्यों रोक दिया। उसके साथ-साथ बच्चों की स्टील की थाली, गिलास मिलने लगा था वह स्टील गिलास और थाली पता नहीं कहाँ चली गयी। जो बच्चों को सप्ताह में एक दिन फल मिलना चाहिए था यह सरकार बताये कि बच्चों को कितने सप्ताह फल खिला पायी है और क्या सरकार बच्चों को दूध दे पायी है या नहीं दे पायी है और सरकार यह बताये कि जो आपने एन0सी0ई0आर0टी0 की बुक्स तय की हैं वह कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी हैं। अगर पहुंचायी हैं तो बता दें। यहाँ जितने सदस्य हैं वह जाते होंगे पता कर लें। इसलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचेन आज चालू हो गयी होती तो मिड-डे-मील योजना में हो सकता है कि जो घोटाला है वह भी बन्द होता और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता। कभी-कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखायें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ना नहीं जानते वह भी सिखाने लगते हैं।

मान्यवर, पिछले पांच साल में लगभग 18 हजार रुपये गड्ढामुक्ति में, मेंटीनेंस में पैसा खर्च हो गया। यह केवल गड्ढामुक्ति का है। मेंटीनेंस का पैसा है। अगर आंकड़े गलत हों तो आप ठीक कर दें। खराब सड़कों का सवाल नहीं है। सवाल बजट का है। हमने तो हवाई जहाज उतारा था उसमें गड्ढा नहीं हुआ। मिराज, सुखोई और हरक्यूलिस उतार दिया। शायद हमारे मा0 सदस्य यह नहीं जानते होंगे कि हरक्यूलिस से भारी कोई जहाज नहीं होता है। अगर हो तो बता दो वह भी उतार देते वहीं पर। मैं एक किताब का केवल दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं यह किताब सभी मा0 सदस्यों को बांटना चाहता हूँ क्योंकि कभी-कभी हमें बताया जाता है कि समाजवाद यह है, समाजवाद वह है। हालांकि हमारे नेता सदन तो समाजवाद के बारे में जानते हैं और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवायी और छपवायी और उसमें फ्रंट पर लिखा कि ''द राइज ऑफ सैफरन सोशलिस्ट।'' क्या गलत है। अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है। आप भी तो सोशलिस्ट हो। यह जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो क्या यह सोशलिस्ट सिद्धान्त नहीं है। क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, यह बात अलग है कि आपने वादा कुछ किया दे कुछ रहे हो। जो गरीब बेटियों को दे रहे हो क्या वह समाजवादी सिद्धान्त नहीं है। मा0 मुख्य

मंत्री जी तो जानते हैं नेता सदन तो समझते हैं इसलिए उन्होंने अपने लिए किताब लिखवायी है द राइज ऑफ सैफरन सोशलिस्ट।

अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे हैं कि सोशलिज्म क्या है तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझायें और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कान्स्टीट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रिएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी और प्रिएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। अगर आप सोशलिस्ट पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) अगर आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं तो आप सेक्युलर भी नहीं हो सकते। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) ये तीनों ही एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसीलिए कहा गया कि हमारी कन्ट्री डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर कन्ट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं हैं तो आप न सेक्युलर हैं, न डेमोक्रेटिक हैं और आप एक भी चीज हटा देंगे तो हमारा देश नहीं चल सकता है। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी शब्दों में बातें इधर-उधर हो जाती हैं। एक और किताब लिखी गयी है, द मॉक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, हम तो आपको योगी समझ रहे थे, ये आपको मॉक कौन लिख दिया। (हंसी) ये डिफरेंस भी आप ही बता सकते हो, मैं ये डिफरेंस नहीं जानता हूँ। जो आपकी बजट स्पीच है और जो जनता से आपने वादे किये, जो बजट आप रखते हैं और जो बजट आप खर्च करते हैं उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प-पत्र है और आपका बजट है उसमें कुछ नहीं है। अगर आप पांच साल की बात करते हो तो पिछले पांच साल में क्यों नहीं पूरा किया ? आपने किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की ? (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) अगर ये लोक संकल्प-पत्र पांच साल के लिए है तो आपने अपना ही संकल्प-पत्र नहीं पढ़ा होगा जिसमें आपने खुद लिखा है कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी। हमें जानना है कि ये दूरियां क्यों हैं ? आपने पहले संकल्प-पत्र में लिखा था कि आप 70 लाख लोगों को नौकरी एवं रोजगार दे देंगे, वह सूची कहाँ है ? आपने कहा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो दोगुनी आय कहाँ है ? इन्वेस्टर्स समिट में आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर एम0ओ0यू0 हुए, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में चल रहा है। अब आप ये बता दीजिए कि ये चरण कौन से हैं ? किस-किस चरण में काम चल रहा है ? इसका मतलब है कि जमीन पर कुछ नहीं चल रहा है। फिर जो डिफेंस कारीडोर के बड़े-बड़े सपने दिखाये जा रहे हैं, शायद सरकार यह नहीं जानती होगी कि वह डिफेंस कारीडोर कहाँ बना है। जो उद्योगपति एवं कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हें यह लगता होगा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे डिफेंस कारीडोर होगा लेकिन नेता सदन को शायद अधिकारियों ने नहीं बताया होगा कि डिफेंस कारीडोर कहाँ बनाया गया है।

डिफेंस कारीडोर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर नहीं है, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से आप हटकर जब जाओगे तब डिफेंस कारीडोर है और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अगर कोई बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जायेगा और आपके डिफेंस कारीडोर में जगह ढूंढ़ना चाहेगा तो शायद वह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और जिस-जिस ने जगह देख ली होगी, वह शायद इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पानी, सड़क, बिजली आदि जरूरी है, बताइये, तीनों चीजें वहाँ पर हैं या नहीं हैं ? ये तीनों नहीं हैं और जो डिफेंस कारीडोर की जमीन है ये कभी समाजवादी सरकार में एक्वायर की गयी थी केवल आपने उसका नाम बदल दिया और आप उसे कागज-फाइल में देखिये, ऐसे मत देखिये। वह इण्डस्ट्रियल हब बन रहा था और अगर नेता सदन को यह लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो नेता सदन हमें बता दें कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से डिफेंस कारीडोर जो आप बना रहे हैं वह कितनी दूर है ? पानी के लिए ऐरच डैम बन रहा था, हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गये। शुरू में दूसरे मंत्री थे आज शायद सो रहे हैं। (हंसी) आप शुरुआत में थे, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे, लेकिन नहीं होने दिया गया।

मैंने यही कहा कि आप अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वह काम नहीं कर पाये। एरच डैम वैसा का वैसा पड़ा है। तो जब इण्डस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली कहाँ है, फिर उसमें दूसरे मंत्री बन गये और अब तो नये मंत्री अच्छे बने हैं, जिनका डॉयलाग सबको याद है और पता नहीं क्यों ऐसा डॉयलाग उन्होंने कहा ? उन्होंने कहा कि थोड़ा-बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। (हंसी) यही डॉयलाग था न ? अगर किसी को ठीक करना हो तो ठीक कर दे।

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर)

यह मेरा डॉयलाग नहीं हो सकता, यह मेरा डॉयलाग नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, जब यह नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तो बीच में माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, जब अवसर आयेगा तब अपनी बात कहियेगा, कृपया शान्ति बनाये रखें। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें।

श्री अखिलेश यादव-

यह तो जो इन्वेस्टमेंट है, यह केवल सपना है और वहाँ पर क्या दिखाया गया कि मिसाइल यहाँ बनेगी, यहाँ पर तोप बनेगी और तोप ऐसी बनेगी, जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पायेगा, चीन मुकाबला नहीं कर पायेगा। तो यह चीन का मुकाबला अलग बात है, हालांकि इस सदन में वह बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा

रहा है, जल्दी करिये आप, जल्दी बनाइये, सब तोप और मिसाइल वगैरह और हम तो कहते हैं कि जो यह नया हवाई जहाज आया है, राफेल, कोई बुन्देलखण्ड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइये, क्यों बाहर से आप ला रहे हैं ? हमारे बुन्देलखण्ड में ही राफेल बने और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने और इसीलिए उस समय भी मैंने मांग की थी कि ग्वालियर से ले करके लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा और जिस समय सुझाव मांगे गये थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने भी सुझाव लिख कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें तो जो सड़क मांगी थी, ग्वालियर टू लिपू लेक, वह किस स्टेज पर है, यह भी जानकारी दे दें।

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने बैठे-बैठे कहा कि भारत सरकार से स्वीकृत हो गयी है)

बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जमीन पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। हालांकि ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे ग्वालियर जानते होंगे। दूसरी हमारी मांग है कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, एक्सप्रेस-वे बन रहा है मुम्बई टू दिल्ली और जिस प्रदेश ने दिल्ली की सरकार बनवाई हो, दो-दो बार प्रधानमंत्री बनवाये हों, उस प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है ? कम से कम नेता सदन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, एन0एच0ए0आई0 से कहिये कि उत्तर प्रदेश को भी उससे जोड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही दिल्ली की सरकार बनायी है। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) और गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भी मैंने अपने गवर्नर भाषण में कहा था कि गंगा एक्सप्रेस-वे पर आप अपना खजाना क्यों खर्च कर रहे हो, हालांकि खजाने का पैसा, जितनी बड़ी सड़क है, उतना पैसा तो आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका मॉडल दूसरा है। वह मॉडल किसके सिर पर आयेगा, जब सड़क पर गाड़ी चलेगी तो वह किसके सर पर आयेगा ? वह जनता की जेब से पैसा जायेगा। अध्यक्ष जी, शायद वह सड़क पी0पी0पी0 मॉडल पर है ? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि वह पी0पी0पी0 मॉडल पर है तो टोल कितना होगा ? इसलिए मैं नेता सदन की मदद करना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं तो एक इंजन ही क्यों भागे, दूसरा इंजन उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है ? हजारों करोड़ उसके लिए लेकर आइये। एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी। वह बस चल रही है या नहीं चल रही है, उस समय मैंने मांग की थी कि एन0एच0ए0आई0 की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए। दिल्ली सरकार बना सकती है। वह केवल बस चला करके भूल गये। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है ? मैं चाहता हूँ कि यदि कोई सुबह वहाँ से चले, अयोध्या आ जाये, दर्शन करे और फिर वापस चला जाये, कम से कम ऐसी सड़क तो बनाओ। उसके लिए दिल्ली से आप पैसा मांगिये। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, आगरा में लेदर प्रोडक्ट, पता नहीं कितना बजट है इसके लिए। अम्बेडकरनगर को कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट में इसको कवर करेंगे।

अम्बेडकरनगर के लोग बतायें कि उसमें बजट कितना है। आजमगढ़ ब्लैक पॉट्री, बांदा में स्टोन क्राफ्ट के लिए, इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए अगर यह इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लास वेयर का बजट कितना है, हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है। झांसी साफ्ट टॉयज के लिए और कन्नौज परफ्यूम के लिए। मैं नेता सदन से कहूँगा कि हमें गोबर नहीं चाहिए। हमें गोबर प्लाण्ट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लाण्ट को गोरखपुर ले जाइये। हमें अपना परफ्यूम पार्क चाहिए और मैं परफ्यूम पार्क के बारे में बता दूं, वह इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि लोग बेला का, गुलाब का और जो हसाइन के लोग हैं वह भी जानते होंगे कि कन्नौज के लोगों के यहाँ प्लाण्ट लगे हुए हैं। यह बहुत अच्छा कारोबार है और सभी कन्नौज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी और समय के हिसाब से बहुत बड़ा परफ्यूम पार्क बन रहा था कि लोग वहाँ आएंगे और म्यूजियम भी देखेंगे, म्यूजियम के साथ-साथ जो हमारी इण्डस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है उस बढ़ावे के लिए वहाँ प्लाण्ट भी लगना था क्योंकि अभी ट्रेडीशनल तरीके से वहाँ एसेंस निकालते हैं और अगर वह प्लाण्ट लग जाता तो मैं समझता हूँ आपके कन्नौज और यू0पी0 का इत्र दुनिया के इत्रों पर बराबर मुकाबला कर लेता और वहाँ पर समाजवादी इत्र बनता। कुछ मा0 सदस्य जो इत्र व्यापारी के बारे में कह रहे हैं मैंने सुना है उसमें कि उससे कुछ बजट लेकर के छोड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे आप ही लोग मिले हों। उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है। अगर हम एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े देखें कि हम कहाँ दिखाई देते हैं और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस और आम लोगों के लिए कि यह जो आरोप दूसरे दल पर लगाते हैं और यह आप पर किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं, उसे आप देखिये। आप चाहे नेता सदन मैं एक-एक करके पढ़ सकता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिये घूम रहे हैं। यहाँ पर कैसे ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है।

आपने नमामि गंगे में बजट तो बहुत रखा है, उसमें कि माँ गंगा साफ हो जायेंगी, लेकिन माँ गंगा अकेली नहीं साफ हो सकतीं जब तक कि उसकी सहायक नदियां नहीं साफ होंगी। मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि नमामि गंगा के साथ-साथ जो वरुणा नदी है उसकी सफाई के लिए सरकार क्या कर रही है जो काली नदी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो काली नदी कन्नौज में आकर गंगा से जुड़ जाती है उस काली नदी को साफ करने के लिए क्या इन्तजाम हैं। समाजवादी सरकार में मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी जो न केवल मेरे चाचा हैं वरुणा नदी को साफ करने के लिए इन्तजाम किया गया था और मेरी कोशिश थी कि गंगा से पहले कम से कम एक इक्जामपरी काम करके दिखा दें कि वरुणा नदी बनारस में कैसे साफ बहेगी। जितना काम उस सरकार में हुआ था उससे आगे नहीं

बढ़ पाये हैं वैसे का वैसा ही काम रोक दिया गया है। यहाँ पर गोमती का भी उदाहरण है। गोमती का भी काम देश के लिए एक्जाम्पल होता है। जो लोग यह एक्जाम्पल देते हैं देश के लिए कि साबरमती का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है तो मैं मा0 सदस्यों से कहूँगा कि आप साबरमती को भी देख कर के आईये और साबरमती के बाद अगर आप अपने गोमती को देखेंगे। यह अलग बात है कि जांच चल रही है, जांच चलेगी। लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। यह देश का पहला रिवर फ्रंट होता और मैं तो कहूँगा कि मैंने उस काम को आसान करने के लिए कि काम आसान और अच्छा हो जाय, जो आर्किटेक्ट था साबरमती का, वही आर्किटेक्ट आपकी गोमती का है। जो कान्ट्रैक्टर साबरमती का था, वही कान्ट्रैक्टर गोमती का है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि 900 मीटर के करीब नाले अगर आज भी रुक जायें तो देश के लिए सबसे बड़ा इग्जैम्पिल होगा कि किस तरीके से एक शहर में साफ नदी बहती है। यह एक इग्जैम्पिल था, उसको नेता सदन ने पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया, सी0बी0आई0, ई0डी0 के पास और न जाने कहाँ-कहाँ ? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इससे बेहतर कहीं कोई और रिवर फ्रंट मिल जाये तो बता देना आप। जो-जो चीजें वहाँ हो रही थीं, एक-एक पेड़ लग रहा था। अब नेता सदन को कितना शौक है पेड़ों के बारे में, मुझे नहीं पता। मुझे तो उनका शौक नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक-एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है ? लोग दुनिया में जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर चेरी ब्लाजम होता है। मैं यह दावा कर सकता हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के फारेस्ट के अधिकारी हैं, मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर चेरी ब्लाजम दुनिया के लिए एक फ्लावरिंग ट्री है तो उससे बेहतर ट्री अगर किसी के पास है तो वे भारत में हैं और यू0पी0 में उन्हें समाजवादियों ने लगा करके दिखाया। रिवर फ्रंट के किनारे वे पेड़ लगाये गये जिससे कम से कम सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग देखने को मिले। वह काम रुक गया लेकिन उनके फूल खिलाना नहीं रुके, वे आज भी वहाँ पर खिल रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क मुख्य मंत्री आवास से लेकर आखिर तक जाती है, उस पर भी दोनों तरफ अगर किसी ने सोच करके, समझ करके स्टैटिकली पेड़ लगाये तो समाजवादियों ने लगाये। उस सड़क पर एक फुट ओवर ब्रिज भी बनाया। सरकार जब पिछली बार बनी थी तो हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने, जो उस समय नगर विकास मंत्री थे, इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि मुझे उद्घाटन करना है बहुत जल्दी से तो सोचिए कि इनका पहला उद्घाटन क्या था ? समाजवादी सरकार में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज इनका पहला उद्घाटन था। बतायें वही पहला उद्घाटन हुआ था कि नहीं हुआ था। फुट ओवर ब्रिज, इतने बड़े विभाग के मंत्री और उद्घाटन किसका कर रहे हैं, एक फुट ओवर ब्रिज का और वह भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ। लेकिन नदियां अगर साफ होतीं तो हमारे एक नये मंत्री हैं, गलती उनकी नहीं है। उनको मछली का विभाग मिला, यह अच्छी बात है क्योंकि वे उस समाज से जुड़े हैं तो उन्हें वही विभाग दे दिया गया। लेकिन उनकी गलती नहीं है, वे वहाँ पर जिन्दा मछली लेकर गये, पूरी तैयारी के साथ कि जिन्दा मछलियां जाएंगी और गंगा में छोड़ी जाएंगी।

लेकिन पता नहीं, जैसे ही वे मछलियां माँ गंगा में डाली गईं, सब मर गईं। अध्यक्ष महोदय, वे सब जिन्दा मछलियां थीं। मुझे तो यह लगता है कि नेता सदन ने जहाँ सेल्फी खिंचाई थी, वह प्लाण्ट खराब हो गया जिसकी वजह से गंगा माँ में सब सीवेज जा रहा है और वहाँ डिजाल्व आक्सीजन खत्म हो गई जिससे मछलियां मर गईं। मछलियों के मरने में गलती मंत्री जी की नहीं है। वह जो जिन्दा मछलियां लेकर गये थे और शायद मंत्री जी यहाँ पर होते तो वे यह बात बता सकते थे। वे [xxx] मंत्री, जिन्दा मछली लेकर के गये थे लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ गंगा में मछलियां डालीं, सब मछलियां मर गईं। इसका मतलब यह है कि माँ गंगा में डिजाल्व ऑक्सीजन कम है। अध्यक्ष महोदय, आप मेरा अभी पहले का वह एक शब्द निकलवा देना, स्लिप ऑफ टंग है इसलिए वह शब्द निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री अखिलेश यादव-

तो वह जो माँ गंगा में मछलियां डाली गईं, उसकी वजह से वे मर गईं क्योंकि माँ गंगा में डिजाल्व ऑक्सीजन नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि यह बजट नहीं, बंटवारा है और अगर इसमें कोई बड़ी योजना बन रही हो तो मुझे बताइए कि इस बजट से यह बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता पक्ष के अन्य लोग यह कहते हैं कि हमने इतने एयरपोर्ट बनाये हैं। लेकिन अयोध्या का एयरपोर्ट अभी तक नहीं बन पाया। मैं तो नेता सदन को यह कहूँगा कि आप अपना पूरा ध्यान अयोध्या पर दीजिए। जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइये ताकि आप उतरें, फिर हम भी उतरें उसी एयरपोर्ट पर। जो समाजवादियों ने एयरपोर्ट बनाये, वह अभी तक पूरे नहीं हो पाये। चित्रकूट का किसी समय पर नेताजी ने एयरपोर्ट बनवाना शुरू किया था, उस समय हवाई पट्टी छोटी थी। जब मैं चित्रकूट की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अब तो हवाई जहाज अलग तरह के आने लगे हैं। यदि इस हवाई पट्टी की लेंथ बढ़ जायेगी और हवाई पट्टी चौड़ी हो जायेगी तो बड़े-बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। उसी समय समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया कि जो एक्स्ट्रा लैण्ड है, वह ली जायेगी। चूंकि फारेस्ट की लैण्ड लेनी थी जिस कारण समय लग गया। लैण्ड ली गयी और काम शुरू हो गया लेकिन 5 साल तक सरकार उस पर काम ही करती रही, उसको चालू नहीं कर पायी। मेरठ में भी समाजवादी सरकार का ही है। मुरादाबाद में भी नेताजी का बनाया हुआ एयरपोर्ट है, वहाँ जो हवाई पट्टी बनी थी। कुशीनगर में जो हवाई अड्डा बना है, वह समाजवादी सरकार में बजट देकर बना है। समाजवादी सरकार ने इसमें बजट दिया था। जो उस विभाग के मंत्री रहे होंगे, उन्होंने तो फाइल देखी होगी लेकिन हमें डर यह लगता है कि मा0 सदस्य एक दिन कुछ कह रहे थे कि यह एयरपोर्ट बन तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नयी

[xxx] मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया है।

स्कीम चल रही है 'वन नेशन और वन पूंजीपति' तो कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी सरकार का बना हुआ है। आजमगढ़ का तो पता नहीं क्यों शुरू नहीं किया गया ? मैं कई बार उस एयरपोर्ट पर उतरना चाहता था, मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिख कर दिया तो उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। एक दिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जरा देखकर आइये कि काम चल रहा है कि नहीं तो वह बोले कि काम सब पूरा हो चुका है और बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने फिर जिलाधिकारी से पूछा कि काम तो पूरा हो गया है, सब साफ है हवाई पट्टी पर तो उन्होंने कहा कि अभी टेक्निकल टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन ज्यादा आया है। अब पता नहीं कि फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है जिसकी वजह से आज तक आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने दिया। मुझे तो लगता है कि समाजवादी सरकार ने बनाया था, इसलिए चालू नहीं होने दे रहे हैं। एक रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनी थी लॉजिस्टिक्स, तो यह कहते हैं कि आप बिल्कुल बगल में उतरें। हेलीकाप्टर से उतर कर तुरन्त पहुंच जाये। अब सोचिये, नेता सदन आप इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग जा रहे होंगे परन्तु कहाँ उतरेंगे लखनऊ में ? आपने अगर काम पूरा कर दिया होता तो आपको लखनऊ नहीं उतरना पड़ता। आप बगल में उतर जाते और वहाँ से 2 मिनट, 5 मिनट की फ्लाइंग में आप कार्यक्रम में पहुंच जाते। एक बार जरूर वहाँ पर कोई हवाई जहाज उतरा था और जब हवाई जहाज उतरा था तो उसमें कुछ उद्योगपति बैठकर गये थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम कायाकल्प कर देंगे और न जाने कितना इन्वेस्टमेंट ले आयेंगे, वह एक बार हवाई जहाज उतरा और उसके बाद दोबारा हवाई जहाज उस पर नहीं उतरा। जब एक बार थोड़ा पानी ज्यादा बरस गया और लोगों के घर में पानी भराव हुआ तो वहाँ के लोगों को पुलिस ने पीटा क्योंकि उन्होंने पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। जो हवाई पट्टियां हैं, वह मुरादाबाद में समाजवादी सरकार की बनी हुई हैं, आजमगढ़ में समाजवादी सरकार की बनी हुई है, चित्रकूट में नेताजी ने बनवायी, झांसी का कब पूरा होगा ? ललितपुर में कहाँ जगह चिन्हित है ? सोनभद्र में बहुत पुरानी हवाई पट्टी है, मेरठ के लिए समाजवादी सरकार में ही फैसले लिये गये थे। मैं चाहूँगा कि आप अयोध्या का एयरपोर्ट बहुत जल्दी बनवा देंगे। हमें इस बात की खुशी होगी कि आप उतरें और उसके बाद हम लोगों को भी उतरने का मौका मिलेगा।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

उसको कोई नहीं रोक सकता। जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा था और मैं आज भी कहता हूँ कि कई बार प्रोजेक्ट्स से लैण्ड एक्यूजीशन के इश्यू आ जाते हैं तो समय पर लैण्ड नहीं ले पाते हैं। जब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बना था, उस समय लैण्ड एक्यूजीशन की दिल्ली में बहस चल रही थी। मैंने जगह-जगह पर किसानों से बातचीत की और किसानों से राय-मशविरा करके जो किसानों के सुझाव थे, उनको शामिल किया। कई जगह पर मुझे सर्किल रेट बढ़ाना था तो मैंने सर्किल रेट

बढ़वाया। सर्किल रेट बढ़वा कर मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जायें यदि एक भी जगह किसी एक भी किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैण्ड एक्यूजीशन नहीं हुआ जितने कम समय में लैण्ड एक्यूजीशन समाजवादी पार्टी की सरकार ने आगरा-लखनऊ में करके दिखा दिया और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में किया। वहाँ भी कोई इश्यू नहीं आया। अगर इश्यू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर्ड न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती तो सी0बी0सी0 ऐक्ट के तहत जब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा जमीन एक्वायर्ड नहीं होगी तब तक आप टेण्डर नहीं कर सकते क्योंकि जमीन एक्वायर्ड से ले करके करार 70 प्रतिशत तक हो गये थे इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में वो टेण्डर हो गये थे। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद में किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे समय-समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है उसके लिए सरकार को अगर 6 गुना सर्किल रेट बढ़ा करके किसानों को मुआवजा देना पड़े तो दे देना चाहिए। आपको सब किसान जमीन दे देते। लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गये ? आप फैसला लीजिये, कलम उठाईये और 6 गुना सर्किल रेट कर दीजिये, कोई रोक दे तो आप मुझे बताइये। वैसे तो कहते हैं लोग कि आप बहुत सख्त हो, लेकिन आप किसानों के लिए सख्त नहीं हैं। सर्किल रेट बढ़ाने के लिए कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा। आप 6 गुना सर्किल रेट बढ़ा दीजिये आपको 02 दिन में जमीन न मिल जाये तो कहियेगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई। आपने जैसी कार्यवाही गाजियाबाद में की है आप अयोध्या में भी वही कार्यवाही कर दीजिये। मुझे उम्मीद है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

मण्डी को ले करके सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल के पैदावार की एम0एस0पी0 दिलवायेगी। पिछली बार धान की कीमत सरकार दिला पायी हो तो जो माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं वह बता दें। माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कि कितने किसानों को धान की कीमत मिल गयी थी। उसके बाद अब गेहूँ की जो कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली वो मार्केट की वजह से मिली। सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कम्पनियों को कि जाओ जितना गेहूँ खरीदना चाहो खरीद लो। सब गेहूँ खरीद गया। सरकार बताये कि इन्होंने कितना गेहूँ खरीदा। अगर गेहूँ खरीद की तो सरकार वो आंकड़े बतायेगी कि सरकार ने कितना खरीदा ? ये सही है और हमें खुशी है कि किसानों को कीमत मिल गयी लेकिन आपने अपने लोक कल्याण के संकल्प-पत्र में कहा है कि हम किसानों के लिए विशेष योजना भामा शाह योजना चलायेंगे। आप किसानों को एम0सी0पी0 दीजिये, बोनस दीजिये। क्यों नहीं देते किसानों को ? आप किसानों को बोनस नहीं देना चाहते थे। आप चाहते थे कि प्राइवेट लोग खरीद लें और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे तो कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा। तो सोचो कितना मुनाफा वो

लोग कमायेंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मुनाफा कमाने के लिए मौका दिया। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन कई पूंजीपति। आटे की कीमत क्या होगी और महंगाई के आंकड़े हमारे सदस्यों ने कई बार दिये हैं कि बाजार में आंकड़े क्या हैं और सरकार कहती है कि वह महंगाई नहीं रोक सकती। तो फिर सरकार किस बात के लिए है। आज आपकी हर चीज महंगी होती चली जा रही है। सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गयी, गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, आपने बिजली कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइण्ड कितना महंगा कर दिया, जरूरत की हर चीज महंगी कर दी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आप तो कह रहे थे कि नोटबन्दी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा, काला धन वापस आ जायेगा। आर0बी0आई0 की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी। आर0बी0आई0 ने क्या कहा है कि 5 सौ के नोट और 2 हजार के कितने फर्जी नोट बाजार में आ गये हैं। आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जी0एस0टी0 लगाकर कह रहे थे कि बाजार हमारा छा जायेगा, उद्योग कारोबार बढ़ जायेगा। वित्त मंत्री जी बतायें कि दिल्ली की सरकार जी0एस0टी0 का आपका कम्पनसेशन बहुत जल्दी बन्द करने जा रही है। आप कहाँ से उतने कम्पनसेशन के गैप को फुल-फिल करेंगे ?

आप वह फुल-फिल कहाँ से करेंगे ? इसलिए मैंने कहा कि जब जी0एस0टी0 बन्द हो जायेगी। आप तो उस जी0एस0टी0 को मान रहे हैं कि जितना पिछले वर्ष में आपको जी0एस0टी0 का कम्पनसेशन मिलता था, उसी हिसाब से आपको इस बार कम्पनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिये आपको दिल्ली की सरकार ने वह कम्पनसेशन नहीं दिया तो उस गैप को यह सरकार कहाँ से फुल-फिल करेगी ? यह तो डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार पेड़ लगाने में भी बहुत आगे है, पर इयर [Per Year] न जाने कितने पेड़ लगाती है ? 2017-18 में कहा कि कई करोड़ पेड़ लगायेंगे। इस बजट में आपने 35 करोड़ पेड़ लगाने को कहा है, पहले आपने कुछ कम पेड़ लगाये थे। सरकार कह रही है कि हम इतने पेड़ लगायेंगे। मुझे याद है जब मैंने एक जगह पर प्लाण्टेशन किया और मैं ग्रीन प्लाण्टेशन करता था, एक ग्रुप बना करके, ग्रुप प्लाण्टेशन और ग्रीन बेल्ट क्रियेट करता था। हो सकता है कि आंकड़े थोड़े आगे-पीछे हों, 1 लाख 24 हजार पेड़ लगवाये थे और वह 1 हजार एकड़ में लगे थे। 1 हजार एकड़ में लगभग 1 लाख 24 हजार पेड़ लगे थे। आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे ही नहीं जा रहे हो। इस बार बजट में कहा है कि 35 करोड़ पेड़ लगायेंगे। क्या आप गमलों में लगा रहे हैं, सड़क पर गमलों में लगवा रहे हैं, क्या गमलों में भी पेड़ गिन लेते हैं, घास गिन ली तब तो लग ही गये होंगे और लखनऊ में ही इतनी घास लग गई होगी। अगर 1 हजार एकड़ में 1 लाख 24 हजार पेड़ लगते हैं तो 35 करोड़ पेड़ों के लिए आपके पास जमीन कहाँ है, आप हमें यह बतायें कि कहाँ जमीन है ? मुझे इस बात की खुशी है कि नेता सदन को

जानवरों का भी शौक है। जानवर के साथ आपकी तस्वीर आती है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैंने लायन सफारी इसीलिए बनाई थी कि बच्चे जाकर लायन सफारी देखें। मैंने विभाग के मंत्री जी से कहा कि वहाँ पर लेपर्ड, तेंदुआ आ गया है, वह ब्लैक बक और हिरण को खा चुका है। कुछ अधिकारियों ने भागदौड़ की है लेकिन अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। अभी सुनने में आया है कि कतर्निया घाट में एक बच्ची को तेंदुए ने मार दिया तो लोगों के अन्दर गुस्सा आया और लोगों ने वन विभाग की पुलिस पर अटैक कर दिया, वह घटना घट गई। इससे पहले भी लेपर्ड को किसानों ने मार दिया था, पूरे के पूरे गांव पर मुकदमे दर्ज कर दिये गये। यह जिम्मेदारी वन विभाग की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसलिए मैं नेता सदन से कहूँगा कि आपने चिड़ियाघर तो अच्छा बनवा लिया, उसके लिए कॉरपस फंड भी आपने 50 करोड़ डाल दिया ? लेकिन दूसरे जानवरों को आप क्यों भूखा रखना चाहते हो ? जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वह स्टेट के लिए उपलब्धि थी, लेकिन सरकार ने उस उपलब्धि का क्या किया ? लायन सफारी, एनिमल सफारी, हो सकता है कि हमने और नेताजी ने बनवाई हो। लेकिन वह इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से आपके विधायक हैं, हमारे विधायक नहीं हैं, फिर आपको क्यों भेदभाव है ? आपको यह याद रखना चाहिए कि नेता सदन, जो आप शेर लेकर गये हैं, उसको इटावा वालों ने खिलाया-पिलाया है। अगर खिलाया-पिलाया नहीं हो तो आप बताइये। मोटा-तगड़ा करके गोरखपुर भेज दिया। ध्यान रखियेगा कि वह कमजोर न हो जाये। (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

यह सरकार कह रही है कि सैनिक स्कूल बनवायेंगे। आपने सैनिक स्कूल कहाँ बनवाया ? वित्त मंत्री जी, आप बताइये कि आपने कहाँ सैनिक स्कूल बनवाया है ? माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या सैनिक स्कूल छायापुर में बन गया ? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बन करके तैयार हो गये थे, वह स्कूल चालू भी हो गये थे, एक स्कूल बाद में आपकी सरकार में चालू हुआ। अगर आप राष्ट्रवादी हैं और आप कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट ही नहीं हैं, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम देशभक्त ही नहीं हैं। हम बनायें सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर बच्चों को लड़ने के लिए तैयार करें। लेकिन आप कहते हैं, हम राष्ट्रभक्त ही नहीं हैं। आप राष्ट्रभक्त हो, आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा ? और आपने सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनवाये, सैनिक स्कूल उस समय मुझे दिल्ली की सरकार ने दिये थे। वह अमेठी में एक सैनिक स्कूल दे रहे थे लेकिन मैंने कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं लूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल देना चाहते हैं तो मुझे दो और सैनिक स्कूल दीजिये तो मुझे खुशी है उस बात की कि दिल्ली की सरकार ने मेरी वह बात मानी। एक अमेठी में, एक मैनपुरी में, जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया है। आज यू0पी0 में चार

सैनिक स्कूल हैं और 5 साल से यह राष्ट्रवादी सरकार है, आपने कौन-सा नया सैनिक स्कूल बनाया है यह बता दीजिये। आपने एक भी सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिये और फिर जो बजट देना चाहिए था उसके लिए अब दिया है। पहले आपने सैनिक स्कूल के लिए बजट क्यों नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से एक संस्कृति स्कूल है, जहाँ पर बड़े-बड़े लोग जाते हैं और वह उन स्कूलों में एडमिशन नहीं पाते हैं, एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या-क्या तरीका अपनाते हैं, उस संस्कृति स्कूल में दिल्ली में किसी को एडमिशन नहीं मिल पाता है। उस समय अधिकारियों की बैठक हुई और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह संस्कृति स्कूल यहाँ बनाना चाहते हैं मैंने उसको स्वीकार किया। दिल्ली के बाद अगर कहीं संस्कृति स्कूल बना है तो लखनऊ के चक गंजरिया में समाजवादी सरकार ने बनाया है लेकिन अगर उसके पास जाकर देखें क्या दुर्दशा है बर्बाद कर दिया। मैं तो कहता हूँ जब आप सरकार वाले बोलते हैं कि हमारा स्कूल देखो। आप संस्कृति को तैयार कर दीजिये और दिल्ली वालों से कहो कि आओ संस्कृति स्कूल देखो किसका बेहतर है और मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली वालों को बुलाओ और कहिये कि सैनिक स्कूल देखिये आप उसकी डिजाइन देख लो, एरिया देख लो किस तरीके से बन रहा है लेकिन आप रुचि नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं आप। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं क्योंकि बजट हमारे पास सीमित था, उस समय एक सैफई में और एक लखनऊ में मैंने एक नये तरीके का स्कूल बना करके दिया था और मैंने विभाग से कहा कि इसके मानक जो बदलने हैं बदल लो लेकिन यह मॉडल है इसको तैयार करिये आप और जहाँ आपको स्कूल नये बनाने हैं इसी तरह प्राइमरी स्कूल बनायें। वह दो बन गये हैं लखनऊ का तो आप नाम बदलकर चलाना चाहते थे लेकिन जनता के विरोध में केवल नाम लिख पाये मंत्री वहाँ उद्घाटन नहीं कर पाये लेकिन सैफई से इनका रिश्ता कुछ अलग है, सैफई क्यों पसंद करेंगे, इसलिए वैसा का वैसा आज भी पड़ा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं चलाईये आप सैफई में। कम से कम नेता सदन 5 साल हैं आपके पास, उसी की नकल करके गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों स्कूल नहीं बनवाते हो आप और अगर उससे बेहतर बना सकते हो तो बनाईये उससे बेहतर।

जो चीनी मिल का मामला है, सरकार हमेशा यह कहती है और बजट में भी सरकार ने लिखा है कि हमने चीनी मिलों का इतना भुगतान किया है, अच्छी बात है भुगतान होगा और हर बार जैसे-जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे-जैसे शुगर कन्टेन बढ़ेगा आपका भुगतान ज्यादा होगा। सरकार यह कभी नहीं बताती है कि बकाया कितना है, जितनी भी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलें हैं, हमारे वित्त मंत्री जी और नेता सदन यह बतायें कि कितना बकाया है अभी जो मुझे जानकारी मिली है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में बड़े पैमाने पर चीनी मिलों का पैसा बकाया है। एक-एक चीनी मिल का बकाया है और जो बजट में दिया है, वह बजट सहकारी चीनी मिलों का है सरकार की चीनी मिलों का है तो क्या जो बजट दिया गया है उससे

पूरे किसानों का भुगतान हो जायेगा ? यह सरकार हमें बताये। यह जो भुगतान अभी बकाया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो बजट में पैसा रखा है क्या उससे किसानों का जो चीनी मिल का बकाया पैसा है उसका भुगतान हो जायेगा ? अगर भुगतान हो जाये तो सरकार बताये। इसीलिए मैंने कहा कि यह बजट केवल सपने दिखाने का है।

यह सरकार कहती है कि हम बसों को अच्छा करेंगे और बसों में सबसे ज्यादा गरीब चलते हैं और करोड़ों-करोड़ लोग उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बड़ी संख्या में सरकार के पास बसे हैं, मुझे याद है जब मजदूर पैदल-पैदल चल रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि सरकार के पास इतनी बसे हैं कि कोई मजदूर पैदल नहीं चलता उसे घर पहुंचाया जा सकता था लेकिन सरकार बस की लड़ाई में फंस गई और अपनी बसें नहीं चलाईं और पांच साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिशील है। आपको अगर ढूंढ़ने से कोई बस स्टेशन मिला तो केवल समाजवादी सरकार में बना हुआ बस स्टेशन मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री जी पता नहीं आपने ऐसा कैसे लिख दिया, हो सकता है कि नेता सदन ने भाषण को न पढ़ा हो। आपको अगर कोई एसग्जाम्पिलरी काम दिखाई दिया तो वह समाजवादी सरकार का दिखाई दिया है। आप यकीन मानिये अध्यक्ष महोदय यह सबसे अच्छा एक बस स्टैण्ड बना करके तैयार किया गया था, सरकार चाहे तो अपने बजट से या पी0पी0पी0 मॉडल पर बनाये, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर पांच साल आप क्यों सोते रहे, आपने आलमबाग बस स्टैण्ड ही नहीं देखा था। यह हमारी गलती हुई कि जिसने बनाया था मुझे पहले ही उसे आपकी पार्टी में भेज देना चाहिए था, क्योंकि मैंने देरी की इसलिए बस स्टैण्ड बनने में देरी हो गई। जब तक आपके पास स्वीटनर अच्छे नहीं होंगे तब तक यह मॉडल आपका कामयाब नहीं होगा, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि अगर सरकार अपने बजट से बनायेगी तो अच्छा है। मान्यवर, बसों की हालत सभी लोगों ने देखी है, हर दिन यात्री उतरकर बस को धक्का लगाते हैं तब बस चलती है, हर दिन अखबार में ऐसी तस्वीर मिल जाती है। एक्सीडेंट तो अलग है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने स्कैनिया की नई बसों को लेने की तैयारी की थी और अगर सरकार पांच साल में बसेज लेती तो आज बहुत बड़े पैमाने पर नई बसेज मिल जातीं जिससे हमारे गांवों के गरीब आदमी चल सकते। आज भी मैं सड़क पर कभी-कभी देखता हूँ, इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन किसी-किसी जगह पर मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई पड़ जाती है, अब उन्हें छोड़ देना उनमें पेंट मत लगाना, अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढ़ना। मान्यवर, 2 हजार बसें खरीदने जा रहे हैं, पता नहीं कब खरीदेंगे 2 हजार बसें। जो

आप आलू पर एमएसपी देने की बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ माननीय सदस्य ऐसे क्षेत्रों से जीत करके आते हैं जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आलू होता है। आलू के काम में, आलू के कारोबार में कभी-कभी नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। पिछली बार भी सरकार ने कहा था।

श्री अध्यक्ष-

आलू की फैक्ट्री तो नहीं लगा रहे हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

मैं आलू के बारे में जानता-समझता सब-कुछ हूँ। मेरा सुझाव नेता सदन नहीं मानेंगे। हालांकि मैंने पब्लिक प्लेटफार्म पर सुझाव दिया था, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था मैंने मंच पर सुझाव दिया था अगर नेता सदन उनका सुझाव मान लें तो आलू की समस्या कुछ हद तक समाप्त हो सकती है। मा0 अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि आलू के लिए हमने एक फण्ड बना दिया है, आलू के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। वह फण्ड बना लेकिन किसी की मदद नहीं हुई। जिन किसानों का कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ गया, वो दुःखी थे। उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम जाकर आलू मा0 मुख्य मंत्री जी को दे आयेंगे। वो नये किसान थे, कभी लखनऊ नहीं आये थे। वे किसान यहाँ पर आलू लेकर आये और जो सबसे बड़ा घर दिखाई दिया, वहीं आलू फेंक दिया। उन्होंने किसी को बताया कि आलू फेंक दिया है, ये किसका घर है, तो पता चला कि ये तो गवर्नर साहब का घर है। किसान बोले मुख्य मंत्री जी का घर कहाँ है ? तो वो बोले कि आपको इधर से जाना पड़ेगा। वो किसान नहीं जानते थे कि मुख्य मंत्री जी कहाँ रहते हैं ? वो आलू ले जाकर मुख्य मंत्री जी के यहाँ छोड़ आये थे। वो आलू आपको दिखाना चाहते थे। आपने किसानों को एम0एस0पी0 नहीं दी, उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्हें बाद में क्या मिला ? सी0सी0टी0वी0 से गाड़ी का नम्बर देखकर/ढूंढ़कर उन्हें जेल भेज दिया। अब आप कह रहे हैं कि आलू पर एम0एस0पी0 देंगे और एक अन्य फसल पर भी कहा है। आपने दो फसलों पर कहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

टमाटर और प्याज पर भी।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 वित्त मंत्री जी, टमाटर पर नहीं दे पायेंगे, लेकिन अगर टमाटर पर भी देंगे, तो बहुत खुशी की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई दूंगा, अगर ये किसानों को आलू की कीमत दे दें और एक कदम ये और आगे गये हैं कि टमाटर और प्याज पर भी देंगे, तो हमारे मैनपुरी जिले के लहसुन को क्यों भूल गये ? तो आप अब देंगे कहाँ पर ? जो मण्डियां बन रही थीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो आपने पूरा नहीं किया। यहाँ जितनी पुरानी मण्डिया बनी थीं, चाहे

जालौन की बनी हों, झांसी की बनी हो, ललितपुर की बनी हो। पिछली सरकार में बुन्देलखण्ड पैकेज में हर जिले में मण्डी बनी थी, लेकिन आप कोई मण्डी नहीं चला पा रहे हैं। एक्सप्रेस-वे के किनारे मण्डियां बननी थीं। इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया बने, वह ठीक है, लेकिन वो मण्डियां भी बननी थीं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कन्नौज में आलू की विशिष्ट मण्डी बनायी थी। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूँ कि आपने वो मण्डी क्यों रोक दी ? पांच साल से मण्डी में ऐसे ही काम चल रहा है। मेरा वहाँ पर कोई खेत नहीं है। मैं वहाँ से केवल चुनाव लड़ता हूँ, तो कम से कम किसानों के लिए वो मण्डी बना दें। पूर्वांचल में गाजीपुर, आजमगढ़ और अम्बेडकरनगर में मण्डी बननी थी। क्या आपने एक्सप्रेस-वे के किनारे मण्डी बनायी है ? अभी तक आपने जगह नहीं ली है। इसलिए वो बातें मैं कह चुका हूँ।

दिल्ली से तो एक लाख करोड़ रुपये मण्डियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहा था, वो पैसा कहाँ है ? अगर हमारी मण्डियां नहीं होंगी, तो हम अपने किसानों को एम0एस0पी0 कहाँ से देंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप एम0एस0पी0 देने की बात कह रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बताइये कि मंडियों को बेहतर करने के लिए क्या हम ये इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ? हम न केवल सरकारी मण्डी बना रहे थे, बल्कि हमने बाबा रामदेव जी को भी एक जमीन मण्डी बनाने के लिए दी थी। बाबा रामदेव जी योग के बाद मण्डी बनाना चाहते थे, उन्होंने भी अभी काम शुरू नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि वो भी अपनी एक नई मण्डी बना देंगे। जिससे कम से कम किसानों को सुविधा मिल सके और जो दावा सरकार कर रही है कि एम0एस0पी0 मिलेगी, वो वहाँ पर मिल जाये। इसलिए जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम बेहतर नहीं होगा, तब तक कुछ कर पाना सम्भव नहीं होगा। आप जो बजट में हमें इतने बड़े-बड़े आंकड़े दिखा रहे हो, आप बजट तो दिखा रहे हो, लेकिन खर्च कितना करते हो, आपको खर्च बताना चाहिए। खर्च में हर विभाग में आप नीचे जा रहे हैं। जितना आपको खर्च करना चाहिए, उतना आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बजट तो है, लेकिन ये बंटवारे वाला बजट है।

जो बात मैं भूल गया था, समाजवादी सिद्धान्त की। जो लोग कभी-कभी समाजवाद के बारे में थोड़ा-बहुत पढ़ लेते हैं, ट्वीट कर देते हैं, कभी-कभी प्रेस में कह देते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने एक किताब लिखी थी हिन्दू बनाम हिन्दू। उसका मैं केवल दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी मा0 सदस्यों को ये किताब भिजवाऊंगा। वो किताब मैं पढ़ता हूँ कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिन्दू धर्म में उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई पिछले पांच हजार सालों से भी अधिक समय से चल रही है और उसका अन्त अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोई कोशिश भी नहीं की गयी, जो होनी चाहिए थी। किस लड़ाई को नजर में रखकर हिन्दुस्तान का इतिहास देखा जाय। उसे भुनाया जाय।

लेकिन देश में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय में उदारवादियों और कट्टरवादियों में लड़ाई हुई है। लेकिन हिन्दू धर्म के अलावा वे बंट गये अक्सर उनमें रक्तपात हुआ और थोड़े या बहुत दिनों लड़ाई के बाद वो झगड़े पर काबू पाने पर कामयाब हो गये। हिन्दू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरवादियों का झगड़ा चला आ रहा है। जिसमें कभी एक की जीत होती है कभी दूसरे की, खुला रक्तपात तो कभी नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा आज तक हल नहीं हुआ और झगड़े के सवालों पर एक धुंध छा गयी है। तो मैं चाहूँगा यह किताब आप पढ़ेंगे तो शायद कभी-कभी जो सवाल आप मुझसे करते हैं समाजवादी होने का और समाजवाद को लेकर जो चर्चा करते हैं उस पर भी कभी-कभी आप सवाल खड़े करते हैं और जो पिछड़ों की बात करते हैं हमारे यहाँ जितने समाजवादी लोग हैं कभी पुराने समाजवादियों ने नारा दिया वह आज भी नारा लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी ओर सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य हैं पिछड़े हों या बहुजन के लोग हों, लेकिन वो नारा नहीं लगा सकते। क्योंकि वो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते, पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते हैं। बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं और यह बात अगर सच नहीं है तो मैं अपने भाइयों से कहूँगा जो उधर बैठे हैं, हमारे मा0 सदस्य अभी कह रहे थे कि जातीय जनगणना हो, क्यों आप तैयार नहीं हैं जातीय जनगणना के लिए। आज टेक्नोलाजी है और आप बहुत-बहुत बड़े डेटा सेण्टर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आपके पास किसानों का, 2 करोड़ 47 लाख लोगों का डेटा है, आपके पास शौचालय बनाने का डेटा है, आपके पास और भी बहुत कुछ डेटा है। क्यों आपके पास जातियों का डेटा नहीं है। आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच नफरत फैलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पाये सौ में साठ बताइये कितने सत्ता पक्ष के सदस्य यह नारा लगा सकते हैं और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र जी से सीखा और जनेश्वर मिश्र जी से इसलिए सीखा वह हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, और भी बड़े नेता थे, इसीलिए अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। इसीलिए हम कहते हैं जो कभी एक नारा दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप यह नारा लगा पायेंगे ? मैं लोहिया जी के बहुत से नारे पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। जब आप डेटा सेंटर बना रहे हैं डेटा सेंटर में आप बड़ी-बड़ी कम्पनियों का इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं तो अपने लोगों का डेटा क्यों ना हो। हमेशा-हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म कर दो। हमेशा-हमेशा के लिए लड़ाई खत्म कर दो। आप गिन लीजिए आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान दे दीजिये। न जाने कितनी नौकरियां चली गयीं, मैं उन बातों को पढ़ चुका हूँ। मैं

उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले जहर फैलाने का काम करते हैं। वो न किया जाये। अमृत महोत्सव मनायें, लेकिन भाईचारा भी बढ़ायें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि बहुत लम्बा भाषण हो गया मेरा और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सरकार जो अपने बजट को ले करके आयी है बजाय खर्च करने की बात कहें और वहीं खर्च करने के साथ-साथ उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे। जमीन के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है जिस प्रकार वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की योजना तत्काल लेकर आयें।

केन्द्र सरकार जनवरी, 2022 का डी0ए0 घोषित कर चुकी है, परन्तु राज्य कर्मचारियों का जनवरी, 2022 का डी0ए0 घोषित नहीं किया गया है, डी0ए0 घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करे। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान रोक दिया गया था, अब राज्य कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ते को बहाल किया जाय, यह हमारे सभी विपक्षी दलों की मांग है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासों में दिव्यांग कार्मिक को उनकी सुविधानुसार भू-तल पर आवास दिये जाने की सुविधा भी दी जाय। ये तमाम सुझाव हैं। तृतीय श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर रखे गये कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 25 हजार रुपया किया जाये। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मैं तो यह कहूँगा कि हमने अपने मेनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है ? हमने तो अपने मेनिफेस्टो में कहा था कि धीरे-धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप संविधान से दिया हुआ हमारा हक और सम्मान छीन रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) ये आखिरकार रिसोर्सेज हमारे हैं, इन रिसोर्सेज का बंटवारा आबादी के हिसाब से हो, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे सबके हैं, अकेले किसी एक के रिसोर्सेज नहीं हैं। इन रिसोर्सेज के बंटवारे के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बन्द होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 68,500 शिक्षक भर्ती की भर्ती के बाद उनके प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए वेतन भुगतान रोका गया था, सत्यापन कार्य अब पूर्ण हो चुका है, परन्तु अवशेष वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, इसका भुगतान शीघ्र कराया जाय। साथ ही साथ जो आपने अपने संकल्प-पत्र में कहा है कि हम नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरियों के सभी पद भरे जायेंगे। जो सरकारी नौकरी रुकी पड़ी हुई है, वह कब पूरी होंगी। साथ ही साथ जो पेपर आउट, पेपर लीक में बड़े पैमाने पर नौकरियां फंस गई हैं, कुछ आरक्षण को लेकर नौकरियां फंस गई हैं। एस0आई0 की भर्ती में

इतना बड़ा घोटाला, जहाँ पर 100 से ज्यादा लोग पकड़े गये हों उसकी भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है ? जबकि सब चीजें सामने हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन चीजों पर भी सरकार विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी, अपने सभी साथियों का तथा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत देर से हम लोग नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुन रहे थे। बजट पर बोलने के बजाय उनका पूरा ध्यान समाजवादी व्यवस्था को ले करके था। सामान्यतया हम सब जानते हैं कि बजट पर जब चर्चा होती है तो देश के डेवलपमेंट के बारे में, प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के बारे में, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के बारे में, किसानों, महिलाओं, नौजवानों के बारे में चर्चा करके चिंता करने का काम करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अपना पूरा भाषण समाजवादी पार्टी को ही विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए किया। साथियों हम सब जानते हैं। चूंकि अभी जून आने वाला है और बच्चों की मई की छुट्टी चल ही रही है। हमें बचपन के दिन याद आते हैं जब गांवों में छुट्टियां होती थीं, तब मनोरंजन के साधन इस प्रकार के नहीं थे। गांवों में बहरुपिया आते थे, तरह-तरह का वेष धर करके आते थे, वही व्यक्ति पहले दिन लैला-मजनू बन करके आता था, वही व्यक्ति दूसरे दिन हीर-रांझा बन करके आता था, वही व्यक्ति अगले दिन बड़ा डाकू बन करके आता था और उसके अगले दिन वही व्यक्ति पुलिस का दरोगा बन करके आता था। मित्र समाजवादी साथी जो इस प्रकार का भाषण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से नकली समाजवादी हैं और नकली समाजवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को चिंतक, विचारक दिये हैं, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान रचनाकार दिये हैं, पं0 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि दिये हैं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि समाजवाद और समाजवादी का मतलब क्या होता है ? अगर देखा जाये तो असली समाजवादी आचार्य नरेन्द्र देव जी, डॉ0 लोहिया जी तथा श्री राज नारायण जी थे।

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में स्वर्ग में बैठकर तीनों सोच रहे होंगे कि हमारी मार्केटिंग करने वाले लोग किस ढंग से हमारे नाम को बेचकर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। वैसे किताबों में लिखा है चूंकि समाजवाद के दर्शन को किताब के माध्यम से वह समझाने आये थे। समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है, समाजवादी व्यवस्था में धन, सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जब-जब समाजवादी सरकार आयी, समाजवाद की जो परिभाषा है, इन लोगों ने उसके विपरीत काम किया है। इन लोगों ने कभी भी व्यवस्था का नियंत्रण समाज के हाथ में नहीं दिया। इन्होंने अपने परिवार को, अपने लोगों को उत्तर प्रदेश के पूरे बजट को किस प्रकार से बांटा जाये, उस पर ही चिन्ता करने का

काम किया है। ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी सी0ई0एम0 जोड ने इंग्लैण्ड में समाजवाद को एक ऐसी टोपी कहा है जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। देश की आजादी की लड़ाई में तो हमने जवानी को कुर्बान होते देखा है। हंसते-हसंते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। नेता प्रतिपक्ष चले गये, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने जा रहे थे तो इसी प्रदेश के लोगों ने जवानी कुर्बान गैंग को भी सुना था। पूरे प्रदेश में नारा लगता था ये जवानी तेरे नाम, ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। वह जवानी कुर्बान गैंग आज कहाँ है, मुझे दिखती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तब इन लोगों ने पूरे बजट का वितरण जिस ढंग से किया उस सम्बन्ध में हमें अन्दर की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा।

जब वर्ष 2022 में दोबारा आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने मुझे विक्रमादित्य मार्ग पर आवास एलाट कर दिया। जो आवास आवंटित हुआ वहाँ पर सफाई के दौरान मुझे कुछ डायरियां मिली थीं। हमने कहा कि देखिये कबाड़ में कुछ डायरियां हैं, उसमें जरूर कुछ आवश्यक मिल सकता था। मेरे हाथ जो डायरी लगी मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। उस डायरी में पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को किस प्रकार से बांटा गया था, वह मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह डायरी हमें सार्वजनिक स्थल पर मिली थी, उसमें साफ-साफ लिखा था कि उत्तर प्रदेश के बजट का किस प्रकार से वितरण किया जायेगा, उसमें लिखा था कि जी बटोरेगा, कोई 'जी' नाम का व्यक्ति है जो पैसे को बटोरेगा और 'एस' को जमा करेगा, लेकिन 'जी' इतना महत्वपूर्ण है कि मुखिया की बात को नहीं सुनेगा यानी तत्कालीन मुख्य मंत्री की बात को वह नहीं सुनेगा। 'एस' जो पैसा बटोरेगा, वह 'ए' के लिए जमा करेगा, लेकिन 'ए' को नकद नहीं देगा बाद में हस्तान्तरित करेगा। 'आर' जमा धनराशि का प्रबन्ध करेगा। जो 'आर' नाम का व्यक्ति है वह जमा धनराशि का प्रबन्धन करेगा और 'एन' की भूमिका पूरी व्यवस्था को संयोजन करने की होगी। मेरे समाजवादी मित्र जो जान रहे होंगे, वह इसकी डिकोड कर सकते हैं। इसकी डिकोड हमें नहीं मिली है कि 'एन', 'ए' और 'एस' कौन है, लेकिन समाजवादी साथी जानते होंगे। चले गये नहीं तो अपने मित्रों की बातों को सुनते हुए उन्हें जरूर अच्छा लगता। उत्तर प्रदेश के विकास की बजाय, जब-जब यह लोग सत्ता में रहे चाहे इनके पिताश्री रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, प्रत्येक जनपद दलालों का अड्डा बन गया था। लखनऊ में तो दर्जनों अड्डे खुले थे। जिस नोएडा की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, उस नोएडा की जमीनों को खुलेआम पूरे देश में लूटा और बेचा गया और पैसे सरकारी फण्ड में नहीं जमा हुए बल्कि अपने व्यक्तिगत फण्ड में जमा हुए। जो बिल्डर पैसा नहीं दे पाया, उससे इन लोगों ने पैसा नहीं लिया कहा कि आधी जमीन हमारे नाम पर एलाट कर दो। अगर जांच हो जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। नोएडा, गाजियाबाद हर जगह को इन लोगों ने दलाली और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ था।

मान्यवर, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग इनके सामने क्या था। ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के अड्डे थे। एक प्रकरण हम सभी को याद होगा सदन में सभी पुराने साथी बैठे हैं एक मंत्री खनन विभाग के मंत्री थे राज्य मंत्री थे 15 दिन पहले बर्खास्त हो गये लेन-देन के झगड़े में और 15 दिन बाद उनको उसी विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उनकी तस्वीर छपी थी कि अपने नेता के चरणों में बैठ करके पैर दबा रहे थे पूरा जमा कर देंगे हमें कैबिनेट मंत्री बना दीजिये और कैबिनेट मंत्री बन भी गये थे। जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां प्रदेश में उड़ाई गईं पूरा प्रदेश जानता है किसी से वह छिपा हुआ नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष चले गये, लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूँ कि मैं स्वास्थ्य देखता हूँ समाज के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था देना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। 2012 से 2017 तक समाजवादी लोग थे उससे पहले जो भी सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत लम्बे समय के बाद सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल था। लेकिन जबसे आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता की कमान संभाली उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सालय उच्च कोटि का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस ढंग से प्रबन्धन हुआ है आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। हम गुजरात में गये थे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन था जापानी इन्सेफेलाइटिस के विषय में जब वहाँ पर चर्चा हुई तब सभी स्टेट अपने-अपने बेस्ट प्रेक्टिसेस को ले करके आये थे। पूरे देश के लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जापानी इन्सेफेलाइटिस पर बहुत बेहतर काम हुआ है और इसको बेस्ट प्रेक्टिसेस माना गया। कोरोना प्रबन्धन के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य एक नम्बर पर है। हमने शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सभी को किया है और बच्चे जो अनुमन्य हैं वहाँ पर भी हम शत-प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं। बजट के मामले में जानते हैं चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षा में भी हमने पर्याप्त बजट आवंटित करने का काम किया है। सड़कों के निर्माण में पहले जब समाजवादी मित्रों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में घुसने का मतलब था कि गड्ढे आ गये, लाइट चली गई, इसका मतलब उत्तर प्रदेश आ गया है। सड़कों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे सदन के साथी हैं वह उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जायेंगे वहाँ आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें मिलेंगी। बिजली के मामले में पहले मात्र कुछ जिलों में बिजली आती थी। इटावा, मैनपुरी, रामपुर, बदायूं, कन्नौज लेकिन 75 के 75 जनपदों में बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जो हमारा 2022-23 का बजट उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सबसे प्रमुख बात यह है कि संकल्प-पत्र में 110 जो हमारे संकल्प थे उसमें सत्तानबे का समावेशी सरकारी घोषणाओं के रूप में इसी बजट में कर दिया गया है। सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद इस प्रकार की

घोषणा सरकार की ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है कि हम सकारात्मक रूप से जो संकल्प-पत्र में हमारे वादे हैं उनको हम शीघ्रता से पूरा करना चाहते हैं। महिला, गांव, किसान, युवा उत्थान के लिए लगातार हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनामी बनने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पांच सालों में योगी की सरकार ने 2012 से 2017 के बीच में छठे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पिछले पांच सालों में दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम था कि 2017 में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के बजट को पांच साल में आज हमने दुगुना किया। इसी दौरान स्टेट की जी0डी0पी0 11.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

जब नेता प्रतिपक्ष का हम लोग भाषण सुन रहे थे वास्तव में बहुत कष्ट हो रहा था। वह आम आदमी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी पीड़ा आम आदमी के बारे में न हो करके मात्र कुछ लोगों के बारे में थी। उनकी पीड़ा अपने परिवार के बारे में थी और उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि उनके हाथ से सत्ता फिसल गयी। वह जानते हैं कि किस ढंग से उन्होंने 100 सीट हासिल कर ली। हमारे कुछ मित्र जो अभी यहाँ पर नहीं हैं चले गये, अगर वह समझदारी दिखाते तो 47 से भी नीचे आने वाले थे यानी जनता में उनकी कहीं भी कोई पहचान नहीं थी और न ही जनता उन्हें चाहती थी। यह आम आदमी की बात करते हैं, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया तथा मवाली तत्व थाने चलाने का काम करते थे। ट्रांसफर-पोस्टिंग में उन्हीं गुंडे-बदमाशों का बोलबाला रहता था। यह वही पार्टी है जिनके नेता कहते थे यदि रेप हो जायेगा तो बच्चे हैं, छोटी-मोटी गलतियां कर देते हैं।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 उप मुख्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा संशोधन कर लें।

(इस मध्य सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा एक साथ बैठिये, बैठिये कहे जाने पर सदन में शोर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश जी, आप बैठिये। आप अनावश्यक उस बात को मत कहिये। मा0 उप मुख्य मंत्री जी ने कोई असंसदीय बात नहीं कही है। अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक और असंसदीय बात कही होगी मैं उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा बाकी उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। मा0 उप मुख्य मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, यह वही पार्टी है, जिसके 2012 से 2017 के शासनकाल के दौरान हमारी माताएं और बहनें घरों से निकलने में कतराती थीं। यह उसी पार्टी के मुखिया थे जो

अभी बोलकर चले गये हैं, जिनको सुनना अच्छा नहीं लग रहा था और वह सच सुनना नहीं चाहते थे। यह वही समय था जब बेरोजगारी की दर 17 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी। मैं मा0 मुख्य मंत्री योगी जी को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जिनके कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी की दर 2.9 प्रतिशत रह गयी है। यह आम आदमी के लिए सोच थी जिसके तहत पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी जी की सरकार में प्रतिभा और कौशल के दम पर जिन नौजवानों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको नौकरी मिली है। पूरा प्रदेश जानता है कि 2012 से 2017 के बीच में सरकारी नौकरियों में किस प्रकार बन्दरबांट होती थी। प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने उसका नाम तक बदलने का काम किया था और 'लोक' हटा करके एक जाति विशेष का नाम लिख दिया था। जब एसडीएम पद का रिजल्ट आता था और उप जिलाधिकारी जैसे गम्भीर पद का रिजल्ट आता था तो 100 पदों में से आधे से अधिक पद एक ही समाज के और ज्यादातर एक ही जिले के होते थे। जब सिपाही की भर्ती होती थी तो बड़ी संख्या में एक ही समाज के लोग और एक ही जिले से होते थे, लेकिन उस पर भी कोई अहसान नहीं था न उस समाज का अहसान था और न ही जनपद के लोगों का अहसान था। उसमें भी काउंटर खुले हुए थे कि किस प्रकार धन जमा होगा और किस प्रकार लोगों को नौकरी मिलेगी। आज जब प्रतिभा के दम पर नौजवान नौकरी पा रहा है तो उनको लगता है कि हमारे जो लूटने के अड्डे थे वह बन्द हो गये हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा थी और वह देश के सभी गरीबों को मकान देना चाहते थे। 2014 में जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पूरे देश में सभी गरीबों को निःशुल्क मकान मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी का कि जबसे उन्होंने सरकार संभाली है तबसे 45 लाख गरीब व्यक्तियों और पात्र लोगों को आवास देने का काम किया है और सबसे बड़ी बात यह रही है कि जिन लोगों का नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं था ऐसे लोगों को भी मुख्य मंत्री आवास योजना चला करके उनको भी निःशुल्क आवास देने का काम मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम सभी गरीबों को निःशुल्क शौचालय प्रदान करेंगे। 2017 से 2022 के बीच में 02 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाकर सभी गांव वालों को सम्मानपूर्वक जीने का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मा0 योगी जी की सरकार ने किया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके साथी नोट कर लें कि वर्ष 2012 से 2017 तक वह बता दें कि कितने गरीबों को मकान और कितने गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने का काम हुआ है। प्रदेश

की अर्थव्यवस्था गम्भीर विषय है लेकिन समाजवादी साथियों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था से मतलब है कि किस ढंग से उनका रहन-सहन हो, किस ढंग से उनकी कार्य प्रणाली हो, किस ढंग से बड़ी-बड़ी गाड़ियां और किस ढंग से वातानुकूलित कक्ष उनके लिए तैयार हों। नेता प्रतिपक्ष ने गन्ना किसानों की बात उठाई, मुझे अच्छी तरह याद है ? कि इसी प्रदेश में खाद के लिए किसान लाइन में खड़े होकर लाठी खाता था। हमारी सरकार ने सबको यूरिया उपलब्ध कराने का काम किया है, बीज उपलब्ध कराने का काम किया है और सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने का काम किया है। आज गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का वर्तमान बजट उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए उपयोगी बजट है, इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस आशा और भरोसे के साथ कि विपक्ष के साथी इस बात को समझेंगे क्योंकि आपके नेता यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, कुछ हमारे मित्र हमारी बातों को समझ रहे हैं। नेता विपक्ष का वही हाल हो गया है जैसा कि राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2022-23 के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, अब तक महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर और अब 2022-23 के बजट पर जो चर्चा हो रही है उस पर नेता प्रतिपक्ष ने श्री जनेश्वर मिश्र जी की बात कही कि हमने उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया जिसको सुन करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि वह जनेश्वर मिश्र पार्क नहीं बल्कि अम्बेडकर जी के नाम पर बना अम्बेडकर उद्यान था। माननीय अध्यक्ष जी यह कहा जाता है कि इस सदन में कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये बात मैंने अभिभाषण में भी कही थी और फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसके लिए आज कोई व्यवस्था दे दी जाये। जिन-जिन बातों पर चर्चा हो रही है, नोएडा के मेट्रो पर चर्चा हो रही है, एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है, इकाना स्टेडियम की चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इन सारे प्रोजेक्टों का एक बार लैण्ड एक्विजीशन से लेकर, लैण्ड एक्वायर एवं शिलान्यास तक के दस्तावेज निकाल के सदन के पटल पर रख दिये जायें तो फिर ये सब बातें शुरू नहीं होंगी कि हमने ये किया, हमने वो किया। मैं ये सरकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाय जिससे कि हम लोग समय व्यतीत न करते हुए सीधे आकर बजट पर बात करने लगें। हम लोग अपना पूरा समय इसी में व्यतीत कर देते हैं इसलिए हमको भी बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया था, हमारे काम को न गिनाया जाय इसकी कोई व्यवस्था बना दी जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा पिछला 2021-22 का बजट पांच लाख पचास हजार दो सौ इकहत्तर करोड़ का था। हम उस बजट का खर्चा देखें तो चार लाख चौरासी हजार पांच सौ बयालिस करोड़ यानी 12 प्रतिशत कम बजट खर्च कर पाये। अध्यक्ष जी, 2022-23 में 6 लाख 15 हजार पांच सौ अट्ठारह रुपये बजट लाये हैं। इसमें 27 प्रतिशत बढ़ाया है। पिछला बजट जो साढ़े पांच लाख का था उसमें से चार लाख चौरासी हजार खर्च कर पाये तो क्या यह बजट हम खर्च कर पायेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि काफी समय निकल गया है। हम यह कहें कि काम करने का समय अप्रैल और मई दो माह पूरी तरह से व्यतीत हो गया और 15 जून से बरसात का सीजन आ जायेगा। प्रमुख विभाग जिसका बजट में अंश है अगर उनका काम देखें तो 15 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितम्बर, साढ़े तीन माह तक कोई काम नहीं होगा। इसमें भी हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि इतना बजट हम कैसे खर्च करेंगे ? अगर देखा जाये तो पिछले बजट का खर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 32 हजार करोड़ बजट था, लेकिन हम पूरा बजट नहीं खर्च कर पाये। हमने 26 हजार 328 करोड़ खर्च किया। पुलिस विभाग, गृह विभाग का 29 हजार करोड़ बजट था जिसके सापेक्ष 24 हजार करोड़ बजट खर्च कर पाये। सिंचाई एवं बाढ़ का 20 हजार करोड़ बजट था जबकि हम 17 हजार करोड़ बजट खर्च कर पाये। मान्यवर, काम करने की उदासीनता को खत्म करके, काम करने की रुचि को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश हित के विभाग जो सीधे-सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उसमें भी उदासीनता बरतेंगे तो ठीक नहीं है। सरकार जो बजट लाई है और जिन स्रोतों का उस बजट में हवाला दिया गया है कि इन स्रोतों से आय इकट्ठा करेंगे और खर्च करेंगे। सन् 2021-22 में जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति अनुदान से आठ हजार आठ सौ दस करोड़ मिलना था, लेकिन हम मात्र 7 हजार सात सौ करोड़ ही अचीव कर पाये यानी 12 प्रतिशत कम मिला। इस बार जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति अनुदान से हमने 10 हजार से ऊपर आंका है यानी हमको 10 हजार से अधिक जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा। दो-तीन विभाग जो सरकार के मेन आय के विभाग हैं। सरकार ने बजट में दिखाया है कि इन-इन स्रोतों से बजट लेंगे। स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में पिछले बजट में बताना चाहता हूँ कि पिछले बजट सत्र में सरकार ने यह अन्दाजा लगाया था कि हमको स्टाम्प ड्यूटी से 25 हजार पांच सौ पचास करोड़ रुपया मिलेगा परन्तु मान्यवर, 19 हजार सात सौ पैंतालिस करोड़ मिला है यानी 23 प्रतिशत कम मिला। वाहन टैक्स से 9350 करोड़ मिलना था, पर हमको लगभग 5900 करोड़ यानी 36 प्रतिशत कम मिला। केवल विद्युत ऐसा विभाग है जिस पर सरकार ने 2021-22 में अन्दाजा लगाया गया था कि 4 हजार सात सौ पचास करोड़ प्राप्त होगा और इसमें शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया। शत-प्रतिशत का आंकड़ा मैं सदन में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि विद्युत विभाग सीधा ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता के लिए है, उनका पूरा टैक्स वसूल लिया गया। विद्युत विभाग ने काम किया हमारे पूर्व मंत्री जी ने सहयोग किया होगा। जितनी

सरकार ने उम्मीद की थी, उतना दिला दिया। मेरा तात्पर्य यह है कि प्रमुख विभागों से हमें कम बजट मिला।

(इसी मध्य अपराहन 03 बजकर 01 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं दो-तीन बातों को और आपके बीच रखूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी की जगह पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर हम बजट की चर्चा करें तो प्रमुख हमारा अंश कृषि होना चाहिए। जो बजट का प्रावधान है तो उसमें देखा जाये तो जो राष्ट्रीय औसत कृषि पर है 6.62 प्रतिशत पूरे का अपने बजट में रखते हैं। लेकिन हम इस विभाग से बहुत ही उदासीन हैं। इसमें वर्ष 2021-22 में 2.7 प्रतिशत रखा और वर्ष 2022-23 में भी हम 2.8 प्रतिशत ही रख रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से शिक्षा में देखें तो शिक्षा का जो राष्ट्रीय औसत है 15.2 प्रतिशत है इसमें भी हम बहुत नीचे हैं। मेरा सरकार से कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने राज्यों को कर्ज की सीमा 4 प्रतिशत रखी है। सरकार ने इस बजट में 3.96 प्रतिशत का अपना प्रारूप बनाया है। मुझे लगता है कि इतना सारा जो हमारा 6 लाख 15 हजार करोड़ का बजट है और जिन स्रोतों का जिक्र किया है तो उसमें हम कहीं न कहीं जाकर पिछड़ जायेंगे। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है इसमें सरकार ने जरूर अच्छा किया है कि जो बटाईदार होंगे या जिसके पिता के नाम पर वह खेत है और वह कमाऊ पुत्र है तो उसको भी सरकार दुर्घटना बीमा देगी। परन्तु कई बार मैंने अपने जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह की हम लोगों के पास कोई गाइडलाइन नहीं आयी है। वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस तरह के किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिला है कृपया बताने की कृपा करें। सरकार काशीराम शहरी आवासों को भी आवंटित करने की कृपा करे। वित्त मंत्री जी ने चीनी मिलों का जिक्र किया है हमारे बलिया जनपद में उद्योग के नाम पर एक ही चीनी मिल है और उस चीनी मिल को चालू करने के लिए पिछले 7-8 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ। सरकार का जवाब आ जाता है कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलेगी और मुझे लगता है कि पिछले सालों से कोई डीलर नहीं आया तो क्या सरकार इसको किसी तरह से चलाने का काम करेगी। पुरानी पेंशन की बात पर मैं कहना चाहूँगा कि वर्ष 2003 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिल्ली से नियम लागू किया। उस समय उत्तर प्रदेश में मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बन्द कर दिया था और जो आज तक बन्द चली आ रही है। इसमें मेरा सरकार से आग्रह है कि कुछ राज्यों में पुनः इस पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है तो यह उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के हित में भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दी जाये।

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती बिजयलक्ष्मी गौतम)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के नागरिकों को भी बहुत-बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस सम्मानित सदन तक पहुंचाया है और जिनकी बदौलत मैं पहली बार इस सदन में निर्वाचित होकर आई हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो 615518.97 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है उससे बड़ा दूसरा कोई बजट नहीं हो सकता है। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इकोनामी को एक ट्रिलियन की इकोनामी बनाने हेतु भाजपा की डबल इंजन सरकार कृत संकल्पित है। यह बजट प्रदेश की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, नगर, किसान, नौजवान और समाज के हर तबके के विकास की पूर्ति के लिए यह बजट बनाया गया है। इस बजट में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में अन्त्योदय की संकल्पना एवं जन-जन के विकास का संकल्प समाहित है। गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7000 करोड़ रुपये की व्यवस्था एवं मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 508.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से महिला कल्याण हेतु मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना हेतु 155.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 7373.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बिजली पर बहुत बात हो रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि इसके पहले वर्ष 2012-2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल चार-पांच जनपदों में ही बिजली आती थी। जनपद देवरिया जैसे जिलों में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बिजली के दर्शन नहीं मिल पाते थे। पहले एक सीरियल आता था जिसका नाम शक्तिमान था, उस सीरियल में एक पात्र किलविश होता था। जब वह आता था तो वह कहता था कि अंधेरा कायम हो। यही हाल हमारे देवरिया जैसे जनपदों का था। शाम को छह-सात बजे वहाँ पर व्यापारी जब अपना व्यवसाय करने बैठते थे तो एकदम से लाइट गायब हो जाती थी और यह पता नहीं चलता था कि वह शहर है या गांव है। हमारे यहाँ सलेमपुर में इससे पहले एक नेता थीं जो वहाँ से विधायक थीं। चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में बिजली न पहुंचे लेकिन जैसे ही वह सलेमपुर में प्रवेश करती थीं तो वहाँ पर बिजली पहुंच जाती थी और वहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती थी। उनको वहाँ पर बिजली रानी के नाम

से जाना जाता था। आज हम वहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। वहाँ पर लोग हमसे कहते हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आनी चाहिए क्योंकि यहाँ बिजली रानी हुआ करती थीं और 24 घंटे बिजली आती थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी समग्र विकास के लिए संकल्पित हैं उनको 75 जिलों को समान रूप से बिजली देनी है। जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली गांव के अन्तिम व्यक्ति तक पूरी पहुंच रही है। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गांव में खूब उजाला हो रहा है और खूब बिजली आ रही है और शिक्षा के स्तर पर माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक प्राथमिक विद्यालय को देखकर लगता था कि क्या दयनीय स्थिति है। उसमें गाय और भैंसे बांधी जाती थीं। बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। प्राथमिक विद्यालयों की ऐसी स्थिति थी लेकिन आज प्राथमिक विद्यालयों का ऐसा कायाकल्प हुआ है कि गरीब के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, चाहे शिक्षा हो या अस्पताल हो सबमें अच्छी व्यवस्था की गयी है। पहले जब अस्पतालों में किसी व्यक्ति को लेकर जाते थे तो वहाँ खड़ा होने की स्थिति नहीं होती थी आज जिलों में अस्पतालों में, साफ-सफाई, फूल, पेड़, पौधे हैं और डॉक्टर्स बैठते हैं। आज अच्छा इलाज हो रहा है, आज गरीब अस्पतालों में जाने लगा है और उसको सम्पूर्ण रूप से दवाईयां मिलने लगी हैं।

आज गांवों में हमारे समाज के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो घर में शौचालय के बारे में नहीं सोचते थे, उनके यहाँ आज घर-घर शौचालय बन गया है। यहाँ बैठकर तो बहुत लोग बुराई करते हैं, लेकिन उनके सपने में कभी नहीं आया था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए गरीबों के पास मकान हो और शौचालय हो। अधिष्ठाता महोदय, देवरिया जनपद में जहाँ-तहाँ कूड़ा फेंका जाता रहता था जबसे मा0 योगी जी की सरकार आयी है तबसे हमारे वार्डों में सड़कों में गाड़ियां चल-चलकर आती हैं गाना गाती हुई आती हैं दरवाजे-दरवाजे से कूड़ा उठाकर ले जाती हैं और निश्चित स्थान पर फेंकती हैं। हमारी योगी जी की सरकार इतनी साफ-सुथरी तरह से चल रही है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सदन में जो यह बजट आया है, यह गरीब, दलित, महिला हर वर्ग के लिए यह बजट लाभकारी है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। आज गांव-गांव में जो महिलायें अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं वह बाहर निकलने में डरती थीं, घबराती थीं आज हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना से आज गांव-गांव में हमारी महिलाएं निकलकर बिजली सखी, कृषि सखी, बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं और सामुदायिक शौचालयों में हर जगह लगी हुई हैं। हर व्यवस्था में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार में हमारी गरीब और अनुसूचित महिलायें बहुत ही लाभान्वित

हैं। हर वर्ग के लोग लाभान्वित हैं। समग्र जाति और लोगों का विकास हो रहा है। कहीं भेदभाव नहीं है। कहीं जाति-भेदभाव नहीं है। इसी पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि-

''वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से
वो और थे जो हार गये आसमान से''

अधिष्ठाता महोदय, आपने हमको इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बजट कटौती पर जो बोला गया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य है। लगभग 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। पूरा उत्तर प्रदेश यह आस लगाये बैठा था कि उत्तर प्रदेश में जो 2022-23 का बजट आ रहा है इसमें उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत सारी योजनायें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो बजट लाया गया इस बजट को देखकर और सुनकर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या अपने को हताश और निराश महसूस कर रही है। अगर हम इस बजट में किसान की बात करें तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश या देश बिना किसानों को आगे बढ़ाये नहीं चल सकता। जिस देश में नारा लगता हो, जय जवान जय किसान। जिस उत्तर प्रदेश में किसान की आबादी 68.2 प्रतिशत हो। जो देश और प्रदेश किसानों से ही चलता रहा हो।

जहाँ रोजगार का मुख्य साधन कृषि रहा हो तो आज हम यह बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ खड़ा हुआ है। बातें बड़ी-बड़ी हो सकती हैं, घोषणाएं भी बड़ी-बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 68.2 प्रतिशत किसान है, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो सन् 1982 में जब पेट्रोल की कीमत तीन रुपये बीस पैसे थी तब इसी देश में गेहूँ की कीमत दो रुपये अस्सी पैसे थी, आज पेट्रोल की कीमत सौ रुपये पार हो गयी है, लेकिन आज इस देश के अन्नदाता किसान के गेहूँ की कीमत 2200 रुपये प्रति कुंटल से ऊपर नहीं बढ़ पायी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है, ये कैसा देश है, ये कैसे किसानों को आगे बढ़ा सकता है और कौन सी कल्पना हम इस सदन में बैठकर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हो जायेगा। जब यही किसान आपकी सरकार में 1600 रुपये की डी0ए0पी0 खरीद रहा है, बीज लगभग दोगुना हो गया है 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1200 प्रति घंटा आज वह ट्रैक्टर की जुताई दे रहा है। लेकिन जब गेहूँ बेचने जायेगा तो 2200 रुपये में बिकेगा, जब धान बेचने जायेगा तो 1450 रुपये में बिकेगा और अगर हम इसकी तुलनात्मक गणना करें तो हम यह पाते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान आज घाटे की खेती कर रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे निकटवर्ती राज्य चाहे बिहार हो,

झारखण्ड हो, छत्तीसगढ़ हो उनमें अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट देखें तो हम उत्तर प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं। सरकार में वर्ष 2012 से 2017 तक हमें भी कृषि मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, 3.7 प्रतिशत जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हम छोड़कर गये थे, आज भी सरकार के बजट भाषण में 4.9 प्रतिशत की ग्रोथ रेट की कल्पना की गयी है। बिहार में 6 प्रतिशत से ज्यादा कृषि दर है, 5.9 प्रतिशत कृषि दर छत्तीसगढ़ की है, झारखण्ड भी 5.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर चल रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी भी सौभाग्य से बैठे हुए हैं, हमने यह कई बार कहा है और आज भी कहेंगे कि जब तक घरेलू कृषि से किसानों को बाहर ले जाकर व्यवसायिक कृषि की ओर ध्यान नहीं देंगे और उस ओर उन्मुख नहीं करेंगे तब तक कभी भी किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। किसान के साथ आज एक बहुत बड़ा संकट बेरोजगार नौजवानों का है। सरकार बजट में यह बात तो करती है कि हमने बेरोजगारों को इतनी नौकरी दी, लेकिन भारत के कांस्टीट्यूशन से लेकर सरकारी नौकरी के जो नियम, ऐक्ट और प्रोविजन बने हैं, सभी में स्थायी नौकरी की संज्ञा दी गयी है, सर्विस प्रोवाइडर और मनरेगा में लगाये गये मजदूर भाइयों को सर्विस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि जिस सरकार ने कहा था कि हम 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, इसी सदन में हमारे प्रश्न के उत्तर में पांच साल में कुल 04 लाख नौकरी देने की बात कही गयी। यह कितना दुर्भाग्य है कि आप सपना कुछ दिखायेंगे और हकीकत में कुछ करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि यह देश के नौजवानों और किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। आज बेरोजगार आत्महत्या की ओर जा रहा है। आज जो नौजवान इस उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य है अगर उसे हम सरकारी रोजी-रोटी से नहीं जोड़ सकते तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। बेरोजगारी के ग्रोथ रेट में बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार यह बात तो करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई डाटा नहीं है और सरकार यह नहीं बता पा रही है कि आज कितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एस0पी0एम0 की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में मजदूर आज लगातार पलायन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश में मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अभी गांवों के समग्र विकास की बात हो रही थी। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बोला था कि गांवों के विकास के लिए और गरीबों के लिए आवास के क्षेत्र में सरकार ने काम किया। आजाद हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बनी होगी जिसने उत्तर प्रदेश में गरीबों को सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया बल्कि सपना साकार भी किया, एक लाख प्रधानमंत्री आवास के सापेक्ष सवा तीन लाख रुपये को लोहिया आवास 29,629 लोगों को देने का काम वर्ष 2012-17 में किया गया।

13 हजार ग्राम पंचायतें, समग्र गांव में जुड़ी हैं, और कोई नाम से योजना नहीं बनाई गयी थी, बल्कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में एक ब्लाक है, 1900 लोगों को लोहिया आवास दिया गया और 1300 करोड़ रुपये से अकेले उस गांव का विकास किया गया। जब कोई योजना दी गयी तो उसके सापेक्ष धन दिया गया। योजनाएं बहुत

आयीं, पंडित दीनदयाल समग्र ग्राम योजना आयी, लेकिन एक रुपये का भी गांव के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है और आज सबसे ज्यादा अन्नदाता और किसान संकट में है और हम तो धन्यवाद देंगे, अपने तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगने दिया। कहीं लाठी चार्ज नहीं हुआ और अगर किसान ने एक बोरी खाद मांगी तो दो बोरी खाद देने के लिए केन्द्र तैयार रहे। अपने क्षेत्र की तीन समस्याओं को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियां से एक बकुलही नाला जिसकी लम्बाई लगभग 42 कि0मी0 है जो रोहनिया ब्लाक से चल रहे प्रतापगढ़ की सई नदी में गिरता है। 2016-17 के बजट में उसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार नहीं आयी और हमारे सामने बैठे हुए बन्धुओं की सरकार आयी, उस 10 करोड़ के स्वीकृत बजट को भी अस्वीकृत कर दिया गया। वह केवल मनोज पाण्डेय का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वह उस क्षेत्र में रहने वाले, उस क्षेत्र में पड़ने वाली 13600 हेक्टेयर जमीन के उन किसानों की समस्या है, जिनकी जमीन सीपेज के कारण बर्बाद पड़ी हुई है। वह उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक और समस्या के बारे में कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से इसौर नाले की भी खुदाई नहीं करायी। हमने तीन बार इस बात को उठाया कि जर्जर तारों के कारण हमारे यहाँ खेत में रोपाई करती हुई महिलाओं के ऊपर तार गिरा, उसमें 05 लोगों की डेथ हो गयी, 16 लोग विकलांग हो गये। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यह आश्वासन आया था कि 6 महीने के अन्दर जर्जर तारों को बदलवा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ, आगे कोई ऐसी घटना न घटे, उन जर्जर तारों को शीघ्र ही बदलवाया जाये, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेश चौबे-

अधिष्ठाता महोदय, जो यह बजट पेश किया गया है, अगर मैं यह कहूँ कि यह बजट सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उस चरैवेति-चरैवेति मंत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर किया है। चाहे वह बच्चे की चिन्ता हो, चाहे नौजवान की चिन्ता हो, चाहे किसान की चिन्ता हो, चाहे व्यापारी की चिन्ता हो, चाहे यातायात की चिन्ता हो, चाहे सुरक्षा की चिन्ता हो, चाहे पर्यटन की चिन्ता हो, चाहे वन के विकास की बात हो, चाहे औषधि की बात हो, चाहे वह सबको राशन और सबको शासन की बात हो हर दिशा में सर्वांगीण विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। चाहे वह श्रमिक हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे वह ठेला-पटरी वाले हों, सबकी चिन्ता इस बजट में की गयी है। गांव का गरीब बच्चा भी अब कोचिंग करके प्रतियोगी परीक्षा हेतु अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वह भी अपनी प्रतियोगी परीक्षा

पास कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था की गयी है और इतना ही नहीं, गांव का बच्चा जब पढ़ेगा, गांव में किसान उन्नत खेती करेगा, गांव की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और अब गांव में बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर ग्राम उन्नति योजना के तहत गांव की सड़क भी प्रकाशित होगी। इस प्रकार से सभी लोगों की चिन्ता करते हुए, इस सरकार ने जहाँ पटरियों पर काम करने वाले लोगों की चिन्ता किया, जहाँ गरीब बच्चों की कोचिंग हो सके, उसकी चिन्ता किया तो वहीं पर ऐसे बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं आईपैड, लैपटॉप, कम्प्यूटर से भी पढ़ाई कर सकता हूँ, ऐसे सभी बच्चों को, इस सदन में बैठे हुए तमाम लोग होंगे जो इस बात को महसूस किये होंगे कि जब वह पहले आईपैड खरीदे होंगे या मोबाइल एन्ड्रायड खरीदे होंगे, तो किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ होगा।

मान्यवर, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विद्यार्थियों को टैबलेट देने की व्यवस्था बनाई है जिससे कि नौजवानों को पठन-पाठन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधा होगी और वहीं उनका गौरव और आत्मसम्मान भी बढ़ा है। यह जो बजट है इसका मैं पूर्ण समर्थन करते हुए कुछ बातें आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बात रखना चाहता हूँ कि सरकार के बजट का प्रावधान इस प्रकार से हो कि अपने क्षेत्र के जो भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, वह कार्य भी पूरे हो सकें। अपना क्षेत्र पहाड़ी अंचलों से घिरा हुआ है, बरसात में पानी जो बहकर निकल जाता है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका इस प्रकार से समायोजन किया जाये कि जो हमारे क्षेत्र में कठौता, करही, सिरसी, देवरी, नरसों और पीपर खाड़, चिरुई आदि जैसी जगहों पर जो बड़े-बड़े बांध हैं, उन बांधों में जो पहाड़ के नाले हैं उन बांधों के साथ जोड़ दिये जायें, जिससे कि बांध का जल स्तर ऊंचा हो जायेगा और उससे सिंचाई समुचित रूप से जो बांध की क्षमता है उससे अधिक बढ़ जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपना क्षेत्र धधरौल बांध जो एक ऐतिहासिक बांध है उस बांध की तलहटी से अभी हर घर नल और हर घर जल की योजना का शुभारम्भ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। वहाँ से घाघरा नहर निकलती है और सोन लिफ्ट की नहर परियोजना के बीच में कुछ गांव ऐसे हैं वहाँ पर जैसे वार, परसौना, करमांव, बबुरी, खैराही ऐसे गांव जो सिंचित हैं वहाँ पर मैं आग्रह करूंगा कि सोन लिफ्ट को पांचवें चरण का एक्सटेंशन करके वहाँ भी पानी की व्यवस्था सिंचाई हेतु की जाये। एक बसुहारी परियोजना बड़े लम्बे समय से लटकी पड़ी हुई है तो इसको पूरा कराने के मामले में योगी सरकार सक्षम भी है और कर भी रही है। जो पूर्व की सरकारों में जो योजनाएं लटकी अटकी पड़ी हुई हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, जो बसुहारी सिंचाई परियोजना है उसे भी पूरा किया जाय। मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा अपने सोनभद्र से जुड़ा हुआ चकबन्दी को लेकर अपने जिले में कोई कार्य पेंडिंग नहीं है जिन गांव की अभी चकबन्दी नहीं हुई है उन गांवों की भी चकबन्दी कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, इससे काफी सुविधा होगी। हमारा जनपद एकमात्र नगर पालिका है राबर्ट्सगंज नगर है आज भी

जमींदारी प्रथा चली आ रही है इसलिए वहाँ पर कई जमीनों की खरीद-फरोख्त और बाकी चीजों में विवाद होते रहते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कि वहाँ जमींदारी प्रथा को समाप्त कराया जाय। इसके अलावा राबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र से निकलने/गुजरने वाला जो ओवरब्रिज है उस ओवरब्रिज पर ऊपर लाइट न लगने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं इसलिए वहाँ पर लाइट लगायी जाय और साइड की जिस दीवार पर जहाँ तहाँ खतरनाक मोड़ हैं वहाँ एक जाली लगाई जाये जो बजट 2022-23 का पेश किया गया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जो अग्रसर है वह और आगे बढ़े वन्दे मारतम्।

मत्स्य मंत्री (डॉ0 संजय निषाद)-

अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तर प्रदेश के 2022-23 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूँ। त्रेता में भगवान राम ने अपने कैबिनेट में निषादराज को अतिथि के रूप में बुलाया था और उस समय एक रामराज का स्वरूप आया था सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हो। रामराज की कल्पना थी आज भारतीय जनता पार्टी की मा0 मोदी जी, मा0 योगी जी की सरकार बनी है। इन निषादराज के वंशज के बेटे श्री संजय कुमार निषाद को उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस सदन में लाया है। निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ कि इस बजट की चर्चा में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पिछली की सरकारें किस तरीके से जनता को बजट का शिकार बनाती थीं।

मा0 योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने पहली बार यह काम किया है कि जनता को किस तरीके से बजट का हिस्सेदार बनाना है, कैसे उनके हिस्से का बजट उनके दरवाजे तक जायेगा ? मैं उसकी एक बानगी पेश करना चाहता हूँ कि पहले मत्स्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधीन होता था और जो मत्स्य पालक हैं, नदियों के किनारे के मछुआरे हैं, उनकी दशा-दुर्दशा अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो उजाड़ी ही थी, खराब की ही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कभी उनकी चिन्ता नहीं की। चिन्ता की मोदी जी ने, उन्होंने दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय को अलग किया, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना बनाई। मछुआरे जो गरीब हैं, गंवार थे, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, जिनके झउवा पर वोट पर पउवा का लेबल लगा था। लेकिन आज उन पर निषादराज होने का एक राजनीतिक लेबल लग गया है और निषाद पार्टी यानी निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के साथ आने के बाद उन्हें जब ज्ञान हुआ और उन लोगों ने संघर्ष किया तो हमें दिल्ली में जाने का मौका मिला और जिनके निवेदन पर दिल्ली की केन्द्र सरकार ने मत्स्य मंत्रालय को अलग कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा मा0 योगी आदित्यनाथ जी को कि 70 साल बाद पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए, मछुआरों के विकास के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, मत्स्य मंत्रालय को अलग किया गया और उन्होंने डॉ0 संजय निषाद को उसका कैबिनेट मंत्री बनाकर सेवा का अवसर दिया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज के दिन में इन पिछली सरकारों ने क्या-क्या किया है ? मत्स्य पालक लोग जो वर्ग-3 और 4 की जमीन पर अपना पेशा करते थे, वे सदियों से वर्ग-3 और 4 की जमीन पर काम करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसने कुर्सी पर बैठते ही इनका आरक्षण तो ले ही लिया, लेकिन उनकी रोजी-रोटी भी ले ली। जैसे अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर, 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया था, फिशरीज ऐक्ट बनाकर घाट ले लिये थे, फिशरीज ऐक्ट बनाकर मछली मारने का अधिकार छीन लिया था, माइनिंग ऐक्ट बनाकर माइनिंग का अधिकार ले लिया था और फॉरेस्ट ऐक्ट भी बनाया था। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने कुर्सी पर बैठते ही उनसे वर्ग-3 और 4 की जमीन वापस ले ली और ये मछुआरे आज बेघर हो गये। पहले उसमें उनका नाम आसामी दर्ज था, लेकिन उनका नाम खारिज होकर उसमें राज्य सरकार का नाम दर्ज हो गया। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि वह गरीबों की जमीन जो बहुजन समाज पार्टी ने छीनी थी, वह जमीन सरकार के लिए विचारणीय बिन्दु है कि वह जमीन उनको वापस कर दी जाये ताकि वे फिर से उसमें मछली पालना शुरू करें और मा0 मुख्य मंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज के दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआरों के लिए एक विशेष बजट दिया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में मछुआरों का नाम जो छूट गया था, उस पर विचार चल रहा है, लेकिन मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर विचार किया कि जो नाम छूटे हैं, कहीं वे इस लाभ से वंचित न हों तो उन्होंने उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में शुरुआत की, उन्होंने मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में उन्हें अपने पहले बजट में स्थान दिया और तो और निषादराज बोट सब्सिडी योजना बना दी कि आज के दिन में ये जो नदियों और तालाबों में मछली मारने वाले लोग हैं, उनको अलग से भी लाभ दे दिया। इनका मामला जो अनुसूचित जाति में चल रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि इनके जो मामले हैं, यह 70 साल में पहली बार है कि रजिस्ट्रार जनरल ऐण्ड सेंसस कमिश्नर ऑफ इण्डिया ने 18 जनवरी, 2022 को मान लिया कि केवट, मल्लाह और मंझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जैसे अनुसूचित जाति को 60 परसेंट की छूट है, उत्तर प्रदेश के मत्स्य सम्पदा क्षेत्र में उस अनुदान में निषादों और मछुआरों को भी, जो उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली, 2016 में लिखा हुआ है कि मछुआरा मतलब होता है, केवट, मल्लाह, बिन्द, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरहिया, सुराह, तोरहा ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में 60 परसेंट का अनुदान मिलना चाहिए। मैं इस चीज की सरकार से मांग करता हूँ, मैं यह विचारणीय बिन्दु भी आपके सामने रखता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी को कि हमारे इस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बजट दिया है, मा0 मुख्य मंत्री जी मत्स्य सम्पदा योजना में भी उन्होंने अभी 2 करोड़ रुपये का बजट दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा

योजना में आज के दिन इस मछुआ समुदाय के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गयी है कि अगर कहीं उनकी कैजुएल्टी हो जाती है तो 5 लाख रुपये हैं, अगर कहीं उन्हें सीवियर चोट लग जाती थी तो 2.5 लाख रुपये की व्यवस्था है और अगर वे अस्पताल में भर्ती हो गये तो उनके लिए 25 हजार रुपये की व्यवस्था है और इसमें निःशुल्क बीमा भी है। मैं बधाई दूंगा मा0 प्रधानमंत्री जी को और मा0 मुख्य मंत्री जी को कि एक ऐसी बिरादरी जो सदियों तक मुगलों और अंग्रेजों से लड़ती रही, उसके लिए उन्होंने निःशुल्क बीमा की व्यवस्था की है।

मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि इस विभाग के लिए उन्होंने एक विशेष व्यवस्था दी है कि कैसे इस समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसमें मछुआ समुदाय के लिए मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना की गयी है, जिसमें 25 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करके इनके कल्याण के लिए, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए फण्ड बनाया गया है। 70 साल से इनके लिए कोई भी पार्टी चिन्ता नहीं करती थी। इनको केवल वोट बैंक का साधन माना गया। वोट ले लिया और इनको बहका दिया, गुमराह कर दिया। हमारे समाज के एक दर्जन नेता पिछली सरकारों में मारे गये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनीराम वर्मा, मयंक सिंह पाल राजपूत, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल, कश्यप, झूरी बिन्द, जमुना निषाद, फूलन देवी जैसी पिछली सरकारों में, जिसने भी इस समुदाय के लिए आवाज उठायी, उसे इस धरती से उठा लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि डॉ0 संजय को सुरक्षा प्रदान करके और अपनी कैबिनेट में जगह देकर इस समुदाय का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आज के दिन मैं इस विभाग को धन्यवाद दूंगा कि जो बेरोजगारी है, उसके रोजगार के साधन हमारे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय में 60 परसेंट महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए 60 परसेंट का अनुदान है। कोई भी इस क्षेत्र में काम कर सकता है। सरकार ने चिन्ता की है कि अब उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आनी चाहिए। यह प्रोटीन युक्त साधन है। दूसरे प्रदेश से जब मछली आती है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जायेगा और मत्स्य क्षेत्र में इसे विकसित कराकर एक नम्बर में लाया जायेगा। उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी मछलियां जायेंगी, अब ऐसी व्यवस्था हो रही है। इस देश से दूसरे देशों में भी सरकार के साथ मिलकर हम लोग मत्स्य व्यापार में कामयाबी हासिल करेंगे।

महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहूँगा कि मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है, जिसकी चिन्ता की गयी है और दुर्घटना बीमा दिया गया है। आज से पहले हमारे इस समुदाय के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। इस समुदाय के लोगों के साथ अंग्रेजों ने जिस तरह से नाइंसाफी की, इसलिए ही तो इसे क्रिमिनल कौम घोषित करके उनको बर्बाद कर दिया। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सहयोग से, तो हमारी आरक्षण की फाइल को इनके दो मंत्रियों ने गायब

करा दिया। मैंने उनके खिलाफ संसद भवन, नई दिल्ली मार्ग में मुकदमा लिखा रखा है। इस तरह से इन जातियों के साथ अन्याय होता था। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज निषाद पार्टी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी से जो एन0डी0ए0 की सरकार बनी है, उसमें सरकार के बजट का मैं समर्थन करता हूँ। महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मिशन शक्ति की योजना है। युवाओं के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इतिहास में है कि हमारे वंश में एकलव्य ने अंगूठा दान किया था। एक अंगूठा कटने के कारण उनका एकलव्य नाम हो गया। एकलव्य का अर्थ अंगूठा होता है, परन्तु उनका नाम अभ्युदय था तो उनके नाम से मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के नाम से युवाओं के लिए खेल जगत में पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। खिलाड़ियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के सम्बन्ध में किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए तमाम बीमा भी है। तमाम तरह के क्षेत्रों में किसानों को कोई पूछता नहीं था। जो मिल होता है, वह किसान का दिल होता है। पिछली सरकार तो केवल मिल बेचती थी। हमेशा सुनने में आता था कि जो मिल है, उसकी कीमत लगाने में इतने करोड़ रुपये खर्च हो गये। हमारे यहाँ एक बस्ती जगह है।

श्री अधिष्ठाता-

संजय जी, अब इसे संक्षेप करिये।

डॉ0 संजय निषाद-

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मुंडेरवा एक जगह है, वहाँ एक पार्क बना है, जहाँ पर मूर्तियां लगी थीं। मैंने पूछा कि यह मूर्तियां कैसे लगी हैं, उन्होंने बताया कि गन्ने का मूल्य मांगने आये थे, सरकार ने गोली मार दी और यह शहीद के रूप में खड़े हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया गया। कहीं कोई दंगा-फसाद नहीं और किसी को भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। गन्ना किसानों को, कृषकों के बच्चों के सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि मैंने एक बार दिल्ली में कई हजार लोगों के साथ प्रदर्शन किया था। मा0 भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने इस पर चिन्ता की। उत्तर प्रदेश में जो सन्निर्माण कर्मकार योजना के नाम पर 36 योजनाएं दीं। उसमें धरातल पर कितना भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के नाते गरीबों के, श्रमिकों के लिए मैं लड़ाई लड़ता था। लेकिन जब देखा पिछली सरकारों में इतना भ्रष्टाचार है। उस विभाग में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गरीबों और श्रमिकों का जो रुपया है उसको बन्दरबांट करने का काम किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कर्मकार और श्रमिकों के लिए जो योजनाएं हैं सरकार उन योजनाओं को उनके दरवाजे पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने झलकारी बाई कोरी के नाम से हथकरघा उद्योग में भी जगह दी। हमारे लोधी समाज में लोधी भी मछुआ समुदाय का एक पार्ट

है, जिसे लोधी राजपूत कहते हैं, बाबू जी कल्याण मुख्य मंत्री योजना के नाम से सोलर लाइट लगी है। समुदाय के सभी वर्गों का ध्यान अगर कोई करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी करती है। अन्तिम बार कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें तीर-धनुष-मछली है। जिस भी तरीके से हो इस मत्स्य समुदाय को मछुआ क्षेत्र में काम करने के साथ-साथ हर एक जाति को, हर एक बिरादरी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में जगह दी है। यह बजट पिछली सरकारों की बजट की तुलना में काफी बेहतर है। पिछले 05 साल के बजटों का उपयोग योजनाओं को धरातल पर लागू करने में किया गया, चाहे वह खाद्यान्न योजना हो, चाहे वह इलाज की योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, धरातल पर लागू होने के नाते जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर मोहर मारकर दुबारा योगी जी को गद्दी पर बैठाया और हम सहयोगी दलों को यहाँ तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

***श्री महबूब अली-**

शुक्रिया अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में जो कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आज प्रदेश की क्या स्थिति है ? प्रदेश में राजकीय कोष का जो घाटा है वह तरक्की कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश के विकास की बात तो शायद हो सकती है, बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। माननीय अखिलेश जी की सरकार में बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49 हजार 960 करोड़ 88 लाख रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 81 हजार 166 करोड़ 97 लाख पहुंच गया है, जिसमें 62.48 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो अपना पेपरलेस बजट रखा है, उस पेपरलेस बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ऐसा लगता है कि पेपरलेस बजट नहीं अल्पसंख्यक कल्याण लेस बजट है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के बजट में 11.86 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है वहीं अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव करते हुए उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अल्पसंख्यकों को सरकार ने आर्थिक रूप से अपंग करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1896 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1782 करोड़ 75 लाख करके यानि कि 5.97 प्रतिशत लेस करने का काम किया है। सरकार जो मदरसों को अनुदान देती थी उसे बन्द करने का काम कर रही है। मैं कहूँगा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नारा दिया था जिसका बजट भाषण में जिक्र भी किया गया था। इसमें लोगों को रोजगार से जोड़ने के बड़े-बड़े वायदे किये गये। हमारा जनपद अमरोहा ढोलक के नाम से मशहूर है और ढोलक को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चिन्हित करके आर्थिक रूप से मजबूत करने का सपना जरूर दिखाया गया, लेकिन उसकी आज तक कोई योजना नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनायी है। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे महंगी बिजली, डीजल, पेट्रोल पिछले 05 वर्षों से खरीद रही है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो सस्ती बिजली देंगे, नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे। हर हफ्ते, हर महीने तो डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, नौजवान परेशान हैं।

हमारे प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। यह बजट किसान विरोधी है और मैं कहूँगा कि पूरी तरह से लोग लुट रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। आप लोगों का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मैं तो कहूँगा कि इसको बदल लें तो ठीक रहेगा कि हमारा विकास और बाकी प्रदेशवासियों का सत्यानाश। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बात करते हैं कि पढ़ो बेटियां-बढ़ो बेटियां, कन्या विद्या धन जैसी योजनायें थीं जो बच्चियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी थी। बच्चियों को जूडो-कराटे सिखाने के लिए और बच्ची स्वावलम्बी बने और अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर किसी भी घटना का मुकाबला कर सके, लेकिन आज तक वह लागू नहीं की गयी है। मैंने बहुत गम्भीरता से एक प्रश्न की बात की थी और मैं कहूँगा कि आज अगर प्रदेश में देख लिया जाये कि जिस तरह से लोग बीमार हैं, 50 परसेंट बीमारी पर कंट्रोल हो जायेगा, अगर हमने प्रदूषण पर कंट्रोल कर लिया। आज प्रदूषण की यह स्थिति है कि अगर उत्तर प्रदेश में देख लें, जो भारत के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित प्रदूषण जांच संस्था सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट यानि सी0एस0ई0 है, उसने जांच की है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रदूषण बहुत चरम पर है। अगर उस पर कंट्रोल हो जायेगा तो समझ लीजिये कि 50 परसेंट बीमारियां कम हो जायेंगी। इसके साथ ही देश के बाहर, स्विट्जरलैण्ड की एक प्रतिष्ठित कम्पनी आई0क्यू0एयर ने भी जांच की है और जांच करने के बाद वर्ल्ड में जो टॉप 10 प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें चार डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं, जोकि हमारे लिए कितनी गम्भीर बात है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए था और इस पर बजट लाना चाहिए था। मैं कहूँगा कि आज सरकार इसे गम्भीरता से ले तो निश्चित ही वह दिन बहुत करीब होगा, जब हम स्वस्थ हो जायेंगे और जब स्वस्थ हो जायेंगे तो स्वतः ही प्रदेश का विकास आगे होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में मेरी विधान सभा क्षेत्र अमरोहा को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, लम्बे समय से हमारे अमरोहावासियों की मांगें रही हैं और बहुत समस्याएं रही हैं। अभी जैसे कि सरकार लगातार मेडिकल कालेज के बारे में घोषणाएं कर रही है कि हर जनपद में मेडिकल कालेज बनेगा, लेकिन आज तक अमरोहा के अन्दर जनपद होने के बावजूद मेडिकल कालेज बनाने की कोई घोषणा नहीं हुई। अमरोहा में मेडिकल कालेज की तुरन्त स्थापना करवाने का काम किया जाय। बुनकरों के लिए समाजवादी सरकार में 2 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के अन्दर वह अकेला ऐसा शहर है जो एशिया के अन्दर डस्ट से यानी कतरन से बहुत बेहतरीन रूई बनाता था, उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह सब्सिडी समाप्त कर दी गई या कम कर दी गई।

श्री अधिष्ठाता-

महबूब भाई, कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री महबूब अली-

मान्यवर, बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए शायद यह सरकार गम्भीर नहीं है। यह बात तो करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की, लेकिन कैसे प्रोडक्ट बन पायेंगे, अगर सब्सिडी खत्म कर दी जायेगी, नगर अमरोहा की जल निकासी की व्यवस्था कराई जाये। अमरोहा जलमग्न हो जाता है। हमारी सरकार ने उस वक्त 38 करोड़ रुपये दिये थे। आज तक यह सरकार कनेक्टिविटी के लिए उतना धन नहीं दे पाई ताकि उसकी कनेक्टिविटी हो जाये। नगर अमरोहा में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना बहुत जरूरी है, उसे कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

महबूब भाई, अब समाप्त करें।

श्री महबूब अली-

ठीक है मान्यवर, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपका शुक्रिया करते हुए इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि-

'कितना आसान है दोजख में बदलना इसको। कितना दुश्वार है इस सूबे को जन्नत करना। तुम्हारे दौरे कयादत में, यही सुबह-शाम होगा कि कहीं अस्मतें लुटेंगी, कहीं कत्लेआम होगा।' बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अमित अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2022-2023 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से आता हूँ जो धनुर्धर अर्जुन की भूमि है, जो प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध भीष्म पितामह की भूमि है, जो उस मन्दोदरी की भूमि है जिसने भगवान राम के शरणागत होने का अन्तिम समय तक रावण से आग्रह किया। मैं भगवान कृष्ण की उस कूटनीतिक कर्म की भूमि से आया हूं जिन्होंने न्याय की स्थापना के लिए महाभारत की रचना की। मैं बाबा औघड़नाथ की उस भूमि से आया हूँ। जहाँ 10 मई, 1857 को 165 वर्ष पूर्व क्रांति हुई थी और 85 सैनिकों के साथ मातादीन बाल्मीकि हवलदार और कोतवाल धनसिंह गुर्जर ने उस क्रांति को प्रारम्भ किया था कि ''दिल्ली अब दूर नहीं।'' आजादी के 75 साल बाद 75 साल में पहला कोई मुख्य मंत्री हुआ जिन्होंने 10 मई को मेरठ की धरती पर पहुंचकर उन वीर शहीद क्रांतिकारियों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। अपनी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण के कारण ही 37 वर्ष बाद कोई ऐसा मौका आया जब कोई सरकार लगातार दोबारा पुनः यहाँ पर पदासीन हुई है और यह मेरे लिए भी गौरव का विषय है, गौरव का अवसर है कि मैं भी 20 साल बाद इस सदन में आपके समक्ष जीतकर उपस्थित

हुआ हूँ। निश्चय ही यह लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मान्यवर, बजट यहाँ रखा गया, इस बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 31 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 56 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, परिवहन में 11 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, ऊर्जा में 17 प्रतिशत का, पुलिस विभाग 30 प्रतिशत का, समाज कल्याण और पेंशन में 33 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में 19 प्रतिशत, शहरी विकास में 48 प्रतिशत, जलापूर्ति और सैनिटेशन में 58 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 21 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है। यह बजट वर्ष 2016-2017 के समाजवादी पार्टी की सरकार बजट के मुकाबले सवा दो गुना अधिक धनराशि व राजस्व का बजट है और पिछले वर्ष इसी सरकार ने जो बजट रखा था उसके मुकाबले 28 प्रतिशत अधिक धनराशि व राजस्व का यह बजट है। चूंकि कुल राजस्व का 45 प्रतिशत वेतन, पेंशन और ब्याज में चला जाता है, मात्र 55 प्रतिशत ही विकास के कार्यों के लिए बचता है। मान्यवर, सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 4 हजार 747 करोड़, ग्रामों एवं मजरों को सर्वऋतु मार्गों से जोड़ने के लिए 1 हजार 965 करोड़, बाईपास एवं रिंग रोड एवं चौराहों के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 600 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतुओं के लिए 1250 करोड़, जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 2600 करोड़, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। इसमें राजकोषीय घाटा मात्र लगभग 4 प्रतिशत दर्शाया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है, निश्चित ही बचत और मितव्ययिता अपनाकर उसे पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, वर्ष 2016-2017 के सापेक्ष एथनाल का उत्पादन ढाई गुना हुआ है। पिछली सपा सरकार के समय में यूरिया के बोरे के लिए किसान को डण्डा खाना पड़ता था जो अब नहीं खाना पड़ता। कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया व्यवस्था बनाकर रखें, आपस में बातचीत न करें।

श्री अमित अग्रवाल-

श्रमिकों का ई-रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके खातों में 1000, 2000, 4000 रुपयों का भुगतान हो रहा है। घरों में काम करने वाली माता, बहनों का भी अब श्रमिक श्रेणी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वह सम्मान पा रही हैं। वहीं उज्ज्वला गैस के अन्तर्गत उन्हें सिलेण्डर देकर उनकी आंख व फेफड़ों को मोदी जी व योगी जी ने बचाया है। शौचालय देकर तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करके योगी जी मां-बहनों की आंख का तारा बन गये हैं।

''माँ बहनों की आंख का तारा,
हम सबका दुलारा,
सबका प्यारा, सबसे न्यारा,
योगी जी हमारा।''

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके लिए निवेश प्रदेश में बढ़ रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से अनाथ, प्रभावित हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा हेतु मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपये और अन्य भिन्न कारणों से माता-पिता के खो देने वाले बच्चों को 2500 प्रतिमाह सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। जब पूरा विश्व कोविड-19 की वैश्विक महामारी से त्रस्त था और कोई घर से भी नहीं निकल रहा था सब बेबस थे और सड़कों पर आदमी भी नहीं दिखाई देता था तब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खुद बीमार रहते हुए भी बाहर निकलकर जनता की सेवा की और विश्वस्तरीय इलाज का उन्होंने प्रबन्ध किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अगर लिख करके लाये हैं तो वह जमा कर दें उसे पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, कोविड-19 के समय हमारे यहाँ 195 करोड़ को वैक्सीन की डोज दी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे श्रद्धेय अटल जी की उन पंक्तियों को सार्थक किया है।

बाधाएं आती हैं आयें,
घिरे प्रलय की घोर घटायें,
पांवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसे यदि ज्वालायें,
निज हाथों से हंसते-हंसते,
आग लगा कर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।

श्री अधिष्ठाता-

लिख करके लाये हैं तो वह जमा कर दें उसे पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा, आप कहिये तो जमा करा दें।

श्री अमित अग्रवाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे श्रद्धेय अटल जी की उन पंक्तियों को सार्थक किया है, जब सड़कों पर लोग नहीं निकलते थे और सड़कें सूनी थीं तो उन्होंने लिखा था-

बाधाएं आती हैं आयें, घिरे प्रलय की घोर घटायें,
पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालायें,
निज हाथों से हंसते-हंसते आग लगा कर जलना होगा,
कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा।

मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को, सरकार को, मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राज कुमार सहयोगी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री और गुणी वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण योजनाओं के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, प्रदेश के विकास और महिलाओं की सहभागिता के लिए प्रतिबद्धता दर्शायी गयी है। व्यापारियों का कल्याण, युवाओं का उत्थान, गांव-गरीब, किसान, बेरोजगार, नौजवान, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास में अच्छी सड़कों की भूमिका अहम होती है। बजट में अच्छे सम्पर्क मार्ग, अधिक एक्सप्रेस-वे, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की प्रतिबद्धता दर्शायी गयी है। आदरणीय योगी सरकार का बजट आदरणीय मोदी जी के नये भारत की परिकल्पना की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। इस बजट में देश के महापुरुष आदरणीय पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, जो हम सबको प्रेरणा देती है, समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे गरीब व्यक्ति को भगवान का स्वरूप मान करके उसकी सेवा करने के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास से विधायक हूँ और जाटव समाज से हूँ। सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब क्या चाहते थे उसका चिन्तन-मनन किया और उसी चिन्तन में से एक चिन्तन निकाला कि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव के गरीब का बेटा, जाटव समाज का बेटा, आज कायाकल्प हुए प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जा रहा है, पौष्टिक आहार बच्चों को मिल रहा है, यह परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की है। जबसे देश आजाद हुआ, इतनी सरकारें केन्द्र में रहीं किसी ने भी जाटव समाज की चिन्ता नहीं की, बाबा साहब की चिन्ता नहीं की कि बाबा साहब क्या चाहते थे। मान्यवर, आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सम्मान 2014 से अपने जाटव समाज की बेटियों को आज मिला है वह जबसे देश आजाद हुआ आज तक कभी नहीं मिला। सब जानते हैं कि जब पहले गरीब जाटव समाज की बेटियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती थीं तो माँ को तब तक रोटी अच्छी नहीं लगती थी जब तक कि बेटी घर नहीं आ जाती थी। जबसे प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है गुण्डे और माफियाओं से भयमुक्त समाज बन गया है।

मान्यवर, 2022 के संकल्प-पत्र में 97 घोषणा धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारी हैं। पिछले गत वर्ष में 5 लाख 50 हजार 271 करोड़ का बजट था और वर्तमान में वर्ष 2022-2023 में 6 लाख 15 हजार 519 करोड़ सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, 11.86 प्रतिशत ज्यादा पेश किया है। आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को और अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सरकार की यह भूमिका है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री राज कुमार सहयोगी-

मान्यवर, अभी 28 तारीख को हमारे एक मा0 सदस्य कह रहे थे कि एस0सी0 और बी0सी0 की चिन्ता नहीं की जाती है। मैं आपको अलीगढ़ जनपद की बात बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें एस0सी0 और बी0सी0 को एडमिशन नहीं मिलता है। आदरणीय योगी जी को जब पता चला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एस0सी0 और बी0सी0 को खासतौर से एडमिशन नहीं दिया जाता है तो आदरणीय योगी जी ने उससे बड़ी यूनिवर्सिटी जाट शिरोमणि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के नाम से अलीगढ़ में देने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

सहयोगी जी, अब आपका हो गया। आप अपनी बात समाप्त कर दीजिये। श्री अनिल प्रधान जी

***श्री अनिल कुमार अनिल प्रधान-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम चित्रकूट की जनता-जनार्दन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सादर प्रणाम करता हूँ। उनको हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चित्रकूट की जनता ने और मा0 अखिलेश यादव जी ने किसान घर के लड़के को मौका देकर लखनऊ की विधान सभा में भेजने का काम किया है ताकि किसान, मजदूर और मजलूमों की आवाज लखनऊ तक पहुंचायी जा सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी का और जनपद चित्रकूट की प्रत्येक जनमानस को मैं हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, आपने बजट के संदर्भ में मुझे बोलने का मौका दिया। जो बजट सरकार द्वारा इस सदन में पेश किया गया, उससे निश्चित रूप से किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ी निराशा प्रतीत हुई है। चूंकि मैं बुन्देलखण्ड के चित्रकूट सदर सीट से आता हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बुन्देलखण्ड में अगर किसी ने सबसे ज्यादा विकास करने का काम किया है, तो वर्ष 2012-2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में मा0 अखिलेश यादव जी ने विकास और काम करने का काम किया है। वर्ष 2012-2017 के बीच में बुन्देलखण्ड में सूखे जैसी स्थिति पड़ी थी। उस दौरान पूरे बुन्देलखण्ड में किसानों को तीन-तीन बार 18 हजार रुपये के चेक देने का अगर किसी ने काम किया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग छह हजार वार्षिक किसान सम्मान निधि देने का ढिंढोरा पीटते हैं। पर वहीं छह हजार की राशि से एक-एक किसान से 20-20 हजार रुपये आप उनकी बिजली, खाद, पानी, डीजल-पेट्रोल से साल भर वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार करने का काम कर रही है।

जनपद चित्रकूट में जिस जगह से मैं प्रतिनिधित्व करके आया हूँ। जनता ने चित्रकूट सदर से मुझे विधान सभा में भेजा है, जो भगवान कामतानाथ की पावन धरती है और पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक अलग अपनी आस्था के लिए जाना जाता है। वर्ष 2012-2017 के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने भी काम करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। कामतानाथ स्वामी के परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टीन शेड का निर्माण, रोप-वे का निर्माण, कामतानाथ परिक्रमा जाने के लिए भरतकूप से खोही तक रोड का निर्माण, बेड़ी पुलिया से रोड का निर्माण, बस अड्डा का निर्माण, 220 केवीए विद्युत केन्द्र का निर्माण, दो तहसील का निर्माण, सैंकड़ों, दर्जनों की मात्रा में पुलों का निर्माण अगर किसी की सरकार में हुआ है तो मा0 नेता जी और अखिलेश यादव जी की सरकार में सबसे ज्यादा काम जनपद चित्रकूट में हुआ है।

इसीलिए तमाम सारी बातों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ हमारे बुन्देलखण्ड के विधायक बैठे हुए हैं। हम सब लोग बड़े पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और मैं विशेष रूप से चित्रकूट की बात कहना चाहूँगा कि चित्रकूट में सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। डॉक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, लोग परेशान हैं। लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है, हालत यह है कि 98 प्रतिशत मरीजों को इलाहाबाद में रेफर किया जाता है और इलाहाबाद में भी हमारे लोगों को नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं अपने बुन्देलखण्ड के सभी विधायकों की ओर से और अपनी ओर से सरकार से निवेदन करता हूँ कि बुन्देलखण्ड में मेडिकल की व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए एक मेडिकल, एक एम्स की स्थापना बुन्देलखण्ड में करायी जाये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट में सभी कार्य हमारी सरकार के समय में हुए

थे। अभी तक हमारे मा0 सदस्य कह रहे थे कि अयोध्या के लिए मा0 योगी जी की सरकार में लगभग 100 करोड़ रुपये की योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया है मैं सरकार से निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि चित्रकूट में भी जहाँ हमारे पूर्वज श्रीराम चन्द्र जी ने भी वास किया है मेरा निवेदन है कि चित्रकूट के विकास के लिए भी तमाम सारी परियोजनाएं और बजट देने की व्यवस्था की जाये। जनपद चित्रकूट में जो गौशालाएं संचालित हैं 8 महीने से उनका भुगतान नहीं किया गया है। जनपद चित्रकूट की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाय। मां मंदाकिनी की सफाई कार्य कराने के लिए अलग से व्यवस्था की जाये। जनपद चित्रकूट में 220 बेड के मातृत्व चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 समेत सभी व्यवस्थाएं संचालित की जायें। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को देखते हुए उसमें सरकारी नलकूप लगाये जायें और सिंचाई के लिए बरुआ बांध तक पानी ले जाने की कार्य योजना बनायी जाये। जनपद चित्रकूट के संयुक्त जिला चिकित्सालय में हड्डी और प्रसव रोग के लिए महिला विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञों की व्यवस्था कराकर 24 घंटे आपरेशन की व्यवस्था की जाये। चित्रकूट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं वहाँ पर समुचित मात्रा में डॉक्टर की व्यवस्था करायी जाय। 108 एम्बुलेंस सेवा में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको दूर किया जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवा लाचार है उसको सुधारने की आवश्यक कार्यवाही की जाय, देवांगना घाटी से खोवा बाईपास का निर्माण कराया जाय और हमारे चित्रकूट में रामराज्य आ गया है अभी 7 दिन पहले खुलेआम 55 लाख की डकैती पड़ गयी। 10 दिन हो गये पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कई इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो घटनाएं घटीं उन पर तत्काल पुलिस खुलासा करे और एक हमारी बहन रोशनी मिश्रा थीं जिसकी दर्दनाक मौत हो गयी थी, जिला अस्पताल में उसकी भी जांच करायी जाय और हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है।

***श्री अनिल राजभर-**

मान्यवर, आपने हमें बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ और सर्वप्रथम श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ मैं उनका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, यह सम्मानित सदन इसकी दरें और दीवारें इसका जर्रा-जर्रा सरकारों के लिए गये फैसलों का गवाह है और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ बजट पेश किया है, मान्यवर लोकतंत्र में जनता की इच्छाएं उसके सपने जब परवान चढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का यह मंदिर भी सार्थक होता है। बहुत से फैसले सरकारों ने लिए होंगे, बहुत सी सरकारों ने अपना बजट पेश किया होगा। लेकिन जो उम्मीद, जो भरोसा, जो यकीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुमार खन्ना जी ने यहाँ पर जो बजट रखा है उसमें जो भरोसा जनता के दिलोदिमाग में पैदा किया है वह एक बड़ी बात है और हम स्वागत करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे संघर्ष की विरासत को एक नई पहचान देने का काम यह सरकार कर रही है, खासतौर से हमारे उन महापुरुषों के लिए जिनको भुला दिया जमाने ने, उन महापुरुषों के नाम को, उनकी वीरता को, उनके भारत भूमि पर किये गये काम को, जिस तरह से हमारी सरकार पहचान दे रही है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ।

आजमगढ़ की धरती पर, पूर्वांचल की माटी पर, जिस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम का विश्वविद्यालय बनाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो हमने देखा है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता अभी बोल रहे थे, हमने देखा है कि किस तरह से देश को लूटने वालों, जो देश को लूटने आये, जो एक आक्रान्ता थे, आक्रमणकारी थे ऐसे लोगों की मजारों को सजाने का काम इन लोगों की सरकारों ने किया है। मैं बहराइच की बात करूं तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की वो धरती और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने हिन्दू और हिन्दुस्तान की रक्षा करने का काम किया, उनको इन लोगों ने भुला दिया और एक डाकू की मजार को इन लोगों ने सजाने का काम किया। यह सिर्फ एक घृणित प्रयास ही नहीं था बल्कि उनके द्वारा किया गया एक पाप था। मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का, अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि उस महामानव ने जिसने भारत भूमि के लिए अपना सब-कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि उनकी वीरता और प्रताप का असर यह था कि जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का तूफान चला तो हिन्दुस्तान की धरती पर ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर भी उनके चिरागों को बुझा देने का काम किया था। मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का जब अयोध्या की धरती पर आते हैं, भगवान श्रीराम के मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो उन्होंने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। जब बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के धाम को, भारत की जनता को समर्पित करते हैं तब भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। हम यह सवाल करते हैं कि यह कौन है सैय्यद सालार मसूद गाजी, क्यों उनकी मजारों को सजाने का काम किया गया। उसी बहराइच की धरती पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान इन लोगों ने किया है। यह सच्चाई को समझना नहीं चाहते। उसका परिणाम आज इनके सामने है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम बार-बार अभिनन्दन करना चाहते हैं जब हमारी सरकार बहराइच के अन्दर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाती है, जब स्मारक बनाती है तब हम अभिनन्दन करना चाहते हैं। गाजीपुर की धरती से दिल्ली तक जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का काम यह सरकार करती है, मोदी जी का रेल मंत्रालय करता है तो हम स्वागत करना चाहते हैं। जब डाक टिकट जारी करके सरकारी दस्तावेजों में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का नाम जब सरकार दर्ज कराती है तो अनिल राजभर ही नहीं भारत भूमि से प्यार करने

वाला, भारत भूमि को अपनी माँ समझने वाले हर राष्ट्रभक्त को इस सरकार पर गर्व होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये एक डाकू की मजार को सजाते हैं। ये सैय्यद सालार मसूद गाजी को ये भगवान बनाकर पूजते हैं जो अफगानिस्तान से लूटने आया था। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हम इसलिए स्वागत करना चाहते हैं, अभी हमारे साथी महेन्द्र सिंह चर्चा कर रहे थे जो विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया, बहराइच की धरती पर वहाँ के मेडिकल कालेज को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का नाम देकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम सरकार ने किया है तो इनको दर्द होता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं भाषण सुन रहा था कि पिछड़े पावें सौ में साठ। यह पूरी तरह से बकवास है। राजभर, बिन्द, बियार, चौहान, केवट, मल्लाह अभी संजय भाई बोल रहे थे। यही बात करके इन लोगों ने हमारे अति पिछड़े समाज को ठगने का काम किया है। यह चार बार सरकार में रहे हैं और कभी बैठेंगे तो मै चारों बार के आंकड़े रख दूंगा कि राजभर को कितना पूछा, निषाद को कितना पूछा, चौहान को कितना पूछा, मल्लाह, पाल, गड़रिया को कितना पूछा, प्रजापति कुम्हार को कहाँ पहुंचा दिया। इन गरीबों ने मौका दिया और जब भी इनको मौका मिला तब यह अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पाये। यह सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं और सदन में आकर अपना फ्रस्टेशन दिखाते हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से भागें मत सच्चाई को स्वीकार करें तो शायद राजनीतिक अस्तित्व बच जायेगा नहीं तो आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं बचेगा, इसलिए आज जो गरीबों का काम हो रहा है, हमारे जो महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, हमारी जो परम्पराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम उनका स्वागत और अभिनन्दन करना चाहते हैं। साथ ही मैं अपने विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूँ। इस बजट में हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिल खोलकर जो समाज में अन्तिम पंक्ति पर खड़ा है, जो गरीब है, जो मजदूर का बेटा है, जो सैनिक का बेटा है, जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, जो सगड़ी चलाने वाले का बेटा है, वह कमजोर लोग, जिनके सपने कभी साकार नहीं होते, हमारी सरकार ने कहा है, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है दोनों बांह फैलाकर गरीबों को हमारी सरकार ने आवास दिया है। हम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहते हैं, तुम्हारे अरमानों को भी परवान चढ़ाना चाहते हैं। आज जिस तरह से हमारी सरकार ने फैसला किया है, नवोदय की तर्ज पर विद्यालय बनाने जा रहे हैं। कभी सपना भी नहीं देखा होगा 75 वर्ष के आजाद हिन्दुस्तान में कभी श्रमिक ने सोचा नहीं होगा कि अटल विश्वविद्यालय जो हम बनाने जा रहे हैं, यह श्रमिक का बेटा, यह भट्ठे पर काम करने वाला, मट्टी और माटी में अपना बचपन गुजारने वाला, कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे लिए भी कोई सरकार इतना दिल खोलकर काम कर सकती है। यह आवासीय अटल विद्यालय बनाने जा रहे हैं, यह नवोदय की तर्ज पर बनाने जा रहे हैं, हर मण्डल के मुख्यालय पर बनाने जा रहे हैं।

हमारा गरीब और गरीब का बेटा आज उसमें पढ़ेगा, उनकी बेटियां पढ़ेंगी। हमारे जो सड़क के किनारे मजदूर पड़े रहते हैं, हम उनके लिए शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला जब मेहनत करता है तो रात में कैसे सोता है, कभी किसी ने देखा नहीं होगा, सड़क के किनारे पटरी पर रात गुजारकर चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी दिन हो, दिन भर काम करता है और किस तरह से वहाँ उसकी रात बीतती है, किसी सरकार ने चिन्ता नहीं की होगी, लेकिन हम अपनी सरकार का स्वागत करना चाहते हैं। हम शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर हम ऐसे लोगों को पनाह देंगे, ऐसे लोगों को हम घर बनाकर देंगे, ऐसे लोगों को रुकने की व्यवस्था देंगे, हम पेट भरने का भी उनका इन्तजाम करने जा रहे हैं। हम ऐसे गरीब, ऐसे मजदूर, ऐसे बेबस और लाचार लोगों को सड़क के किनारे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को हम घर देंगे, हम उनके भोजन का इन्तजाम करेंगे, मन चाहे तो वह अपने परिवार को भी लेकर आयें, उनको भी रुकने की हम व्यवस्था देंगे, शेल्टर होम में वह रहेगा। दिन में हमारा श्रमिक मजदूरी करेगा और रात में आराम से जाकर दो जून की रोटी खाकर वहाँ समय बिता सकता है। यह जातीय जनगणना की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, यह अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ। आपको दोबारा टोकना नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जाति और जनगणना की बात बार-बार उठाते रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी भी सरकार थी और आपके समर्थन से दिल्ली में भी सरकार चल रही थी क्यों नहीं जाति जनगणना करा लिया। आजाद हिन्दुस्तान में 75 वर्ष के आजाद हिन्दुस्तान में हमें जरूरत नहीं है आप आरक्षण की बात करते हैं आपने जो नौकरियां दीं आपकी सरकार में जो नौकरी मिली माननीय अखिलेश यादव जी 62 प्रतिशत अकेले आपके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में जगह मिली है। राजभर दशमलवों के भी आंकड़े में भी नहीं है। हमारे चौहान दशमलवों के आंकड़े में भी नहीं हैं, हमारे निषाद दशमलवों के आंकड़े में भी नहीं हैं। आपकी सरकार अगर यहाँ चल रही थी तो यह राजभर, बिन्द, बियार, चौहान, निषाद यह गरीब आदमी कहाँ थे बंगाल की खाड़ी में थे कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। वह सामाजिक न्याय कहाँ गया यह सामाजिक परिवर्तन के नाम पर समाजवादी पार्टी बनाने वाले लोगों से अनिल राजभर सवाल करता है और यह जवाब दें कि चार बार की सरकार में मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि 62 प्रतिशत अकेले उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिली है।

राजभर, चौहान और निषाद के दशमलवों की भी संख्या नौकरी में नहीं है और यह समाजवाद की बात करते हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह ढकोसलावाद है, समाजवाद नहीं है। समाजवाद का नारा देकर यह अति पिछड़ों और अति दलितों को ठगने वाले हैं। जब-जब यह सरकार में आये हैं तब-तब हमारे हक, अधिकार को हड़पने का इन लोगों ने काम किया है। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देकर अपनी बात को रोकता हूँ कि आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम अट्ठारहवीं विधान सभा के समस्त नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूँ। साथ ही माननीय मुख्य मंत्री योगी सरकार-2 के द्वारा सर्वसमावेशी लोक हितकारी जनसरोकारों से जुड़ा बजट प्रस्तुत करने हेतु हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, साथ ही उत्तर प्रदेश विधान सभा को पूर्णतः डिजिटल विधान सभा, पेपरलेस विधान सभा बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुआयामी वैज्ञानिक विजन और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रगतिशील तकनीकी मिशन को माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो पूरा किया गया है उसके लिए सादर आभार प्रेषित करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी सैंतीस वर्ष के उपरान्त पहली बार उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया। जब एक सरकार के कार्यकाल के बाद एन्टी इन्कमबेन्सी के स्थान पर प्रो इन्कमबेन्सी की अवधारणा सत्य साबित हुई और यह माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है कि योगी सरकार जन आक्रोश के स्थान पर जन आकांक्षाओं के द्वारा पुनः वापसी में सफल हुई। मान्यवर, मात्र राजा और राजधानी का सफल होना राज्य की सफलता नहीं माना जाता है। किसी का राज होने और किसी का राज्य होने में अन्तर होता है। राज में राजा का महत्व होता है किन्तु राज्य में प्रजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज की धारण निर्भरता की पोशक है तो राज्य की अवधारणा आत्मनिर्भरता को पल्लवित करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी रामराज को नहीं अपितु राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पर व्यक्ति से अधिक महत्व विचार का है व्यवस्था का है जहाँ प्रजा के रक्षण और पोषण का कार्य कोई व्यक्ति नहीं विचार करते हों जहाँ व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था के महत्व को बढ़ाना हो वहाँ चरण नहीं आचरण को धारण करना पड़ता है। योगी सरकार ऐतिहासिक रूप से अपना लगातार छठवां बजट प्रस्तुत कर रही है। जिसमें सर्वसमावेशी संकल्पों को साकार किया गया है। पांच वर्ष के लिए बने लोक कल्याण संकल्प-पत्र के 130 संकल्पों में से सत्तानबे संकल्पों को अपने बजट में शामिल करना माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अद्भुत क्षमता और आदरणीय मुख्य मंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की असीमित क्षमता का परिचायक है। इस बजट में पूर्ववर्ती सरकारों के वर्ग विशेष की पुष्टि की संकल्पना के स्थान पर प्रत्येक वर्ग की संपुष्टि को सर्वाधिक महत्व दिया गया

है। जिसके बारे में मुझसे पहले तमाम पूर्ववक्ताओं ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। मैं भी हृदय से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद देती हूँ। केवल एक बात पर विशेष तौर पर बल दूंगी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अयोध्या, मथुरा और काशी को आध्यात्मिक पर्यटन हेतु सुसज्जित करने की बात रखी है वह अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़े खुशी का विषय है। बहुत बड़े संतोष का विषय है।

मैं एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को विराम दूंगी कि मेरे स्वर्गीय पिता श्री राम प्रकाश त्रिपाठी इसी सदन के चार बार सदस्य रहे हैं। वह मुझे अपना एक अनुभव बताया करते थे कि वह जिस समय बी0एन0एस0डी0 कालेज रामपुर के छात्रसंघ के अध्यक्ष थे, उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के साथ तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव का आना हुआ था। वह बताते हैं कि जब सुबह उन्होंने अखबार देखा तो उस अखबार में लिखा था कि रूस के राष्ट्रपति महोदय आगरा का ताजमहल देखकर आये और उन्होंने अपना उत्तर भी दिया कि मैंने ताजमहल देखा, वह एक सुन्दर इमारत है, लेकिन उसमें कछ मजदूरों के पसीनों की दुर्गन्ध लगी। मेरे पिताजी ने उसी लाईन को कोट किया और उन्होंने पांच मिनट का वक्त मांगा जिस पर उन्हें केवल पांच मिनट का वक्त दिया गया। उन्होंने मंच के पैर छुए और कहा कि पंडित जी महाराज, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल एक ही बात कहूँगा कि आज के बाद जब भी कोई विदेशी मेहमान आये तो उसको अरावली की वह पहाड़ियां दिखाईये, हल्दीघाटी की वह जगह दिखाईये जहाँ आज भी चेतक की टाप सुनाई देती है, वह छत्रपति शिवाजी की तलवार की चमक दिखाईये। अगर दिखाना है तो अयोध्या की वह धरती दिखाईये जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ था। दिखाना है तो हमारे मथुरा की वह यमुना नदी दिखाईये जहाँ पर कालिया नाग का नाच हुआ था। दिखाईये तो कुरुक्षेत्र की वह धरती दिखाईये जहाँ योगीराज कृष्ण ने गीता का पाठ किया था। निश्चित रूप से आज मुझे इस बात की ख़ुशी हो रही है कि वह स्वर्ग में जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से बैठकर देख रहे होंगे और सोचते होंगे कि चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, जब भी कोई यहाँ घूमने का मन बनाता है, भारत को देखने का मन बनाता है, उत्तर प्रदेश को देखने का मन बनाता है तो सबसे पहले सोचता है कि अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, मथुरा जायेंगे, वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ के कारीडोर को देखेंगे। हमारे आदरणीय योगी जी ने हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आज जिस प्रकार से मान और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मा0 अधिष्ठाता जी, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उनको मैं लिखकर के इस विश्वास के साथ आपके पास भेज दूंगी कि उन्हें निश्चित रूप से इसमें शामिल कर लिया जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार जी।

(सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार के अनुपस्थित रहने पर)

अब अगला नाम मा0 सदस्य श्री कमाल अख्तर जी का है।

***श्री कमाल अख्तर-**

मा0 अधिष्ठाता जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2022-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया। हर बार सरकार द्वारा एक बड़ा बजट लेकर के आया जाता है और कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा बजट है, लेकिन इस बजट के बाद उत्तर प्रदेश के जो नौजवान थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने निश्चित तौर पर अपने को ठगा-सा महसूस किया होगा। हम बड़ा बजट जरूर लाते हैं, लेकिन जो पिछला बजट है अगर हम उसको देखेंगे तो उस बजट को हमने पूरा खर्च करने का काम नहीं किया। इसलिए जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा बजट लाने की कोई वजह थी।

मान्यवर, सरकार द्वारा पंचायत राज के अन्दर पंचायतों की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग से प्रधानों को धनराशि मिलती है। हर गांव के विकास की जड़ राज्य वित्त आयोग तथा 15वां वित्त आयोग है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने करोड़ों नौकरियां दे दीं, पांच लाख नौकरियां दे दीं। उन्होंने नौकरियां कैसे दी हैं ? नौकरियां ऐसे दी हैं कि उन्होंने अभी पंचायत सहायक की एक भर्ती की और हर ग्रामसभा के अन्दर एक पंचायत सहायक रखा, लेकिन इस बजट के अन्दर कहीं भी उनके वेतन के लिए प्रावधान नहीं किया, बल्कि राज्य वित्त आयोग से जो धनराशि गांव के विकास के लिए मिलती थी उसी से 6000 रुपये उनको देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने शौचालय बनाये और उसमें जो सफाई कर्मचारी रखे उसका भी पैसा प्रधानों से देने का काम किया। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सरकार अगर गांवों का सच्चा विकास करने वाली, पंचायत राज को सुदृढ़ करने वाली तथा गांवों को मजबूत करने वाली होती तो इन नौकरियों का अलग से प्रावधान करती और जो गांव के प्रधान हैं उनके पेट पर लात मारने का काम नहीं करती। निश्चित तौर पर यह पैसा जो खर्च हो रहा है यह गांवों के विकास का पैसा खर्च करके सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है।

मान्यवर, जहाँ तक सरकार कायाकल्प करने के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन जो स्कूलों के अन्दर पैसा लग रहा है वह भी राज्य वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत जो मिलने वाली राशि है उससे लग रहा है। जहाँ तक चिकित्सा के ऊपर बजट का सवाल है तो अभी यहाँ पर मा0 मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जगह-जगह ऑक्सीजन प्लाण्ट लगवाने का काम किया है। कोरोनाकाल के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी थी, इसलिए मा0 विधायकगणों ने भी 50-50 लाख रुपये ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाने के लिए दिये हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाये गये हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाये गये हैं वह 90 प्रतिशत डीजल की वजह से या बिजली के कनेक्शन की वजह से बन्द पड़े हुए हैं। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत है तो वेन्टीलेटरों की भी जरूरत है, अगर जरूरत है तो फिजीशियन की भी जरूरत है, अगर जरूरत है तो आई0सी0यू0 की भी जरूरत है। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल के अन्दर आई0सी0यू0 और वेन्टीलेटर नहीं लगाये गये हैं। ऑक्सीजन प्लाण्ट आज वहाँ पर इस तरह से रखे हैं जैसे उनको सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है। अभी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि हम अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ाई करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनाये जा रहे हैं। कक्षा-6 से कक्षा-12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चे कहाँ जायेंगे ? पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चे क्या होटलों पर बर्तन मांजेंगे या वे गरीब बच्चे कहीं पर मजदूरी करके, बाल मजदूरी का ढिंढोरा पीटने का काम करेंगे ? मैं कहना चाहता हूँ कि अटल आवासीय विद्यालयों के अन्दर पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम करना चाहिए था।

मा0 मुख्य मंत्री जी की एक भावी आर0ओ0 पेयजल योजना है, प्रदेश के जापानी इन्सेफेलाइटिस और ए0ई0एफ0 प्रभावित बस्ती, गोरखपुर मण्डल, बुन्देलखण्ड, बांदा, चित्रकूट के जनपदों के अन्दर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के अन्दर आर0ओ0 यंत्र लगाये जायेंगे जिससे बच्चों को अच्छा पानी मिल सकेगा, बच्चों को क्लीन पानी मिल सकेगा, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बच्चा स्कूल के अन्दर 6 घंटे तक रहता है, 6 घंटे तो वह आर0ओ0 का पानी पियेगा और उसके बाद घर जाकर 18 घंटे जो पानी पियेगा वह पानी उसको बीमारी की ओर ले जायेगा और बर्बाद करने का काम करेगा। सीधे-सीधे मैं कह सकता हूँ कि यह सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए योजनाएं हैं और ये लोग इस तरह की योजनाओं को लाकर लोक-लुभावन के कार्य करने का काम करते हैं। अभी मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचार इस योजना का किया जा रहा है और जब-जब इस योजना का जिक्र आता है तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे इसी योजना ने सरकार बनाने का काम किया है। सरकार ने इस योजना को 2 जून, 2022 तक बढ़ाया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस योजना को आप पूरे साल चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर बजट के अन्दर इसका प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह योजना जून, 2022 के बाद बन्द हो जायेगी ? अगर कहीं भी इस योजना को चालू करना होता तो निश्चित तौर पर सरकार इसको चलाने का काम करती। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे मुरादाबाद के

अन्दर रामगंगा बहती है, मुश्तापुर से लेकर सलमसरायं एक गांव पड़ता है जो मेरी विधान सभा के अन्दर आता है। जब रामगंगा जी में बाढ़ आती है तो पूरी फसल, पूरा इलाका गंगा जी के पानी में डूब जाता है। मेरा अनुरोध है कि गंगा जी पर जो बांध बनना है वह सलमसरायं तक बना दिया जाय। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बात हो रही थी कि हमारा बजट बड़ा है, जो कि निश्चित रूप से है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बजट को बहुत बड़े दिल के साथ बनाया गया है। बजट में जो व्यवस्था की गयी है, विशेषकर समाज कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जहाँ एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है और हमारा प्रदेश एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। अर्थव्यवस्था एक कारवां की तरह है। कुछ लोग बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और कुछ लोग पीछे छूट सकते हैं। कोई बहुत पीछे न छूटे इसीलिए समाज कल्याण विभाग अपना काम करता है और उसमें विशेषकर अन्तिम पायदान पर खड़े हुए भाई-बहन या थर्ड जेण्डर के लोग हैं, हम लोगों को उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। उससे पहले यह वह अवसर है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। डॉ0 बाबा साहेब आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था दी थी वह मूल रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर दी गयी थी। अब धीरे-धीरे इस पर व्यवस्था बदली है। सामाजिक न्याय के जो पात्र हैं उसमें पिछड़ा वर्ग भी जुड़ा तथा महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने में जुड़ीं और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया जिसकी पहली बैठक अभी हुई थी। किन्नर समाज की बात करें तो वह सबसे बहिष्कृत समाज या शायद इससे ज्यादा अन्याय हमारे समाज ने किसी व्यक्ति, समूह के साथ नहीं किया होगा। उनका उपहास किया, उनके नाम को एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। अब इसमें बड़ा परिवर्तन हो रहा है। किन्नर कल्याण बोर्ड को सक्रिय किया गया है और बजट भी दिया गया है, जिस पर काम होगा। दूसरा हम लोग बाबा साहेब के लेखन को पढ़ते हैं। उनके भाषण को पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होने बार-बार अवसर की समानता की बात कही। हम अगर किसी खेल, जैसे कुश्ती की बात करें तो एक सोच यह हो सकती है कि सारे पहलवान बराबर हैं, बराबर लड़े और जीते। लेकिन उसी में वजन की कैटेगरी होती है जिसके आधार पर लोग खेल में प्रतिभाग करते हैं। यही प्रतिभाग ऐसी कैटेगरी में व्यवहारिक बनाना, अवसर की समानता है। मुझे बताते हुए

प्रसन्नता है कि उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभ्युदय योजना विगत वर्ष शुरू की थी। इस योजना के साथ जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का सिस्टम बदल गया है। अब क्लास में बैठकर पढ़ाई कम होती है, ऑनलाइन ज्यादा होती है। इसके लिए इस बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिससे कि जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनको टैबलेट देकर या जो मेन परीक्षा या इण्टरव्यू की परीक्षा दे रहे हैं, उनको कोचिंग में अच्छी तैयारी करा पायें। इसी के साथ समाज कल्याण की जो अन्य योजना है, उसमें सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा। वृद्धावस्था पेंशन जो हम लोग चला रहे हैं इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 3694 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और इस बार बढ़ाकर 4278 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया।

अब 56 लाख लाभार्थी हो गये हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी वृद्ध न छूटे एवं कोई अपात्र व्यक्ति या जिसकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गयी है, उनका समय से नाम कट जाये। जिसके लिए आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। करीब 50 प्रतिशत से अधिक लिंक हो चुका है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जो हम लोग बच्चों को देखते है। उसमें इस साल 1510 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ताकि कोई बच्चा न छूटे, व्यवस्था को और पारदर्शी कर रहे हैं। साफ्टवेयर को और आसान कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को शुरू से पता चल जाये कि उनको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी मिलेगी जिससे कि उनके मन में कोई संशय न रहे। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत परिवार की मुखिया की मृत्यु एक्सीडेन्ट या अन्य कारण से हो तो उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं और इसके लिए बजट बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और एक बहुत ही सफल योजना है मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना जिसमें अभी भी आगे 10 से 17 जून को विवाह आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 विधायकगणों को आमंत्रित करना चाहूँगा और सभी जिलों, स्थानीय स्थल पर भी आमंत्रण पहुंचा दिया जायेगा। पिछले वर्ष 118 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी इसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए हम लोग एक आनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रहे हैं जिससे कि सभी का पहले ही पंजीकरण हो जाये और समय से सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार का बजट सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला है।

श्री अशोक कुमार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट भाषण पर बोलने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सदन में पहली बार सदस्य बनकर आया हूँ, इसके पूर्व में मेरे पिता स्वर्गीय दल बहादुर कोरी जी इस सदन के तीन बार सदस्य रहे हैं और राज्य सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। सदन में उपस्थित मैं सभी सदस्यों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। विशेष आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पर जितने भी विधान भवन रक्षक कर्मचारी हैं, क्योंकि लगभग बीस वर्ष

पहले मैंने उन सबके साथ इसी विधान सभा में विधान भवन रक्षक के रूप में भी कार्य किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली जनपद रायबरेली की सलोन विधान सभा क्षेत्र जोकि एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र है जो जनपद रायबरेली के साथ-साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र को भी जोड़ती है वहाँ की महान जनता के आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय सरकार के इस बहुआयामी बजट के लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उ0प्र0 की भाजपा सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महोदय महाराजा मान्धाता के वंशज हमारे समाज की वीरांगना झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना इस बजट में सम्मिलित की गयी है। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(इसी मध्य सायं 04 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता श्री उमाशंकर सिंह पीठासीन हुए)

महोदय, सरकार के इस नये बजट में प्रतिपक्ष द्वारा बहुत सारी बातें कही गईं कि यह बजट ऐसा है, वैसा है। विगत वर्ष के बजट को यदि देखा जाये तो इस वर्ष के बजट में काफी बढ़ोत्तरी की गयी है। सरकार का जो मूल्यांकन पिछली बार का रहा है उसको देखते हुए इस बार हर मद में काफी बढ़ोत्तरी की गई है। खेल, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण, परिवहन, ऊर्जा, पुलिस, समाज कल्याण, पोषण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जलापूर्ति, सैनिटेशन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण में पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर औसतन देखा जाये तो 11 प्रतिशत से लेकर 58 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी नीति का परिणाम है कि प्रदेश में जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जिस तरह की आवश्यकता बढ़ी है उसी तरह से उन्होंने बजट में भी बढ़ोत्तरी करने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं विपक्ष के एक नेता को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं करती। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से कौशल विकास मंत्रालय पूरा काम करता है और आज-कल तो सब कुछ इण्टरनेट पर उपलब्ध है। माननीय सदस्यों के सामने जो टैबलेट लगा है उसमें भी गूगल पर जाकर देखा जा सकता है कि स्किल डेवलपमेण्ट मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय हिन्दुस्तान में 11000 ट्रेनिंग सेंटर वर्क कर रहे हैं। 36 ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें स्किल काउंसिलिंग की जा रही है। ढाई हजार से ज्यादा उसमें जॉब रोल्स हैं, 14000 से ज्यादा उसमें नेशनल आक्यूपेशन स्टैण्डर्ड शामिल किये गये हैं। यह सब करीब पूरे 28 राज्यों में क्रियान्वित हैं। हमारे 600 से ज्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। साथ ही साथ स्किल इंडिया डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और (असीम) आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्पलायमेंट मैपिंग सिस्टम यह सब काम किया जा रहा है जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की माननीया सदस्य उस दिन कह रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों ही प्रकार के लेबर के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर थोड़ा सा

ज्ञानवर्धन करने की आवश्यकता है। महोदय इस बीच थोड़ी सी चर्चाएं ऐसी हुईं कि एक जानवर को लेकर कुछ ज्यादा ही विपक्ष की ओर से चर्चा दिखाई दी। सांड़ की चर्चा यहाँ पर बहुत हुई। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस पशु की बहत ज्यादा बात की गयी है लगता है उसने भी पक्ष और विपक्ष को देखकर ही चरने का काम किया है और इसका परिणाम 2022 के चुनाव में दिख चुका है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सीताराम वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट पर हमें बोलने का मौका दिया। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हम सभी सम्मानित सदस्यों का वन्दन और नमन करते हैं। विश्व के महान नेता और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किये गये जन-कल्याण एवं विकास कार्यों पर विश्वास कर प्रदेश की जनता-जनार्दन ने भाजपा सरकार को पुनः प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए प्रदेश की आदरणीय जनता एवं विशेष रूप से जनपद सुल्तानपुर की लम्भुआ विधान सभा क्षेत्र की जनता-जनार्दन को नमन और वंदन करता हूँ। प्रदेश के इतिहास में 37 वर्ष बाद यह अवसर आया है जो यह सिद्ध करता है कि सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरी है। कानून व्यवस्था में हमारी योगी सरकार ने आशातीत सुधार किया है। विगत पांच वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। गुण्डे-बदमाश या तो जेलों में चले गये हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गये हैं। इसके कारण प्रदेश में अमन-चैन कायम है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में उद्योगपति योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टीनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के माध्यम से जनाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गयी है। इसके लिए हम अपने यशस्वी मुख्य मंत्री एवं विद्वान वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं। बजट में बुनियादी ढांचे के प्रति निवेश पर विशेष बल दिया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पांच एक्सप्रेस-वे वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है और पांच इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का प्रथम राज्य बनने वाला है। जन-कल्याण एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान बजट में सुधार एवं विस्तार प्रस्तावित किया गया है। 2017 तक प्रदेश में केवल 13 राजकीय मेडिकल कालेज थे। हमारी सरकार ने पांच वर्षों में 22 मेडिकल कालेज शुरू किया है और 14 नये मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा दो एम्स स्थापित किये जा रहे हैं। अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है।

मान्यवर, इन मेडिकल कालेज की स्थापना से जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्र को जनपद में ही सुविधा उपलब्ध हो जायेगी वहीं हमारे किसानों और मजदूरों के बच्चे भी कम फीस होने के नाते राजकीय मेडिकल कालेज से डॉक्टर बन सकेंगे और डॉक्टरों की कमी दूर हो जायेगी। कोविड महामारी के दौरान हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो सराहनीय कार्य किया गया। हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी, आशा बहू आदि ने जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचायी उनके लिए समर्पण के साथ काम किया। उनके लिए हम इस अवसर पर नमन और वंदन करते हैं। आयुष्मान कार्ड विश्व की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अन्तर्गत हमारे गरीब भाई जो पैसे के अभाव में अपने परिवार के किसी सदस्य को खो देते थे वह पांच लाख तक प्रतिवर्ष इलाज करा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। इसी तरह इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो। अभी तक ग्रामीण मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं थी। इस बजट में ग्रामीण मजदूरों के लिए एक योजना प्रस्तावित की गयी है। इसके अलावा जन-कल्याण में वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह कर दी गयी है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए दी जाने वाली राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि 1.50 लाख से पांच लाख की गयी है। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि दैवीय आपदा में जो धनराशि दी जाती है वह बहुत कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। हम केवल प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास ही नहीं देते अपितु बिजली भी देते हैं और गैस देते हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं वह मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बाबा वरियार शाह को पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाये। बाबा जनवारी नाथ धाम सिद्धपीठ एवं धार्मिक स्थल है उसका जीर्णोद्धार एवं विकास किया जाये। जर्जर तारों को बदलवाया जाये। पखरौली से हनुमानगंज, कन्हईपुर होकर ज्ञानीपुर रामगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायै। कोईरीपुर नगर पंचायत शिवाला होकर सफीपुर शाहपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाये। लखनऊ वाराणसी 4 लेन से मदनपुर शाहपुर हरिवंश मरीधाम होकर वेलहरी बरौसा तक जाने 15 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री मौहम्मद नासिर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया। पहली बार मैं निर्वाचित होकर सदन का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य हुआ हूँ। मान्यवर, मैं मुरादाबाद की धरती से आता हूँ। यह बजट जो पेश हुआ है वह निराशाजनक है और मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी है। इस बजट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मैं इनता कहना चाहूँगा कि मैं मुरादाबाद विधान सभा क्षेत्र 27 से आता हूँ जोकि अभी वर्ष 2012 में नये परिसीमन में विधान सभा क्षेत्र का परिसीमन चेंज हुआ और मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 40 प्रतिशत देहात आता है और 60 प्रतिशत शहर आता है। जहाँ पर देहात शहर से करीब 35 किमी0 दूर है और देहात के अन्दर बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर एक नगर पंचायत भोजपुर जिसको तहसील होने की बहुत जरूरत है, वहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक कन्या डिग्री कालेज होना चाहिए और आये दिन वहाँ के कारखानों में आग लग जाती है, एक फायर स्टेशन की वहाँ पर बहुत जरूरत है। मैं यह चाहता हूँ कि वहाँ देहात के अन्दर बिल्कुल लाइट नहीं आती तो विद्युत की आपूर्ति कराई जाये ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। जो 60 प्रतिशत शहर का हिस्सा है चूंकि मुरादाबाद पीतल का शहर है, पीतल की नगरी है वहाँ पर हाथ के दस्तकारों और मजदूरों की ज्यादा बड़ी आबादी है, वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यह चल रही है कि बिजली की वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है। वहाँ पर 24 घंटे में चेकिंग भी किसी भी वक्त हो जाती है। वहाँ के फीलखाना मोहल्ले में सरदार अहमद नाम के एक शख्स को कल ही चौरासी-पचासी हजार का बिल दे दिया गया, जिसको हाथ में लेते ही उसकी जान चली गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर चेकिंग का वक्त निश्चित किया जाना चाहिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कोई गलत काम करे और आप चेकिंग न करायें, चेकिंग बिल्कुल करायें, लेकिन उसका वक्त निश्चित होना चाहिए और उन लोगों की कम से कम इतनी सहायता करनी चाहिए कि जिन पर ज्यादा बिल चढ़ जाता है, कम से कम उनसे किस्तवार बिल ले लें जिससे उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी न हो। आप यह पता कर सकते हैं कि कल ही वहाँ सरदार अहमद नाम के एक आदमी की मृत्यु हुई जोकि फीलखाना मोहल्ले में रहता था उसे चौरासी हजार बिल हाथ में दे दिया गया, बिल हाथ में लेते ही उसकी जान चली गयी, उसकी मौत हो गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र का जो 60 प्रतिशत हिस्सा है वहाँ सभी मजदूर और दस्तकार रहते हैं। वहाँ पर तमाम डॉक्टर लोग रहते हैं, वे डॉक्टर जिनके खुद के लाइसेंस हैं और वहाँ पर दुकानें खोल रखी हैं, उनके यहाँ गरीब मरीज इलाज के लिए जाते हैं, उनकी एक फीस निर्धारित की जानी चाहिए। वे लोग मरीजों से दो हजार रुपये भी ले लेते हैं, ढाई हजार रुपये भी ले लेते हैं और गरीब लोगों से उनकी फीस नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि उनकी एक फीस निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो देहात का हिस्सा है, उस देहात के हिस्से के अन्दर एक कन्या डिग्री कालेज जरूर होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद देने के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अब श्री गुलाम मौहम्मद।

श्री मौहम्मद नासिर-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे वहाँ जो 60 परसेंट शहर का हिस्सा है, जो मेरी विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है, वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बिल्कुल नहीं। श्री गुलाम मौहम्मद जी शुरू करें।

श्री मौहम्मद नासिर-

सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। (माइक बन्द कर दिये जाने के कारण आगे सुनाई नहीं दिया)

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपने इस भाषण को अपने नेता, प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव साहब के भाषण से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहूँगा-

'अपने हुस्न के जलवे बिखेरे जा रहे हैं,

मगर कहाँ आइने उठाये जा रहे हैं।'

(मेजें थपथपाई गईं)

आप अपना आइना देख लीजिए कि आपने मजदूर को बहुत ही महंगाई की चक्की में पीस दिया है। मैं गन्ना किसान बेल्ट से आता हूँ, कुल 25 रुपया बढ़ाया गया है जबकि रिकवरी रेट पहले 8 था, माननीय अखिलेश यादव साहब ने उस वक्त पर प्रति कुन्टल 35 रुपया बढ़ाया था और उस वक्त रिकवरी रेट 8 था। आज रिकवरी रेट 12 है और 25 रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाया है जो ऊंट के मुंह में जीरा है, कोई मदद नहीं है, इससे आय दोगुनी नहीं, बल्कि उनको और घाटा हो रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक किनौनी मिल रही है। किनौनी मिल के सम्बन्ध में मैंने कई बार उनसे कहा कि उसकी चिमनी से जो राख निकलती है, उसके जो कण हैं, वह जब लोगों के फेफड़ों में जाते हैं, कई लोगों की तो आंखें खराब हो गयी हं। मैंने खुद देखा है, किनौनी गांव में एक आदमी की आंख खराब हो गयी, फूट गयी। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और इसी दौर में उस वक्त के हमारे मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव साहब ने 10 करोड़ रुपया देकर मोहिद्दीनपुर मिल को चलवाया था, जिसका

श्रेय आज की सरकार ले रही है। यह किसानों के लिए इनका बजट है। अब मैं बहुत शार्ट में अपनी बात करना चाहता हूँ -

'वह पी रहे हैं, छलका रहे हैं और झूम रहे हैं,

ऐ-सीकरी मयखाना, कुछ तो इधर भी है।'

हमारे हालात यह बना दिये हैं कि माइनॉरिटी के लिए बजट है, इसमें 506 करोड़ रुपया एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत है। इसी तरह से पिछले 5 साल में भी बजट आता रहा होगा, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज बच्चियों का है, जो इसी योजना के तहत बना लेकिन 5 साल में एक पैसा भी नहीं लगा, यह इनका बजट है। मैंने इसके अलावा एक माइनॉरिटी का नहीं, बल्कि सभी के लिए पालीटेक्निक कालेज इसी योजना के तहत बनवाया था, वह पालीटेक्निक भी अधूरा पड़ा हुआ है, बल्कि उसको पीपीपी मॉडल के तहत देना चाहते हैं। उसे राजकीय ही रहना चाहिए, जिससे अच्छी और सस्ती शिक्षा मिले, यह होना चाहिए। पीपीपी मॉडल फिर वही महंगी अमीरों के लिए शिक्षा हो जायेगी। जबकि हमने उसको बनवाया, जमीन दिलवायी थी। इसी तरह से बच्चियों के दो इण्टर कालेज इसी एमएसडीपी योजना के तहत बनवाये गये थे, 5 साल में उसके बाद से उनमें एक ईंट नहीं लगी। आखिर ये बच्चियों के कालेज हैं, बच्चियां सबकी पढ़ती हैं, स्टूडेंट सबके पढ़ते हैं। पालीटेक्निक पास करने के बाद में बच्चे जे0ई0 बनेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र को भी अलग से रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस एमएसडीपी योजना के तहत बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाये और इसी तरह से मेरा एक कस्बा है उस वक्त मैंने वहाँ एक पी0एच0सी0 बनवायी थी, तब से ले करके आज तक उसमें दो ईंट नहीं लगी, उसका कोई काम आगे नहीं बढ़ाया गया। इलाज तो सबका होगा ना, किसी एक तबके का, किसी एक वर्ग का तो नहीं होगा।

पी0एच0सी0 इसी योजना के तहत बनी थी वह भी अधूरी पड़ी हुई है। दूसरी ओर मैंने 6 बिजली घर बनवाये थे उस बीच में एक भी बिजली घर नहीं बना। मैंने जमीन लोगों से दान दिलवायी है। इसी तरह से एक मॉडल कालेज हम लोगों ने बनवाया था। हमने जमीन की भीख मांगी तब 60 लाख की जमीन एक आदमी ने दान दी उस पर मॉडल कालेज खड़ा हुआ है जो अभी तक चल नहीं रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि उन पर गौर किया जाय। मैं चाहता हूँ कि जनरल शाह नवाज के नाम पर मेरठ हेडक्वार्टर पर एक माइनारिटी के लिए एक कोचिंग सेण्टर सहायता देकर चालू करें, जिसमें बोर्डिंग भी हो। मैं चाहता हूँ कि अभी बजट में शायरी का इस्तेमाल किया गया बोलने में भी लोग शायरी का इस्तेमाल करते हैं। हिन्दी और उर्दू दोनों बहनें हैं छोटी बहन उर्दू के लिए मेरठ में एक सेमिनार हॉल बनवा दिया जाय।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी)-

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं जनपद बलिया से आता हूँ जिसको बागी बलिया भी कहा जाता है। गंगा और घाघरा नदी के बीच में बना हमारा बलिया एक ऐतिहासिक छवि रखता है। बलिया एक क्रांतिकारी धरती है जिसने प्रदेश को और देश को सदैव कई क्रांति के रास्ते दिये हैं। बलिया का इतिहास प्रेम और सद्भाव की एक अनूठी संस्कृति है। लिट्टी, चोखा, सत्तू और धोती, कुर्ता, पगड़ी यह सब हमारे विशेष परिधान और विशेष व्यंजन हैं। मैं उस धरती से आता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज वर्ष 2022-23 के इस बजट में मुझे अपने विषय को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर से यह एक ऐतिहासिक बजट है जो हमारे प्रदेश के विकास के नए रास्ते खोलेगा। निश्चित तौर पर यह हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यकों को, युवाओं को, किसानों को, हमारे प्रदेश के हर जन को वह उन्नति और तरीके देगा जिसकी ख्वाहिश वह रखते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज हम सब एक नये उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2012 से 2017 तक यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश की पिछली सरकारों में आप देखिए इस प्रदेश में गुण्डागर्दी और भ्रष्टाचार का राज हुआ करता था, लेकिन हमारे मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश सुशासन का प्रदेश माना जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी के सुशासन का जो चरित्र है वह इन पंक्तियों से कृतार्थ होती है- कि दंगाइयों की हर नीति बिखर गई, विरासत की सियासत भी अपने घर गई। यह योगी जी के ही नेतृत्व का परिणाम है कि दुनिया भर में यू0पी0 की छवि सुधर गई। अब तो प्रदेश में तरक्की है, भाईचारा है। हर तरफ कानून व्यवस्था का जय जयकारा है। आज एक और ऐतिहासिक दिन है, आज हमारे केन्द्र की सरकार के मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आठ वर्ष पूरे हुए हैं, आज इस सदन के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह भी इस देश को विश्व गुरू बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश का मान-सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाया है, हम सब उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम सबके प्रेरणा-स्रोत आदरणीय मुख्य मंत्री जी निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश को वह उत्तम प्रदेश बना रहे हैं।

देश की आजादी जिसके लिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी। आज अगर वे स्वर्ग से उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर दोनों हाथों से मा0 मुख्य मंत्री जी को आशीष दे रहे होंगे। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि साल 2017 में जब हमें सरकार मिली थी तो साल 2012-2017 के दौरान जो सरकार थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने हमें सरकार दी थी और हमारे प्रदेश की क्या स्थिति थी ? लेकिन ये हमारे मा0 मुख्य मंत्री

योगी आदित्यनाथ जी थे जिन्होंने चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और इन पंक्तियों को चरितार्थ किया कि-

सच है कि चुनौती जब आती है, कायर को ही दहलाती है,

सच है कि चुनौती जब आती है, कायर को ही दहलाती है,

सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खाते,

विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।

तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कांटों में राह बना के आज उत्तर प्रदेश को वह प्रदेश बनाया है जिस उत्तर प्रदेश में आज देखिये, पूरे विश्व भर से आज इन्वेस्टमेंट होता है। हम आगामी तीन तारीख को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कोई व्यापार करने से भी डरता था आज उस उत्तर प्रदेश में लोग देश और विदेश से आ करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये प्लीज।

श्री दानिश आजाद अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता जी, अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते, अल्पसंख्यक और खासतौर से बलिया से होने के नाते बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता-

असली बात वही जो अब करने जा रहे हैं, यही पहले कर ली होती।

श्री दानिश आजाद अंसारी-

मान्यवर, पहले अल्पसंख्यकों के हित की बात जो विपक्ष करता था, वह केवल कोरे वादे करता था।

श्री अधिष्ठाता-

अब मा0 रजनी तिवारी जी।

श्री दानिश आजाद अंसारी-

मान्यवर, मैं बस एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सही मायनों में अगर अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है तो उनकी शिक्षा का, उनकी सुरक्षा का, उनकी तरक्की का तो मा0 योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और चन्द लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। केवल दो लाइनों में अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये विपक्षी जो सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं, मैं इस लाइन के साथ अपनी बात कहूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

इस समय तो कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है। कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई जा रही है, ऐसा आरोप मत लगायें।

श्री दानिश आजाद अंसारी-

सदन में ये रवैया सही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह सदन बहुत अच्छा चल रहा है। आप कोई आरोप न लगायें।

श्री दानिश आजाद अंसारी-

मैं कहना चाहता हूँ कि सदन में ये रवैया सही नहीं है, ऐसा लगता है,
रस्सी जल गई है, मगर ऐंठन नहीं गई है,
यकीन कीजिये कि ये वक्त है सलीके का,
आपके दौर को गुजरे एक मुद्दत हुई है।

***उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती रजनी तिवारी)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश किये गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट से स्पष्ट है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रगति के पथ पर गतिशील है। बजट सर्वसमावेशी है और यह उज्ज्वल भविष्य की रूप-रेखा तय करेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। यह प्रदेश की जनता-जनार्दन के लिए अगले पांच वर्षों का विजन है। इसमें प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व आशाओं का समावेश है। मैं इस बजट के लिए मा0 वित्त मंत्री जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट में सब-कुछ है, सभी वर्गों के लिए है, सर्वसमाज के लिए है, बहनों के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है लेकिन सामने बैठे हमारे साथियों को बजट में कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इनको भी जनता ने मौका दिया था, लेकिन जब जनता ने इनको मौका दिया तो इन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, पूरे पांच वर्ष इन्होंने जनता के हित के लिए कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन अगर इनकी कुछ योजनाएं बनीं भी तो वे पूरे पांच वर्ष नहीं चल पाईं। न जाने क्या हुआ कि उनमें बन्दरबांट हो गया, योजनाएं क्यों नहीं चल पाईं ? इनकी कोई भी योजना पूरे पांच साल नहीं चल पाई। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं भी लम्बे समय से इस मा0 सदन का अंग रही हूँ। मा0 प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है तो वहीं हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। फिर भी मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्य मंत्री जी ने विकास गति को अवरुद्ध नहीं होने दिया, परन्तु मुख्य मंत्री जी के कुशल प्रबन्धन, औद्योगिक निवेश और विकास योजनाओं ने विकास की गति को रुकने नहीं दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 6 लाख 15 हजार करोड़ से अधिक के बजट की घोषणा करके सपा सरकार के 2016-17 में घोषित बजट से लगभग दोगुनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि हम ढिंढोरा नहीं पीटते। हम ढिंढोरा पीटने के बजाय काम करने में विश्वास रखते हैं। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि-

सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु।
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु।।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार का जो बजट आया है, उस बजट में आत्मनिर्भरता एवं जन-जन के विकास का संकल्प है। बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस बार भी सरकार ने भारी-भरकम राशि की व्यवस्था की है। मान्यवर, यह लोग जो ऊर्जा की बात कर रहे थे, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि मैंने पिछले वर्षों में भी देखा, जब हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी। यदि एक गांव में अगर कहीं एक विद्युत का पोल लगवाना पड़ता था तो हम लोग एड़ी-चोटी की ताकत भी यदि लगा देते थे, तब भी गांव में हम लोग वह पोल नहीं लगवा पाते थे। अगर एक बिजली का कनेक्शन करवाना होता था तो दौड़ते-दौड़ते हम लोग परेशान हो जाते थे। हम लोग आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी परेशान होते थे, तब जाकर कहीं हम लोग वह विद्युत कनेक्शन करवा पाते थे। इसके लिए हम अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम मा0 ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों ने पूरे-पूरे गांव का विद्युतीकरण करवाने का काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह लोग शिक्षा की बात करते हैं, इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगी कि शिक्षा की व्यवस्था आपने भी देखी, हमने भी देखी, सामने बैठे लोग भी जानते होंगे, लेकिन वह विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए कुछ कह नहीं कसते हैं। शिक्षा का इन्होंने सत्यानाश कर दिया था। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो उसके स्तर को बहुत खराब करने का व गिराने का काम इन लोगों ने किया था। अधिष्ठाता महोदय, आज की शिक्षा व्यवस्था देखिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी, अब समाप्त करें।

श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार में इतने काम हुए हैं कि जिसके बारे में यदि मैं गिनाना शुरू करूं।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ तो बाकी लोग गिनवा देंगे।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, मैं कुछ अपने विभाग से सम्बन्धित बात कर लूं। हम लोगों ने टैबलेट बांटे, स्मार्टफोन बांटे। यह लोग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और कालेजों की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मां शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में बनाने का काम किया है। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है। सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में बन रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी, माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी है, उसके तहत हम सब लोग कापरेट करें, तभी ठीक रहेगा।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, सब कुछ एक में समेट कर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने अराजकता का माहौल दिया था, शिक्षा की स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। प्रदेश को विकास से कोसों दूर कर दिया था। अर्थव्यवस्था को जीर्ण-शीर्ण कर दिया था। प्रदेश के विकास की जगह व्यक्तिगत विकास आप लोगों ने किया था। हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में रामराज्य लाने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता खुशहाल है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। जनता कह रही है कि रामराज्य आ गया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाजवादी पार्टी की मा0 पिंकी जी।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में मुख्य मंत्री बनने पर प्रदेश की जनता कह रही है। अन्त में मैं रामचरित मानस की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि-

राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गये सब शोका।

बयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहू ब्यापा।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीती।

अल्प मृत्यु नहिं कवमिऊ पीरा। सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा।

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोऊ अबुध न लच्छन हीना।

श्री अधिष्ठाता-

यह बहुत लम्बी चौपाई है, इसमें बहुत समय लग जायेगा।

श्रीमती रजनी तिवारी-

प्रदेश में राम राज्य आ गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

***श्रीमती पिंकी सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। वित्त मंत्री जी द्वारा इस देश के सबसे बड़े सूबे का बजट पेश किया गया। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, छात्र-छात्राओं को इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि योगी सरकार दुबारा सत्ता में आयी। कहीं न कहीं उन किसानों को लगा कि हमारी आय को दुगुना करने की बात कही जायेगी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं, उन नौजवानों को लगा कि कहीं न कहीं हमें नौकरियों को देने की बात कही जायेगी। उन माताओं और बहनों को लगा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जायेगी, क्योंकि यहाँ बड़ी-बड़ी बातों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिला सुरक्षा की बात कही। बढ़ती हुई महंगाई के लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश की महिलायें सोचने लगीं कि इस बजट में उस महंगाई को कम करने की बात क्यों नहीं कही गयी ? हमारे अल्पसंख्यक और बुनकर भाई ये सोचते रहे कि कह तो दिया बुनकरों के लिए बजट में, लेकिन सब्सिडी के साथ क्यों नहीं उन लोगों के हकों की बात को रखा गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि पूर्णतः निराशापूर्ण, भ्रामक और एक लच्छेदार बजट तैयार किया गया। बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गयीं रोजगार की, जो हमारे बच्चे प्रतिदिन 18 से 20 और 21 घंटे तक तैयारियां करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं कि कहीं न कहीं नौकरी की आस में उनके माता-पिता अपने गाढ़े खून-पसीने की कमाई से उन्हें पढ़ा-लिखाकर काबिल इस आस के साथ बनाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं अफसोस होता है कि उन नौजवानों के साथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन माता-पिताओं के सपनों के आस को भी तोड़ने का काम किया।

रोजगार के नाम पर अगर बात करें तो मैं कहना चाहती हूँ और आप भी जानते हैं कि सरकारी पदों की जो रिक्तपूर्ति है उसको भरने का काम नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक लाख अध्यापकों की रिक्तपूर्ति है, उनके पदों को भरने का काम सरकार नहीं कर रही है। हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी और मेरा सुझाव है सरकार को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दुरुस्त करें। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों ने अपने घरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिया है, अपनी बेटियों की शादियों के लिए लोन लिया, अपनी सोच में गम्भीरता लाते हुए उनके बारे में सोचा जाय। सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप उत्तराखण्ड का अनुसरण क्यों नहीं करते ? वहाँ शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में रुपये 25,000 मिलते हैं। आप भी उस सीख को लेते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का काम करें। आप 4 लाख लोगों को केवल रोजगार दे पाये, लेकिन बात की थी 70 लाख की, कहाँ गया आपका वो वादा ? रोजगार के नाम पर मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं तड़प रहे थे लाखों युवा रोजगार के लिए सड़कों पर, तब उनके लिए मददगार कोई नहीं आया, हाँ पुलिस आयी, फोटो खींची, न्यूज चली पर उनका दर्द बांटने कोई महकमा या हकीमदार नहीं आया। ये बात पूरी तरह से सार्थक होती है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कायाकल्प की बात कही जा रही है, लेकिन कायाकल्प की वास्तविकता क्या है ? सरकार में बैठे हुए व्यक्ति स्वयं वहाँ जाकर देखें और पता करें, अगर आप लोग वहाँ जायेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि स्मार्ट क्लासेज कहाँ से चल जायेंगी जब वाईफाई के कनेक्शन और इण्टरनेट की सुविधाएं अभी ग्रामीण अंचल के उन प्राइमरी विद्यालयों, उन गांवों तक नहीं पहुंची हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार शिक्षा के प्रति यदि गम्भीरता दिखा रही है तो हमारी मां कैला देवी धाम पर बच्चियों के पढ़ने के लिए एक स्कूल, एक डिग्री कालेज की आवश्यकता को पूरा करे। लोक भावना के अन्तर्गत पूर्व की सरकार में मेरे द्वारा कई बार यह प्रश्न उठाया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

भाषण बहुत लम्बा हो गया। श्री शशांक त्रिवेदी जी।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे 02 मिनट और दीजिये मैं अपनी बात बस खत्म कर रही हूँ। हम आपसे इस बात का संरक्षण चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि डिग्री कालेज के लिए यहाँ पर जो मांग की गयी थी, अगर बेटियों के लिए वहाँ डिग्री कालेज बन जाय। शवाजपुर कलां में अल्पसंख्यक का इण्टर कालेज बना है, वह अधूरा पड़ा है। उसके लिए पैसा दिलाने का काम हो जाये। पेयजल की व्यवस्था कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आपका काफी समय हो गया है, अब समाप्त करें।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मान्यवर, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, इस बात को लेते हुए कि सरकार ने वादे बहुत किये, वादों का सपना बहुत दिखाया, पर जमीनी धरातल पर सिर्फ अपनी पीठ नौकरशाहों की तरह, उसके चश्मे लगाकर अपनी पीठ को थपथपाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अब शशांक त्रिवेदी जी, अब आप बोलना शुरू करें।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मान्यवर, बस दो लाइन में अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं आखिर में यही कहूँगी कि-

अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो,

तुम मुझे यह बताओ कि क्या कभी सच भी बोलते हो ?

जय हिन्द, जय समाजवाद।

***श्री शशांक त्रिवेदी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी के ऐतिहासिक द्वितीय कार्यकाल के प्रथम बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर कहना चाहता हूँ कि-

मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना,

पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी, खन्ना जी, पूर्व में जितने भी बजट लाये हैं, वह प्रदेश की दिशा-दशा बदलने वाले बजट रहे हैं। आगामी 3 जून को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी का नतीजा होने जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। निखरने का नतीजा है कि आज प्रदेश में किसान खुशहाल है, क्योंकि किसानों के लिए सोलर पम्प, मुफ्त सिंचाई, किसान सम्मान निधि, प्रदेशवासियों के लिए एक्सप्रेस-वे, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मुफ्त चना, साबुन, तेल, नमक, आवास, बिजली और कितनी चीजें गिनाई जायें, महिलाओं के लिए सुरक्षा, मुफ्त स्मार्ट फोन, टैबलेट। साथ ही बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों के बिखरने का नतीजा था, लूटपाट, आगजनी, दलाली, गुण्डागर्दी, मक्कारी। मान्यवर, और तो और कुछ दिन पहले सदन में इनके बिखरने को सदस्यों ने और प्रदेशवासियों ने भली-भांति देखा है और किस तरीके से बिखर गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। सदन में आपने जो किया है, उसे हम भी दिखा सकते हैं, चाहें तो कुछ नई कलायें भी सिखा सकते हैं, पर मान्यवर, हमें मालूम है, प्रदेश ही नहीं अपितु देश जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हमें संस्कारों में रहना आता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल वर्षा से उगती है, बाढ़ से नहीं उगती है। आज-कल उत्तर प्रदेश की सरकार, देश ही नहीं अपितु विदेशों में तरक्की के लिए नये आयाम लिख रही है। जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में कोरोना के समय में प्रदेश में जितना भी कार्य हुआ है, उसकी सराहना कई देशों में की गई। मान्यवर, इनको यह सब कार्य नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहते हैं न कि आंखों में अगर गुरूर हो तो इंसान नहीं दिखता और छत पर चढ़ जाओ तो नीचे अपना मकान नहीं दिखता। अधिष्ठाता महोदय, यह बजट प्रदेशवासियों के लिए नया आयाम लाने वाला बजट है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की ओर आंखें गड़ाये देख रही है कि जिस तेजी से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, वह ऐतिहासिक होने जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश में कानूनराज कायम है, इन्स्पेक्टरराज खत्म हुआ है, उद्योगों की सम्भावनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हमारी महोली भी जो सम्भावनाएं देख रही है, वह मैं कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल, महोली में डिग्री कालेज और ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग बहुत शीघ्र वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और इस सम्भावना से हम लोग बहुत खुशगंवार हैं। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अधिष्ठाता महोदय, बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। शशांक त्रिवेदी जी के प्रति बहुत आभार कि आपने समय का ख्याल रखा।

(सदस्य श्री बावन सिंह जी का नाम पुकारा गया, लेकिन वह अनुपस्थित थे।)

***श्री मनोज कुमार प्रजापति-**

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बजट की इस सामान्य चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको दिल की गइराइयों से धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। इस लोकतंत्र के मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ, साथ ही साथ इसी मंदिर से मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ भेजने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पिछड़े व्यक्ति को इस विधान सभा में आने का उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मनोज जी, चूंकि आपके साथ अन्य और भी हमारे सम्मानित नये सदस्य हैं। प्रबोधन में बताया गया होगा कि जब आप इस मंडप में बैठते हैं तो मंडप में केवल पीठ को संबोधन करके ही बोला जाता है, चूंकि हम लोग अन्य लोगों की चर्चा जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं तो हम पीठ को सम्बोधन करते हैं। पोलिटिकली जो मंच चौराहों पर बोलते हैं वह भाषा यहाँ पर नहीं होती है केवल पीठ को सम्बोधन करें।

श्री मनोज कुमार प्रजापति-

बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बजट पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। मुझे इस विधान सभा में 7, 8 दिन का जो अनुभव मिला, अभिभाषण के समय जो अनुभव मिला, नेता प्रतिपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला और बार-बार वह लोग जो यह कहते हैं कि हम पिछड़ों के हिमायती हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आदरणीय केशव प्रसाद मौर्या जी पिछड़े समाज में नहीं आते हैं। एक जरा सी बात को लेकर उन्होंने यही तो कहा था कि 25 साल आप मुख्य मंत्री नहीं बनेंगे। आप देख लीजिये मैं विपक्ष के साथियों से कहता हूँ इसी विधान सभा के मंडप में एकचित्र वीथिका लगी है आदरणीय योगी जी के बाद आगे कोई स्थान नहीं कि किसी का कोई स्थान वहाँ पर बन जाये, आदरणीय योगी जी का ही आखिरी चित्र लगा है वहाँ पर यह प्रमाण है कि आगे आदरणीय योगी जी का ही चित्र लगा रहेगा वहाँ पर। आप लोगों ने पिछड़ों का वोट लेकर सिर्फ उनका उपयोग करने का काम किया है, आपने ही हमारे समाज के एक व्यक्ति को मंत्री बनाया था और वह कहाँ-कहाँ हिसाब देता था यह आपको पता होगा और जबसे वह जेल चले गये तबसे किसी ने सुधि नहीं ली। जिनको यह वोट बैंक समझते हैं उनके यहाँ इनके चाचा भी जाते हैं, पिता भी उनका हाल-चाल पूछते हैं, बेटा भी उनका हाल-चाल पूछता है, क्योंकि वह वोट बैंक है, प्रजापति वोट बैंक नहीं है इसलिए उनका हाल-चाल जानने के लिए कोई नहीं जाता है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, रही बात बजट की मैंने पूरे बजट को सुना और पढ़ा है। बजट के एक-एक बिन्दु को पढ़ने के बाद लगता है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला विकास का क्षेत्र हो, चाहे सुशासन की जितनी भी बाते हैं सभी बातें उसमें समाहित हैं, निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी के मंत्रि-मण्डल को मैं धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कृषि की बात करूं तो 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को क्रियान्वित करने का काम किया गया है और वह कृषि विज्ञान केन्द्र जो पहले सिर्फ एक सफेद हाथी हुआ करते थे। मेरे जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र है जो वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, वर्ष 2017 तक उसमें कभी स्टाफ पूरा नहीं हुआ एक वैज्ञानिक और एक सहायक के साथ चलता रहा, वर्ष 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो पूरे स्टाफ के साथ आज भी वह कृषि विज्ञान केन्द्र जनपद को सेवाएं दे रहा

है। इसी प्रकार से मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक तो बुन्देलखण्ड से मैं आता हूँ और बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और जब गरीब परिवार के लोग शादियां करते हैं, उनके गांव में विद्यालयों में बारातों के रुकने की व्यवस्था होती थी तो बड़ी सहजता होती थी लेकिन आदरणीय न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ बारातें नहीं रुकती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारातशाला या सामुदायिक केन्द्र बनाने का काम करें, साथ ही साथ जिस तरीके से किसान दुर्घटना बीमा चल रहा है कि रोज आये दिन सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं में लोग अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हों अगर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको भी कहीं न कहीं उस बीमा से आच्छादित किया जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में परेहटा गांव पड़ता है वहाँ चन्द्रावल नदी पड़ती है, बाढ़ के समय उस गांव के लोगों को 15-20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है, अगर उसमें एक लघु सेतु का निर्माण हो जाय तो 5-6 गांवों के लोग अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक सुचारु रूप से कर पायेंगे। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में यदि एक बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हो जाये तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अभय सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपने आपको अपने नेता मा0 अखिलेश यादव एवं श्री लालजी वर्मा से सम्बद्ध करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत निराशाजनक बजट है। सत्ता के लोग आंकड़ों का बीज बोते हैं, आश्वासनों की खाद डालते हैं और भाषणों की फसल काटते हैं। ये पहले 2022 में कहा करते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन 2022 आ गया, किसानों की आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन अब ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले पांच सालों में कोई भला नहीं किया, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिले में किसानों के बड़े बुरे हालात हैं। ऋण मोचन योजना के तहत कई सालों से किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया है, लगातार उनके पत्र जाते रहते हैं। अयोध्या जनपद में लगभग 3924 कृषकों को अभी तक ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिला है, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो स्थिति किसानों की है, वह बहुत ही बुरी है, वह बहुत कमजोर होता जा रहा है। 2013 में हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत 5 लाख रुपये देने का फैसला लिया था जोकि आज तक चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि किसानों को जो 5 लाख रुपया किसान दुर्घटना बीमा में मिलता था उसे बढ़ाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

10 लाख रुपया किया जाय। अभी मैं सुन रहा था और पढ़ा भी कि चिकित्सा में बजट बहुत कम कर दिया गया है। हम लोगों के यहाँ से मरीज आते हैं, रात-रात भर पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बेड नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि किसी तरीके से इनको भर्ती कराओ तो डॉक्टर कहते हैं कि या तो कोई मर जाये या ठीक हो करके चला जाय। तब बेड मिलेगा तो हमारा आपसे अनुरोध है कि चिकित्सा पर बहुत ज्यादा बजट बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मनोज जी, मा0 मुख्य सचेतक महोदय, थोड़ा सा अपने यहाँ व्यवस्था दीजिये। आपके यहाँ से मुख्य सचेतक महोदय और सचेतक महोदय बीच-बीच में बोलने वालों की सूची में संशोधन करके सूची को अपने दस्तखत से भेज रहे हैं। अभी आपके सचेतक महोदय ने आ करके क्लियर किया कि इस तरह से बुलाया जाय बाकी सारी सूची बेकार है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

जो सूची हमने दी है, उसी सूची के हिसाब से नाम बुला लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

बीच में आपके दस्तखत से आ गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 संग्राम जी ने दे दिया, चूंकि वह सूची आपके यहाँ से ही आ रही है, इसलिए इसमें पीठ का कोई इण्टरफेयर नहीं है। दूसरे, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री अभय सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी बजट में दिखाया गया है कि लोकतंत्र सेनानियों को बीस हजार रुपया दिया जा रहा है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये व्यवस्था जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग 15 हजार दिया करते थे और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको 20 हजार रुपये करने का काम किया था। लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने इस प्रदेश-देश में लोकतंत्र को पैदा किया, तानाशाही और इमरजेंसी के काल में लड़ाई लड़ी।

श्री अधिष्ठाता-

हमारे माननीय सदस्यों को सीखना चाहिए कि पीठ को कभी पीठ न दिखायें और दूसरे जब हम किसी की बात का समर्थन करते हैं, तो हाथ से ताली न बजाकर मेजें थपथपाते हैं।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाय। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर यहाँ सेंटर बनना

शुरू हो गया था। यहाँ सदन में बैठे लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी जब पूरे देश में गैर कांग्रेसी नेता, चाहे उधर बैठे दल के हों, चाहे इधर बैठे दल के हों, लगभग सभी के सभी बन्द किये जा रहे थे। एन0एस0ए0, रासुका लग रहा था। बहुत से दलों के नेता उस समय माफी मांगकर छूट रहे थे। उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने बड़ा आन्दोलन शुरू किया और एक तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को फिर से स्थापित किया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि सिर्फ 50 करोड़ रुपया दिया गया है, उसको बनने में रुपये 130 करोड़ की आवश्यकता है। पूरा-पूरा 130 करोड़ दिलवाइये, जिससे कम से कम उस लोकतंत्र के मंदिर पर लोग जायें और समझ में आये कि हाँ, लोकतंत्र की स्थापना कैसे किया था ? ये हमारे ही लिए नहीं है, लोकतंत्र सेनानियों से, लोकतंत्र मंदिर से उनका भी भला है, हमारा भी भला है। हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से संघर्ष किया गया और किस तरीके से तानाशाही सरकार को इमरजेंसी के पीरियड में सबने उखाड़ कर फेंका।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहेंगे कि इस बजट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गयी है। दो साल कोरोना के पीरियड में वर्ष 2019-20 में लगभग 56 लाख परीक्षार्थी थे और वर्ष 2020-21 में लगभग 53 लाख परीक्षार्थी थे जिन्होंने रुपये 500 और 600 के हिसाब से परीक्षा शुल्क जमा किया था, जिसमें कई अरब रुपये की गड़बड़ी हो गयी है। उसके बाद भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने शासन से पैसा लिया और आज तक उन पैसों से न तो उत्तर पुस्तिका छपवाई गई है, न कोई प्रश्न-पत्र छपवाया गया, न उस पैसे का हिसाब-किताब कहीं पटल पर रखा गया कि उस पैसे से हुआ क्या ? हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इसको भी देखें और जांच करायें। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से अभी मैं बजट पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि बाल श्रम खत्म कर दिया गया है। आप सभी मा0 सदस्य गाड़ियों में चलते हैं, लगातार इधर-उधर आते-जाते रहते हैं। ढाबे और चाय की दुकानों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाल श्रम हो रहा है, गरीब बच्चे मेहनत, परिश्रम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अभय जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अभय सिंह-

महोदय, धन्यवाद।

माननीय सदस्यों के भाषण हेतु समय का निर्धारण

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जैसे कल सभी मा0 सदस्यों को बोलने के लिए 03 मिनट का समय दिया जा रहा था, उसी तरह से आज भी सभी मा0 सदस्य को बोलने के लिए 03 मिनट का समय रख दें, तो ज्यादातर मा0 सदस्य को बोलने का समय मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अगर हमारे सभी मा0 सदस्य इस आग्रह को स्वीकार कर लें कि 03 मिनट में ही अपनी बात को रख दें, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक मा0 सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, ठीक है। हम सब सहमत हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री ऋषि त्रिपाठी जी।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री ऋषि त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 संजय निषाद जी का और मेरे विधान सभा क्षेत्र नौतनवां की देवतुल्य जनता, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से इस सदन में आया हूँ, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट हमारे यशस्वी वित्त मंत्री ने गुरुवार को इस सदन में पेश किया। यह बजट एक नये उत्तर प्रदेश का, एक सशक्त उत्तर प्रदेश का, एक विकसित उत्तर प्रदेश और एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसा मैं सिर्फ वक्तव्य के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि किसी भी देश में या प्रदेश के आर्थिक विकास की दशा और दिशा इस बात से तय होती है कि हम कितना खर्च करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं ? इन दोनों बातों में एक सामंजस्य हो, बैलेंस हो।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पिछले वर्षों की तरह इस बार भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अधिक खर्च हो और उचित खर्च हो। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह

बजट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि ये बजट भारतीय जनता पार्टी के संकल्प-पत्र में किये गये वादों को पूर्ण करने का भी काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं, वो करते हैं।

2022 विधान सभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण-पत्र जारी किया था, इसमें 130 घोषणाएं की थीं, उसमें से 97 संकल्पों को इस बजट में स्थान दिया गया है। इन योजनाओं के लिए बजट में 54 हजार 583 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है यानि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो वादा किया उसे पूरा करने की दिशा में सरकार बनने के 2 महीने के अन्दर कार्य शुरू हो गया है, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी सरकार ईमानदार है और हमारे नेता दमदार हैं। हमारा काम असरदार है।

श्री मुकेश चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। निश्चित तौर पर यह बजट गांव, किसान, मजदूर, रेवड़ी वाला, खोखे वाला, गांव में अन्तिम छोर पर रहने वाले उस आदमी के हक का, उसके फायदे का बजट है, जो गांव के अन्तिम छोर पर रहता है जिसका कोई सिफारिशी नहीं है। मा0 अधिष्ठाता जी मैं अभी अपने उस तरफ के मित्र की बात सुन रहा था, स्कूल कायाकल्प के बारे में ये मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है उस मजदूर का बच्चा पढ़ता है जिसके पास पैसा नहीं जो मजदूरी करके अपने परिवार का लालन और पालन करता है। मा0 योगी जी को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद उन प्राइमरी स्कूलों की चिंता करने का काम किया उनका कायाकल्प कराने का काम किया और मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी जी की सोच देखिये जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो टाट और पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे। आज उन स्कूलों में बेंच हैं, उन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, मॉडल स्कूल बनाया गया है और मुझे वह दिन भी अच्छे से याद है जब हम कालेज में जाते थे तो हम देखते थे कि शहर के अन्दर प्ले स्कूल होता था, तब मैं यह पूछता था कि भाई ये प्ले स्कूल क्या होता है तो कहते थे कि यह प्ले स्कूल उनके लिए है जो गाड़ी में चलते हैं, जो अमीर के बच्चे हैं, व्यापारियों के बच्चे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस महात्मा को उस योगी को जिसने आज आंगनबाड़ी केन्द्र को प्ले स्कूल के रूप में स्थापित करके यह साबित कर दिया है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी प्ले स्कूल में पढ़ सकता है। खेल सकता है, यह सोच है, यह नीति है साफ नीति और नीयत है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मा0 वित्त मंत्री जी को जिन्होंने खेल के प्रति इतना बजट देने का काम किया। जब गांव, गरीब, किसान का बच्चा खेल कर आगे बढ़ने का काम करेगा वह स्वस्थ

बुद्धि होगा और निश्चित रूप से गरीब का बच्चा भी कम्पटीशन में हिस्सा लेकर अधिकारी बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है और मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे जनपद की बात, मैं सहारनपुर जनपद से आता हूँ 2012 से 2017 के बीच में सहारनपुर जनपद में 500 मकान आये गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और 2017 से 2021 के बीच में 18 हजार मकान बने, यह सोच है, यह नीति है हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जनपद को, मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान इस बजट में किया जाये और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जनपद में मां शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय बना दिया गया है। धन्यवाद।

***श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-**

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2022-2023 के उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह भाजपा सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की निष्पक्षता, कर्मठता, मेहनत और ईमानदारी को दर्शाता है। इस बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के भी अथक प्रयासों को धन्यवाद देता हूँ। यह बजट उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ-साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के साथ-साथ अन्य सभी वर्ग के कल्याण का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस निष्पक्षता के आधार पर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम किया है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दोबारा मौका देकर सिद्ध कर दिया है।

यह बजट किसानों के हित का तथा सर्वांगीण विकास करने वाला बजट है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और किसान कृषि विज्ञान केन्द्र तथा मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसके साथ-साथ 15 हजार सोलर पम्प, नहर और रजवाहों के साथ-साथ राजकीय नलकूपों के द्वारा सिंचाई की सुगमता के हेतु बजट दिया है तथा उन्नत बीज और उर्वरक की उपलब्धता कराने के लिए भी बजट का प्राविधान किया है। मान्यवर, जो हमारी महिला शक्ति है, समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क, महिला पी0ए0सी0 की बटालियन और हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहन राशि, ग्रामीण महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं कन्या सुमंगला योजना तथा मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए भी इस बजट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान किया गया है। युवाओं के विकास के लिए 2 करोड़ टैबलेट एवं स्मार्ट फोन देने का भी संकल्प किया है और लगभग 12 लाख स्मार्ट फोन बांट दिये गये हैं। युवाओं के विकास के लिए मेजर ध्यान चंद खेल स्टेडियम, एक जनपद एक खेल, मिनी स्टेडियम, बिना भेदभाव के पिछले पांच वर्षों में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ हमने 1.61 करोड़ निजी क्षेत्र में भी नौकरी के अवसर दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजीव जी, आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो तो वह बता दीजिये क्योंकि आपका समय समाप्त होने वाला है।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

मान्यवर, केवल 2 मिनट और लेना चाहता हूँ, तीन मिनट आप दे रहे हैं दो मिनट और दे दीजिये तो पांच मिनट हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

पीठ से यह व्यवस्था बनायी गयी है कि सबको 3-3 मिनट का समय दिया जा रहा है। जो आप बता रहे हैं इसको कई मा0 सदस्य बता चुके हैं आप अपने क्षेत्र की बात रख लीजिये तो अच्छा रहेगा।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट सभी के विकास का बजट है। निःसंदेह यह उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जायेगा। एक विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र का है जो केन्द्र सरकार से संबंधित है, लेकिन मैं पीठ से आग्रह करूंगा कि दातागंज मेरी विधान सभा क्षेत्र है, तो बदायूं से दातागंज होते हुए तिलहर तक रेलवे लाइन का प्रस्ताव इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजने की कार्यवाही करें। दूसरे, मेरे यहाँ गंगा एक्सप्रेस-वे निकल रहा है, मेरठ-बलिया गंगा एक्सप्रेस-वे, उसका एक उतार-चढ़ाव, जिसको जंक्शन कहते हैं, उसको भी दातागंज के डहरपुर में बनवाने का निर्देश देने का कष्ट करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

***श्री अखिलेश-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने बजट की चर्चा में मेरे जैसे छोटे आदमी को भी शामिल करने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

यहाँ सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के चलते मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर मिला है। महोदय, जो बजट पर चर्चा के लिए आपने हम लोगों को समय दिया है, हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं। जो सुबह बोलता है वह 10 मिनट बोलता है, जो दोपहर में बोलता है वह 05 मिनट बोलता है, और जो सुबह से शाम तक बोलने का इन्तजार करता है वह 03 मिनट बोलता है। बहरहाल कुछ हमारे सामने वाले साथी जो बजट पर चर्चा कर रहे थे तो इनके यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है, इनको आप ज्यादा समय दे रहे हैं, जरूरत तो हम लोगों को है जो कमजोर और पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बजट में हिस्सा दिलाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, लोकतंत्र का तकादा भी है कि जो लोग पिछड़े हैं, कमजोर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण का भी यही मूल आधार है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित, दलित, पिछड़े, कमजोर, अल्पसंख्यक हैं, उनको विशेष अवसर देकर समानता के स्तर पर लाया जाय। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गन्ना किसानों के विषय पर आपके बजट में काफी हेराफेरी की गयी है। में उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे भी क्षेत्र में एक चीनी मिल है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने 400 करोड़ रुपये का बजट देकर पुनर्स्थापित करने का काम किया था। लगातार वर्ष 2016-17 से वह चीनी मिल पेराई करती चली आ रही है। दुःख के साथ कह रहा हूँ कि वर्ष 2021-22 में उस चीनी मिल में 82.85 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदने का काम किया गया। आज तक की जो सूचना है, गन्ना किसानों को मात्र 42.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। आज भी 40.72 करोड़ रुपये उस चीनी मिल में गन्ना किसानों का बाकी है। किसानों की आय दोगुना करने वालों के आंकड़ों के अनुसार 51 प्रतिशत आपने पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान किया है और 49 प्रतिशत आज भी बकाया है। यह आंकड़ों का हेरफेर है। हम कहना चाहते हैं कि आप किसानों की आय दोगुना कर रहे हैं। अगर यही हालत रहेगी तो पूरे प्रदेश के गन्ना किसान अपने गन्ने की बुआई कम कर देंगे। मैं दो मिनट के लिए अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी सठियांव चीनी मिल की बात कर रहा हूँ।

श्री अधिठाता-

कृपया समय-सीमा के अन्दर ही कहिये, चूंकि सबको सुनना है।

श्री अखिलेश-

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुधराम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जनपद बस्ती से आता हूँ। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। हम आपके माध्यम से महादेवा विधान सभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यालय जो कुदरहा ब्लाक है, वह मुख्यालय करीब 50 कि0मी0 दूर है, यदि वहाँ आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है तब वहाँ दमकल की गाड़ी केवल राखी बुझाने के लिए जाती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे कुदरहा ब्लाक, चाहे बनकटी ब्लाक, चाहे महादेवा पर एक दमकल का कार्यालय तैयार कर दिया जाय तो काफी अच्छा होता। कुदरहा ब्लाक बहुत दूरी पर है, अगर वहाँ पर तहसील बन जाती तो आने-जाने के लिए जनता को बहुत सुविधा होती। मैं यही आपसे अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरोज सोनकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव की धरती जनपद बहराइच, बलहा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आयी हूँ। मैं अपनी बलहा की जनता का सादर आभार प्रकट करती हूँ और इस सदन में आये हुए सभी माननीय सदस्यों को नमन करती हूँ, वन्दन करती हूँ, अभिनन्दन करती हूँ। आज प्रदेश में 37 वर्षों के बाद किसी पार्टी को लगातार दोबारा प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है। हमारी पार्टी राष्ट्रहित, दलित, शोषित, वंचित, महिलाओं, बेटियों, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों के लिए काम करती है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है, न कि अवसरवादी है। वर्ष 2017 से पहले की जो सरकारें थीं, वह अवसरवादी थीं। वह अपने महापुरुषों को भूलकर दूसरे देश के जिन्ना की तारीफ करती थीं, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया, उन्हें ढकेल दिया, उनको पीछे कर दिया।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता कहना चाहती हूँ कि अटल जी ने कहा था कि-

''भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं यह जीता-जागता महापुरुष है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अभिनन्दन की धरती है। यह वंदन की धरती है। यहाँ कंकड़-कंकड़ हमारे लिए शंकर है और यहाँ नदी-नदी हमारे लिए गंगा है। मैं मरूंगा तो मेरी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर देना और जब कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आयेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम जीयेंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए''।

मान्यवर, इस बार हमारे माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने और हमारे मुख्य मंत्री जी के सहयोग से जो बजट पेश हुआ छह लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अट्ठारह करोड़ सत्तानबे लाख रुपये का जो हमारे इस प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में चार-चांद लगाने का काम करेगी। मैं अपने क्षेत्र के लिए थोड़ा बोलना चाहूँगी जो हमारी सरकार ने हमारे क्षेत्र के लिए कराया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी विधान सभा क्षेत्र में करमोहना में ठोकर बनवाकर वहाँ की जनता व उस गांव को कटान से बचाया है और हमारे बलहा विधान सभा क्षेत्र में तकिया का पुल जो कई बरसों से अधूरा पड़ा था वह भी बनवाने का काम किया है। हमारे यहाँ चहलवा एक ग्राम सभा है जिसमें चार किलोमीटर का कटान है क्योंकि वह बाढ़ वाला क्षेत्र है और इसे बनवाने का काम किया जाय। हमारे यहाँ पर कोई भी नगर पंचायत, पालिका नहीं है। हमारे यहाँ मेहीपुरवा, मोतीपुर को नगर पंचायत पालिका बनाने का काम किया जाये और मैं विपक्ष के लिए दो शब्द बोलकर बैठ जाऊंगी कि-

"पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर के मत रहना"

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री शशांक वर्मा -**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कल्याणकारी बजट हम सबके सामने रखा है। इस इंक्रीमेंटल बजट से हमारे प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के अनुसार पूरे देश में गांव-गांव तक जनकल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम होगा। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि मैं लखीमपुर खीरी के जिले से 138 निघासन विधान सभा क्षेत्र से चुना गया हूँ। मेरे क्षेत्र में एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। जहाँ पर बेलरायां चीनी मिल है।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले बीते हुए समय में हमारे क्षेत्र में 2017-2022 के बीच में सारे गन्ना किसानों का भुगतान समय पर कराने का सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकार ने इस बजट में चीनी मिल अपग्रेडेशन माडिफिकेशन के लिए 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बेलरायां कोआपरेटिव चीनी मिल में एक एथेनॉल प्लाण्ट लगाने की कृपा की जाय। साथ में मेरी जो चीनी मिल है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज भी की जाये और साथ में उसका माडिफिकेशन अपग्रेडेशन का काम भी किया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की नीति के अनुसार हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्रेशर और प्राइवेट इकाईयां लगाई गई हैं जिससे जितने भी किसान भाई-बन्धु हैं, वह अपनी फसल का सही दाम पा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हम सबके अभिभावक बाबू कल्याण सिंह जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने उनके नाम से स्ट्रीट सोलर लाइट के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। जिससे सोलर लाइट की व्यवस्था गांव में की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से आज हमारे लोगों के लिए युवाओं के लिए सरकार ने काम करते हुए उनको निःशुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन देने का काम किया है। साथ में उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप नीति के अनुसार उनके नये इन्ट्रोगेटेट इन्टर्नशिप इन्टरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाई है। साथ में जिस तरह से हमारी सरकार हर जिले में एक स्टेडियम बनाने के लिए आगे बढ़ी है जिससे वहाँ के युवाओं को भी खेल-कूद में आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे जिले में एक मेडिकल कालेज देने का काम किया है जिस कारण से अब हमारे नये-नये डॉक्टर, नये-नये एम0डी0 हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के बीच में आकर लोगों की सेवा करेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार ने नये नर्सिंग कालेजों की स्थापना के लिए जो प्राविधान किया है उसी तरह से हमारी विधान सभा क्षेत्र-138, निघासन में एक नर्सिंग कालेज देने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में तिकुनिया एक इंडो-नेपाल क्षेत्र है वहाँ पर जो तिकुनिया पी0एच0सी0 पड़ती है उसको सी0एच0सी0 में परिवर्तित किया जाय। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के क्षेत्र से आता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया आप समाप्त करें। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी।

श्री शशांक वर्मा-

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है और वह दुधवा नेशनल पार्क है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर नेशनल पार्क कारीडोर बनाया जाये, जहाँ पर अपग्रेडेशन/ मॉडिफिकेशन के माध्यम से लोगों को आने का मौका मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सरोज सोनकर जी, आपके पीछे अभी शशांक वर्मा जी बोल रहे थे और आपका फोटो पूरे भारत वर्ष में लाइव हो रहा है। आपका फोन आया और आप फोन पर बात कर रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी ने इतनी लिबर्टी और इतनी व्यवस्था दे रखी है कि हम लोगों का मोबाइल अन्दर हाउस तक आ जा रहा है। अगर हमारी यह परम्परा बाहर फैलेगी कि हम अपनी सीट पर बैठकर भी मोबाइल से बात कर रहे हैं तो आप अन्दाजा लगाईये कि इससे मा0 सदस्यों की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि अगर सदन के अन्दर फोन अलाऊ है तो गेट से अन्दर आते समय इसे साइलेंट कर दें अथवा ऑफ कर दें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि किसी भी कीमत पर सदन के अन्दर फोन रिसीव न करें। मा0 सदस्य राघवेन्द्र जी, अब आप प्रारम्भ करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

संविधान शिल्पी, परमपूज्य बाबा साहब को कोटि-कोटि नमन। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत आभार और शुक्रिया। आज दो दिन से मैं बजट पर चर्चा सुन रहा हूँ जिसमें हमारे तमाम साथियों ने अपनी-अपनी राय रखी। सरकार ने प्रदेश को बहुत भारी-भरकम बजट दिया है, लेकिन इस बजट में कहीं से यह नजर नहीं आता कि इसमें नौजवानों का, किसानों का, युवाओं का, छात्रों का, महिलाओं का कोई सुदृढ़ प्रारूप दिया गया हो। आज यह जो नारा दिया गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह नारा भी खोखला प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। दो दिनों से मैं यह देख रहा हूँ कि चारों तरफ से यही आवाज आ रही है कि सड़कों का जाल, पुलों का जाल, विद्यालयों का जाल, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं भरथना विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जिसमें हमारा एक चकर नगर ब्लाक पांच नदियों से घिरा हआ है जिसे पचनदा बोला जाता है। मा0 मुख्य मंत्री योगी जी जब पिछली बार हमारे यहाँ गये थे तो उनके द्वारा औपचारिक रूप से यह घोषणा की गयी थी कि हम यहाँ पर बांध बनायेंगे और मुझे लगता है कि यदि वहाँ पर बांध बन जाता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर सिंचाई, बिजली तथा पर्यटन जैसे तमाम साधन उपलब्ध हो जायेंगे जिससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ता और बहुत अच्छा भी लगता। हमारे यहाँ पर लगभग 800 मीटर की एक बहुत छोटी सड़क थी और सपा सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर/रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन मात्र 800 मीटर की यह सड़क उससे नहीं जोड़ी जा सकी, क्योंकि वह सपा सरकार के द्वारा बनायी गयी थी। इसी तरह से स्वास्थ्य के नाम पर बहुत सारी बातें की गयीं। बकेवर में 50 शैय्या का एक अस्पताल है जिसमें 05 साल से कोई भी डॉक्टर नहीं है। वह 50 शैय्या का अस्पताल है इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भेजने का काम किया जाय।

जिस तरह से कानून व्यवस्था पर बात की गयी तो मैं कहना चाहूँगा कि 11 महीने पहले ग्यारह साल के एक लड़के का वहाँ पर अपहरण हुआ था जिसका नाम सोमन था। मैंने कई बार वहाँ पर कप्तान साहब से मिलने का प्रयास किया और उनसे कहा भी, लेकिन आज तक पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ़ पायी और आज तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पायी। इस सरकार का बजट और व्यवस्था पूरी तरह से खोखली साबित हो रही है। कहीं पर भी यह नहीं लग रहा है कि कानून, सुरक्षा, सड़क, व्यवसाय, रोजगार, किसान किसी के लिए भी कोई ठोस रणनीति बनायी गयी हो। इनकी बातें और सारा का सारा कार्यक्रम हवा-हवाई रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह बजट किसान विरोधी बजट है तथा नये वातावरण का जो एक नारा दिया गया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस नये वातावरण के नाम पर एक झूठ का वातावरण पैदा किया जा रहा है, एक सपने का वातावरण पैदा किया जा रहा है। सपने दिखाने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो अभी तक भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं,

सबसे ज्यादा तो उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार हुआ है, चाहे वह किसान सम्मान निधि की बात हो या अन्य योजनाओं की बात हो। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***डॉ0 आर0 के0 पटेल-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, 18वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। वर्ष 2017-18 में 3 लाख 84 हजार करोड़ का जो बजट था, आज वह 6 लाख 15 हजार करोड़ का हो गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 18वीं विधान सभा के किसी भी सत्र में यह 10 लाख करोड़ के बजट को पार करेगा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चिकित्सक होने के नाते मैं चिकित्सा के विषय पर जरूर बोलना चाहूँगा। देश के 10 बेहतरीन मेडिकल कालेजों में आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, के0जी0एम0सी0 और एस0जी0पी0जी0आई0 का नाम आता है और दुनिया के 100 बेहतरीन मेडिकल कालेजों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थित आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 का भी नाम आता है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय देश में 13 मेडिकल कालेज थे आज के समय में 600 मेडिकल कालेज हैं। हमारा उत्तर प्रदेश 65 मेडिकल कालेजों के साथ दूसरे या तीसरे स्थान पर है। जल्द ही 95 मेडिकल कालेजों के साथ इस देश का अग्रणी प्रदेश होगा।

हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी ने और मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेडिकल शिक्षा पर जो विशेष ध्यान दिया है इसकी वजह से हमारे प्रदेश में जो होनहार डॉक्टर तैयार होंगे वह प्रदेश में देश में और विदेश में भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेडिकल टूरिज्म जोकि बड़े शहरों में और कारपोरेट अस्पतालों में सीमित है, उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्था सुदृढ़ होगी जब सारे मेडिकल कालेज सुचारु रूप से काम करने लगेंगे तो हमारा प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का हब भी बनेगा अभी-अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सभी डॉक्टरों का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा और टेली मेडिसिन एवं फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से सेवा का जो निर्यात हो रहा है इससे अपना देश मेडिकल सेवाओं का भी निर्यात करने में अग्रणी होगा। वर्ष 2014 में अपने देश में 82 हजार एम0बी0बी0एस0 की सीटें थीं आज वह बढ़कर 1 लाख 50 हजार हो गयी हैं। यह केन्द्र सरकार की उन नीतियों का परिणाम है। आप सबको पता है कि एक नौकरी के लिए विज्ञापन निकलता है तो हजार से दो हजार लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन डॉक्टरों की वैकेन्सी खाली जाती है। इसका एक ही मतलब है कि डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने का जो प्रयास केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार कर रही है वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास अत्यधिक डॉक्टर होंगे और यही डॉक्टर देश-दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राज प्रसाद उपाध्याय-**

[xxx] (सदन में शोर) मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

यह भाग कार्यवाही का अंग नहीं होगा, चूंकि हमारे माननीय सदस्य नये हैं।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का सुअवसर दिया। साथ ही साथ मैं इस सदन में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण भाइयों-बहनों का, सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर की देवतुल्य जनता का वन्दन अभिनन्दन करता हूँ। जिनकी कृपा से मुझे इस विधान भवन के मंदिर में आने का मौका मिला। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसमें जन आकांक्षाओं को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यह बजट नये उत्तर प्रदेश की रूप-रेखा तैयार करने वाला बजट है। इस बजट से प्रदेश का सर्वसमावेश और समग्र विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है। जो बजट सिद्ध योगी जी के कुशल नेतृत्व में और एक सन्त रूप वित्त मंत्री जी द्वारा बनाया गया हो, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वह बजट कैसा होगा ? हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि 2022-23 का बजट अन्त्योदय के संकल्प को शीर्ष तक पहुंचाने वाला बजट है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाला बजट है। मैं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपकी पीठ के माध्यम से आपका अनुग्रह अपनी विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद सुल्तानपुर की कुछ विशेष समस्याओं की तरफ ले जाते हुए उनका अविलम्ब निराकरण चाहता हूँ। महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में बहुत से विकास के कार्य कराये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जो लखनऊ से बलिया गई है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें, आप अपनी समस्या लिखकर दे दीजियेगा।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

मान्यवर, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कमलकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वर्ष 2022-23 के बजट में सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तथा माननीय लाल जी वर्मा के भाषण से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में जिन तथ्यों और आंकड़ों को रखा गया है, वह जमीनी स्तर पर किये गये कार्यों से मेल नहीं करता। प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं की बात हो। इन सभी पर बड़े-बड़े आंकड़ों और योजनाओं के उल्लेख किये गये। परन्तु जैसी तस्वीर बजट में प्रस्तुत की गयी वह हकीकत से परे है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कार्यवाही के अन्तर्गत किये गये कार्यों और आंकड़ों पर बात की परन्तु इसके बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध देखने और पढ़ने को मिलता है। महिलाओं में आज असुरक्षा के भय का माहौल है। आये दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी अनेक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की बढ़ती घटनायें सरकार के राम राज्य की कल्पना के आधार पर कैसे हो सकती हैं ? यह समझ से परे है। मान्यवर, मैं एक युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं की समस्याओं और उनकी भावनाओं को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। आज युवा वर्ग निराश और हताश है क्योंकि वह सरकार से रोजगार की अपेक्षा रखता है लेकिन उसे रोजगार की जगह लाठियां मिलती हैं। वह रोजगार के लिए आन्दोलन करने को विवश है। सरकार ने दावा किया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जायेंगी लेकिन उनके साथ विश्वासघात की स्थिति पैदा हो गयी है ? करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। बजट में युवाओं को रोजगार देने के सम्बन्ध में बड़ी खूबसूरती से आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है परन्तु लाखों की संख्या में नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं।

(इसी मध्य सायं 6 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उनकी जो स्थिति पांच वर्ष पहले थी। वही आज भी है। यह बजट उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व हमने कोविड महामारी का सामना किया उस समय आक्सीजन व हास्पिटल की कमी और लाचार स्वास्थ्य सेवाएं देखीं। प्रदेश की जनता ने सुविधाओं के अभाव में अपनों को खोया है। हमने गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इस बजट में विकास की बात कहीं नहीं कही गयी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में चार स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं। स्वर्गीय श्री सुखदेव राजभर जी ने वर्ष 2008 में हास्पिटल बनाने का काम किया था लेकिन 70 प्रतिशत काम पूरा हो जाने के बाद भी 8 साल बाद भी वह अधूरा बना पड़ा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में चार हास्पिटल और ऐसे हैं जहाँ अभी भी न डॉक्टर हैं

न दवा है। महुआ नवादा में एक हास्पिटल है वह 80 प्रतिशत कम्पलीट होकर पिछले दस साल से खड़ा है। कुशल गांव में 30 बेड का हास्पिटल बना खड़ा है न वहाँ डॉक्टर है, न वहाँ दवा है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है इसमें हमने अपने विभाग की जो मांगे रखी थीं उनको भी बजट में स्थान दे दिया गया है। जो विपक्ष चाह रहा था उसका भी समावेश इस बजट में कर दिया है। लटकते हुए तारों की जो दुर्दशा है वह आपके समय से है और जो जर्जर तार हैं वह भी आपके समय से हैं। उसी प्रकार आप लोगों द्वारा नगरों में सफाई की बात की गयी उसका भी इस बजट में पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है और सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि नगर विकास के लिए नई योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं जैसे कि जो विस्तारित नगर निकाय हैं, जिनकी सीमा का विस्तार हुआ है जिनमें नये गांव आये हैं उनके लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उसी तरह एक प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट नगर निकायों में चल रहे हैं उनके लिए एक संकलित यूनिट की मांग की थी उसको भी 48 घंटे के अन्दर मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट में शामिल कर लिया है। उसी तरह से नगरों में फाइनेंस से अपने प्रोजेक्ट खड़े करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट और फाइनेंस कम्पनी की हमने मांग की थी उसका भी बजट में समावेश कर लिया गया है। रही बात ऊर्जा की, तो यहाँ यह बात घूम-घूम कर आ रही है कि पिछले पांच वर्ष में ऊर्जा की क्या-क्या सुविधाएं खड़ी की गयी हैं। मैं इस बात को बहुत विस्तार से सदन में बता चुका हूँ लेकिन एक और पहलू इसी बात का मैं इस सदन को बताना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 से 2017 की बात और वर्ष 2017 से 2022 की बात बार-बार यहाँ पर आ रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर कह रहे थे कि आपने अपने समय में कितनी इकाईयां लगाई हैं। मैं एक बार इसे समझा चुका हूँ और मैं फिर से एक बार इस बात को दो तरह से समझाना चाहूँगा। वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक का जो पांच साल का समय है उसमें से किसी एक साल की पीक डिमाण्ड को आप देख लीजिये। उससे ज्यादा तो हम वर्तमान में दे ही रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि किसी भी दो साल की बात आप बोल दीजिये। उन दो सालों का जोड़ भी हमारे द्वारा दी जा रही बिजली से कम पड़ता है। उदाहरण के रूप में वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 की जो पीक डिमाण्ड थी यदि उन दोनों को जोड़ दिया जाये तो भी हमने वर्ष 2022 में इसी महीने में जो बिजली दी है वह उससे कम होती है। उसी तरह से वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के आंकड़ों को अगर आप देखें। यदि आप कहें तो मैं इनको बोल दूं। उदाहरण के रूप में वर्ष 2013-2014 में 12327 मेगावाट

पीक डिमाण्ड थी और वर्ष 2014-15 में 13003 मेगावाट पीक डिमाण्ड थी। इन दोनों को अगर जोड़ा जाये तो हमने दिनांक 15 मई, 2022 को जो पीक डिमाण्ड पूरी की है वह उससे कम पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे समय की जो नान पीक डिमाण्ड है वह आपके उस समय की पीक डिमाण्ड से भी ज्यादा है यह मैं पहली बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को कह रहे थे इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि यह बताऊं कि नये प्रोजेक्ट कितने आये हैं। अगर नये प्रोजेक्ट नहीं आते तो आप जो 12000 मेगावाट दे रहे थे उसकी जगह जो हम 25000 मेगावाट दे रहे हैं तो वह सम्भव नहीं हो पाता। अगर हमने नई व्यवस्था नहीं की होती तो क्या यह सम्भव हो पाता। यह सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि आपके 12000 के सामने हमारी 25000 की खपत है।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, यह डिबेट नहीं हो रही है। आप जवाब देंगे तो फिर माननीय मंत्री जी का भी जवाब आयेगा। इसी में सब रह जायेगा। कृपया आप बैठ जाईये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह क्यों है यह भी सुन लीजिये। जिन झोपड़ियों में पंखे और लाइट नहीं जलती थी उनमें प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत मकान देकर लाइट लगवाई है इसलिए उन गरीबों की झोपड़ियों में भी बिजली की खपत होना शुरू हुई। हमने ओ0डी0ओ0पी0 योजनायें चलाकर एक-एक गांव, एक-एक मोहल्ले, एक-एक गली में जो छोटे-छोटे उद्योग थे जो छोटी-छोटी दुकाने थीं उनको ऊर्जीकृत किया है और वह चलने लगे हैं। आज वह एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इसलिए बिजली की खपत बढ़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2017-2022 में मेजा और हरदुआगंज में प्रोजेक्ट दिये हैं। हमारे अभी जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं उनमें ओबरा-सी के दो प्रोजेक्ट 660 गंगापार कुल मिलाकर 1320 मेगावाट, पनकी से 660 मेगावाट, जवाहरपुर में 660 गंगापार के दो प्रोजेक्ट कुल 1330 मेगावाट, घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन यूनिट कुल 1980 मेगावाट। इस प्रकार वर्तमान में 5280 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जो माननीय योगी जी की देन हैं। बहुत जल्दी ही यह प्रोजेक्ट ऊर्जीकत हो जायेंगे। इस प्रकार पहले की अपेक्षा जो हमारी तापीय ऊर्जा से उत्पादन था वह लगभग डबल हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अंकित भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन के माध्यम से सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जनता

को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे मात्र 25 वर्ष की उम्र में इस सम्मानित सदन में बैठने का अवसर दिया है और 18वीं विधान सभा का सबसे यंगेस्ट मेम्बर बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बता दीजिये कि आपकी उम्र 25 वर्ष से कम तो नहीं है।

श्री अंकित भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 25 वर्ष का हूँ। मैं ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-सैदपुर, गाजीपुर से चुनकर आया हूँ और मेरे क्षेत्र के सैदपुर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा इसी के अधीन स्थापित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और महिला चिकित्सालय है। यहाँ पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो आवास बने हुए हैं वह एकदम जर्जर हालत में हैं। इतना ही नहीं चिकित्सालय परिसर में मरीजों और अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की जो टंकी थी वह जर्जर होने के कारण जल निगम द्वारा वर्ष 2018 में ध्वस्त कर दी गयी थी। परन्तु आज तक न तो तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए जो आवास बना था उसकी मरम्मत हुई न ही पानी की टंकियों का निर्माण हुआ। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इन दोनों कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2018 से लगातार पत्र भेजकर अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन यह सरकार इस विषय पर सोयी हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वर्णित कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर सड़कों की दशा भी बहुत ही खराब है। सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं जिसके कारण एक्सीडेन्ट होने की सम्भावना बहुत ही बढ़ चुकी है। भाजपा सरकार जैसा दावा करती है उसके ठीक विपरीत बिजली बहुत कम आती है और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय सरकार द्वारा बनाये गये हैं वह इस्तेमाल लायक नहीं हैं। वह दिखावा मात्र हैं। किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने हेतु संसाधनों का अभाव है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से उदाहरण के तौर पर वर्तमान सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में भितरी-धुर्वाजुन शदियाबाद मार्ग एवं सैदपुर से चोचकपुर मार्ग कई वर्ष पहले बनाया गया था। आबादी बढ़ने के कारण वहाँ यातायात भी काफी बढ़ा है और इन दोनों ही सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है और गड्ढों के कारण एक्सीडेन्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। कम दूरी तय करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यह बात सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी सरकार ने इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मा0 अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वर्णित सड़कों व अन्य को तत्काल प्रभाव से मरम्मत व चौड़ीकरण करने का कार्य पूर्ण कराया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार तमाम सरकारी विभागों का निजीकरण लगातार करा रही है जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ0बी0सी0 व अन्य के लिए सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण समाप्त होने के कगार पर है जो हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग

करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से आरक्षित खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर पूरा करने का कार्य करें।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत-बहुत बधाई। बैठिये।

श्री अंकित भारती-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक मिनट।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा बोल दिया इससे ज्यादा क्या कहूँ। फिर आगे बोलना पड़ेगा। प्लीज बैठिये।

श्री अंकित भारती-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 अमित सिंह चौहान, डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 रागिनी, श्री अरविन्द गिरी, श्री जियाउर्रहमान, श्री पंकज सिंह, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय अनुपस्थित हैं। इन्हें दोबारा याचिका देनी पड़ेगी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार की गयीं :-

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, डॉ0 नीरज बोरा, डॉ0 मुकेश वर्मा, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री अभय सिंह, श्री अमिताभ बाजपेयी, श्री कविन्द्र चौधरी, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री जगदीश नारायण, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री तसलीम अहमद, श्री पंकज गुप्ता, श्री पंकज मलिक।

(उपस्थित सदस्यों की याचिकाएँ स्वीकार की गयीं।)

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल के विकास खण्ड सोहावल के अन्तर्गत एक नवीन पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद अयोध्या के बीकापुर तहसील अन्तर्गत ग्राम-चन्दीपुर नगहरा के राजकीय महाविद्यालय बीकापुर दूसरी किस्त के सम्बन्ध में श्री राकेश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

3-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड सोहावल ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-कलाफरपुर में घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद आगरा के अन्तर्गत शंकर कालोनी में प्रेम सिंह के घर से संतोष सिंह चौहान के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमा चौहान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के अन्तर्गत आगरा कैण्ट रेलवे स्टेशन से पंजाबी भवन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

3-जनपद आगरा के अन्तर्गत नन्द सिनेमा चौराहा से आर0एम0ओ0 कार्यालय तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजकिशोर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 21, जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 03, जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 01 व जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 01 याचिका†

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहपुरा जागीर में शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम वंशीपुर व परचई के बीच भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम डूंगरपुर से दुनका नगरिया मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानू राठौर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम जालिम नगला से अमौर भोजीपुरा रोड तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पस्तौर में पश्चिमी की ओर नहर पर नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममता गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहपुरा जागीर में नवोदय विद्यालय मार्ग से सरदार बग्गा सिंह के फार्म तक नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार बग्गा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर के निगौही शाहजहाँपुर मार्ग से वाया श्रीमती उर्मिला देवी इण्टर कालेज होते हुए मिश्रीपुर निगौही तिलहर मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

8-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम अमखिरिया तालूके पगार व मन्निया रोड से ग्राम कुरैली तक खदनिया नाले पर लघु सेतु व सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजबहादुर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के रास मोहनपुर मार्ग से वाया गनेशपुर रासमोहनपुर मार्ग तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बसई से वाया चन्द्रपाल मेमोरियल इण्टर कालेज रास, मोहनपुर मार्ग तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बसई में पश्चिम की ओर सहोड़ा मार्ग तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम नगरिया सादात से वाया सिल्लापुर होते हुए ग्राम सिंधौली तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवन्त व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम अमखिरिया तालूके से बलरामपुर तक खदनिया नाले पर लघु सेतु व सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

14-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम गिरधरपुर में केसरीलाल के मकान से शीशगढ़ बल्लिया मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केसरीलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंथरा से ग्राम अमौर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

16-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पटवईया से ग्राम कुरतारा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मीना गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

17-जनपद कौशाम्बी के ग्राम मकदूमपुर की दलित बस्ती की रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मिस्ते व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका,

18-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम बधेंग कंजा नहर की पुलिया से निगौही पुवायां मार्ग तक नहर रोड का चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

19-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम चुरई दलपतपुर चर्च के पास से ग्राम सिरौली मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

20-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रसूलिया से विक्रमपुर तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

21-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम खरसेनी से रसूलिया तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामऔतार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

22-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सेवा ज्वालापुर में शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान दास वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

23-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बगरऊ से बगरऊ की गौटिया तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

24-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बुझिया में ग्राम से शमशान भूमि तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेतराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

25-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम खुजुरिया से वसावनपुर तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

26-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मढ़ौली नहर की पुलिया से टियुलिया बड़े बाईपास तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 व जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 01 याचिका†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद लखनऊ के गोमती नदी पर कुड़िया घाट के निकट पक्का पुल के पास बनाये गये अस्थायी अवरोधक को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे बांस-बल्ली के स्थान पर बिजली के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ में गोमती नदी के किनारे खदरा फैजुल्लागंज व अन्य स्थानों पर छठ पूजा हेतु घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद सीतापुर के प्रखण्ड शारदा नहर सीतापुर में मृतक आश्रित नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल कुमार निवासी जनपद सीतापुर की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के ऐतिहासिक पौराणिक स्थल लक्ष्मण टीला पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 11 व जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद आगरा की तहसील पिनाहट विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत आगरा बाह मार्ग से गुर्जाराम तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदीन व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा की तहसील पिनाहट विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत झंगोला देवी मन्दिर से कांकर रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला दया से नगला वाजदार तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में ग्राम क्यौरी मार्ग से बीच का पूरा मार्ग का सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

5-जनपद आगरा की तहसील पिनाहट विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत बटेश्वर मार्ग से सुंसार का पुरा मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप यादव व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

6-जनपद आगरा की तहसील पिनाहट विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत पिटौरा रोड से कांकर (रजौरा) मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में गोपाल पंडित के मकान से अज्ञान के मकान तक का सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल पंडित व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में श्याम सिंह के मकान से गुड्डी देवी तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी मुस्तफाबाद रोड से मुन्नालाल के मकान तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में अशोक के घर से मनोज के घर तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत दतौजी खुर्द में राजकुमार वर्मा जी वाली गली, धर्मवीर बघेल वाली गली, फकीर बाबा वाली गली, कलमी वाली गली, भटूरे वाली मांई वाली गलियों का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दिखतौली में शैलेन्द्र प्रधान के मकान से भूरी सिंह के खेत तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दिखतौली में दिखतौली लिंक रोड से शेर सिंह के मकान से एफ0एस0 कालेज नहर का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में सरकारी चकरोड राजकुमार के घर से भूरी सिंह के मकान तक की सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में सुखवीर के मकान से प्रमोद के मकान तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सुखवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

16-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत रहचटी में नोवा डेयरी से बाल्मीकि मंदिर तक का सी0सी0 कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका व जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)†

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं-

1-जनपद-मिर्जापुर के ब्लाक-पुतहरियां दाढ़ीराम में रोड, नाली, आर0सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद बिन्द व अन्य निवासी, जनपद-मिर्जापुर की याचिका,

2-जनपद-वाराणसी में राजा तालाब से होते हुए जमुआ-कछवा बाजार मीरजापुर तक बस वाहन चलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद-मिरजापुर की याचिका तथा

3-जनपद-मिरजापुर के ब्लाक-सिटी के ग्राम-प0 जसोवर में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद-मिरजापुर की याचिका।

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ†

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत उतरौला-पचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती फूलमती व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के ग्राम मटेहना से संड़वा गुलरिहा, सिरसिवा, बगहीसीर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत मधवानगर खादर-कोहरगड्डी खादर सम्पर्क मार्ग पर स्थित नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री राधिका यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

4-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत एन0एच0-730 से गैंसड़ी परसापलईडीह, झौव्वा, बेनीनगर होते हुए चन्दरपुर पचपेड़वा-उतरौला मार्ग तक जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलोहा में निर्माणाधीन महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

6-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत बालापुर भोजपुर थारू मार्ग से खखरा-रामवापुर थारू होते हुए जरवा चितौड़गण बांध तक जाने वाले सम्पक मार्ग का विशेष मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू जान व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

7-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत तुलसीपुर-जरवा मार्ग से सेमरी सिसई कुड़ोहा सम्पर्क मार्ग पर स्थित धोबहा नाला पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रहीम खां व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद-जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र-मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम सभा-मोलनापुर में पाल बस्ती, भूजा बस्ती, नाई बस्ती, यादव बस्ती में 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सभाजीत कनौजिया, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ †

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के ग्राम सभा काजीपुर गाडर के 25 किसानों की भूमि अधिगृहीत किये जाने पर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेमिना देवी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितता एवं पक्षपात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के दर्शन नगर में स्थित यश पेपर मिल को सेप्रेट पाइप लाइन से नदी तक जोड़ने और उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड तारून में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम निषाद निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के ग्राम सभा गौहान खुर्द में नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत वर्मा निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

6-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के ग्राम बेरूगंज में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गया शंकर मौर्या निवासी जनपद अयोध्या की याचिका तथा

7-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड तारून में फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर यादव निवासी जनपद अयोध्या की याचिका।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा, जनपद कानपुर नगर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4347-4375/2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24-02-2016, 17-11-2016 व 25-07-2017 के अन्तिम आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 11 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं-

1-जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र गोला गौकर्णनाथ के अन्तर्गत लखीमपुर मार्ग से महेशापुर अम्बारा होते हुए नौगवां तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगतपाल, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

2-जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र गोला गौकर्णनाथ के अन्तर्गत गोला मार्ग से अमीर नगर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शकील खां व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

3-जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र गोला गौकर्णनाथ के अन्तर्गत मढ़िया सड़क से अल्लीपुर होते हुए लखीमपुर मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभाल व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

4-जनपद खीरी में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे से श्री एल0आर0 सचान के आवास तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एल0आर0 सचान व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र गोला गौकर्णनाथ के अन्तर्गत अलीगंज से हरसिंगपुर-गुरुद्वारा नं0-2 बसलीपुर होते हुए छौरासी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

6-जनपद खीरी में विधान सभा क्षेत्र गोला गौकर्णनाथ के अन्तर्गत शारदा नदी से रायपुर प्रा0प0 होते हुए बस्तौली तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

7-जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के अन्तर्गत अलीगंज-रायपुर मार्ग से लखरावां-मूड़ा सवानान-हिकमतनगर-फूलपुर होते हुए छैरासी तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत पाण्डेय निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

8-जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के अन्तर्गत लखीमपुर मार्ग से बेलहा सिकटिहा चकपुरवा रूरा गुजारा होते हुए मोहम्मदी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नैपाली प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

9-जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के अन्तर्गत लखीमपुर बिजुआ मार्ग से चौसंदे बाबा स्थान होते हुए चंदपुरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

10-जनपद खीरी के विकास खण्ड कुम्भी गोला के ग्राम कंधरापुर के अन्तर्गत गोमती नदी पर कांकरघाट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका तथा

11-जनपद खीरी के विकास खण्ड कुम्भी गोला के अन्तर्गत गोला मार्ग पर टेढ़ेनाथ मन्दिर से मगदापुर भोगियापुर गफ्फारनगर होते हुए मोहम्मदी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका

श्री कवीन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री कवीन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम बढ़नी चौराहे से धंशरियागांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल मुकुन्द यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत खजुहा मार्ग से अनिहाजोत होते हुए रमवापुर, रानीपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदयराम यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

† छापी नहीं गई।

3-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत जलेबीगंज से कुर्दा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपांकर गौतम निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत बेलवरिया जंगल से मांझा मानपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 वीरेन्द्र यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम सिकटा से प्रतापपुर गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुनीत चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

6-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत खजुहा में बुलाकी के मकान से बड़े बाबू के घर से होते हुए काली जी के स्थान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहरैची गौतम निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत टिनिच कप्तानगंज मार्ग से कुर्दा मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीराम मौर्या निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम वेसौरा पिच से प्रतापपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

9-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत परखती घाट से केवटली गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

10-जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम-पिलखांव में कहार टोला से सेठा चौधरी पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चन्द्र चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद मेरठ की ग्राम पंचायत करनावल में राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद मेरठ के विकास खण्ड रोहटा के ग्राम किनोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

3-जनपद मेरठ के विकास खण्ड रोहटा की ग्राम पंचायत रोहटा को नगर पंचायत बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्लू व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत ग्राम सभा राजघाट को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत गंगा किनारे राजघाट नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश सारस्वत व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत राजघाट नरौरा कर्णवाश गंगा घाटों पर डूबने से बचाव हेतु (एन0डी0आर0एफ0) टीम गोताखोर सोनार सिस्टम लगवाने के सम्बन्ध में श्री ओ0पी0 वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत राजघाट नरौरा कर्णवाश बैलौन रामघाट को जोड़कर कॉरीडोर रिवर फ्रंट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश कुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री छोटे लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के आगरा शमसाबाद मार्ग से बांगुरी सेवला गौरवा गढ़ी ठाकुरदास मलैला से कुन्डोल तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फौरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा याचिका,

2-जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र आगरा-फतेहाबाद मार्ग से कल्याणपुर-रणपुरा तांसपुरा शमसाबाद-फतेहाबाद रोड क्रास करते हुए झाल की पुलिया गढ़ी ताल पीपरा चौड़ाया

---

† छापी नहीं गयी।

डन्डनियापुरा हीरापुरा नगरिया चमरौली बीजला मझारा मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामौतार तोमर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा याचिका तथा

3-जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के आगरा फतेहाबाद बाह मार्ग से सांकुरी कलां से होते हुए रिहावली मार्ग तक सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री बनवारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा याचिका।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के चरगांवा स्थित रेल विहार कालोनी फेज-प्रथम के पार्क को जनहित में विकसित कर बाउण्ड्रीवाल, सौन्दर्यीकरण व वृक्षारोपण युक्त व पार्क में ओपेन जिम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में एवनी एवं ककरवई में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में लेखरी नदी पर तथा ससुर नाले पर लघु सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गुरसराय में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के औरंगाबाद में बिजनौर रोड से राहुल कनौजिया के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में धसान नदी पर कचीर के पास एवं झारखण्ड गुढ़ा के पास रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

6-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बेतवा नदी पर खिरिया घाट के पास रपटा के स्थान पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

7-जनपद उन्नाव की रामअमरापुर के ग्राम रामापुर में जल निकासी हेतु नाली एवं माइनर में साइफन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ[†]

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनन्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

2-जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत टडवा रतसड मुख्य मार्ग से ग्राम सभा सतडसड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सच्चन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)[†]

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद के विधान सभा कुन्दरकी में रोडवेज का बस डिपो एवं मिनी बस डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिलाल व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ [†]

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के पूरनपुर बिजोरी चट्टी वाली मार्ग से मूर्ति देवी इण्टर कालेज तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के नगीना बुदकी मार्ग से ग्राम दरियापुर होते हुए जोगी रम्मपुरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरफराज अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राजारामपुर से मुबारकपुर नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मो0 जाकिर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयी।

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम लालपुर सौजीमल से बालवाली पुल तक 105 कि0मी0 मार्ग नवनिर्मित कराने जाने के सम्बन्ध में श्री इश्तकार व अन्य निवासी जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम सलेमपुर भट्टा से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ तथा जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में नगर पालिका परिषद् गंगाघाट में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में नगर पालिका परिषद् गंगाघाट में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर के पं0 दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन सिन्हा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद लखनऊ की वृन्दावन आवासीय योजना के भू-खण्ड संख्या 9डी/जी0एच0-1 के संशोधित मानचित्र और पूर्णता प्रमाण-पत्र को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथिलेश कुमारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में विकास खण्ड बिछिया के ग्राम रूपऊ में डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में उन्नाव कानपुर हाई-वे पर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश उर्फ लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-सदर में रेलवे स्टेशन उन्नाव से कासिमनगर होते हुए हाई-वे मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-मेसर्स लावा इण्टरनेशनल लिमिटेड नोएडा द्वारा रजत वूमेन्स कालेज ऑफ एजुकेशन को आपूर्तित टैबलेट की खराब गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री प्रिया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

10-मेसर्स लावा इण्टरनेशनल लिमिटेड नोएडा द्वारा रजत वूमेन्स कालेज ऑफ एजुकेशन को आपूर्तित स्मार्ट फोन की खराब गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अनुराधा मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ[†]

श्री पंकज मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम जडौदा में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूरखान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम चरथावल से कुटेसरा मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम लच्छेडा से तावली तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम बघरा के तावली में एक राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

6-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम मान्डी से काजीखेड़ा तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव बालियान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

[†] छापी नहीं गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 13 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गौतमबुद्धनगर के विभिन्न अविकसित कालोनियों में प्रमुख मार्गों को सी0सी0 रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार झा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

2-जनपद गौतमबुद्धनगर के बरौला गांव के हिण्डन विहार एवं शताब्दी इन्क्लेव कालोनी में पानी की सप्लाई जोड़ने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

3-जनपद गौतमबुद्धनगर के पुराना हेबतपुर, यूसुफपुर चक्साहबेरी व तिगड़ी तथा गढ़ी चौखण्डी, एफ0एन0जी0 के बीच हिण्डन नदी में पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

4-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम आगाहपुर में श्मशान घाट की चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

5-जनपद गौतमबुद्धनगर के गांवों के आस-पास अविकसित कालोनियों में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

6-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम बसई में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जन्टर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

7-जनपद गौतमबुद्धनगर के सदरसराय कालोनी में बिजली एवं पानी से संबंधित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी पटवाल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

8-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम छिजारसी में एस0सी0 बस्ती में आर0सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

9-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम बरौली की पुरानी कश्यप और राजपूत कालोनी में विकास कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

10-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम सलारपुर में कालका इन्क्लेव कालोनी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कमल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

11-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम बहलोलपुर से ककराला कालोनी तक पुस्ता रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौतम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

12-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम नयागांव में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका तथा

13-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम सलारपुर में मुख्य नाले पर बने पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम रिझौडा में वीरेन्द्र के ट्यूबवेल से चन्द्रवीर के ट्यूबवेल तक खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर, विकास खण्ड बभनान के ग्राम पंचायत धारीघाट में अग्निशमन केन्द्र का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर, विकास खण्ड छपिया में बभनजोत रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नंदी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर, विकास खण्ड मनकापुर, ग्राम पंचायत सुमेरपुर में सद्भाव मण्डप/मैरिज हाल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत घनश्यामपुर ग्रांट में विशुही नदी पर गऊ घाट पर पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तुषीर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर विकास खण्ड बभनजोत ग्राम पंचायत दौलतपुर ग्रांट में 33/11 विद्युत सब स्टेशन का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेषधर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 02 याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत दुर्जनपुर से बलेश्वरगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग सिसई से तेहला होते हुए बनुआ बाजार सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-39 से मद संख्या-78 तक याचिकाएँ उपस्थित हुई मानी गईं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत फतेहपुर में जर्जर तार बदलने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत पूरे इलाके में बिजली संकट दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत किरावली स्टेडियम का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत भगोली खुर्द से राजस्थान सीमा तक पक्का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पारासर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राजस्थान सीमा से लगे हुए ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्रामों में आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी के निराकरण हेतु कान्हा उपवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारीलाल छौकर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 03 तथा कुशीनगर से सम्बधित 01 याचिका[†]

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली के विकास क्षेत्र रामनगर में भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग से अडवाघाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली के विकास क्षेत्र में ग्राम पंचायत शंकरपुर में विद्युत प्रवर्तक की क्षमता में वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-330, पडरौना में विकास क्षेत्र विशुनपुरा में गांधी माइनर हेड से सुखुई रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309 रुधौली के विकास क्षेत्र रामनगर में भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग से नया घाट सम्पर्क मार्ग पर पिच रोड का लगभग 3.00 (तीन किमी0) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णा कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

[†] छापी नहीं गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में नहर खीरी ब्रांच की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र ग्राम भण्डिया में स्थित सीहा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीशंकर गिरी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में कान्हा गौशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में बन्द पड़ी कमलापुर मैगना चीनी मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

5-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में विकास खण्ड पहला में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीशंकर गिरी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

6-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

7-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में आश्रम पद्धति विद्यालय (ए0टी0एस0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

8-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा गोदलामऊ में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यबक्श सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

9-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में नव निर्माण सड़क का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

10-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की तहसील नौगावां सादात, जनपद अमरोहा में याचीगण के घर के ऊपर से जाने वाली 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री तालिब शाह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ †

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के कानपुर डिस्ट्रिक्ट राइफल क्लब के बैंक एकाउण्ट शस्त्र लाइसेंस और नवीन शस्त्र लाइसेंस बनाये जाने व शूटिंग रेंज विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चावला मार्केट में सी0टी0आई0 तक मार्केट के दोनों तरफ डिवाइडर एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वीटी सरदार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के बाबू पुरवा नया सेण्टर पार्क में महिला शौचालय एवं ड्रेसिंग रूम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बल ओझा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के यशोदा नगर सड़क मार्ग से टाट मिल चौराहे तक दोनों ओर अतिक्रमण हटवा कर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद कानपुर नगर में हिन्दी के आधुनिक काल प्रवर्तक आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की कर्मस्थली जूही क्षेत्र में निवास स्थान को संस्कृति विभाग व पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

6-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नम्बर-38 में करिपात्रि नगर तालाब के बीचो बीच में स्थित प्राचीन हनुमान मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नम्बर 14 में मकान नम्बर-127/399-400 से लेकर मकान नम्बर-127/544 लगभग लम्बाई 400 मीटर तक सड़क और दोनों पटरी पर नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

8-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र में वार्ड 14 धोबी तालाब के बीचो-बीच में स्थित संविधान के निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की स्थापित मूर्ति का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

9-जनपद कानपुर नगर में पटवा जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर पटवा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत सहाव मोड़ (फोर लेन) से गौहन तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत गोपालपुर से कुरतला मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत तरसौल रजवाहा में बैनीपुरा से सुरावली तक लाइनिंग (पक्का) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कुठौंद शाखा नहर में कुरौंती से हरौली के आगे तक लाइनिंग (पक्का) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्योतिष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कैलोर माइनर में (नहर से कैलोर आगे तक) लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत गौराभूपका से इटवां मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रतीक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत गालामपुरा से गीदन की खोड मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत जायघा से जगम्मनपुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत महेशपुरा से सलैया मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्णवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत चटसारी से ऊंचा मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के तहसील बिल्हौर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बोधराज सिंह एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर में ग्राम रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-209, बिल्हौर में स्थापित सभी 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वार्ड ब्वाय व सफाई कर्मी को तैनात करने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज और राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री आंचल गुप्ता, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम अभनपुर सम्पर्क मार्ग से मुडिया भीकम की रेलवे क्रासिंग तक पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री मुजीब अहमद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत मिनी खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री फैसल इरफान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-उत्तर प्रदेश के समस्त सहारा इंडिया निवेशकों को उनके धन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नी देवी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पार्क का सौन्दर्यीकरण कर रैन बसेरा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश रफीक, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत नौवापुर के सम्पर्क मार्ग के अधूरे पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 31 याचिकाएँ †

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद चन्दौली के सकलडीहा डिग्री कालेज के उत्तर की तरफ पिच रोड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कश्यप व अन्य की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के जफरपुर ग्राम में होज पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामविलास सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में पड़ाव चौराहे से नीबूपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चन्दौली सदर के ग्राम सभा कुरई में प्राथमिक विद्यालय से गौरी पुरवा होते हुए मेन रोड तक पिच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद में ग्राम सभा गंगेहरा में लालजी साव के मकान के बगल से कोटी माई मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

6-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद में ग्राम सभा छिबिया में जगदीश भारती के घर से मुन्ना बिन्द के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

7-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम अमोधर में चकिया मेन रोड से ओ0पी0 दयाल के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

8-जनपद चन्दौली के पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर व पटेल नगर में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जैन व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

9-जनपद चन्दौली के पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर में जी0टी0 रोड राम जानकी मंदिर से काली महाल तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विभूति जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

10-जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर के ग्राम सभा मवई सहजौर, कैथापुर, हिलौनी हरीशंकर व महदेवपुर में पम्प या लघु नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

11-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम खुटहाँ लिंक रोड से सैदपुर भुजहुंआ लिमुहानी तक पिच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

12-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम कुण्डा खुर्द में डीह बाबा मंदिर से राम मंदिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

13-जनपद चन्दौली के पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर में डॉ0 लक्ष्मी यादव के घर से कैथापुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम मोदी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

14-जनपद चन्दौली के ग्राम कुण्डलिया से हिन्द बाटी बार्डर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र माही व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

15-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद में चकिया रोड जे0एस0 पब्लिक स्कूल से दिहुलिया हनुमान जी के मंदिर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका,

16-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम कुण्डा कला मलहिया बस्ती से पासवान बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

17-जनपद चन्दौली में लीलीपुर रेलवे क्रासिंग से सिरसी गांव तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

18-जनपद चन्दौली में एन0एच0-2 से जसूरी मार्ग होते हुए जिला भाजपा कार्यालय तक पिच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

19-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चन्दौली सदर के ग्राम सलेमपुर महदेउ दानवीर मंदिर से रमेश सिंह के खेत तक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

20-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-08 पथरा भाग-1 के परहुपुर में विपिन भारती के घर से रंजीत पासवान के मकान तक सीवर व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन भारती व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

21-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-04 गिधौली में मदीना अस्पताल से विनोद केशरी के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद केशरी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

22-जनपद चन्दौली के गांधीनगर कालोनी कैथापुर में अर्चना बर्तन भण्डार से यादव बस्ती तक आर0सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

23-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-08 पथरा भाग-1 में लखीमपुर मुख्य मार्ग पर कैप्टन विनोद उपाध्याय के मकान से मनोज श्रीवास्तव के मकान तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

24-जनपद चन्दौली के महावलपुर जी0टी0 रोड से मामू पान वाले से होते हुए साहनवाज के दुकान तक जीरो से लेपन व सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री साहनवाज व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

25-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-14 सिकटिया परशुरामपुर में आर0सी0सी0 में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

26-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-15 हनुमानपुर में मंसूर आलम के मकान से शाह आलम के मकान तक पिच रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशर्फी सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

27-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-08 हनुमानपुर में श्री राहुल राय के मकान से जवाहर यादव के मकान तक पिच रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राय व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

28-जनपद चन्दौली के नगर पंचायत मुगलसराय में मठ वाली सड़क के पास बड़ा नाला में ह्यूम पाइप डालकर ऊपर से इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र अग्रहरी, निवासी जनपद मुगलसराय की याचिका,

29-जनपद चन्दौली की तहसील मुगलसराय स्थित बबुरी ग्राम सभा में संचालित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सत्यनारायन सिंह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की वस्तुस्थिति का अवलोकन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार, निवासी जनपद मुगलसराय की याचिका,

30-जनपद चन्दौली में सुवास पार्क से चकियां तिराहे तक ऊपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कनौजिया, निवासी जनपद मुगलसराय की याचिका तथा

31-जनपद चन्दौली की तहसील मुगलसराय स्थित बबुरी ग्राम सभा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त लाल गुप्ता, निवासी जनपद मुगलसराय की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद झांसी में महानगर वार्ड नं0-27, शिवाजी नगर में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन में प्रवाह की गति को बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पाराशर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद झांसी में महानगर वार्ड नं0-32 के मोहल्ला महाराणा प्रताप नगर, पिछोर गुमनावारा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी में जल संस्थान, झांसी के श्रमिकों/कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी में महानगर वार्ड नं0-13 कोछाभांवर, कुम्हार का कुआं, आवास विकास रोड पर पटेल के मकान से नाथूराम रायकवार के मकान तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नाथूराम रायकवार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी में महानगर वार्ड नं0-31 के सिद्धेश्वर नगर में श्री अखिलेश सेन के मकान से श्री बाबूलाल कुशवाहा के घर तक व अन्य स्थानों पर सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र अहिरवार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सैय्यद सादिक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ [†]

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत कादीपुर से रसूलपुर, बाकरगंज तक सड़क के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री तिलकधारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत बोदरा के गेदुरीगंज प्रधानमंत्री सड़क तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत बरियावन से सिसरा बरौली होते हुए (किछौछा मोड़) बसखारी-जलालपुर मार्ग तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयी।

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत कांदीपुर से रसूलपुर, बाकरगंज तक सड़क के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री तिलकधारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत चैनपुर चौराहा से सकरा दक्षिण होते हुए बोदरा ग्राम तक सड़क के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम सदरौना में नगर निगम (ग्राम समाज) की जमीन भूमि गाटा संख्या-406 को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0पी0 कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत पानी की समस्या हेतु कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीपेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 08 याचिकाएं†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-भगवानपुर में जयराम के खेत से राम सेवक के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर से रम्मनपुर ओम प्रकाश के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभाा-मुसेपुर गिलन्ट में बुढ़वा बाबा के स्थान से राजभर बस्ती तक जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-इल्तिफातगंज सम्पर्क मार्ग से करमुलहा-छितूनी होते हुए बनगांव डिहवा तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-शाहगंज सम्पर्क मार्ग से जाफरगंज बाजार से अटंगी तक सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राणा प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-बसखारी सम्पर्क मार्ग से बरियावन बाजार माइनर से मोहरई तहिरापुर होते हुए परसकटुई तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

7-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-अयोध्या सम्पर्क मार्ग से पॉलीटेकनिक कालेज से दुल्लापुर तक सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

8-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-महरुआ सम्पर्क मार्ग से सहतूगंज के आगे तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संग्राम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से संबंधित याचिका †

श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा, जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कतिपय रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से संबंधित 10 याचिकाएँ †

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत बकसरिया सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत शिवालापुर सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत धैसरा सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत भदईपुरवा सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

5-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत किढ़हौना सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राना प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

6-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के इकौना में ऐलहवा पिच रोड से पण्डितपुरवा बिदुहनी के मध्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनोखी लाल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

7-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती के इकौना में धर्मपुर एवं शिवाजोत लेपित मार्ग के मध्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

8-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के इकौना में सीताद्वार सम्पर्क मार्ग से बरईपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

9-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में गिलौला के अन्तर्गत भवानी नगर ग्राम सभा में मनिकापुर बार्डर से भवानी नगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

10-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में गिलौला के अन्तर्गत कसियापुर से बेदौरा सम्पर्क मार्ग के मध्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुधनरायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से संबंधित 11 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', मा0 सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सताव के ग्राम-मछरिया में राम सेवक के घर के पास से नाग पवरियां तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सताव के ग्राम-कन्दुरी में प्राथमिक विद्यालय से तालाब तक नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सताव के ग्राम-शमशेर का पुरवा बाजार से गगवा के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सागर व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली-गुरूबक्सगंज मार्ग से ग्राम-देदौर वाया दुर्गा इण्टर कालेज ग्राम-सुरपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सतावं के ग्राम-अटौरा बुजुर्ग में पक्की रोड से बरौटा तालाब तक नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत लाल व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर में अंगूरी पूरा सम्पर्क मार्ग से वाया पूरे गरवर धौकलपुर तक डामरीकरण रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

7-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर के ग्राम-फरीदपुर में हरनी सम्पर्क मार्ग से लोधन का पुरवा तक डामरीकरण रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर में बरगदहा माइनर से हिलालगंज तक नहर में जल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामविलास पासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर में छतैया भोला का पुरवा सम्पर्क मार्ग से पूरे शीतल तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश पासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर में ददौर-हिलालगंज सम्पर्क मार्ग से वाया भोला का पुरवा सम्पर्क मार्ग हरचन्दपुर हाई-वे तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र पासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

11-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर में ग्राम-सोहलिया से सोहलिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम-भगना का पुरवा तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका †

श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-पलिया में सन् 1956-57 में किसानों को आवन्टित गवर्मेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट की भूमि को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से संबंधित 02 याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-वारा तथा विकास खण्ड-अमिलिया के अन्तर्गत शंकरगढ़ में महिला स्वास्थ्य भवन में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं नियमित रूप से बैठने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-वारा के अन्तर्गत शंकरगढ़ में महिला स्वास्थ्य भवन में नवीन भवन बनाये जाने एवं नियमित तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से संबंधित 02 याचिकाएँ †

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर के अयाहशाह के ग्राम-पल्टूपुर मजरे के ललौली ब्लाक असोथर यमुना किनारे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के अयाहशाह ग्राम सभा सरकण्डी में गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-कालपी में एन0एच0-217 पर मुन्ना पुल पावर से मेन बाजार होते हुए अहमल तास तक 02 किमी0 अत्यन्त जर्जर व खराब सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित 03 याचिकाए †

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय हरदी, विकास खण्ड-धौरहरा में इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

2-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-ईसानगर में ग्राम-गोड़वापुरवा मजरा गनेशपुर से नई बस्ती होते हुए प्राथमिक विद्यालय, चन्द्रासा खुर्द तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका तथा

3-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-ईसानगर में जालिमनगर पुल से ईसानगर ग्राम तक घाघरा नदी के किनारे तटबन्ध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित 08 याचिकाएँ †

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-खड्डा में लक्ष्मीगंज शुगर फैक्ट्री चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित राव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-मंडार बिन्दवलिया में पण्डित दीनदयाल मॉडल इण्टर कालेज की जमीन पर अतिक्रमण हटाकर बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-खड्डा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/फस्ट रेफर यूनिट, खड्डा तुर्कहा में बीमारियों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग व आई0सी0यू0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री निखिल जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद कुशीनगर के गन्ना किसानों का कप्तानगंज कनोडिया शुगर वर्क्स लि0 में बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशु गोविन्द राव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-खड्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खड्डा में नारायणी नदी के तलहटी पर बसे ग्राम-महादेवा व सालिगपुर में भीषण बाढ़ से निदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुनाल राव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

6-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड-कोटवा के पशु चिकित्सालय पर एक चार्ज पर पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष रौनियार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

7-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड-कोटवा के जर्जर एवं परित्यक्त अनुकूल पशु चिकित्सालय भवन के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

8-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र-खड्डा के अन्तर्गत खड्डा शुगर फैक्ट्री में वेतन विसंगतियां दूर कराने के सम्बन्ध में श्री राजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज में ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय म्यूना से खुदागंज तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-तिलहर में जिगनिया चौराहे से ग्राम-हवासपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-तिलहर में जैतीपुर रोड से खिरिया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर-तिलहर मार्ग कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम-गोरा से बकैनिया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं तथा जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-जगदीशपुर अवतार में योगेन्द्र के घर से अमर चौहान के खेत तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनन्जै चौहान, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कालूपुर में मनोज यादव के घर से जयप्रकाश चौधरी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम गुरूसहाय खेड़ा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री श्याम धनी राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित 5 याचिकाएं†

श्री श्यामधनी राही, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र-303 के कपिलवस्तु के अन्तर्गत सिकरी बाजार खखरा रोड (लम्बाई लगभग 03 कि0मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

2-जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र-303 के कपिलवस्तु के अन्तर्गत मधुबेनिया गाय घाट मार्ग (लम्बाई लगभग 06 कि0मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अपूर्व मोहन मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र-303 के कपिलवस्तु के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ी से खजूर डाड तक (लम्बाई लगभग 05 कि0मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डब्लू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

4-जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र-303 के कपिलवस्तु के अन्तर्गत उस्का राष्ट्रीय राजमार्ग से भढिया तक (लम्बाई लगभग 05 कि0मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्तू विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

5-जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र-303 के कपिलवस्तु के अन्तर्गत बांकी से बगलवा तक (लम्बाई लगभग 02 कि0मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में नानामऊ रोड भुड्डा चौराहे से भिखासीपुर तपसिया, गहरपुरवा होते हुए आगरा एक्सप्रेस-वे तक की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरमऊ में मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत जाजमऊ में एम0ए0बी0 का पावर स्टेशन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद में पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद में निरीक्षण भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र के तीनों विकास खण्ड में बाल विकास पुष्टाहार का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुणेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में पावर हाउस तिराहा बिल्लौर रोड के पास से किरन पेट्रोल पम्प तक आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत बांगरमऊ-सण्डीला मार्ग पर जर्जर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

9-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के फायर स्टेशन में दो दमकल गाड़ी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड लखावटी के ग्राम औरंगपुर, मीरपुर में मनोज के मकान से वीरू के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जयमंगल, सदस्य विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री जयमंगल, सदस्य विधान सभा की जनपद महाराजगंज के नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत बासपार बैजौली मार्ग से पड़री के बीच बलियानाला पर अर्धनिर्मित लघु सेतु को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री संजीव शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 5 याचिकाएं[†]

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बसंतपुरधूसी नगर से सिरसिया गौठा (नहर के किनारे) चौराहे तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत रामपुर कारखाना नगर कम्पोजिट विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बरियारपुर चौराहे पर जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम निवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयी।

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत सिरसिया गौठा व सकुतई सम्पर्क मार्ग के मध्य में छूटी हुई कड़ी को पिच सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृपाल प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

5-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत खुखन्दू-नुनखार-भटनी मार्ग तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनन राय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएं†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद कानपुर के वार्ड-53 सरांयमीता इण्डस्ट्रीज एरिया के अन्तर्गत आने वाले तालाबों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पनकी पावर प्रोजेक्ट के कारण आने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के वार्ड-8 मसवानपुर स्थित सदियों पुराने नकटी तालाब पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत पाल ढाबा नौरीरूयाखेड़ा से लेकर रविदासपुरम् छठ पूजा घाट तक तथा नहर नया पुल से इण्डस्ट्रियल स्टेट रोड तक का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आरती गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

6-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के रतन लाल नगर में निजी स्कूल चिंटेल्स हाई द्वारा कब्जा किये गये पार्क की लीज की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर में तहसील चांदपुर के ग्राम रतनगढ़ से मिलक होते हुए हिमपुर बुजुर्ग से होते हुए चांदपुर-नूरपुर मार्ग तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ †

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम अमदापुर के अन्तर्गत अरिल नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम सथरा धर्मपुर से ग्राम मकरन्दपुर रोड पर सोत नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आजाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम कबरा सलेमपुर पश्चिमी में सम्पर्क मार्ग पर अरिल नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम याकूतपुर से ढाईघाट मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हवलदार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम चितरऊ-कुशवाह मढ़ैया सम्पर्क मार्ग पर बद्री प्रसाद के खेत के पास पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अख्तर कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक जलालाबाद के ग्राम शेरपुर चुरघुटी से खण्डहर घाट जाने वाले मार्ग पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

7-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक जलालाबाद के ग्राम खण्डहर से जलालाबाद मार्ग पर पुराना घाट बहगुल नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर में रामसरन इण्टर कालेज से नाले के पुल तक सी0सी0 व नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

9-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम याकूबपुर चौराहा रामजानकी मन्दिर से नगरिया अस्पताल के सामने तालाब तक आर0सी0सी0 व नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

10-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान के ग्राम रहीमादासपुर के अन्तर्गत सोत नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बीवीपुर में दलित बस्ती से यादव बस्ती होते हुए ज्ञानपुर पम्प नहर तक के सम्पर्क मार्ग का इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत चवरवा चौहान बस्ती से बन्दीपट्टी बिन्द बस्ती तक के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 कुन्ज बिहारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत भुषलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती हुबलाल बिन्द के आवास तक के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीलाल बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत उमरी मनोहरपुर श्यामधर बिन्द के आवास से नेशनल हाई-वे बगहा तक के सम्पर्क मार्ग का

[†] छापी नहीं गयी।

चौड़ीकरण व नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत हण्डिया में जल समस्या के स्थाई निदान हेतु नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकान्त भारतिया व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में स्थित हनुमान चौकी को पर्यटन स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

2-जनपद हाथरस की तहसील हाथरस में दाउजी महाराज का प्राचीन मंदिर में लगने वाले मेले को राज्य मेला घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव आर्य व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्रीमती पूजा पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूजा पाल, सदस्य विधान की जनपद कौशाम्बी के ब्लाक नेवादा की ग्राम सभा उसमानपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 20 याचिकाएं†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र वरीपाल में रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू शिवहरे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में गौवंश संरक्षण हेतु तीन 1000 क्षमता की गौशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री अंकिता त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद कानपुर नगर में घाटमपुर चौराहे पर जहानाबाद से मूसानगर मुगल रोड क्रासिंग में फ्लाई-ओवर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर में पतारा चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

5-जनपद कानपुर नगर के बिहूपुर से फत्तेपुर शून्य से लेपन मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

6-जनपद कानपुर नगर में जर्जर खम्भे, जीर्ण-शीर्ण बिजली के तार पुनः लगवाने एवं नये मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

7-जनपद कानपुर नगर में 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने एवं सी0एच0सी0 घाटमपुर में हड्डी एवं न्यूरो एम0डी0 डॉक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

8-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर के गांव परास में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल की बाउण्ड्री, गेट व मरीजों के बैठने के लिए हाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू पंडित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

9-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर के प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराकर पर्यटन के योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

10-जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनी पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

11-जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में मिलकिनपुर से मुरलीपुर तक डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेन्सू सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

12-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर में मिलकिनपुर गांव से मुरलीपुर गांव तक के रजबहे बम्बे में पांच पुलियों का चौड़ीकरण एवं सज्जन तिवारी के खेत के सामने पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

13-जनपद कानपुर नगर के ग्राम रार में मेन रोड से सज्जन तिवारी के ट्यूबवेल होते हुए सीहूपुर सरहद तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

14-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर के संडौली से सीहूपुर सरहद होते हुए रार तक डामरीकरण रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाला राम कुरील व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

15-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर के विहूपुर लिंक मार्ग पी0डब्लू0डी0 से इटर्रा गांव तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तन्मय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

16-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर थाने को दूसरी जगह पर बनाये जाने हेतु बजट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

17-जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर में सिंचाई हेतु पन्द्रह नलकूप स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

18-जनपद कानपुर नगर के नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में सीवर लाइन एवं जल-मल निकासी हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

19-जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर में 200 नये हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में श्री शशि कुमार अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

20-जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर के कोरो गांव की नहर पुल को चौड़ा कराकर ऊंचाई से बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

सदस्यों द्वारा याचिका के प्रति सक्रियता पर माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मद संख्या-15 से मद संख्या-78 तक लगभग 60 माननीय सदस्यों की तीन सौ से ज्यादा याचिकाएं आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। (सभी सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यह हमारे सदस्यों की अपने क्षेत्र के प्रति सक्रियता को दर्शाता है। डॉ0 अमित उपस्थित हो गये हैं इसलिए इनकी याचिका उपस्थित मानी जायेगी। जो सदन में आ गया है उसकी उपस्थिति मान लेंगे। माननीय सदस्यों की जो अच्छी बात हो,

उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं, इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के विकास के प्रति रुचि जो इस विधान सभा के सभी मा0 सदस्यों में दिखाई पड़ रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, कम है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत सजगता के साथ अपने इन कार्यों को लिया है।

(उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

[06:33] सदन चलते समय जिले में किसी तरह की बैठक न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, नियम है कि जब भी सदन चलता है, उस समय जिला पंचायत आदि की बैठकें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे एटा जिले में ऐसा हुआ है। आपने मुझे 20 और 21 तारीख में प्रबोधन कार्यक्रम के लिए बुलाया था और यहाँ से पत्राचार भी हुआ था, उसके बावजूद हमारे वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने बैठक की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जो बात आयी है, कई माननीय सदस्यों की तरफ से आयी है। जिस समय सदन यहाँ पर बुलाया गया है या माननीय सदस्यों को उपस्थित होने की यहाँ से सूचना गयी है, उन दिनों में यह बैठकें नहीं हो सकती हैं, इस प्रकार का पहले भी शासनादेश है। यदि इस प्रकार की बैठक हुई है और अगर माननीय सदस्य ने सूचना दी है और यहाँ से सूचना गई है, उसके बाद भी अगर जिलाधिकारी के द्वारा बैठक की गयी है तो बहुत गम्भीर बात है। इस बात का संज्ञान आप लें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ठीक है, मान्यवर। इसमें जरूर संज्ञान भी लेंगे और उसमें कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मद संख्या-80 में कुछ नहीं है। मद संख्या-81 में भी कुछ नहीं है। अब मद संख्या-82।

[06:46] उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उमाशंकर जी, कुछ कहेंगे ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के मा0 सदस्यों के नाम बाद में दे दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी संशोधन लाये हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भूमि आवंटित की गयी है, 05 साल तक अगर उसमें वह व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए उसने वह जमीन ली है, यदि उस उद्देश्य के लिए वह उपयोग नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः समाप्त कर दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने फिर इसमें एक अन्तिम व्यवस्था दी है कि कोई इस तरह की बात आयेगी तो एक साल के लिए उसे और अवसर दिया जायेगा। मेरा केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील है, आप देख लीजिये, इसके पहले भी यह विधेयक आया था और अक्सर यह देखने में आता है और आप ही की सरकार में 2017 से 2022 के बीच में कई विधेयक लेकर आये हैं, उसमें बीच में फिर से संशोधन करना पड़ा। कारण क्या है, जब हमारा हाउस आहूत होता है, तब आनन-फानन में हम विभाग से बैठक कराते हैं, कैबिनेट की बैठक कराते हैं, फिर यहाँ लाकर अध्यादेश का रूप दे देते हैं। मेरा केवल आग्रह यह है कि जो प्रवर समिति बनती है, उस प्रवर समिति में भी आपका ही बहुमत रहेगा। लेकिन प्रवर समिति बनाने का उद्देश्य ही यही है कि अगर कोई भी अध्यादेश आये, कोई भी इस प्रकार का विचार आये तो उस प्रवर समिति में पूरी तरह से अगर उसमें कोई कमियां हों, संशोधन हों, तो हम उसको दूर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप जैसा चाहेंगे, आपका बहुमत है, वैसा ही होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें जल्दबाजी न करके इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके आधार पर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करना सिवाय डिलेइंग करने के कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उसमें यह देखिए कि किसी भी इण्डस्ट्रीज को जिस समय जमीन दी जाती है तो उसको इण्डस्ट्रियल उपयोग के लिए दी जाती है। कालान्तर में यह देखा गया है कि जिन्होंने इण्डस्ट्रियल लैण्ड ली थी इसको लेने के बाद उसको रियल स्टेट के लिए इस्तेमाल करते थे। पांच साल, दस साल, 15 साल, 20 साल इण्डस्ट्रीज नहीं लगाते थे। जिनको इण्डस्ट्रीज लगानी थी, उनको जमीन नहीं मिलती थी और लोग जमीन लेकर बैठे हुए थे इसीलिए उसके ऊपर

बंदिश लगाने की जरूरत थी कि इतने समय के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगा दें। पांच साल इण्डस्ट्रीज लगने का तो टाईम ही होता है एक दिन में थोड़ी लगती है।

श्री लाल जी वर्मा-

इसमें जो पिछली बार था वह पांच साल का था उसको बढ़ाकर आठ साल किया और अन्तिम समय 31-12-2022 तक का किया है तो सुनिश्चित रूप से जो आप कहना चाहते थे आपका जो मकसद है आपने जो कहा कि अगर वह अपना काम नहीं शुरू करता तो जमीन लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर पांच साल में वह एक ईंट भी वहाँ नहीं रख पाया है तो आठ साल बढ़ाये जाने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इण्डस्ट्रीज जरूर लगे। आप लोग भी चाहते हैं कि औद्योगीकरण हो और हम भी चाहते हैं कि निवेश हो तो अगर कहीं कोई परिस्थिति आती है तो इसलिए बढ़ाया जाय।

मान्यवर, अनुरोध है इसमें प्रश्न उपस्थित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने क लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 जनवरी 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा-7 का संशोधन-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्

परन्तु यह कि,

(क) जहाँ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाईयों (आई0टी0/आई0टी0इ0एस0) की स्थापना हेतु दिनांक 28-07-2020 के पूर्व पट्टे पर आवंटित की गई हो, तथा

(ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता/न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28-07-2020 तक न किया गया हो, तथा

(ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि, अथवा आवंटन की निबन्धन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 28-07-2020 तक व्यतीत हो चुकी हो, तथा

(घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को दिनांक 31-12-2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 31-12-2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह आवंटित की गई हो, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा आवंटी को ऐसा करने से विफल होने सम्बन्धी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत करा दिया गया हो, तथा

(ङ) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 31-12-2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय,

तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 31-12-2022 को स्वतः रद्द हुआ माना जायेगा तथ उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जायेगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से युक्त परन्तुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।

स्पष्टीकरण-1 पूर्वोक्त संशोधन से कोई आवंटी/इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबन्धनों और शर्तों तथा सम्बन्धित प्राधिकण की नीति से शासित होंगी जिसमें समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण-2 आवंटन तथा पट्टा विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[6:55] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

अपने महाराजा सुहेलदेव जी हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे केवल इस प्रदेश के ही पुरोधा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के पुरोधा हैं। आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)

विधेयक/अध्यादेश, 2022 के माध्यम से आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के स्थान पर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ नामकरण करने का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें विधेयक को प्रवर समिति को दिये जाने का कोई प्रस्ताव तो है नहीं।

(कतिपय सदस्यों द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित किये जाने की बात की गई)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने क लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 जनवरी 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 की धारा-4 का संशोधन-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-4 में, उपधारा-(1-क) के खण्ड (ञ) में, शब्द "आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन-

3- मूल अधिनियम की अनुसूची में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या-2 में क्रम संख्या-16 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टि में शब्द "आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" के स्थान पर शब्द "महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[06:57] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रख्यापित यू0जी0सी0 सम्वत् विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान विनियम, 2017 द्वारा किसी निजी विश्वविद्यालय को सम्वत् विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित करने के प्रावधान दिये गये हैं। उसी के अन्तर्गत यू0जी0सी0 सम्वत् विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान विनियम, 2017 की धारा-6.1(ग) के अन्तर्गत शिवनाडर यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर को सम्वत् विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से एक पत्र दिनांक 04-09-2019 को राज्य सरकार से इस आशय की वचनबद्धता दिये जाने के अनुरोध के साथ किया गया है कि इस शिवनाडर यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर को सम्वत् विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित किये जाने के पूर्व शिवनाडर विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर का निजी विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लिये जाने हेतु यथोचित विधायन राज्य विधान मण्डल में पुनर्स्थापित किया जाय।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, फिर मेरा आग्रह है कि हम द्वितीय संशोधन ले करके आये हैं और फिर इसी तरह से यह जल्दबाजी का ही विधेयक है। इसमें चूंकि मैं देख रहा हूँ कि मा0 मंत्री जी द्वारा जो लिस्ट इसमें अंकित की गयी है, अटैच की गयी है, उसमें 30 विश्वविद्यालयों का जिक्र है तो मेरा केवल आपके माध्यम से आग्रह है। जैसे अभी हम पूरा सदन एक साथ, एक स्वर से सर्वसम्मति से जो माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव था, उसे हम लोगों ने पास किया लेकिन जहाँ पर ऐसा हो, चूंकि हम एक द्वितीय संशोधन ला रहे हैं तो इसका मतलब कि हम पहला जो विधेयक लाये थे या पहला संशोधन, उसके बाद फिर एक संशोधन लाये, पहले विधेयक लाये फिर संशोधन, फिर अब द्वितीय संशोधन ला रहे हैं। इसमें मेरा कहना है कि हम इसमें जल्दबाजी न करें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। 30 विश्वविद्यालयों की आपने लिस्ट दी है, 30 विश्वविद्यालयों से रिलेटेड मामला है जिसमें आपकी जो और बात होगी, उसमें आप भी अपना पक्ष रखेंगे और आपके भी माननीय सदस्य उसमें अधिक संख्या में रहेंगे। आप भी अपना पक्ष रखेंगे, हम सभी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो निचोड़ आ जायेगा, फिर इस सदन में हम लोग सर्वसम्मति से उस विधेयक को पास करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने क लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 जनवरी 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन-

उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 15 पर, क्रम संख्या 15 की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी और उक्त अनुसूचियां तद्नुसार पुनः संख्याकित की जायेंगी :

परन्तु यह कि उक्त संशोधन यू0जी0सी0 (सम्वत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के अधीन पूर्वोक्त अनुसूचियों में क्रम संख्या 15 पर सम्वत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के रूप में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय की अधिसूचना के दिनांक में प्रवृत्त होगा।

निरसन और व्यावृत्ति-

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ?

[07:02] **नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

माननीय सदस्यों द्वारा मा0 अध्यक्ष जी से नियम-51 की समस्त सूचनाओं को ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, जो हमारी कार्य मंत्रणा है, उसके हिसाब से कल सदन की समाप्ति है तो आज जितने भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं, उन सभी की नियम-51 की सूचनाएँ लेकर बड़ा हृदय दिखाईये।

श्री अध्यक्ष-

आपको छोटा हृदय कितने दिनों से दिखायी पड़ रहा है ?

(सदन में हंसी)

लेकिन मैं इसमें एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, इससे पता चलता है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि याचिका में सब लोगों ने रुचि दिखायी है। अगर सुबह नोटिस देकर अपने घर चले जाते तो उनकी सूचनाएं तो स्वीकृत नहीं होनी चाहिए। जो लोग रिक्वेस्ट करके गये हैं, मैं उनकी सूचनाएं भी स्वीकृत कर लूंगा। आज दिनांक 30-05-2022 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमे से 69 सूचनाएं स्वीकार की गयीं, शेष सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

निम्नलिखित सूचनाएं शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं-

पहली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं श्री लालजी वर्मा की एन0एच0-227 पर अवैध चौड़ीकरण के एवज में ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर में हो रही अवैध खुदाई के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के ग्राम खलिया के ब्लाक अमानीगंज में 50 बेड के अस्पताल को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर में नजूल की जमीन पर गलत तरीके से हस्तांतरण के उपरान्त हो रहे नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर में भू-माफिया से तालाब को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कमलाकान्त

राजभर उर्फ पप्पू की जनपद आजमगढ़ में सामुदायिक केन्द्र के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन में लोक निर्माण के गेस्ट हाउस के निर्माण के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रयागराज में धोखाधड़ी और हत्या का मुकदमा दर्ज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में राशन कार्ड डीलर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री जै किशन साहू की जनपद मेरठ में पंजीकृत ठेकेदारों के शेष भुगतान व सहायक अभियन्ता पर कठोर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर में इण्टर कालेज की मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर में मार्गों का नवनिर्माण एवं मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली में नदी के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर में मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री कैलाश की जनपद चन्दौली में बनवासियों के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री रामकृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर में नैमिष विकास परिषद् के गठन एवं मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद बस्ती में डाक बंगले की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर में टौंस नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री जियाउर्रहमान की जनपद मुरादाबाद में परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर में जिला प्रशासन द्वारा घर गिराने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की प्रदेश में मा0 कांशीराम आवास योजना में बने हुए मकानों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री मौहम्मद फईम इरफान की उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दिनांक 26-09-2016 को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट को निरस्त किाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर में मार्ग के नवनिर्माण एवं तालाब की दीवार बनाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज मुकदमे में अभी तक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं

सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह की जनपद हाथरस में मकान पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर में मानक विहीन तरीके से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली में लीज पर दी गई जमीन को सरकार के पास हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है तैंतीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर में कोविड हास्पिटल के संचालन के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर में ग्राम झाझर को चकबन्दी प्रक्रिया से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दिनांक 26-09-2016 को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय पुस्तकालयों में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर से सम्बन्धित पुस्तकों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली में एन0टी0पी0सी0 परियोजना में चिमनी का निर्माण तालाब की भूमि पर कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर के पडरौना तहसील में स्थित बांस मेला को राज्य स्तर पौराणिक बांसी मेला स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के गन्दे पेयजल के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया में 100 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की सिंचाई विभाग में शासनादेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की जनपद महाराजगंज तहसील मुख्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र शिलापट्ट पार नाम बदलवाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर में बालिकाओं के लिए विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्रीमती ओममणि वर्मा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी में सरकारी चिकित्सालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर में कोल्ड स्टोरेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन नियमावली को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी में सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद रामगंगा नदी बंधा की मरम्मत के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट में अवैध खनन के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की सिंचाई विभाग के अतिथि आवास के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रुदौली में आईटीआई के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री रवि शर्मा की नगर निगम झांसी सिक्योरिटी गार्डो की भर्ती के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की एन0एच0 पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय डिग्री कालेज स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद में प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना डॉ0 सुरभि की सहकारी चीनी मिल की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के छावनी में बालिका स्कूल में शिक्षक तैनात के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के क्षेत्र नौगांवा सादात के ग्राम रतनपुर तक कच्चे मार्ग को पक्के किये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री रामखिलाड़ी सिंह की उ0प्र0 सरकार की योजना के अन्तर्गत टैबलेट एवं स्मार्ट फोन को देने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की मुरादाबाद मण्डल में अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सोजा के साथ तुर्क भी अंकित कराने के सम्बन्ध में है तथा उन्हत्तरवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के घाट रोड स्थित गोमती नदी पर 02 लेन सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं-

श्री दिनेश रावत, श्री विनोद कुमार, श्री कैलाश नाथ, श्री सचिन यादव, श्री जगदीश नारायण, श्री भूपेश चौबे, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री किरत सिंह, श्री जय प्रकाश निषाद, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री अखिलेश, श्रीमती सरिता भदौरिया, श्री पंकज गुप्ता, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री अभय सिंह, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री रफीक अंसारी, श्री संग्राम सिंह, श्रीमती इन्द्राणी देवी एवं श्री बम्बा लाल।

जनपद अयोध्या के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद अयोध्या के....

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती गुलाब देवी-

[पत्रांकः आर0एम0एस0ए0/54/2022-23 दिनांक 29-05-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार राजकीय हाई-स्कूल बहरास, विकास खण्ड रुदौली, वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुआ था जिसकी निर्माण की लागत रुपये 51.98 लाख थी। निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्यदायी संस्था पैकफेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। निर्माण इकाई को प्रथम किश्त की धनराशि रुपये 26.14 लाख राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 04-11-2011 को निर्गत की गयी थी तथा संस्था द्वारा इस विद्यालय का निर्माण दिनांक 02-05-2012 से प्रारम्भ कर दिया गया था। कालान्तर में द्वितीय किश्त की धनराशि रुपये 12.67 लाख दिनांक 03-06-2013 को तथा तृतीय किश्त की धनराशि रुपये 13.17 लाख दिनांक 28-07-2014 को जिला परियोजना कार्यालय, जनपद अयोध्या द्वारा निर्माण इकाई को निर्गत की गयी थी। इस प्रकार अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्माण कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी।

3-राजकीय हाई-स्कूल बहरास की सम्पूर्ण किश्तें निर्गत होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण नहीं कराया गया, इस सन्दर्भ में जिला परियोजना कार्यालय, जनपद अयोध्या के पत्र दिनांक 13-03-2014, दिनांक 02-04-2014, दिनांक 24-12-2014, दिनांक 15-04-2015 के माध्यम से राजकीय हाई-स्कूल बहरास विकास खण्ड रुदौली के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु निर्माण इकाई को निर्देशित किया जाता रहा, किन्तु निर्माण कार्य अद्यतन पूर्ण नहीं कराया गया तथा अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा विद्यालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु रुपये 10.76 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक/जिलाधिकारी के माध्यम से निर्माण लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत रुपये 5.198 लाख निर्धारित करते हुए दिनांक 13-01-2016 को राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रेषित किया गया, जिसके सन्दर्भ में राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान के पत्र दिनांक 22-01-2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत निर्माण की इकाई लागत के अतिरिक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं है। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था जनपद स्तर पर उपलब्ध क्रिटिकल गैप मदों से कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर समिति गठित कर कराये गये निर्माण की जांच करायी गयी, जिसमें प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल गैप मद में धनराशि दिये जाने हेतु पत्रावली जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी। तत्समय क्रिटिकल गैप मद में धनराशि न होने के कारण कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को दिनांक 02-08-2017 व दिनांक 08-12-2017 को नोटिस निर्गत की गयीं, किन्तु निर्माण कार्य अद्यतन पूर्ण नहीं कराया गया तथा अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए क्रिटिकल गैप मद से धनराशि धनराशि की मांग की जा रही है। कार्यदायी संस्था ने अपने कार्यालय के पत्रांक 400/यू0पी0आर0एन0एस0एस0/अधि0अभि0/2021-22 दिनांक 02-08-2021 द्वारा राजकीय हाई-स्कूल बहरास, रुदौली, अयोध्या को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनः पुनरीक्षित आगणन रुपये 69.44 लाख का वर्क डन-वर्क टू बी डन के आधार पर प्रेषित किया गया था।

5-उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था को जिला परियोजना कार्यालय, अयोध्या के पत्रांक आर0एम0एस0ए0/110-113/2021-22 दिनांक 17-08-2021 द्वारा पुनः संसूचित किया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें निर्माण इकाई लागत के अतिरिक्त विद्यालय भवन के लिए किसी प्रकार की कोई धनराशि का प्रावधान नहीं है।

6-जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद अयोध्या द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में ही पैकफेड संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 में स्वीकृत राजकीय हाई-स्कूल पूरेनन्दा तिवारी का निर्माण उसी लागत में पूर्ण कराते हुए हस्तगत कराया जो लागत राजकीय हाई-स्कूल बहरास की थी। इससे स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा राजकीय हाई-स्कूल बहरास के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने तथा समयान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराने के पश्चात् भी विद्यालय के निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए जनोपयोगी न बनाये जाने के सम्बन्ध में शासकीय धन के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए कार्यदायी संस्था के विरुद्ध संगत धाराओं में थाना रुदौली,

जनपद अयोध्या में मु0अ0संख्या-216/22 पंजीकृत कराया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक-अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या अनुसार निर्माणाधीन राजकीय हाई-स्कूल बहरास में फर्श का कार्य आंशिक रूप से, पानी की सप्लाई, सेनेट्री का कार्य, खिड़की-दरवाजों का कार्य एवं रंगाई-पुताई का कार्य शेष है। विद्यालय भवन को पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी, जनपद अयोध्या की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत उक्त विद्यालय हेतु प्रस्ताव किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7-उल्लेखनीय है कि उस क्षेत्र के कक्षा-9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें खुले आसमान के नीचे शिक्षा अर्जित नहीं करते हैं। कक्षा-9 एवं 10 की कक्षायें जूनियर हाई-स्कूल बहरास के अतिरिक्त कक्षा-कक्षों में संचालित हैं।

प्रदेश में डी0एल0एड0 कालेज से सम्बद्धता पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी अनुपस्थित हैं।

जनपद बागपत के ग्राम बाछौड़ में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वादी श्री कान्ति पुत्र श्री श्याम सिंह.....

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[निवासी ग्राम बाछौड़, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा दिनांक 03-05-2022 को थाना छपरौली पर सूचना अंकित करायी कि उसकी पुत्री जिसका नाम कोमल (उम्र 18 वर्ष) है, गांव के ही लड़के प्रिंस पुत्र महक सिंह के साथ दिनांक 03-05-2022 को प्रातः लगभग

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

03:00 बजे घर से चली गयी। प्रिंस को फोन करने पर उसका फोन बन्द है। उसके परिवारीजन द्वारा भी कोई ठीक जवाब नहीं दिया गया। इस सूचना पर मु0अ0सं0-120/2022 अन्तर्गत धारा-366 भा0द0वि0 दिनांक 03-05-2022 को पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचक को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त प्रिंस व अपहृता कोमल, अभियुक्त के घर पर मौजूद हैं। सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह मय हमराह म0कां0 520 पूनम के जी0डी0 रपट नं0-43, समय 18:35 बजे थाना से रवाना हुए। उ0नि0 द्वारा अपने साथ ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामवासियों को साथ लेकर अभियुक्त के घर पर पहुंच कर सभी की मौजूदगी में अपहृता कोमल उपरोक्त की तलाश की गयी। उसी समय अभियुक्त की मां श्रीमती अनुराधा पत्नी महक सिंह उम्र 45 वर्ष व अभियुक्त की बहन स्वाति उम्र 18 वर्ष एवं बहन प्रीति उम्र 17 वर्ष ने एक कमरे में जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इस तथ्य की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों की मदद से उक्त तीनों को सी0एच0सी0 छपरौली में भर्ती कराया गया। सी0एच0सी0 छपरौली से रेफर किये जाने पर मेडिसिटी हास्पिटल बड़ौत में भर्ती कराया गया तथा वहाँ से रेफर किये जाने पर सुभारती हास्पिटल मेरठ में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दिनांक 24/25-05-2022 की रात्रि में स्वाति उम्र 18 वर्ष की मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात् परिजनों द्वारा स्वाति का दाह संस्कार किया गया। मृतका के पिता महक सिंह की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-151/22 धारा-323, 504, 506, 509, 306 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त 1-लोकेन्द्र पुत्र कलाशू, 2-राजीव पुत्र सहेन्द्र, 3-छंगा पुत्र हरदेव, 4-शक्ति पुत्र कान्ति, 5-राजू पुत्र कान्ति समस्त निवासीगण ग्राम बाछौड़, थाना छपरौली (समस्त 05 अभियुक्त अपहृता कोमल के परिजन व सम्बन्धी) एवं 06-उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना छपरौली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उप निरीक्षक नरेश पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। सुभारती हास्पिटल मेरठ में दौराने उपचार श्रीमती अनुराधा पत्नी महक सिंह उम्र 45 वर्ष व कु0 प्रीति उम्र 17 वर्ष की भी दिनांक 25/26-05-2022 की देर रात्रि में मृत्यु हो गयी है। दिनांक 26-05-2022 को परिजनों द्वारा दोनों का दाह संस्कार कर दिया गया है। जिलाधिकारी, बागपत व पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा गांव में पहुंचकर मृतकाओं के परिजनों को सांत्वना दी गयी है। **अभियोग की निष्पक्ष विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी क्राइम के नेतृत्व में एस0आई0टी0 का गठन किया गया है।** आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु गांव बाछौड़ में पुलिस प्रबन्ध किये गये हैं तथा पूरे प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

श्री अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा जो 27-05-2022 को नियम-51 के तहत सूचना दी गयी थी और आज वह निर्धारित हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी का लिखित वक्तव्य आया है, मैंने उसमें सहायता की भी बात की थी और पूरा प्रकरण इतना गम्भीर है कि इस पर चर्चा

जरूर होनी चाहिए। मेरी विधान सभा क्षेत्र, गांव बाछौड़ में 23 तारीख को 3 महिलाओं ने पुलिस प्रताड़ना से तंग होकर जहर खा लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपको जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें आप अगर पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी गम्भीरता को समझें।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूछ लीजिये, अगर मैं गम्भीर न होता तो मैं पूछने के लिए क्यों कहता ?

श्री अजय कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में अधिक से अधिक सहायता पीड़ित परिवार को दी जाये, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन इसमें कम से कम 80 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है, जोकि 17 और 18 साल की थीं। साथ में उनकी मां जोकि 45 साल की थी, उनकी भी मृत्यु हुई है। इसमें तीन सदस्य हैं, इसलिए कम से कम 80 लाख रुपये की सहायता मुख्य मंत्री आर्थिक सहायता कोष से दी जानी चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, जो घटना हुई है, वह बहुत दुःखद है। इसमें एक दबिश के मामले में यह स्थिति पैदा हुई और इसमें जो लोग अस्पताल में भर्ती कराये गये थे, उन लोगों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इसमें लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और अभियोग की निष्पक्ष विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी क्राइम के नेतृत्व में एस0आई0टी0 का गठन भी किया गया है। एस0आई0टी0 की विवेचना के बाद जैसा निष्कर्ष आयेगा, हम आपके माध्यम से सदन को अवगत भी करा देंगे। जो सहायता की बात कही गई है, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके ही कोई निर्णय करना पड़ेगा। मान्यवर, इस समय मुझे यही कहना है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में गल्ला मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

उद्यान, कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा.....

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

दिनेश प्रताप सिंह-

[अवगत कराया गया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मुंगराबादशाहपुर के क्षेत्रान्तर्गत मछलीशहर उपमण्डी स्थल घोषित है। उप मण्डी स्थल मछलीशहर के निर्माण हेतु पूर्व में भूमि चयन हेतु किये गये प्रयास के सम्बन्ध में उप निदेशक (प्रशा0/वि0) मण्डी परिषद् वाराणसी, उप निदेशक (निर्माण) एवं सचिव, मण्डी समिति मुंगराबादशाहपुर द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित-पत्र दिनांक 27-07-2018 के माध्यम से यह सूचना दी गयी है कि तहसील मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम-पुराफगुई में प्रस्तावित भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित न होकर मछलीशहर से लगभग 1.50 कि0मी0 आगे पूरब की तरफ स्थित नहर पटरी पर लगभग 1.50 कि0मी0 आगे चलकर उत्तर की ओर बस्ती की तरफ लगभग गांव के बीच में स्थित है, जिस पर तीन मीटर चौड़े रास्ते से होकर जाना पड़ता है। प्रस्तावित भूमि पर तीन मीटर चौड़ी नहर की पटरी से भी गुजरना पड़ता है तथा नहर चालू हालत में है। प्रस्तावित भूमि के मार्ग की चौड़ाई मात्र तीन मीटर है जिस पर सटे हुए कई मकान भी बने हुए हैं। भूमि के ऊपर हाईटेंशन लाइन जा रही है एवं भूमि की सतह नीची होने के कारण प्राकृतिक रूप से वर्षा में जल का ठहराव भी होता है। उपर्युक्त कारणों से प्रस्तावित भूमि उप मण्डी स्थल के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई। जिला प्रशासन से सहयोग लेकर अन्यत्र उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मण्डी परिषद् मुख्यालय के पत्र दिनांक 28-01-2020 एवं पत्र दिनांक 23-05-2020 द्वारा उप निदेशक (प्रशा0/विप0)/(निर्माण) मण्डी परिषद्, वाराणसी को भूमि चयन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, परन्तु उपयुक्त भूमि चिन्हित नहीं हो पायी। परिषद् के पत्र दिनांक 02-07-2020 द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर से भी मण्डी स्थल के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उप मण्डी स्थल मछलीशहर से औसतन रुपये एक लाख वार्षिक मण्डी शुल्क प्राप्त होता आ रहा है। अतः उस क्षेत्र विशेष में हो रहे थोक व्यापार के परिणाम और भविष्य में व्यापार वृद्धि की सम्भावनाओं के दृष्टिगत उपयुक्त एवं निर्विवादित भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहीत कराने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव उपरोक्तानुसार मछलीशहर में उप मण्डी स्थल के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है। भूमि उपलब्ध होते ही उप मण्डी स्थल मछलीशहर के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।]

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र-मछलीशहर में गल्ला मण्डी के निर्माण के सन्दर्भ में सूचना दी थी। इसमें 6 साल पहले गल्ला मण्डी बनाने के लिए जमीन का आवंटन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह मण्डी नहीं बन पाई। वहाँ पर वाटर लॉगिंग का इश्यू था और जो जमीन भी आवंटित हुई थी, वह कम थी। लेकिन अभी तक 6 सालों में कोई भी जमीन स्वीकृत नहीं की गयी है, ताकि वहाँ पर गल्ला मण्डी बनाई जा सके। वह एक ग्रामीण अंचल है और वहाँ पर कृषि ही मुख्य रोजगार है और संसाधन है। अगर हम सरकारी नलकूपों की बात करें तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लोग अपना खुद का ट्यूबवेल लगाकर वहाँ पर कृषि करते हैं। फिर अपनी वस्तुओं को लेकर जौनपुर जाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ पर गल्ला मण्डी के लिए जो जमीन है उसको शीघ्र ही आवंटित किया जाये, ताकि हम उसको आगे ले जा सकें और एक समय निर्धारित किया जाय।

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

माननीय सदस्या खुद ही कह रही हैं कि वह भूमि उपयुक्त नहीं है, जहाँ पहले से मण्डी प्रस्तावित थी। हमने फिर से सम्बन्धित जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और फिर से अपेक्षा की है कि कहीं इसके आस-पास जहाँ भूमि उपयुक्त हो वहाँ मण्डी स्थल विकसित कर सकते हैं, तो हमारा प्रयास होगा हम खुद भी इसको देखेंगे और अपने विभाग से आख्या मंगायेंगे। उपयुक्त स्थल जितनी जल्दी मिल जायेगा, यथाशीघ्र हम मण्डी की स्थापना करने का प्रयास करेंगे।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक समय निर्धारित कर दिया जाय, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें यथाशीघ्र करा दें।

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद कह चुका हूँ कि इस पर यथाशीघ्र प्रयास करूंगा और मैं अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में जब भी जौनपुर जाऊंगा मैं स्वयं देखूंगा और

आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आयें वहाँ पर जितनी जल्दी कार्यवाही कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे।

जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री योजना के तहत कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय सदस्य द्वारा मैं आपके माध्यम से जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 अध्यक्ष के उक्त निर्देशों के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या-नियम-13/38-9-22-11 (नियम)/2022, दिनांक 28-05-2022 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-730/ए-35/यू0पी0आर0डी0ए0/2022, दिनांक 29-05-2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर स्थिति निम्नवत् है:-

जनपद अमेठी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (पी0एम0जी0एस0वाई0) कादूनाला से थौरी मार्ग, लम्बाई 9.150 कि0मी0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

जनपद अमेठी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में पी0एम0जी0एस0वाई योजनान्तर्गत मुसाफिरखाना से इसौली पारा मार्ग, लम्बाई 5.65 कि0मी0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 15-10-2016 को पूर्ण हुआ था। मार्ग की अनुरक्षण अवधि दिनांक 16-10-2016 से दिनांक 15-10-2021 तक थी।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत दोनों मार्गों की जांच निर्माणावधि में नेशनल क्वालिटी मॉनीटर तथा स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा की गयी थी एवं निरीक्षण आख्या संतोषजनक प्राप्त हुई थी। अनुरक्षण अवधि में भी उक्त दोनों मार्गों की जांच स्टेट क्वालिटी मॉनीटर से करायी गयी, जिसमें मार्गों की स्थिति संतोषजनक पायी गयी।

माह नवम्बर, 2018 तक ठेकेदार द्वारा उक्त मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया गया, जिसमें मार्ग की दशा संतोषजनक थी। उसके उपरान्त उक्त मार्ग पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु निर्माण सामग्रियों की ढुलाई भारी वाहनों से होने लगी, जिसकी वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। यूपीडा द्वारा निर्माण सामग्री ढुलाई बहुतायत में करने की शिकायत स्थानीय निवासियों एवं मार्ग के ठेकेदार द्वारा की गयी, जिसके प्रतिउत्तर में पी0एम0जी0एस0वाई लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ से उक्त मार्गों के मरम्मत का कार्य स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की निर्माण एजेंसी मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लिमिटेड से कराने हेतु अनेक बार अनुरोध किया गया एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा भी उक्त मार्ग के मरम्मत कार्य कराने हेतु पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेंसी मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लिमिटेड को निर्देशित किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त एजेंसी द्वारा मार्ग मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है।

उ0प्र0 विधान सभा की मा0 प्राक्कलन समिति (2019-2020) के प्रथम अध्ययन दल द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग पैकेज संख्या-यूपी68146 कादूनाला से थौरी लम्बाई 9.15 कि0मी0 के निर्माण सामग्री के सैम्पल को सील करके आई0आई0टी0 रुड़की जांच हेतु भेजने के निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण सामग्री के सैम्पल को सीलबन्द करके आई0आई0टी0 रुड़की जांच हेतु भेजा गया था, जिसका परीक्षण परिणाम दिनांक 15-11-2021 को प्राप्त हुआ है। उक्त मार्ग के सैम्पल परीक्षण परिणाम में मार्ग के निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप पायी गयी।

उक्त दोनों मार्ग अति क्षतिग्रस्त होने तथा उन पर होने वाली व्यय धनराशि अधिक होने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पीरियाडिक रिन्यूवल में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है तथा 10 वर्ष पूर्ण न होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई-III योजना के अन्तर्गत भी उक्त मार्ग को सुदृढ़ीकरण में नहीं लिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में मा0 विधायक, गौरीगंज, जनपद अमेठी द्वारा पी0आई0एल0 दाखिल किया गया है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2-उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत उक्त दोनों मार्गों की मरम्मत यूपीडा, लखनऊ द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेंसी एपको इन्फ्राटेक प्रा0लिमिटेड के माध्यम से कराया जाना उचित होगा।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला दो सड़कों का है और दो सड़कों की मरम्मत के लिए दिसम्बर, 2018 में माननीय मुख्य मंत्री जी निर्देश देते हैं कि बार-बार विभाग ठेकेदारों को बचाने के लिए यह बहाना कर लेता है कि एक्सप्रेस-वे के ओवरलोड माल ढुलाई की वजह से सड़क टूट गई है, जबकि दिसम्बर में एक्सप्रेस-वे का काम शुरू होता है उसके पहले माननीय मुख्य मंत्री जी निर्देश दे चुके होते हैं, जब यह अमेठी में गये थे तो लोगों ने शिकायत की कि यह दोनों सड़कें बहुत खराब हैं, इसकी मरम्मत करा दिया जाये। बहुत दिन तक मरम्मत नहीं होती है और मैं इसको लगातार सदन में उठाता हूँ। समिति में उठाता हूँ और सदन में इस पर दो बार आश्वासन आता है। आप देख लीजिये पिछले सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब है कि तीन महीने से भी न्यूनतम समय में दोनों सड़कों की मरम्मत करा दिया जायेगा और दोनों सड़कों पर एक गिट्टी तक भी नहीं डाली जाती है, मुझे इस्तीफा देना पड़ता है, मुझे अनशन करना पड़ता है, आमरण अनशन करना पड़ता है, पुलसि बल द्वारा सरकार जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा देती है। फिर मेरा अनशन टूटता है और जब मैं सड़क अपने संसाधनों से बनाने जाता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों के संसाधनों से उस पर रोलर लेकर जाता हूँ तो 2 बजे दिन में गिरफ्तारी मेरी करा दी जाती है और लेबरों को पीट के भगा दिया जाता है और अपराधिक मुकदमे मेरे ऊपर पंजीकृत करा दिये जाते हैं। आपके विभाग का लगातार यही जवाब आ रहा है कि इफको के द्वारा यह सड़कें तोड़ी गई हैं, एक्सप्रेस-वे की माल ढुलाई में। एक्सप्रेस-वे का काम बाद में शुरू हुआ है, यह सड़कें पहले खराब हो गई हैं तो इफको ने तोड़ा कैसे तोड़ा, फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर विभाग ने यह ठान लिया है कि नहीं हमको भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को बचाना ही है तो किसी भी व्यवस्था से आप इस सड़क को बनवा दीजिये नहीं तो मुझे अनुमति दीजिये मैं उस पर श्रमदान करके उन दोनों सड़कों को मैं बना लूं। मुझे बनाने भी नहीं देंगे आप और आप बनायेंगे भी नहीं। मैं इसमें हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में भी सरकार केवल गुमराह कर रही है आज जवाब दूंगा कल जवाब दूंगा जो स्थिति है मान्यवर कुछ बता नहीं सकते। इन दोनों सड़कों में तीन-तीन फिट गड्ढे हो गये हैं। जहाँ के पांच, पांच सौ लोग शहीद हो गये हैं वहाँ की यह सड़क है, भाले सुल्तान जो असमिदा है, वहाँ के राजपूत उनका पूरा क्षेत्र है।

वहाँ की यह सड़क है। वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक विभाग द्वारा एक भी गिट्टी वहाँ पर नहीं डाली गयी है और उन सड़कों का क्या हाल हो गया है आप स्वयं समझ सकते हैं, मैं केवल इतनी मांग करता हूँ आपसे एक तो केवल इफको ने 35 बार लिखकर दिया है कि मेरे द्वारा यह सड़क नहीं तोड़ी गयी है।

ग्राम्य विकास विभाग के पास पैसा नहीं है तो पी0डब्लू0डी0 हैण्डओवर ले करके इन दोनों सड़कों को बनवा दे।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जनहित का विषय उठाया है, लेकिन इसमें दो-तीन बातें मैं सदन में रखना चाहूँगा, पहले तो यह है कि माननीय सदस्य की पीआईएल के कारण यह मामला विचाराधीन है। जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बन रहा था उसमें एक एग्रीमेंट था कि कान्ट्रैक्टर जिस मार्ग से मैटीरियल ले करके जायेंगे, यदि वह मार्ग खराब होगा तो उसकी वह मरम्मत करायेंगे, इसलिए यूपीडा के माध्यम से नोटिस सम्बन्धित कान्ट्रैक्टर को दी गयी है। गुणवत्ता की जांच करायी गयी तो आईआईटी, रुड़की की रिपोर्ट है कि गुणवत्ता की वजह से नहीं बल्कि ओवरलोडिंग के कारण ही सड़क खराब हुई। मेरे पास उन ट्रकों के नम्बर वगैरह भी हैं, जिनसे माल ढोया जा रहा था, यदि आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ओवरलोडिंग के कारण सड़क खराब होने की शिकायत है, विभाग के द्वारा इसमें सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा सम्बन्धित कान्ट्रैक्टर के खिलाफ दर्ज भी कराया गया है। एसआईटी गठित करके जांच भी करायी जा रही है, उसके तथ्य आना बाकी है, इसलिए उसको मैं नहीं रख रहा हूँ। इस पूरे प्रकरण में इतना ही है कि मामला चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष है, एसआईटी की जांच हो रही है, कान्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और उन गाड़ियों को भी चिन्हित कर लिया गया है, मा0 सदस्य को उससे परेशानी होगी, इसलिए किसके नाम है, किसकी है, मैं नहीं बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी भी गाड़ी हो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा करके बन्द करा दीजिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने तो सदन का समय बचाने के लिए ट्रकों का डिटेल न बताने का अनुरोध किया था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि उप मुख्य मंत्री जी बताना चाहें तो बता सकते हैं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, गाड़ी का नम्बर मेरे पास है, उस गाड़ी की आयु समाप्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

कान्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कराइये।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कान्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, विभाग के नाम से दर्ज है, एसआईटी गठित है, लेकिन चूंकि जनहित का मामला है, हमारे माननीय सदस्य ने उसके लिए आमरण अनशन किया है, मुझे मालूम है, जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं वह भाले-सुल्तानियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मैं भी उस क्षेत्र में जाता था, मेरा भी उस क्षेत्र से गहरा सम्पर्क है, लेकिन मान्यवर, चूंकि इसे अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए जो कान्ट्रैक्टर से बनवाने की प्रक्रिया है उसकी जांच करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या पब्लिक ने अपना घर बनाने के लिए ट्रक चलवायी है। अगर ओवरलोडिंग हो करके ट्रक चल रही थी तो उस पर आरटीओ, पुलिस विभाग ने, खनन विभाग ने कार्यवाही क्यों नही की और यदि की तो कितनी गाड़ियों को सीज किया गया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मा0 मुख्य मंत्री जी 2018 में सड़कों को बनाने के लिए निर्देश देते हैं, सदन में 2019 में आश्वासन दिया जाता है फिर 2020 में तीन महीने का समय दिया जाता है। इसमें यह कहकर आप नहीं बच सकते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, आप सड़क बनवा दीजिये मैं पीआईएल तुरन्त वापस ले लूंगा। आप सड़क नहीं बनाना चाहते, दूसरों को बनाने भी नहीं देंगे तथा लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मोटर साइकिल, साइकिल से गिरने से और गाड़ियों के एक्सीडेंट से 18 लोग मर चुके हैं, आखिर चार साल में एक गिट्टी अभी तक क्यों नहीं पड़ी, क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उप मुख्य मंत्री जी, यह महत्वपूर्ण बात है इसे आपने भी स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको बुलाकर यथाशीघ्र उस सड़क को बनवाने का प्रयास करें।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा में दो सहायता अशासकीय महाविद्यालय.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

[एवं 85 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र-गौरा के ग्राम पंचायत-कूकनगर ग्रन्ट के 10 कि0मी0 की परिधि में 03 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतरिक्त डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के क्षेत्रान्तर्गत संघटक महाविद्यालय भवानीपुरकलां, गोण्डा संचालित है। उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र गौरा के ग्राम पंचायत-कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।]

जनपद कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीन व अन्य जांच उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 में श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

[विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 27-05-2022 को यह सूचना दी गयी है कि-

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कानपुर नगर के जिला अस्पताल उर्सला में मरीजों की जांच हेतु सी0टी0 स्कैन मशीन सालों से कंडम हालत में है, जिसके कारण गम्भीर बीमार रोगी बाहर से सी0टी0 स्कैन

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराने को मजबूर होते हैं। साथ ही अन्य सरकारी अस्पतालों में जांच मशीनों की स्थिति निम्न है-

1-के0पी0एम0 अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं है, जबकि डफरिन में डिजिटल एक्स-रे मशीन अतिरिक्त है, जो चलायी नहीं जाती।

2-डफरिन में अल्ट्रासाउण्ड मशीन है पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। 3 दिन अल्ट्रासाउण्ड नहीं होता है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने एवं उक्त अस्पतालों की जांच मशीनों को क्रियाशील कराये जाने के साथ ही उर्सला अस्पताल में नई सी0टी0 स्कैन मशीन लगाये जाने की मांग करता हूँ।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कानपुर नगर के जिला अस्पताल, उर्सला में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने के दृष्टिगत नवीन सी0टी0 स्कैन मशीन की स्थापना हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के पत्रांक संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/प्रोक्योर/ सी0टी0 स्कैन मशीन/2021-22/27/III/ 7101, दिनांक 04-02-2022 के द्वारा टेण्डर आदि बिड के उपरान्त मे0 कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड को पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत सी0टी0 स्कैन मशीन की आपूर्ति एवं संचालन के लिए चयन किया गया है। कम्पनी के द्वारा चिकित्सालय के स्थान का सर्वेक्षण कर सहमति प्रदान की जा चुकी है।

3-के0पी0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं है, अपितु मरीजों की सुविधा हेतु 500/300 एम0ए0एस0 की मैनुअली एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। ए0एच0एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर में कोई डिजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित नहीं है। यहाँ यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के माध्यम से पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन सैमसंग द्वारा डोनेट की गयी है। ए0एच0एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर में स्थापित अल्ट्रासाउण्ड मशीन को मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेण्टर के रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा सप्ताह मे 03 दिन अल्ट्रासाउण्ड की सेवायें दी जाती हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 07 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 30 मई, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

देखिये नत्थी 'क' के अतारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-53 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के 1-सोमवार हेतु निर्धारित श्री जगदीश नारायण, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर का संलग्नक।

क्र0	माह	कुल ओ0पी0डी0	भर्ती मरीजों की संख्या	अभ्युक्ति
1	01 मई, 2016 से 31 जनवरी, 2017	--	--	वर्ष 2020 एवं 2021 में ट्रामा सेन्टर एल-2 कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित रहा।
2	01 फरवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017	4552	--	
3	01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018	6576	15	
4	01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019	6106	22	
5	01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020	6292	110	
6	1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021	3223	161	
7	1 जनवरी, 2022 से अब तक	1500	25	

देखिये नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-59 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री हाजी इरफान सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 के उत्तर का संलग्नक।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कुपोषण में सुधार हेतु किये गये प्रयासों का विवरण-

- लाभार्थियों के पोषण स्तर के सही चिन्हांकन एवं नियमित वृद्धि निगरानी हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर 03 प्रकार की ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेस उपलब्ध कराई गई है।
- भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन ''पोषण ट्रैकर'' के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी की ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज के माध्यम से नियमित रूप से वजन एवं माप लेकर पोषण ट्रैकर पर अंकित करते हुए उनकी वृद्धि निगरानी की जा रही है।
- **सम्भव (पोषण संवर्धन की ओर एक कदम) अभियान**-गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों विशेषतः सैम/मैम व अल्पवजन बच्चों के चिन्हांकन, आवश्यकतानुसार उपचार हेतु संवर्धन एवं पोषण से सम्बन्धित मौजूद व्यवहारों, धारणाओं एवं मिथकों को दूर करने हेतु प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा 03 माह का एक सघन अभियान **''सम्भव-पोषण संवर्धन की ओर एक कदम''** 01 जुलाई से 02 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से समुदाय में पोषण व्यवहार को वृहद स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर में पोषण माह व माह मार्च में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न कन्वर्जेन्स विभागों के माध्यम से बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर के सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

  इस अभियान के पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेज उपलब्ध कराते हुए दिनांक 17 से 24 जून, 2021 के मध्य पूरे प्रदेश में वजन सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 01 से 05 वर्ष के सभी बच्चों की वजन व लम्बाई लेकर गम्भीर अल्पवजन एवं सैम (Servere Acute malnourished) व मैम (Moderate Acute malnourished) बच्चों का चिन्हांकन किया गया। अभियान के अन्त में भी वजन सप्ताह का आयोजन कराते हुए बच्चों की वजन व लम्बाई/ऊंचाई की माह कराई गई।

  अभियान में मासिक थीम (जुलाई-मातृ पोषण, अगस्त-बाल पोषण, सितम्बर-प्रथम एक हजार दिवस) के आधार पर दो प्रकार की सामुदायिक गतिविधियां सम्पादित की गईं-कुपोषित बच्चों के घर साप्ताहिक भ्रमण व पाक्षिक वृद्धि निगरानी एवं

पोषण परामर्श सत्रों का आयोजन। अभियान में गृह भ्रमण एवं पाक्षिक सत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अभिभावकों को खान-पान सम्बन्धी व वृद्धि निगरानी परामर्श प्रदान करते हुए स्थानीय खाद पदार्थों के सेवन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उक्त अभियान के आयोजन के फलस्वरूप गृह भ्रमण, कुपोषण की पहचान व सन्दर्भन में वृद्धि परिलक्षित हुई है। अभियान में चिन्हित गम्भीर अतिकुपोषित (सैम, मैम) बच्चों की स्वास्थ्य जांच चिकित्सा विभाग के समन्वय से कराते हुए गम्भीर जटिलता वाले बच्चों को प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भित करते हुए चिकित्सीय उपचार कराया गया। सम्भव अभियान माह सितम्बर में आयोजित पोषण माहके साथ किया गया।

- पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह समुदाय आधारित गतिविधियों यथा-अन्नप्राशन, गोद भराई, सुपोषण दिवस, किशोरी दिवस, वजन दिवस आदि का आयोजन किया जाता है।
- आगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय साग-सब्जियों व मौसमी फल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु पोषण वाटिकायें स्थापित कराई गईं।
- अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिकुपोषित बच्चों को उनकी विशेष पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त कैलोरी व प्रोटीन की पूर्ति हेतु प्रतिदिन अनुपूरक पुष्टाहार की मात्रा में बढ़ोत्तरी करते हुए अतिरिक्त पुष्टाहार दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

देखिये नत्थी 'ग' के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-74 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र 2022 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री नफीस अहमद, मा0 सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–55 का संलग्नक

जनपद आजमगढ़ में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों की सूची

S No.	Hospital Name
1	Anand Hospital Multispeciality
2	Azad Hospital
3	Eye Care Azamgarh Pvt Ltd
4	Global Multi Specialty & Trauma Center
5	Khetan Hospital
6	Lotus Multisuperspeciality Hospital Private Limited
7	M K Rai Deep Adarsh Hospital
8	Prakashnursinghome
9	Rainbow Children Hospital
10	Raj Lalit Netralaya And Hospital
11	Rama Multi Speciality Hospital & Trauma Centre
12	Sahaj Hospital
13	Saroj Multispeciality Hospital And Trauma Centre
14	Sharda Poly Clinic
15	Shiva Hospital And Trauma Centre
16	Vedanta Hospital
17	Vidya Hospital
18	Vijay Super Speciality Hospital
19	100 Beded Combined District Hospital
20	C H C Phoolpur
21	Chc Ahiraula
22	Chc Atraulia
23	Chc Bardah
24	Chc Bilariyaganj Azamgarh
25	Chc Harriya
26	Chc Jianpur
27	Chc Jigani Azamgarh
28	Chc Koilsa
29	Chc Kolhukhor
30	Chc Lalganj
31	Chc Mahrajganj
32	Chc Martinganj
33	Chc Mehnagar
34	Chc Mehnajpur
35	Chc Mirzapur
36	Chc Mubarakpur
37	Chc Palhani
38	Chc Parshurampur
39	Chc Pawai
40	Chc Tahbarpur
41	District Women Hospital Azamgarh
42	Divisional District Hospital Azamgarh
43	Govt. Medical College & Super Facility Hospital

देखिये नत्थी 'घ' के अतारांकित प्रश्न संख्या-71 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-81 पर

Ayodhya -100 bed District Combined Hospital Kumar Gani

Medicine Issued during June 2021 to May 2022

S. No.	Medicine Name	Qty Issued during the period
1	ACECLOFINAC : 100 mg (Tab)	100000
2	ACYCLOVIR : 400 mg (Tab)	1500
3	ALBENDAZOLE : 200 mg/5 ml (Suspension)	700
4	Albendazole Tablet 400mg (Fruit Flavored, Chewable Scored)	2500
5	Alcohol based Hand sanitizer	100
6	ALLOPURINOL : 100 mg (Tab)	3000
7	ALPRAZOLAM : 0.5 mg (Tab)	3200
8	AMIKACIN SULPHATE : - 100 mg/2ml : 2ml (Inj)	1900
9	AMIKACIN SULPHATE : IP - 500 mg/2ml : 2ml (Inj)	2000
10	AMINOPHYLLINE DIHYDRATE : IP - 25 mg/ml : 10ml (Inj)	20
11	AMIODARONE HYDROCHLORIDE :- 50 mg./ml. : 3ml (Inj)	100
12	AMLODIPINE BESYLATE : 5 mg (Tab)	22000
13	AMOXYCILLIN AND POTASSIUM CLAVULANATE ORAL SUSPENSION : 200 mg+ 28.5 mg/5 ml (-)	2000
14	Amoxycillin I.P. 500mg Injection	300
15	Amoxycillin Trihydrate Dispersible 125mg Tablets	3000
16	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXYCILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID : 500 mg + 125 mg (Tab)	25500
17	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE Syrup 125mg/5ml 60ml Phial	100
18	AMOXYCILLIN TRIHYDRATE WITH CALVUNATE POTASSIUM Inj. 1.2g Dry Powder	300
19	AMOXYCILLINE TRIHYDRATE WITH CLAVULANATE : 250 mg+125 mg (Tab)	32000
20	AMOXYCILLINE TRIHYDRATE WITH CLAVULANATE POTASSIUM : - 500MG+100mg : Dry powder (Inj)	300
21	Antacid Tablet, Each chewable tablet contains Magnesium Trisilicate 250 mg, Dried Aluminium Hydroxide Gel 120 mg, Peppermint Oil 0.003 ml 10 per strip	10000
22	ANTI SERUM POLYVALENT SNAKE VENOM ASV : USP - 10 ml : LYOPHILIZED POWDER WITH DILUENT (Inj)	30
23	ARTESUNATE : IP - 60 mg : Dry powder (Inj)	500
24	ASCORBIC ACID : 500 mg (Tab)	105000
25	Aspirin Gastro Resistant Tab IP 75 mg	6500
26	ATENOLOL : 50 mg (Tab)	5500
27	ATORVASTATIN CALCIUM : 10 mg (Tab)	3000
28	ATROPINE SULPHATE : IP - 0.6 mg/ml : 1ml (Inj)	400
29	AZITHROMYCIN : 500 mg (Tab)	51000
30	B COMPLEX : VITAMIN B1 5 MG THIAMINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B2 5MG RIBOFLAVIN VITAMIN B6 2MG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE VITAMIN B3 NICOTINAMIDE 50 MG VITAMIN B5 CALCIUM PANTOTHENATE 5 MG Tablet	195000
31	BENZYL BENZOATE APPLICATION : 25% w/w (-)	1500
32	Betamethasone :0.5mg (Tab)	19500
33	BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : 4 mg/ml : 1ml (Inj)	1600
34	Betamethasone Valerate Cream,0.1% W/W, 15 Gm Tube	1100
35	BISACODYL ENTERIC COATED : 5 mg (Tab)	2500
36	BROMHEXINE HYDROCHLORIDE Tablet 4mg 10 strip	5000
37	BUDESONIDE . 0.5mg/ml Raspule 2ML	500
38	BUDESONIDE Inhaler 100mcg	300

39	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IP 0.5%W/V : 20ml (Inj)	20
40	Calcium Vitamine D3 Suspension (Each 5ml contains Calcium Carbonate eq. to Elemental Calcium 250mg+Vitamin D3 -125 IU), 200 ml Bottle)	300
41	CALCIUM CARBONATE WITH VITAMIN D3 : 1250mg+250IU (Tab)	81000
42	CALCIUM CITRATE 500 mg Elemental Calcium	115000
43	CARBAMAZEPINE : 400 mg CR (Tab)	500
44	Cefixime Oral Suspension IP, 100mg/5ml, 30ml Bottle	1400
45	CEFIXIME TRIHYDRATE : 200 mg (Tab)	55000
46	CEFOTAXIME SODIUM : IP - 1 gm : dry powder (Inj) in vial	500
47	CEFOTAXIME SODIUM : IP - 250 mg : dry powder (Inj)	500
48	CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE : IP - 1 gm : dry powder (Inj)	500
49	CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE : IP - 250 mg : dry powder (Inj)	200
50	CEFTRIAXONE 500 mg : dry powder (Inj)	3700
51	CEPHALEXIN : 250 mg (Caps)	10000
52	CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	5000
53	Cetrizine 5mg/5ml 30ml Syp	300
54	Chloramphenicol 5% w/v Benzocaine 1%w/v : 5% w/v+ 1% w/v Ear Drop 5ML	200
55	CHLOROQUINE PHOSPHATE : 250 mg (Tab)	2000
56	CHLORPHENIRAMINE MALEATE : 4 mg (Tab)	50000
57	CINNARIZINE : 25 mg (Tab)	2000
58	CIPROFLOXACIN : 2 mg/ml : 100ml FFS Bottle	500
59	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 0.3% w/v Eye Drop	1900
60	CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE : 500 mg (Tab)	35000
61	CLOBAZAM : 5mg (Tab)	1000
62	CLONAZEPAM : 0.5 mg (Tab)	500
63	CLOPIDOGREL : 75mg (Tab)	2000
64	CLOTRIMAZOLE : 2% w/w (Cream)	1700
65	CLOTRIMAZOLE VAGINAL : 200 mg (WITH APPLICATOR) (Tab)	1000
66	CLOTRIMAZOLE+LIGNOCAINE HCL Ear Drop 1%+2%w/v 10ml VIAL	100
67	DEXAMETHASONE : 0.5mg (Tab)	36800
68	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE : IP - 4 mg/ml : 2ml (Inj)	3200
69	Dextromethorphan Hydrobromide Syrup 15mg/5ml 100ml with measuring cap	660
70	DEXTROSE : IP - 5% w/v : 500ml (Inj)	200
71	DEXTROSE Injection - 25% w/v : 100ml (Inj)	300
72	DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE : IP - 5% w/v +0.9%W/V : 500ml (Inj)	300
73	DIAZEPAM : IP - 5 mg/ml : 2ml (Inj)	400
74	Diclofenac Gel (Diclofenac Sodium 1% W/W), 30Gm Tube	7864
75	Diclofenac Sodium Inj 75mg/ml, 1ml Ampoule	2900
76	DICLOFENAC SODIUM SR Tablet 100 mg 10 per strip	92500
77	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE - 10 mg/ml : 2ml (Inj)	1600
78	DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	40000
79	DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE : 100 mg (Tab)	20000
80	DIGOXIN : 0.25 mg (Tab)	500
81	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE : 30 mg (Tab)	500
82	DISODIUM HYDROGEN CITRATE : 1.53 gm/5 ml (-)	500
83	DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE : USP - 50 mg./ml. : 5ml (Inj)	50
84	DOMPERIDONE : 10 mg (Tab)	2000
85	DOMPERIDONE SUSPENSION 1 mg/ml 30ML Phial	500
86	DOPAMINE HYDROCHLORIDE :- 40 mg/ml : 5ml (Inj)	50
87	DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE : EQUIVALENT OF 100mg DOXYCYCLINE (Caps)	45000
88	ENEMA GLYCERIN SODIUM CHLORIDE Tube 15% W/w+15% W/v 20ml PKT	300
89	ETHAMSYLATE : 250 mg (Tab)	5050

90	FLUCONAZOLE : 150 mg (Tab)	23600
91	FLUOXETINE HYDROCHLORIDE : 20 mg (Caps)	500
92	FRAMYCETIN SULPHATE : 1% W/w 30gm (Cream)	400
93	FRUSEMIDE : 40 mg (Tab)	800
94	FRUSEMIDE : IP - 10 mg/ml : 2ml (Inj)	300
95	GENTAMICIN SULPHATE : IP - 40 mg/ml : 2ml vial	500
96	Gentamicin Sulphate 0.3%w/v+ Betamethasone0.1%w/v : 0.3% w/v+0.1% w/v (-	200
97	GLIMEPRIDE : 1 mg (Tab)	10000
98	GLIPIZIDE : 5 mg (Tab)	500
99	GLYCOPYRROLATE : IP - 0.2 mg/ml : 1ml (Inj)	20
100	HYDROCORTISONE SODIUM SUCCIINATE : IP - 100 mg : dry powder (Inj)	500
101	IBUPROFEN : 200 mg (Tab)	130000
102	IBUPROFEN Suspension: 100 mg/5 ml , 60 ml bottle with meauring cup	800
103	INDOMETHACIN : 25mg (Caps)	2500
104	Ipratropium Bromide Respule 250mcg/ml, 15ml vial	200
105	IRON AND FOLIC ACID CONTAINING DRIED FERROUS SULPHATE IP : equivalent to ferrous iron 60 mg & folic acid 0.5 mgIFA WIFS LARGE BLUE COLOURED	5000
106	Iron and Folic Acid IFA Large Tablet Containing 60 MG Elemental Iron + 500 mcg Folic Acid, Sugar-Coated, Red Color, 105 Strip	35000
107	IRON SUCROSE CONTAINING FERRIC HYDROXIDE AS COMPLEX WITH SUCROSE EQ TO ELEMENTAL IRON 20MG/ML : 20 mg/ml : 5ml (Inj)	400
108	IRON WITH FOLIC ACID : 20 mg+100 mcg/ml 100ml (Syr)	400
109	ISOSORBIDE DINITRATE : 5 mg (Tab)	2100
110	ISOSORBIDE MONONITRATE : 10 mg (Tab)	500
111	ISOXUPRIME HYDROCHLORIDE : 10 mg (Tab)	1000
112	Lactulose Syrup 10gm/15ml,100ml Bottle	2000
113	LEVOCETIRIZINE Tablet 10 mg 10 strip	70000
114	LEVOCETIRIZINE Syrup 2.5mg/5ml, 60ml Bottle	800
115	LEVOCETIRIZINE Tablet 5mg, 10 per strip	15000
116	LEVOFLOXACIN : 500 mg (Tab)	30000
117	LEVOSALBUTAMOL : 1 mg/5 ml (Syr)	300
118	LIGNOCAINE GEL : 2%W/V 30GM	100
119	LIGNOCAINE HCL : 2%w/w : 30ml (Inj)	150
120	Mannitol Injection 20 % W/V in 100 ml FFS Bottle	50
121	METFORMIN HYDROCHLORIDE : 500 mg (Tab)	20500
122	METHYLCOBALAMINE - 500 mcg/ml : 3ml (Inj)	500
123	METHYLCOBALAMINE (B12) : 500 mcg (Tab)	25000
124	METRONIDAZOLE : 400 mg (Tab)	65000
125	METRONIDAZOLE : IP - 5 mg/ml : 100ml (Inj)	1500
126	METRONIDAZOLE BENZOATE Suspension 40mg/ml (-)	400
127	MICONAZOLE Cream 2% 20G TUBE	3800
128	MISOPROSTOL : 200 mcg (Tab)	1000
129	MONTELUKAST SODIUM : 10 mg (Tab)	20000
130	Multivitamin B complex Zinc 200ml Bottle with measuring cap	1000
131	Multivitamin Drops Each ml contains Vit-A-3000IU, Vit D3 - 300IU, Vit- B1 -1mg, Riboflavine Phosphate Sodium- 2mg, D-Pentenol-2.5mg, Niacinamide- 10mg, Pyridoxime HCL- 1mg, Cynocobalamine 1 mcg, Lysine HCL 10 mg, 15 ml vial with	500
132	Multivitamin tab (With B Complex, Vitamin C, Vitamin D3)	10000
133	Nitrofurantoin :100 mg (Tab)	4400
134	NORFLOXACIN : 400 mg (Tab)	10000
135	OFLOXACIN : 200 mg (Tab)	20000
136	OLANZAPINE : 10mg (Tab)	500

137	OMEPRAZOLE : 20 mg. (Caps)	122000
138	ONDANSETRON HCL : 4 mg (Tab)	12000
139	Ondansetron IP Inj 2 Mg/Ml in 2 ML Ampoule	900
140	ORAL REHYDRATION SALTS CITRATE (W.H.O Formula) ORS 20.5Gm. Each sachet Contains Sodium Chloride IP 2.6g Potassium Chloride IP 1.5g Sodium Citrate IP 2.9g Anhydrous Dextorse IP 1	4000
141	ORNIDAZOLE : 500 mg (Tab)	10000
142	OXYTOCIN IP - 5IU/ML : 1ml (Inj)	200
143	PANTAPRAZOLE Injection 40mg/vial with Dilutant	3500
144	PARACETAMOL : 500 mg (Tab)	140000
145	PARACETAMOL : 650mg (Tab)	90000
146	PARACETAMOL Drop : 100mg/ml (15 ml pack with dropper))	600
147	PARACETAMOL INFUSION Injection 10mg/ml 100ml Bottle	300
148	PARACETAMOL Suspension 250mg/5ml 60ml bottle with measuring cup (E)	200
149	PARACETAMOL SYRUP 125mg/ 5ml	1600
150	PENTAZOCINE LACTATE IP - 30 mg/ml : 1ml (Inj)	500
151	PHENOBARBITONE : 60 mg (Tab)	1000
152	Phenobarbitone Susp 20MG/5 ML, 60 ML Bottle With Measuring Cup	100
153	POVIDIONE IODINE SOLUTION : 5% w/v (-)	200
154	POVIDONE IODINE : 5% W/w (Oint) 15G	800
155	PREDENISOLONE : 10 mg (Tab)	25500
156	PREDENISOLONE SODIUM PHOSPHATE : 1.0% w/v Eye Drop 5ML	200
157	PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE : 25 mg/ml : 2ml (Inj)	200
158	RAMIPRIL : 5mg (Tab)	1000
159	RANITIDINE HYDROCHLORIDE : 150 mg (Tab)	23000
160	RANITIDINE HYDROCHLORIDE : IP - 25mg/ ml : 2ml (Inj)	1500
161	RINGER LACTATE : IP - 0.24%w/vLacticAcid (eq.0.32%w/vSod.Lac.) with0 6%w/vSod.Cl., 0.04%w/vPot .Cl. & 0.027% w/vCal Cl : 500ml (Inj)	1140
162	Salbutamol Aerosol 200MTD 100mcg/Metered dose inhaler	200
163	SALBUTAMOL Respule 5mg/ml, 15 ml Bottle	200
164	SALBUTAMOL SULPHATE : 4 mg (Tab)	25000
165	SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONE 250 MCG 120 MDI 25 mcg + 250 mcg	300
166	SERRATIOPEPTIDASE : 10mg (Tab)	20000
167	SILVER SULPHADIAZINE : 1% W/w 250gm (Cream)	100
168	SODIUM CHLORIDE : IP - 0.9% w/v : 500ml (Inj)	900
169	Sodium Chloride Injection 0.9 % w/v in 100ml FFS Bottle	800
170	SODIUM VALPORATE / valporic acid Susp. 200mg/5ml, 100 ml bottle with	100
171	SODIUM VALPROATE : 200 mg (Tab)	6000
172	Syrup multivitamin (with B Complex, Vitamin c, Vitamin D3) 100ml bottle with measuring cup	700
173	Tab Ivermectin 6 Mg	2000
174	TELMISARTAN 40 mg (Tab)	6500
175	THEOPHYLLINE WITH ETOPHYLLINE : IP - 25.3mg+84.7 mg/ml : 2ml (Inj)	1000
176	TINIDAZOLE Tab I.P : 500 mg (Tab)	3000
177	TIOTROPIUM 200 MDI: 9mcg/DOSE Inhaler	200
178	Tramadol Hydrochloride :50 mg Tablets	27000
179	TRANAXAMIC ACID Injection 500mg/5ml ampoule	200
180	TRIMETHOPRIM WITH SULPHAMETHOXOZOLE : 40mg+200mg/5 ml 50ML Phial(-	400
181	VERAPAMIL HCL : 40 mg (Tab)	500
182	VILDAGLIPTIN : 50 mg (Tab)	1000
183	VITAMIN A PALMIPATE Arachis oil base Liquid 100000 IU/ml, 100 ml bottle with feeding spoon (to be packed in mono carton)	20

184	VITAMIN A SOFTGEL : 25000IU (-) 10 per Strips	4000
185	Vitamin D3 Tablet/Capsule 60000IU, 10 Tablet per strip/ blister Chewable/non	10000
186	WATER FOR INJECTION in 10ml Ampoule	1000
187	Wax dissolving Ear Drops: Paradichlorobenzene,Benzocaine, Chlorobutanol,Turpentine oil 2% +2.7% + 5% +15%,15 ml Bottle with dropper	200
188	XYLOMETAZOLINE : 0.001 Nasal Drop 10ML	550
189	ZINC SULPHATE DISPERSIBLE DT : eq. to elemental zinc 20mg	10000

देखिये नत्थी 'ङ' के अतारांकित प्रश्न संख्या-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-83 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा0 आर0 के0 वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-74 के उत्तर का संलग्नक।

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने सम्बन्धी कार्य योजना

भारत सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई0सी0डी0एस0) प्रदेश में संचालित की जा रही है। आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा व संदर्भन सेवायें प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, एवं पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सेवायें स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से लाभार्थियों को दी जा रही हैं। अति कुपोषित बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त कैलोरी व प्रोटीन की पूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुपूरक पुष्टाहार दिया जा रहा है। साथ ही किशोरी बालिकाओं के लिये (Scheme for adolescent Girls-SAG) के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को गैर पोषण मद व पोषण मद से लाभान्वित किया जा रहा है। गैर पोषण मद में किशोरी बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त करना, स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाने सम्बन्धी सेवाओं तथा पोषण मद में अनुपूरक पुष्टाहार से लाभान्वित किया जाता है।

समुदाय में पोषण व्यवहार को वृहद् स्वरूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से पोषण अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर में पोषण माह व माह मार्च में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न कन्वर्जेन्स विभागों के माध्यम से बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह समुदाय आधारित गतिविधियों यथा-अन्नप्राशन, गोद भराई, सुपोषण दिवस, किशोरी दिवस, वजन दिवस आदि का आयोजन किया जाता है।

बच्चों में कुपोषण के चिन्हांकन एवं नियमित वृद्धि निगरानी हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेज उपलब्ध कराई गई है।

आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों के सही चिन्हांकन, सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं तकनीकी सुगमता हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है।

भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन ''पोषण ट्रैकर'' के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी की ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेज के माध्यम से नियमित रूप से वजन एवं माप लेकर पोषण ट्रैकर पर अंकित करते हुए उनकी वृद्धि निगरानी की जा रही है।

देखिये नत्थी 'च' के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-86 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के 1–सोमवार हेतु निर्धारित श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–81 का संलग्नक।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

समु0स्वा0केन्द्र का नाम	बिल संख्या	कुल धनराशि	आयकर	नेट आहरण
सामु0स्वा0केन्द्र कौंठ पर आवासीय भवनों (16) पर भवनों की मरम्मत/पेन्टिंग का कार्य	सी–105	471047	9420	461627
सामु0स्वा0केन्द्र सिंघौली, ददरौल के आवासों पर मरम्मत, पेन्टिंग कार्य, सी0एम0ओ0 कार्यालय में वाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं सी0एम0एस0डी0 स्टोर का कार्य	सी–171	1170237	21183	1149054
सामु0स्वा0केन्द्र निगोही, बण्डा एवं कटरा पर 16 आवासों की मरम्मत, पेन्टिंग का कार्य	सी–18	661538	11709	649829
सामु0स्वा0केन्द्र कौंठ, सिंघौली, निगोही, कटरा, मदनापुर, जरियनपुर, बण्डा, भवलखेड़ा, जलालाबाद एवं पुवायों पर मरम्मत व पेन्टिंग का कार्य	सी–36	2162713	38280	2124433
सामु0स्वा0केन्द्र बण्डा, निगोही पर मुख्य केन्द्र एवं 05 आवासीय भवनों की मरम्मत व पेन्टिंग का कार्य	सी–88	666702	6628	660074
सामु0स्वा0केन्द्र जलालाबाद पर जनरेटर प्लेटफार्म व सी0एम0ओ आवास पर गेट लागाने का कार्य	सी–90	36768	325	36443
योग		5169005	87545	5081460

पी0एस0यू0पी0-एल0-196 विधान सभा (368)-10-01-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।